



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2006/चैत्र 17, 1928

No. 67]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2006/CHAITRA 17, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2006

सं. 1(आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/प्रक्रिया पुस्तक/ए एम 07/पी सी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथा निहित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में 7 अप्रैल, 2006 तक अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट शामिल करते हुए तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर यथा उपलब्ध प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के वार्षिक परिशिष्ट को, एतद्वारा, अधिसूचित करते हैं। यह 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं मदेन अपर सचिव

अनुलग्नक

प्रक्रिया पुस्तक

(खण्ड-1)

1 सितम्बर, 2004—31 मार्च, 2009

1-4-2006 से प्रभावी

अध्याय—एक

प्रस्तावना

अधिसूचना

1.1 विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 2002—2007 अवधि के लिए बनाई आयात-

1057 GI/2006

निर्यात नीति को संशोधित कर उसके स्थान पर 2004—2009 के लिए विदेश व्यापार नीति को अधिसूचित किया है।

यह नीति जब तक कि आवश्यक ना हो, 1 सितम्बर, 2004 से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2009 तक चलती रहेगी।

नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अनुसार महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा समेकित प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), और प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2) और डी ई पी बी दरों की अनुसूची नामक पुस्तकों के संकलन को अधिसूचित करते हैं।

समय-समय पर यथासंशोधित ये संकलन 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेंगे।

उद्देश्य

1.2 इस प्रक्रिया पुस्तक का उद्देश्य आसान पारदर्शी और ई डी आई संगत प्रक्रियाओं के द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनावे गये नियमों और आदेशों तथा निर्यात-आयात नीति (2002—2007) के स्थान पर विदेश व्यापार नीति (2004—2009) को लागू करना जिससे अनुफलन और विदेश व्यापार के प्रबंधन का संचालन करना आसान हो।

परिभाषा

1.3 इस प्रक्रिया पुस्तक के उद्देश्य हेतु, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, उसके तहत बने नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति (2004—2009) में उल्लिखित परिभाषाएं लागू होंगी।

अध्याय—दो

निर्यात और आयात से संबंधित सार्वजनिक सूचनाएं

नीति

2.1 नीति के अध्याय-2 में निर्यात और आयात के बारे में सार्वजनिक सूचनाएं से संबंधित नीति दी गई है।

आयात/निर्यात के देश

2.2 जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी देश से/को आयात/निर्यात करना वैध होगा। तथापि, ईराक से/को हथियारों और संबंधित सामग्री के आयात/निर्यात निषिद्ध होगा।

तथापि, उपर्युक्त प्रावधान आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत यथा आवश्यक सभी शर्तों, अथवा लाइसेंस की जरूरत, अथवा अनुमति के मद्दे होंगे।

आवेदन-शुल्क

2.3 आवेदक की नीति के किसी प्रावधान और इस प्रक्रिया पुस्तक के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय जब तक अन्यथा छूट न दी गई हो, विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क की मात्रा, भुगतान का तरीका, शुल्क-वापसी की प्रक्रिया और शुल्क से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणियां परिशिष्ट-21ख में दी गई हैं।

क्षेत्रीय प्राधिकारियों की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता

2.4 जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रत्येक आवेदन पत्र, परिशिष्ट-1 में उल्लिखित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

2.5 किसी आयात/निर्यात लाइसेंसिंग/प्रमाण पत्र/अनुमति या अन्य प्रयोजन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र को नीति/प्रक्रिया के संबंधित प्रावधानों के अधीन यथा अपेक्षित हर प्रकार से पूरा किया जाना चाहिए और आवेदक द्वारा नीति के पैराग्राफ 9.9 में जैसा परिभाषित किया गया है के अनुसार उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

अधूरे आवेदन पत्र को विशिष्ट कारण बताते हुए रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, मैनुअल आवेदनों के मामले में आवेदक को एम एस वडी फॉर्मेट में आवेदन की एक साफ्ट कापी प्रस्तुत करनी होगी।

आयातक/निर्यातक का प्रोफाइल

2.6 प्रत्येक आयातक/निर्यातक को 'आयात निर्यात प्रपत्र' के भाग-1 में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को एक बार आयातक/निर्यातक प्रोफाइल प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 'आयात निर्यात प्रपत्र' के भाग-1 में दी गई सूचना को अपने डाटा-बेस में डालना होगा ताकि बार-बार सूचना मांगने की जरूरत ना पड़े। 'आयात निर्यात प्रपत्र' के भाग-1 में दी गई सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में आयातक/निर्यातक लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा।

डाक टिकट लगा स्व-पता लिफाफा

2.7 आवेदक मांगे गए कागजातों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने हेतु 40 × 15 सेंमी का स्व-पता लिफाफा प्रस्तुत करेगा जिस पर निम्नानुसार डाक टिकट लगी हो :—

(क) स्थानीय क्षेत्र के भीतर	— 20 रुपए
(ख) 200 कि.मी. तक	— 25 रुपए
(ग) 200 से 1000 कि.मी. तक	— 30 रुपए
(घ) 1000 कि.मी. से अधिक	— 50 रुपए

आयातक-निर्यातक कोड संख्या छूट प्राप्त श्रेणियां

2.8 आयातकों-निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों को आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने से छूट है :—

- (1) विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों से छूट) आदेश, 1993 की धारा 3(1) [उप-धारा (ड) और (ठ) को छोड़कर] में शामिल आयातक तथा धारा 3(2) [उप-धारा (झ) और (ट) को छोड़कर] में शामिल निर्यातक।
 - (2) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग।
 - (3) जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार अथवा विनिर्माण या कृषि से असम्बद्ध माल का आयात या निर्यात करते हैं।
 - (4) जो व्यक्ति नेपाल से/को माल का आयात/निर्यात करता है बशर्ते कि एकल परेषण का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय 25,000 रुपए से अधिक न हो।
 - (5) जो व्यक्ति भारत म्यांमार के सीमा क्षेत्रों से म्यांमार से/को माल का आयात/निर्यात करता है बशर्ते कि एकल परेषण का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय 25,000 रुपए से अधिक का न हो।
- “तथापि, उपर्युक्त श्रेणी-2 द्वारा निर्यात के मामलों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2, परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध विशेष रसायनों, जीवों, सामग्रियों उपकरणों और प्रौद्योगिकियां (एम सी को एम ई टी) के निर्यात के लिए आयातक-निर्यातक कोड (आई ई सी) संख्या प्राप्त करने की छूट लागू नहीं होगी।”
- (6) आयात-निर्यात प्रयोजन हेतु निर्यातक/आयातक की श्रेणियों द्वारा उनके प्रति उल्लिखित निम्नलिखित स्थाई आई ई सी संख्या का उपयोग किया जाएगा।

क्र. सं.	कोड सं.	आयातक/निर्यातक की श्रेणियां
1	2	3
1.	0100000011	केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियां।
2.	0100000029	राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियां।
3.	0100000037	डिप्लोमेटिक कार्मिक, भारत में काउंसिलर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी।
4.	0100000045	विदेश जाने/लौटने वाला भारतीय बैगेज नियमों के अधीन लाभों का दावा करता हो।
5.	0100000053	व्यक्ति/संस्थान/अस्पताल को व्यापार या विनिर्माण अथवा कृषि से जुड़ा न हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात या निर्यात करता हो।

1	2	3
6.	0100000061	वह व्यक्ति जो नेपाल को/से माल का निर्यात/आयात करता हो बशर्ते कि एक खेप का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 25000/- भारतीय रुपये से अधिक न हो।
7.	0100000070	वह व्यक्ति जो म्यांमार को/से भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से माल का निर्यात/आयात करता हो बशर्ते कि एक खेप का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 25000 भारतीय रुपये से अधिक न हो।
8.	0100000088	फोर्ड फाउंडेशन।
9.	0100000096	आयातक जिसने ए टी ए कार्नेट के प्रावधानों के अधीन मेले/प्रदर्शनियाँ या इसी प्रकार के आयोजनों में प्रदर्शन का उपयोग करने के लिए माल का आयात करता हो।
10.	01000000100	निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रुप संदर्भ प्रयोगशाला, मुम्बई या उनके द्वारा प्राधिकृत कार्यालय।
11.	01000000126	व्यक्ति/खैराती संस्था/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन जो माल का आयात करती है और जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ित द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

टिप्पणी:—

वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने "पैन" प्राप्त किया है को भी, आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करनी होगी। गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपर्युक्त अनुसार स्थानीय आई ई सी संख्या प्रयोग करनी होगी।

2.9 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र : आयातक-निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए आवेदक का पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार के तहत, कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय और अन्य के मामले में मुख्यालय आता हो 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में आयातक-निर्यातक कोड संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करेगा और समर्थन में उसके साथ निर्धारित दस्तावेज लगाना होगा। एस टी पी आई/ई एच टी पी/बी टी पी ईकाइयों के मामले में, विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय जिसका उस जिले में क्षेत्राधिकार होगा जिसमें एस टी पी आई ईकाइ का प्रधान कार्यालय/पंजीकरण है को आयातक-निर्यातक कोड जारी अथवा संशोधित करेंगे।

एक "पैन" नम्बर पर एक ही आई ई सी जारी की जाएगी। कोई भी प्रोपराइटर सिर्फ एक आई ई सी प्राप्त कर सकता है तथा ऐसे मामले में जहाँ एक प्रोपराइटर को एक से अधिक आई ई सी नम्बर आबंटित

कर दिए गए हैं वह इसे निरस्त करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को लौटाएगा।

2.9.1 आयातक-निर्यातक कोड फार्मेट और विवरण : संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी परिशिष्ट-18ख में दिए गए फार्मेट पर आई ई सी संख्या जारी करेगा। ऐसे आयातक-निर्यातक कोड संख्या की एक प्रति संबंधित बैंक (आई ई पी आवेदन पत्र में दिए गए बैंक के अनुसार) को भेजी जाएगी।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या का समेकित विवरण, परिशिष्ट-18ग में दिए गए बैंक के अनुसार, परिशिष्ट-18घ में दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण विभाग के कार्यालय को भेजा जाएगा।

2.9.2 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की वैधता : किसी आवेदक को आबंटित आयातक-निर्यातक कोड संख्या, परिशिष्ट-18ख में दिए आई ई सी के प्रपत्र में उल्लिखित इसकी सभी शाखाओं/प्रभागों/यूनिटों फैक्ट्रियों के लिए वैध होगा।

2.9.3 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट प्रति : जहाँ आयातक-निर्यातक कोड संख्या गुम हो जाता है, तो वह जारी करने वाला प्राधिकारी, आयातक-निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट की मंजूरी के अनुरोध पर विचार करेगा जिसने उसे मूल प्रमाणपत्र जारी किया था, यदि एक शपथपत्र संलग्न हो।

2.9.4 आयातक-निर्यातक कोड संख्या को लौटाना : यदि कोई आयातक-निर्यातक कोड संख्या धारक आबंटित कोड संख्या का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करके उक्त कोड संख्या को लौट सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी तत्काल उसे रद्द कर देगा और सीमाशुल्क तथा क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के सूचनार्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेगा।

2.9.5 अनिवार्य विवरण : हटा दिया गया है।

2.10 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट प्रति : आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदों के आयात या निर्यात के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र, इस प्रक्रिया पुस्तक के सम्बद्ध अध्यायों में विनिर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को फार्म पर प्रस्तुत करना होगा।

2.11 आयातक-निर्यातक कोड संख्या को लौटाना : संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्दिष्ट पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि का आयात संयुक्त राज्य निर्यात विनियमों के अधीन किया जाएगा।

संयुक्त राज्य से ऐसी मदों के आपूर्तिकर्ताओं को, भारतीय आयातकों द्वारा संयुक्त राज्य आपूर्तिकर्ताओं को भेजे गए आयात प्रमाणपत्र के आधार पर निर्यात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा। आयात प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (आई. सी. आई. ए.) निम्नलिखित होंगे:—

(1) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग।

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, तकनीकी सहायता खण्ड (टी एस डब्ल्यू), इसके अधीन पंजीकृत संगठित क्षेत्र की यूनिटों के लिए कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर।

(3) रक्षा से संबंधित मदों के लिए रक्षा मंत्रालय।

(4) लघु उद्योगों तथा इकाइयां जो उपर्युक्त में से किसी के लिए तथा उपर्युक्त से भिन्न के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार,

(5) उपर्युक्त किसी भी ओर से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन (डी सी)

आयात प्रमाणपत्रों के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में अनुरोध करना होगा। परिशिष्ट-31 के में दिए गए आयात प्रमाण पत्र आई. सी. आई. ए. द्वारा सीधे ही आयातक को दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि (1) विदेश मंत्रालय (ए एम एस अनुभाग), नई दिल्ली (2) इलैक्ट्रॉनिकी, विभाग, नई दिल्ली, और (3) विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली को दी जाएगी।

तथापि, आई टी सी (एच एस) में यथा प्रतिबंधित मदों के बारे में इस आयात लाइसेंस/अनुमति/प्रमाणपत्र को आयात लाइसेंस के स्थान पर नहीं माना जाएगा और ऐसे मदों के लिए जब अपेक्षित हो आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2.12 लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र/सीसीपी/निर्यात लाइसेंस के आयात की वैधता — लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के आयात की वैधता, लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के जारी होने की तिथि से निम्नवत होगी :—

- | | |
|---|---|
| (1) नीति के अध्याय 4 के अनुसार रत्न और जेवरों के लिए अग्रिम लाइसेंस (वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस सहित)/ डी एफ आर सी और प्रतिपूर्ति लाइसेंस | 24 माह |
| (2) ई पी सी जी लाइसेंस (स्पेयर्स के अलावा) | 36 माह |
| (3) स्पेयर्स, रिफ्रेक्टरींग कैटालिस्ट और उपभोक्ता के लिए ई पी सी जी लाइसेंस | ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात दायित्व अवधि के साथ समाप्त |
| (4) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न सी सी पी और शुल्क हकदारी पास बुक योजना सहित अन्य | 24 माह |
| (5) मान्य निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस (वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम लाइसेंस सहित) | 24 माह अथवा परि-योजना की कार्य अवधि के साथ समाप्त होना, जो भी बाद में हो। |

2.12.1. जहाँ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति/शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख, माह के अंतिम दिन से पहले पड़ती है तो लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति/शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र को माह के अंतिम दिन तक वैध माना जाएगा।

यह प्रावधान पुनर्वैधीकरण लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति/शुल्क शाखा प्रमाणपत्र के आवेदनों पर भी लागू है।

2.12.2. "वैधता की अवधि का अर्थ है, शिपमेन्ट की अवधि अथवा लाइसेंस प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के अधीन शामिल माल का प्रेषण। आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की वैधता शिपमेन्ट की तारीख/इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9.11क में यथा उल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं देश से माल के प्रेषण की तारीख होगी न कि भारतीय पत्तन पर माल की पहुंचने की तारीख।

2.12.3 ऊपर पैरा 2.12.2 के प्रावधान सेवा प्रदायकों, लक्ष्योपरि योजना और विशेष कृषि उपाज योजना के लिए उल्लिखित डी ई पी बी, शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाणपत्र, पर लागू नहीं होंगे। स्तरधारकों और सेवा प्रदायकों, लक्ष्योपरि योजना विशेष कृषि उपाज योजना के लिए डी ई पी बी, शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाणपत्र जो शुल्क साख हकदारी के अंतर्गत आते हैं की वास्तविक वैधता शुल्क जमा करने की तारीख तक मान्य मानी जाएगी।

2.12.4. इसी प्रकार यदि मूल या बड़े हुए निर्यात दायित्व की समाप्ति की तारीख चाहे महीने के अंत में पड़ती हो, निर्यात दायित्व अवधि की वैधता महीने के अंतिम दिन तक मानी जाएगी। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, प्रतिबन्धित मदों हेतु निर्यात लाइसेंस की मूल वैधता जारी होने की तिथि से 12 महीने होगी।

2.13. आयात/निर्यात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति का पुनः वैधीकरण : संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसने लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति जारी किया था, के द्वारा गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति का एक बार में छः माह की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है।

2.13.1 तथापि, हस्तांतरणीय लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति, स्टॉक तथा बिक्री लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों/प्राधिकार पत्र/अनुमति की पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र/प्राधिकार पत्र, सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास ही समाप्त न हो गया है।

2.13.2 लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र अनुमति पत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कब्जे के दौरान समाप्त हो जाने के मामलों में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के कब्जे की अवधि के लिए कार्यालय प्रमुख के विशेष आदेशों के तहत लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र परमिट का पुनर्वैधीकरण अनुमत होगा।

2.13.3. पैरा 2.13 के प्रावधानों के बावजूद और ऊपर दिए गए पैरा 2.13.1 तथा 2.13.2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, जहाँ

लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र, अनुमति, क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास रही है की अवधि के लिए पुनर्वैधता रहेगी।

प्रतिबन्धित मर्दों के आयात के लिए लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन सहित आयात-निर्यात प्रपत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को दिया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन की तारीख को लाइसेंस में उल्लिखित मर्दों के आयात को नियन्त्रित करने वाले सरकारी नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार प्रतिबन्धित सूची लाइसेंस पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन पर विचार करेगा। तथापि, उन मामलों में जहां लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों/प्राधिकार पत्र अनुमति पत्र के पुनः वैधीकरण पर महानिदेशक, विदेश व्यापार को विचार करना है, मूल आवेदन पत्र के साथ टी आर/डिमांड ड्राफ्ट को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा और जिसकी एक स्वसत्यापित प्रति महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत करनी होगी।

निर्यात-आयात लाइसेंसों/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र/सीमाशुल्क निकासी परमिटों की डुप्लीकेट प्रतियाँ 2.14. — जब कोई लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र अथवा वास्तविक प्रयोक्ता शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र खो जाता है तो परिशिष्ट-24 में दिए गए फार्म में शपथ पत्र की प्रति के साथ उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसने मूल लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र जारी किया था।

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, गुणावगुण के आधार पर, मूल लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति को रद्द करने तथा उन संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों, जिनके यहाँ इस लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की मूल प्रति पंजीकृत थी, को सूचित करने के बाद उस लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार-पत्र/अनुमति पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करेगा।

2.15. मुक्त रूप से हस्तांतरणीय लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/प्राधिकार पत्र अनुमति पत्र की डुप्लीकेट प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन के प्रति जारी की जाएगी :—

- (क) बचाए गए शुल्क अथवा शुल्क साख के 10 प्रतिशत के समतुल्य फौस के साथ एक आवेदन पत्र।
- (ख) गुम होने की दर्ज की गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की एक प्रति।
- (ग) नोटरी स्टैम्प पेपर पर मूल शपथपत्र की एक प्रति।
- (घ) डुप्लीकेट लाइसेंसों को जारी करने के कारण सरकार को राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति करने की वचनबद्धता दर्शाने वाला स्टैम्प पेपर जिसमें बचाए गए शुल्क शुल्क साख की राशि कवर होती है।

2.15.1 तथापि, जब लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र सरकारी एजेन्सी द्वारा गुम हो जाता है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो (क) से (घ) तक के दस्तावेज नहीं माँगे जाएंगे।

ऐसे मामलों में, लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए पुनः वैध हो जाएंगे। चाहे नीचे कुछ भी लिखा हो।

2.15.2 क्षेत्रीय प्राधिकारी, लाइसेंस जारी करने से पूर्व मूल लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/पत्र में उल्लिखित पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी से मूल लाइसेंसों/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र के उपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

डुप्लीकेट लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र केवल उस बकाया हेतु जारी किया जाएगा, जिसके बारे में पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार उपयोग में नहीं लाई गई हो।

2.15.3 डुप्लीकेट लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र की वैधता मूल लाइसेंस के साथ समाप्त होगी और इसी लिए यदि मूल लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र की वैधता समाप्त हो गई हो तो किसी अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

तथापि, सीमाशुल्क/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा डी ई पी बी/डी एफ आर सी गुम हो जाये तो छः महीने हेतु डुप्लीकेट लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र जारी होगा।

तथापि, डी ई पी बी गुम होने के मामले में, जिसमें सीमाशुल्क या क्षेत्रीय प्राधिकारियों का कोई वास्तव न हो, जारी की गई डुप्लीकेट डी ई पी बी की वैधता अवधि आवेदन करने की तारीख को मूल डी ई पी बी की बकाया वैधता अवधि के बराबर होगी।

2.15.4 पैरा 2.15 (क) में दिया हुआ 10 प्रतिशत बचाव शुल्क डीएफआरसी पर लागू होगा और आयात निर्यात फार्म के उप खण्ड-5 की क्रम सं. 6 में उपलब्ध सूचना के अनुसार शेष मात्रा और समानुपातिक लागत बीमा भाड़ा मूल्य हेतु बचाए गए शुल्क के आधार पर राशि को परिकलित किया जाएगा। तथापि, शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र यथा डी ई पी बी, पैरा 2.15 (क) में दर्शाई 10 प्रतिशत शुल्क क्रेडिट गुमशुदा शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र पर उपलब्ध क्रेडिट शेष के 10 प्रतिशत के बराबर उपलब्ध होगा।

2.15.5 2.15.2 तथा 2.15.3 पैरा के प्रावधान, पैरा 2.14 तथा 2.15 दोनों के मामले में लागू होगी।

पहचान पत्र

2.16 लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों से अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए आयातक और निर्यातक को प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक और प्राधिकृत कर्मचारियों (तीन से अधिक नहीं) को पहचान-पत्र जारी किए जा सकते हैं।

तथापि लिमिटेड कंपनियों के मामले में, क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख तीन से अधिक पहचान-पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकता है।

पहचान-पत्र जारी करने के लिए आवेदन परिशिष्ट 20क में दिए गए फार्म पर किया जा सकता है।

तथापि लिमिटेड कंपनियों के मामले में, क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख तीन से अधिक पहचान-पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकता है। पहचान-पत्र जारी करने के लिए आवेदन परिशिष्ट-20क में दिए गए फार्म पर किया जा सकता है।

दस्तावेज/लाईसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पहचान-पत्र धारक को दे दिए जाएंगे तथा दस्तावेज/लाईसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र आदि के गुम जो जाने की जिम्मेदारी विदेश व्यापार महानिदेशालय के किसी अधिकारी की नहीं होगी।

पहचान-पत्र खो जाने के मामले में, डुप्लीकेट पहचान-पत्र, शपथ पत्र देने के आधार पर जारी किया जा सकता है। पहचान-पत्र परिशिष्ट 20ख में उल्लिखित प्रपत्र में जारी किए जाएंगे और पहचान-पत्र जारी होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि तक वैध होगा।

साधारण परिस्थितियों में, एक प्राधिकृत कर्मचारी को उसकी कंपनी से संबंधित एक पहचान-पत्र अर्पित किया जाता है। तथापि, एक ही डायरेक्टर/पार्टनर ग्रुप कंपनी तथा समकक्ष मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख लिखित में कारण दर्ज करने के बाद बहुप्रयोजन पहचान-पत्र जारी कर सकता है।

प्राधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार

2.17 आयातक/निर्यातक और उनके कर्मचारी क्षेत्रीय प्राधिकारियों और साक्षात्कार की मंजूरी के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के पास के और साक्षात्कार की मंजूरी के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के पास के कार्यालयों में आसानी से आ जा सकेंगे। विशेष अभ्यावेदन देने के लिए ऐसे अधिकारी आयातक/निर्यातक के किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी साक्षात्कार/स्पष्टीकरण की अनुमति दे सकते हैं। साक्षात्कार/स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी के ई.मेल के माध्यम से भी किए जा सकते हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्यात

2.17 आयातक/निर्यातक और उनके कर्मचारी क्षेत्रीय प्राधिकारियों और साक्षात्कार की मंजूरी के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के पास के कार्यालयों में आसानी से आ जा सकेंगे। विशेष अभ्यावेदन देने के लिए ऐसे अधिकारी आयातक/निर्यातक के किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी साक्षात्कार/स्पष्टीकरण की अनुमति दे सकते हैं। साक्षात्कार/स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी के ई.मेल के माध्यम से भी किए जा सकते हैं।

2.18 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के संबंध में लघु उद्योग एककों से भिन्न अन्य एककों को नई क्षमताओं का सृजन करने या इनमें विस्तार करने की अनुमति है बशर्ते कि उन्होंने उद्योग (विकास

और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो।

यह ऐसे लाइसेंस की शर्त है कि विनिर्माता उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व पूरा करेगा और लाइसेंसधारी को इस आशय की विधिक वचनबद्धता विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। निर्यात दायित्व को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मानीटर किया जाएगा।

गोदामों की सुविधा

2.19 सार्वजनिक निजी सीमाशुल्क वाण्डेड गोदाम, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय-9 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए घरेलू ट्रेडिंक क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसे गोदाम की नीति के पैरा 2.28 की मदों को आयात करने की अनुमति होगी।

माल की प्राप्ति पर, गोदाम इस माल को यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए रख सकेगा। यथा लागू सीमाशुल्क के भुगतान करने पर घरेलू उपभोग के लिए आगम-पत्र और लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र की प्रस्तुति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के प्रति माल की निकासी की जा सकती है बशर्ते कि सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा घरेलू उपभोग की इन वस्तुओं की निकासी का आदेश दिया गया हो।

शुल्क मुक्त श्रेणियों/शुल्क रियायत श्रेणियों के मद्दे निपटान के मामलों में, शुल्क में छूट रियायत, जैसा भी मामला हो की अनुमति दी जा सकती है।

डी.ई.पी.बी. के प्रति निकासी के मामले में, आयात पर सीमाशुल्क को डीईपीबी क्रेडिट के मद्दे समायोजित किया जा सकता है।

माल का सीमाशुल्क के भुगतान किए बिना पुनः निर्यात किया सकता है बशर्ते कि (1) ऐसे माल के मामले में शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो, और (2) ऐसे माल का निर्यात करने के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया हो।

आयात, स्टोरेज, निकासी या पुनः निर्यात, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों तथा नियमों, आदेशों अथवा इन उपबंधों के संबंध में जारी अधिसूचनाओं या अनुदेशों के अधीन होगा।

अग्रिम लाइसेंस तथा ई पी सी जी के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन

2.20. प्रत्यक्ष आयात के मामले में लाइसेंस/प्राधिकार धारक को सीमाशुल्क से माल की निकासी से पूर्व, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा।

प्रत्यक्ष आयात के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी लाइसेंस/प्राधिकार पत्र में

निम्नलिखित शर्त को पृष्ठान्तिक कर देंगे :

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता जो लागू हो संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना/परिपत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी।

तथापि, स्वदेशी माल की प्राप्ति के मामले में, स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं या एजेंसियों से माल की प्राप्ति से पूर्व लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति धारक क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :—

क्र.सं. निर्यातक की श्रेणी	बैंक गारंटी या विधिक वचनबद्धता के संबंधित प्रावधान
----------------------------	--

1	2	3
1.	सभी स्वरधारक (मरचैन्डाईज निर्यातक तथा सेवा प्रदायक)/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू)	विधिक वचनबद्धता (एल यू टी)
2.	विनिर्माता निर्यातक (प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्मों को छोड़कर)	विधिक वचनबद्धता (एल यू टी)
	(क) केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत	
	(ख) पिछले वर्ष में कम से कम रु. 1 करोड़ और उस से अधिक का कारोबार	
	(ग) पिछले दो वित्त वर्ष में निर्यात किया हुआ	
3.	विनिर्माता निर्यातक	
	(क) केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत	विधिक वचनबद्धता (एल यू टी)
	(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 1 करोड़ से अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया हो ऊपर उपबंध (ख) की वैधता के अनुरूप निर्यातक को जहाँ फैक्ट्री स्थापित है के क्षेत्राधिकार अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा	
4.	सभी निर्यातक	
	(क) पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में रु. 5 करोड़ से अधिक निर्यात कारोबार	विधिक वचनबद्धता (एल यू टी)
	(ख) अच्छा ट्रेक रिकार्ड तथा 3 वर्ष का निर्यात निष्पादन	
5.	अन्य विनिर्माता निर्यातक जो 1, 2, 3 व 4 में शामिल न हो (प्रोपराइटरशिप व पार्टनरशिप फर्मों के अतिरिक्त)	15 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा सैस
	(क) पिछले 3 वर्ष से निर्वात कर रहे हो या	यदि लागू हो कौ बैंक गारंटी, बाण्ड के साथ
	(ख) 3 वर्षों में किसी भी वर्ष निर्यात करते हों तथा निम्नलिखित शर्तों को	

1	2	3
	पूरा किया हो उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो, या राज्य बिक्री कर प्राधिकारी के साथ पंजीकृत को निम्नलिखित प्रस्तुत करने की आवश्यकता है :	
	(i) सीमा शुल्क परिपत्र सं. 74/2003 दिनांक 21-8-2003 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पिछले वर्ष के निर्यात का प्रमाणपत्र और	
	(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र व एक्सआईज कंट्रोल कोड (ई. सी. सी.) या राज्य बिक्री कर प्राधिकारियों जैसा भी मामला हो द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र यह प्रावधान श्रेणी (क) के लिए आवश्यक नहीं है।	
6.	विनिर्माता कम्पनियों (जो प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप से अलग हों तथा जो विनिर्माता भी हो) जिन्होंने पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात न किया हो परन्तु निम्नलिखित मापदण्डों में खरी उतरती है :—	15 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा सैस यदि लागू हो, के बाण्ड व बैंक गारंटी
	(i) कम्पनी, केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया हो (जब तक मुक्त न किया हो); और	
	(ii) कम्पनी, राज्य बिक्री कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो तथा बिक्री कर का भुगतान किया हो (जब तक मुक्त न किया हो); और	
	(iii) कम्पनी ने अपना आडिट किया हुआ बैलेन्स शीट प्रस्तुत किया तथा प्लान्ट व मशीनरी में न्यूनतम निवेश 50 लाख हो।	
7.	मरचैन्ट निर्यातक, सभी प्रकार के प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्मों (स्तरधारक/पी. एस. यू. तथा अपर श्रेणी 4 के अतिरिक्त)	100 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा सैस यदि लागू हो, के बाण्ड व बैंक गारंटी
8.	ऊपर श्रेणी 1 व 4 के सेवा प्रदायक के अतिरिक्त	उत्पाद शुल्क और शिक्षा चुंगी पर बचाये गये शुल्क के 100 प्रतिशत सीमाशुल्क बैंक गारंटी का बाण्ड

तथापि निम्न दो श्रेणियों के विनिर्माताओं/मरचैन्ट निर्यातकों को जोखिम प्रोफाइल के आधार पर 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा शिक्षा चुंगी यदि लागू हो, बाण्ड व बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है। यह कार्यालय प्रमुख जो कि उप-महानिदेशक, विदेश व्यापार के पद से नीचे

का न हो, को कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड करके निर्धारित किया जा सकता है :—

(क) गंभीर अनियमितताओं के लिए डीजीएफटी/सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद के प्रतिकूल नोटिस में आया हो।

(ख) बड़े हुए निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिकूल ट्रेक रिकार्ड में हो,

स्वदेशी खरीददारी के मदों के मामलों में जहाँ उत्पाद शुल्क शून्य हो, प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी उसी उत्पाद के मूल सीमाशुल्क का 25 प्रतिशत होगी। बैंक गारंटी व विधिक वचनबद्धता परिशिष्ट-25क व 25ख में दिये गये शर्तों के अनुसार वैध होगी। बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की वैधता निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस सम्बंध में लाइसेंस/प्राधिकार पत्र में विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा।

ऊपर श्रेणी 3, 4 व 5 के संबंध में अगर निर्यातक ने पिछले 3 वर्षों में निर्यात न किया हो तो बचाए हुए शुल्क की राशि पर 15 प्रतिशत बैंक गारंटी लगायी जाएगी बशर्ते की सी. आई. एफ. मूल्य स्वदेशी कारोबार का 200 प्रतिशत या आपूर्ति का 200 प्रतिशत एफओबी/एफओआर मूल्य जो भी ज्यादा हो से अधिक न हो। 200 प्रतिशत पात्रता से अधिक के लाइसेंसों/प्राधिकार पत्र में 200 प्रतिशत सीआईएफ मूल्य की पात्रता के अधिक के लिए बचायी हुई शुल्क राशि का 100 प्रतिशत बैंक गारंटी लगायी जाएगी। तथापि निर्यात निष्पादन तथा निर्यात प्राप्ति/आपूर्ति प्राप्ति के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर पात्रता को फिर से जमा कर दिया जाएगा।

ऊपर श्रेणी 2 और 4 के संबंध में, लाइसेंस/प्राधिकार पत्र धारक को सनदी लेखाकार द्वारा जारी निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र परिशिष्ट 26 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

तथापि ई. पी. सी. जी. स्कीम के अधीन कार के आयात/स्वदेशी खरीद पर 100 प्रतिशत बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। स्तर धारक/पी.एस.यू. जो दी गयी शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी/एल.यूटी प्रस्तुत करेंगे, के मामलों को छोड़कर।

ऊपर निर्दिष्ट बैंक गारंटी की छूट/रियायत उन पिछले लाइसेंस/प्राधिकारों के मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ लाइसेंस/प्राधिकार धारक बैंक गारंटी प्रस्तुत कर चुके हैं परन्तु उस तारीख में लाइसेंस धारक बैंक गारंटी छूट के लिए पात्र है।

ऐसे मामलों में जहाँ फर्म ने सीमाशुल्क में स्वदेशी मदों की खरीददारी का पूरे कीमत के लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र अनुमति पत्र के लिए बैंक गारंटी/एल.यूटी का पहले ही निष्पादन किया हो तथा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया हो, को लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष कोई बैंक गारंटी/एल.यूटी नहीं देनी होगी।

कारपोरेट गारंटी

2.20.1 स्तर धारक अथवा पी. एस. यू. इस संबंध में संबंधित सीमाशुल्क के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक गारंटी/एल. यू. टी. के बदले में कारपोरेट गारंटी प्रस्तुत कर सकते हैं। समूह कम्पनी के मामलों में यदि उस ग्रुप की कोई कम्पनी स्तरधारक हो, दूसरी कम्पनी जो स्तर धारक नहीं है इस कम्पनी द्वारा कारपोरेट गारंटी दी जा सकती है।

उद्गम का प्रमाणपत्र

2.21 उद्गम का प्रमाण पत्र देश से निर्यातित माल के उद्गम का प्रमाण है। उद्गम के प्रमाण पत्र की दो श्रेणियाँ हैं यानी

(1) तरजीही और (2) गैर तरजीही

तरजीही

2.21.1 तरजीही प्रबंध/स्कीमों जिसके तहत भारत अपने निर्यातों हेतु टैरिफ तरजीहें प्राप्त कर रहा है वह हैं - तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जी एस पी), व्यापार तरजीहों की विश्व प्रणाली (जी एसटीपी), सार्क तरजीही व्यापार समझौता (साप्टा) और बैंकाक समझौता और भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएलएफटीए) भारत थाइलैंड मुक्त व्यापार समझौता। ये प्रबंध/समझौते उद्गम के नियमों को निर्धारित करते हैं जिन्हें टैरिफ तरजीहों हेतु मात्र होने के लिए निर्यातों हेतु पूरा करना होता है।

प्राधिकृत एजेंसियों उद्गम के प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में सेवाएं उपलब्ध कराएंगी जिनमें उद्गम के नियमों से संबंधित ब्यौरे, समझौते के तहत आने वाली मदों की सूची, टैरिफ तरजीहों की सीमा, पात्रता आदि का प्रमाणन एवं जाँच। खाली प्रमाणपत्रों को प्रिंट करने के लिए आई सी अकेली एजेंसी है। प्राधिकृत एजेंसियाँ प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क ले सकती हैं।

तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी)

(क) जी एस पी एक गैर अनुबंधीय व्यवस्था है जिसके द्वारा औद्योगिक (विकसित) देश एकतरफा तौर पर और गैर-आदान प्रदान के आधार पर विकसित देशों को टैरिफ छूट दे सकती हैं। निम्नलिखित देश अपनी जी एस पी स्कीम के तहत टैरिफ तरजीहें उपलब्ध कराते हैं।

अमेरिका, जापान, यूरोपीयन संघ, नार्वे, बेलारूस, कनाडा, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, बुल्गेरिया, रूस (केवल एल डी सी की) न्यूजीलैंड

इन देशों की जी एस पी स्कीमों से सैक्टरों/उत्पादों और टैरिफ लाइनों के ब्यौरे हैं जिसके तहत ये लाभ उपलब्ध हैं, ये लाभों को दिलाने की शर्तों और प्रक्रियाओं के अलावा है। ये स्कीमों समय-समय पर नवीकरण और संशोधित की जाती हैं। जी एस पी प्रदान करने वाले देशों के सीमाशुल्क कार्यालय सामान्यतः लाभान्वित देशों के निर्यातकों द्वारा बाकायदा भरे फार्म 'ए' (उद्गम के जी एस पी नियमों हेतु निर्धारित) में अपेक्षित सूचना मांगते हैं जो प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो। उद्गम का जी एस पी प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4क में दी गयी है।

व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली (जीएसटीपी)

(ख) व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली स्थापित करने वाले समझौते के अन्तर्गत विकासशील देशों के बीच व्यापारिक छूटों का आदान-प्रदान होता है जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समय, जी एस टी पी के सदस्य देशों की संख्या 46 है और भारत ने उत्पादों की सीमित संख्या के बारे में 12 देशों के साथ व्यापारिक छूटों को आदान-प्रदान किया है। जी एस टी पी के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्यात जाँच परिषद् (ई आई सी) एकमात्र एजेंसी है।

सार्क तरजीही व्यापार समझौता (साप्टा)

(ग) साप्टा स्थापित करने वाले समझौते पर सात सार्क देशों यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और मालदीव ने 1993 में हस्ताक्षर किए थे तथा यह 1995 में संज्ञान में लाया गया था। व्यापार समझौते के 4 चरण पूरे हो चुके हैं तथा सार्क देशों के बीच टैरिफ रियायत के अधीन 3000 से अधिक टैरिफ लाइसेंस पूरे हो चुके हैं। साप्टा के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4ख में दी गयी है।

बैंकाक समझौता

(घ) बैंकाक समझौता एक तरजीही व्यापार समझौता है जो एशिया और पैसिफिक हेतु आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप) क्षेत्र में टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधकों में छूट के तौर पर इन उपायों और अन्य समझौता तकनीकों के इस्तेमाल के माध्यम से वस्तुओं के व्यापार को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने और उदार बनाने के लिए बनाया गया है। इस समय बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, भारत व चीन टैरिफ रियायत का आदान प्रदान कर रहे हैं। बैंकाक समझौते के अंतर्गत उद्गम का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत एजेंसियों की सूची परिशिष्ट 4-ख पर दी गई है।

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (इसलाफ्टा)

(ड.) भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर 20 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। क्रमशः फरवरी और मार्च, 2000 में श्रीलंका और भारत सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ छूटों की अधिसूचना जारी करने के बाद मार्च, 2000 में समझौते पर कार्यान्वयन शुरू हुआ। इसलाफ्टा के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्यात जांच परिषद् एकमात्र एजेंसी है।

भारत-अफगान तरजीह व्यापार समझौता

(च) ट्रान्जिसनल इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान और भारतीय गणराज्य के बीच एक तरजीह व्यापार समझौता 6 मार्च, 2003 को हस्ताक्षर किये गये तथा दिनांक 13 मई, 2003 के सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 76/2003 को लागू हुआ था। भारत अफगानिस्तान के बीच तरजीह व्यापार समझौता जारी करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् एकमात्र एजेंसी होगी।

मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए भारत थाइलैण्ड फ्रेमवर्क

(छ) 01 सितम्बर, 2004 को भारत थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता के तहत अर्ली हार्बेस्ट स्कीम को कार्यान्वयन करने के लिए भारत और थाइलैण्ड ने एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया। अर्ली हार्बेस्ट स्कीम के मर्दों पर आयात हेतु प्रशुल्क तरजीह केवल उग उत्पादों को होगी जो मूल मानदण्ड जो वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके अधिसूचना सं. 101/2004-सीमाशुल्क दिनांक 31 अगस्त, 2004 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के नियमों को संतुष्ट करते हैं।

भारत-थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क समझौते में अर्ली हार्बेस्ट स्कीम के तहत उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् एक मात्र एजेंसी होगी।

गैर तरजीही

2.21.2 सरकार ने भी सीमाशुल्क औपचारिकताएँ 1923 के सरलीकरण से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के अनुसार मूल के गैर-तरजीह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुछेक प्राधिकृत एजेंसियों को नामित किया है। मूल के ये प्रमाणपत्र सामान के मूल के साक्ष्य हैं और इन पर तरजीह शुल्क का कोई अधिकार नहीं होता है। इन एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4ग में दी गई है।

सभी निर्यातकों को जिन्हें उद्गम का प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) प्रस्तुत करना है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-4ग में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी की आवेदन करना होगा:—

- (क) निर्यात उत्पादों में निवेश/उपभोग्य उपयोग की मात्रा/उद्गम के ब्यौरे।

(ख) बीजक की दो प्रतियां।

(ग) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची (दो प्रतियां)

(घ) प्राधिकृत अभिकरण के नाम पर चलान/डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये संबंधित अभिकरण द्वारा यथा-निर्धारित प्रति प्रमाणपत्र 100/—रु. या इससे कम शुल्क।

उद्गम प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) जारी करने से पूर्व अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उद्गम के नियमों को शामिल करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार वस्तुएं भारतीय मूल की हैं। प्रमाणपत्र परिशिष्ट-4ग के अनुलग्नक 2 में दिये गये मूल प्रमाणपत्र के प्रारूप के अनुसार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र में कोई शुद्धि/पुनः टंकित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-4ग में सूचीबद्ध करवाने हेतु कोई एजेंसी परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-4ग के अनुसार अपने आवेदन संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक परिशिष्ट-1 में दिये अनुसार आता है।

चाय के मामले में, सभी निर्यातक जिन्हें मूल का प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) अपेक्षित है वे चाय बोर्ड अथवा चाय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एवं प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के परिशिष्ट-4ग में सूचीबद्ध जांच एजेंसी को उपरोक्त सूची में दिए दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा।

स्तर धारकों हेतु स्वचालित लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र

2.22 स्तर धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतः ही लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र जारी किए जाएंगे। यदि कोई कमी होती है तो इसे कवरींग पत्र में सूचित किया जायेगा, कमी को सूचित करने की तारीख से 10 दिन के भीतर स्तर धारकों द्वारा इन कमियों को दूर किया जाएगा।

दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना

2.23 जहां कहीं विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरण/नामजद अभिकरण या इसी क्षेत्रीय प्राधिकरण के अलग प्रभाव को मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं तो आवेदक मूल दस्तावेजों के स्थान पर स्वयं विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है।

अग्रिम भुगतान

2.24 जिन मामलों में भुगतान पहले प्राप्त हो जाता है और निर्यात/मान्य निर्यात बाद में किया जाता है तो लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र के लिए आवेदन आगामी माह के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस माह के दौरान निर्यात/मान्य निर्यात जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

ई सी जी सी कवर के माध्यम से भुगतान

2.25.1 उन मामलों में जहां निर्यात पूरा कर दिया गया है लेकिन क्रेता से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे निर्यात को नीति के तहत लाभों के उद्देश्य हेतु ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते की ई सी जी सी कवर के माध्यम से भारतीय निर्यातक द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो।

सामान्य बीमे के जरिए भुगतान

2.25.2 ऐसे मामलों में जहां निर्यात किए गए हैं और भुगतान अन्तरण हानि अथवा अन्य परिस्थितियों में सामान्य बीमा कवर के जरिए वसूल किया गया है, तो अदा किए गए बीमा कवर की राशि विभिन्न

निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यातों के लिए वसूल किया गया भुगतान माना जाएगा।

डाक द्वारा निर्यात

2.26 डाक द्वारा निर्यात के मामले में समुद्र/वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—

1. परिशिष्ट 22क में दिया गया आयात वसूली का बैंक प्रमाणपत्र
2. संबद्ध डाक रसीद।
3. सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा बाकायदा सत्यापित बीजक।

कूरियर सेवा के माध्यम से आयात/निर्यात

2.26.1 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से आयात/निर्यात अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों की आयात/निर्यात नीति के अनुसार विनियमित होगी।

निर्यात दस्तावेजों का सीधे लेन-देन

2.26.2 उन मामलों में जहां निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से दस्तावेज का सीधे (प्राधिकृत डीलर के माध्यम से नहीं) लेन-देन करता है, उसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—

- (क) दस्तावेजों के सीधे लेन-देन की अनुमति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति (तथापि, यह स्तर धारकों हेतु आवश्यक नहीं है जिन्हें आय अनुमति प्रदान की गई है);
- (ख) बी आर सी के बदले में आयकर विभाग के फार्म-10 ज के अनुसार विदेश से स्वदेश में धन प्राप्ति प्रमाणपत्र (एफ आई आर सी) की प्रति; तथा
- (ग) शिपिंग बिलों/बीजक के ब्यौरे देने का विवरण जिसके प्रति एफ आई आर सी जारी की गई थी।

नमूनों का आयात/निर्यात

2.27 किसी आयातक को सब्जियों के बीज, मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित मदों के रूप में उल्लिखित मदों के प्रमाणिक तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि चाय उद्योग से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र के बिना एक परेषण में 2000 रुपए (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) तक चाय के नमूनों के आयात की अनुमति होगी।

रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों को छोड़कर सभी निर्यातकों के लिए 60,000 रु. तक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति और रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों के लिए 30,000 रु. तक सीमा-शुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

मुक्त रूप से निर्यात योग्य मद के प्रमाणिक व्यापार और तकनीकी नमूनों के निर्यात की कोई सीमा नहीं होगी।

पट्टा वित्तीयन के तहत आयात

2.28 पट्टा वित्तीयन के अधीन पूंजीगत माल के आयात के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति की अपेक्षा नहीं है। तथापि, वास्तविक उपयोगकर्ता या लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र की शर्त,

नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक के तहत जहां भी अपेक्षित हो ऐसे पट्टा वित्तीयन के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में लागू होगी।

यह सुविधा ई पी सी जी स्कीम/ई ओ यू/ई पी जैड, स्कीम के अन्तर्गत भी उपलब्ध होगी। मान्य निर्यात के पात्र श्रेणियों के पूंजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता, ऐसे मामलों में भी जहां आपूर्ति पट्टा, वित्तीयन के तहत की गई है, नीति के पैराग्राफ 8.3 में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे।

राष्ट्रीय और अन्तर राष्ट्रीय प्रदर्शनी या मेलों और प्रदर्शनों के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएं

2.29 विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों को भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के किसी अधिकारी जिसका स्तर अवर सचिव, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार/महानिदेशक, विदेश व्यापार से कम का न हो अथवा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के किसी अधिकारी जिसका इसके चेयरमैन में अपनी ओर से ऐसी प्रदर्शनी, मेले या इसी प्रकार के शो या डिस्प्ले, जैसा भी मामला हो, के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया हो, का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र के बिना पुनः निर्यात/आयात के आधार पर छः माह की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेले या इसी प्रकार के शो या डिस्प्ले पर अस्थाई स्टेण्ड हेतु अपेक्षित विनिर्माण और सच्चा सामग्री सहित प्रदर्शनों के आयात/निर्यात की अनुमति होगी जब इसे,

- (1) वाणिज्य विभाग/विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अनुमोदित या प्रयोजित किया हो।
- (2) लोकहित में आयोजित हो रहा हो।

पुनः निर्यात/आयात के लिए छः माह से आगे अवधि बढ़ाने पर विचार सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित पेन्ट, प्रिंट सामग्री, पैम्पफ्लैट, साहित्य आदि जैसे उपभोग्यों का पुनः निर्यात/आयात की आवश्यकता नहीं है।

आयात नीति

2.30 पूंजीगत माल, कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोग्यों अतिरिक्त पुर्जों, उपांगों, उपकरणों तथा अन्य माल के आयात के संबंध में सामान्य शर्तों से संबंधी नीति अध्याय 2 में दी गई है।

प्रतिबंधित सामान के लाइसेंस के लिए सामान्य प्रक्रिया

2.31 जहां इस अध्याय में दी गई नीति, प्रक्रिया के तहत आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी सी पी) नीति के तहत अपेक्षित है।

2.32 धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात

2.32.1 किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रैप को आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव कांटेनेटेड वेस्ट/स्क्रैप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या चला हुआ बारूद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, नहीं होगा।

2.32.2 निम्नलिखित प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात कुछ शर्तों के अधीन होगा जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र. सं.	एकजम कोड	मद ब्यौरा
1.	2	3
1.	72041000	कास्ट आयरन का छीजन और स्क्रेप
2.	72042190	अन्य
3.	72042920	ऑकहाई स्पीड स्टील
4.	72042990	अन्य
5.	72043000	टिन वाले लौह या स्टील का छीजन और स्क्रेप
6.	72044100	टर्निंग, शेविंग, चिप्स, मिलिंग वेस्ट, सॉ डस्ट, फिलिंग, टिमिंग और स्टैपिंग, चाहे गदर में हो या नहीं
7.	72044900	अन्य
8.	72045000	दोबारा पिघलने वाले स्क्रेप इन्गोट्स
9.	74040010	कॉपर स्क्रेप
10.	74040022	ब्रास स्क्रेप
11.	75030010	निकल स्क्रेप
12.	76020010	एल्यूमिनियम स्क्रेप
13.	79020010	जिंक स्क्रेप
14.	80020010	टिन स्क्रेप
15.	81042010	मैगनीशियम स्क्रेप

खंडित रूप : उपर्युक्त पैरा 2.32.2 में सूचीबद्ध धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात भारत के सभी पत्तनों से अनुमत किया जाएगा। होदाईडेह, यमन और बंदार अथास, ईरान से आयात केवल खंडित रूप में होगा।

अखंडित संपीडित और खुला रूप : उपर्युक्त 2.32.2 में सूचीबद्ध धात्विक छीजन, स्क्रेप जोकि अखंडित, संपीडित और खुले रूप में हो, का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (क). समुद्र वारीय आपूर्तिकर्ताओं से आयात केवल उन्हीं के लिए अनुमत होगा जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय और प्रक्रियापुस्तक के परिशिष्ट-V ख के तहत पंजीकृत हैं। केवल उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं से सीधा (प्रत्यक्ष) करार होगा।
- (ख). सभी आवेदन सहायक दस्तावेजों (जहाँ कहीं भी आवश्यक हैं) सहित प्रक्रिया पुस्तक भाग के परिशिष्ट-V क में जमा किए जाएंगे। सभी ब्यौरे विदेश व्यापार महानिदेशालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- (ग). पंजीकरण के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा।
- (घ). प्रारंभिक पंजीकरण केवल दो वर्षों के लिए होगा।
- (ङ). प्रत्यक्ष आयात साख पत्र के मदे केवल पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से अनुमत किया जाए। खुले समुद्र की बिक्री अनुमत नहीं की जाएगी।

(च). स्क्रेप का आयात केवल निम्नलिखित पत्तनों द्वारा किया जा सकेगा और इआयू तथा ऐई जैड के मामले में अपवादों को अनुमत किया जाएगा :

1. चैन्नई 2. कोचीन 3. इन्नोर 4. जे.एन.पी.टी. 5. काण्डला 6. मार्मागोआ 7. मुम्बई 8. न्यू मैंगलौर 9. पारादीप 10. तूतीकोरिन 11. विशाखापटनम 12. आईसीडी तुगलकाबाद 13. पिपाता 14. मुन्ना 15. कोलकाता 16. आईसीडी लुधियाना 17. आईसीडी दादरी, ग्रेटर नोएडा 18. आईसीडी नागपुर 19. आईसीडी जोधपुर 20. आईसीडी जयपुर और 21. आईसीडी उदयपुर 22. सी एफ एस मुलुंड 23. आईसीडी कानपुर 24. आई सी डी अहमदाबाद 25. आईसीडी पीतमपुर और 26. आईसीडी मलानपुर।

(छ). किसी उल्लंघन के मामले में, समुद्रपारीय (विदेशी) आपूर्तिकर्ताओं को अपंजीकृत कर दिया जाएगा। उस भारतीय फर्म के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जोकि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत आयात कर रही हो।

आवेदन दाखिल की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2006 होगी। आवेदन सीधे ही ई मेल, कोरियर द्वारा अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय, एच-विंग, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001 में व्यक्तिगत रूप से आकर जमा किए जा सकते हैं।

पंजीकृत स्रोतों से आयात की प्रणाली 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगी। तथापि प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के पैरा 2.32 के प्रावधानों के अनुसार पोत लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रणाली जोकि सार्वजनिक सूचना सं. 1 दिनांक 8 अप्रैल, 2005 तथा समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा अधिसूचित है, के आधार पर आयात 30 जून, 2006 तक अनुमत किए जाएंगे।

2.32.3 तथापि, अन्य प्रकार की धात्विक छीजन और स्क्रेप आईटीसी (एच एस) निर्यात और आयात मदों का वर्गीकरण, 2004—2009 की शर्तों तथा प्रावधानों के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

2.32.4 पुराने और दोषपूर्ण, पुराने कपड़े (चीथड़े) प्लास्टिक बोतले/छीजन और समुद्री जहाजों के विषय में आयात नीति आई टी सी (एच एस) निर्यात और आयात मदों का वर्गीकरण, 2004—2009 में उल्लिखित हैं।

पुराने पूंजीगत माल का आयात

2.33 रिफर्बिशड/रिकन्डीशन्ड स्पेयर्स सहित पुराने पूंजीगत माल का आयात निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शर्तों के अनुसार अनुमत होगा।

वैयक्तिक कम्प्यूटर और लैपटॉप सहित पुराने कम्प्यूटरों का आयात, आयातों के लिए प्रतिबंधित है।

रिफर्बिशड/रिकन्डीशन्ड पुर्जों का आयात सनदी अभियन्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत होगा जिसमें दर्शाया गया हो कि इन पुर्जों का बचा हुआ जीवन वास्तविक पुर्जों के जीवन के 80 प्रतिशत से कम नहीं है।

2.33.1 उपर्युक्त पैरा 2.33 की शर्तों के बावजूद, पुराने कम्प्यूटर, लैपटॉप और प्रिन्टर, प्लॉटर, स्कैनर, मॉनीटर, कीबोर्ड और स्टोरेज यूनिटों सहित कम्प्यूटर पैरीफेरियल्स निम्नलिखित दानकर्ताओं की श्रेणियों द्वारा दान के रूप में मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं :

- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित स्कूल।
- (2) किसी संस्था द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाई गई शैक्षिक संस्था
- (3) पंजीकृत चैरिटेबल अस्पताल
- (4) पब्लिक लाइब्रेरी
- (5) सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थान
- (6) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित समुदान सूचना केन्द्र
- (7) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
- (8) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र का संगठन

इस उप-पैरा के अन्तर्गत आयातों की अनुमति होगी बशर्ते कि माल किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग न किए जाए, अहस्तांतरणीय हो, और संगत सीमाशुल्क विनियमों और अधिनियमों की शर्तों के अनुरूप हो।

2.33.क सीमाशुल्क अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी पूंजीगत माल की श्रेणियों/मूल्य निर्धारण/खरीद मूल्य दोनों प्रमाणित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट में दी गई निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

लाइसेंसधारी हथियार व्यापारियों द्वारा हथियारों का आयात

2.34 लाइसेंसधारी हथियार व्यापारी द्वारा लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के प्रति निम्नलिखित किस्म के हथियारों का आयात अनुमत है बशर्ते कि यह यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो :

- (1) शाटगन कार्टरिज 28, बोर
- (2) रिवाल्वर कार्टरिज .450, .455 और .45 बोर के।
- (3) पिस्टल कार्टरिज .25, .30 माउजर, .450 और .45 बोर
- (4) राइफल कार्टरिज 6.5 एम एम, .22 सेवेज, .22 हार्नेट, 300 शेरबुड, 32/40, .256, 275, 280, 7 एम/एम माउजर, 7 एम/एम मैनस्कूइनर, 9 एम/एम माउजर, 9 एम/एम मैनस्कूइनर, 8x57, 8x57 एस, 9.3 एम/एम, .375 मैगान, .405, .30 .06 .270, .30/30 विंच, .318, .33 विंच, .275 मेग, .350 मेग, 400/350, .369 पुरडे, .450/400, .470, .32 विन 458 विन, 380 रूक, .220 स्पीष्ट और .44 विन बोर्स के।

लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र विगत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान गोला बारुद की वार्षिक बिक्री कारोबार (देशी अथवा आयातित) के मूल्य के 5 प्रतिशत आयात तक दिया जा सकता है बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य 2000/- रुपये से कम न हो।

उपर्युक्त पैरा में दी गई मदों के लिए लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र हेतु आवेदन पत्र, निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात-निर्यात फार्म पर क्षेत्रीय प्राधिकारी को दिया जाए।

होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेंटों, टूर-ऑपरेटर्स और अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा अपेक्षित प्रतिबंधित मदें

2.35 होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेंटों और टूर-ऑपरेटर्स द्वारा अपेक्षित निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में आयात के लिए प्रतिबंधित के रूप उल्लिखित मद लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र के प्रति अनुमत होगी। आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र महानिदेशक, पर्यटन भारत सरकार की सिफारिशों पर दिया जाएगा।

2.35.1 महानिदेशक, पर्यटन भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पर्यटन होटलों सहित, होटल, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत मूल्य तक के आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र के पात्र होंगे।

ऐसे लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र होटल और पर्यटन उद्योग से संबंधित अनिवार्य सामग्री के आयात के लिए दिए जा सकते हैं।

2.35.2 भारत सरकार के पर्यटक महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, टूर संचालकों, रेस्तराओं तथा पर्यटन परिवहन संचालकों और साहसिक/वन्य जीव जैसे पर्यटन के लिए अन्य यूनिट और कन्वेन्शन यूनिट को गत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत मूल्य का आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे।

ऐसे लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र ट्रेवल तथा पर्यटन उद्योग को उनकी व्यावसायिक प्रयोग के लिए अपेक्षित कार्यालय एवं अन्य उपकरणों सहित अनिवार्य वस्तुओं का आयात करने के लिए दिए जाएंगे।

2.35.3 पैरा 2.35.1 तथा 2.35.2 के अन्तर्गत किसी भी वर्ष की आयात हकदारी के लिए पूरी अथवा उसके एक भाग को आगे ले जाया जा सकता है तथा दो आगामी लाइसेंसिंग वर्षों की आयात हकदारी में जोड़ा जा सकता है।

2.35.4 पैरा 2.35.1 तथा 2.35.2 के अधीन मंजूर आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा तथापि होटलों/रेस्तेरों/ट्रेवल एजेंटों/टूर ऑपरेटर्स को दिए गए ऐसे लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र संबंधित समूहों अथवा विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 में यथा परिभाषित प्रबन्धित होटलों के भीतर हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

2.35.5 अपने या अभिगृहीत लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र के प्रति आयातित माल को विदेश व्यापार महानिदेशक की पूर्ण अनुमति के बिना उनके आयात की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर किसी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

आयातित माल के पुर्ननिर्यात के मामले में हस्तांतरण के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि पुर्ननिर्यात पर आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची II में आवश्यक सभी शर्तों अथवा लाइसेंस की आवश्यकताओं अथवा आज्ञा लागू होगी।

2.35.6 पैरा 2.35.1 और 2.35.2 के अधीन लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति-पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र पर महानिदेशक विदेश व्यापार को निदेशक पर्यटन, भारत सरकार के जरिए

देना होगा। वे इस आवेदन पत्र को आयात किए जाने वाले माल और आयात की पात्रता की सिफारिश करके संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अप्रेषित करेंगे।

अन्य प्रतिबंधित मदों का आयात

2.36 निर्यात और आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण नामक पुस्तक में प्रतिबंधित मदों की सूची दी गई है। ऐसे मदों के आयात के लिए आवेदन पत्र आयात निर्यात प्रपत्र पर, निर्धारित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय को दिया जाएगा।

निर्यात आयात सुविधा समिति

2.37 प्रतिबंधित मद लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक या उनके ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिया जा सकता है। डी जी एफ टी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकते हैं।

सुविधा समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकारियों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

उपभोग्य अथवा अन्य माल का उपहार

2.38 नीति के पैरा 2.19 में दिए प्रावधानों के अनुसार, निर्यात और मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में आयात के लिए प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित मदों का उपहार के रूप में आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली को निर्धारित प्रलेखों के साथ 'आयात निर्यात प्रपत्र' में दिए प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा :

तथापि, जहां उपहार का प्राप्तकर्ता समितियों अथवा ट्रस्टों के पंजीकरण से संबंधित कानून के तहत पंजीकृत अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अनुमोदित चैरिटेबल, धार्मिक अथवा शैक्षिक संस्थान हैं और आयात किया जाने वाला उपहार वित्त मंत्रालय द्वारा सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, ऐसा आयात सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञापन के बिना अनुमत होगा।

एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत आयात

2.39 एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनकी संतुष्टि के अनुसार आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र या सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमत किया जा सकता है।

चैक बुक/टिकट फार्म आदि का आयात

2.40 विदेशी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा ट्रेवल एजेंसियों की भारतीय शाखाओं द्वारा चैक बुक, बैंक ड्राफ्ट फार्म तथा ट्रेवेलर चैक फार्मों का सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना आयात किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में कार्यरत एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों जिनमें ऐसे एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना पैसेजर्स टिकट फार्मों का आयात कर सकती हैं।

पुनरनुकूलन/वायुयान के अतिरिक्त पुराने पुर्जों का आयात

2.41 एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत, पवनहंस लि. तथा अनुसूचित घरेलू निजी एयरलाइंस, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां तथा राज्य सरकार चालित एक्जीक्यूटिव/प्रशिक्षण एयर

क्राफ्ट या जो फसलों के छिड़काव में रत हैं तथा गैर-अनुसूचित एयर-लाइंस, एयरक्राफ्ट तथा चार्टर्ड सर्विस आपरेटर, नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार की सिफारिशों पर रिकंडिशन/सेकिन्ड हैण्ड एयर क्राफ्ट के कलपुर्जों लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना रिकंडिशन/सेकिन्ड हैण्ड एयर क्राफ्ट कलपुर्जों का आयात कर सकती है।

प्रतिस्थापन माल का आयात

2.42 सामान और उसके पुर्जों आयात करने पर खराब या अन्यथा उपयोग के लिए उपयुक्त न हो अथवा जो आयात करने के बाद नष्ट हो गये हों उनका लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है तथा सामान का विदेशी सप्लायरों द्वारा बिना प्रभार की आपूर्ति या समुद्री बीमा के प्रति आयात अथवा बीमा कम्पनी द्वारा निपटार्ये गए समुद्री व निर्माण बीमा दावों का निपटान कर लिया है उसकी मुफ्त आपूर्ति की जा सकती है। ऐसे सामान का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस के बिना निकासी करने की अनुमति होगी बशर्ते कि :

(क) सीमाशुल्क द्वारा पिछले आयातित सामान की निकासी की तारीख से 24 माह के भीतर प्रतिस्थापन माल की निकासी की गई है अथवा मशीन या उसके कलपुर्जों के मामलों में, 24 माह से अधिक समय लग गया है परन्तु गारंटी अवधि के भीतर हो, और

(ख) जब आयातक द्वारा किए गए बीमा और/अथवा भाड़े के भुगतान के अधीन है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की प्रतिपूर्ति पर बीमा और भाड़े के भुगतान को छोड़कर कोई प्रेषण भार नहीं लिया जाएगा और प्रेषण शुल्क देते समय इस प्रयोजन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

आयातक के पास उपर्युक्त सामान की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बजाय, विदेशी सप्लायर को पहले ही किए गए भुगतान, यदि कोई हो तो, उस भुगतान को लौटाने का दावा करने का भी विकल्प होगा।

2.42.1 ऐसे मामलों में जहां माल पोत में कम चढ़ाया, कम उतारा पाया जाए या वास्तविक आयात से पूर्व आवाजाही में गुम पाया जाए और/अथवा सीमाशुल्क से निकासी के समय इसका पता लगा हो तो प्रतिस्थापन माल की आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की क्षमता पर अनुमत होगा। ऐसे मामलों में, कोई आयात लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र की जरूरत नहीं होगी।

वह प्रक्रिया उस मामले में भी लागू होगी जहाँ विदेशी सप्लायर द्वारा पोत में सामान का कम लदान को प्रमाणित किया जाता है और वह सामान मुफ्त बदलने के लिए तैयार है।

2.42.2 जो मामले उपर्युक्त प्रावधानों द्वारा कवर नहीं होते हैं उनके संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी इसके लिए आवेदन पत्र आयात निर्यात फार्म पर करना होगा।

आयातित माल का हस्तांतरण

2.43 जिस माल का बिना प्रतिबंध के आयात किया जा सकता है उसका, आयातक द्वारा बिक्री या अन्यथा रूप में हस्तांतरण किया जा सकता है। ऐसे आयातित माल का जो नीति के अधीन वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन हैं और वास्तविक उपयोक्ता की आवश्यकता से अधिक है, का हस्तांतरण केवल संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व अनुमति

से किया जा सकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना, हस्तांतरण के लिए मंजूरी के अनुरोध सहित, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

- (1) आयातित सामग्री के हस्तांतरण के कारण,
- (2) जिसको हस्तांतरित किया जाता है उस व्यक्ति का नाम, पता, आयातक-निर्यातक कोड संख्या तथा औद्योगिक लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र/पंजीकरण, यदि कोई हो।
- (3) आयातित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य तथा जिसका हस्तांतरण करने की अनुमति मांगी गई है।
- (4) किए गए आयात से संबंधित आयात लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र और आगमपत्र की प्रतियां, और
- (5) क्रेता और विक्रेता के बीच हस्तांतरण की शर्तें।

2.43.1 तथापि, ऐसे माल के हस्तांतरण या निपटान में किए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जिसको वास्तविक उपभोगकर्ता की शर्तों पर आयात किया गया हो बशर्ते कि उसके हस्तांतरण की तारीख को वास्तविक उपभोगकर्ता की शर्तों के बिना मुक्त आयात किया जाता हो।

2.43.2 ऐसे आयातित माल के आयात की तारीख से दो वर्षों की अवधि के बाद हस्तांतरण या निपटान के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि सभी आयातित अग्निशस्त्रों के हस्तांतरण की अनुमति आयातकों/लाइसेंस धारकों को महानिदेशक, विदेश व्यापार के अनुमोदन से आयात की तारीख के केवल 10 वर्ष बाद होगी।

नुमाइशी मर्दों की बिक्री

2.44.1 भारतीय व्यापार उन्मयन संगठन (आई टी पी ओ) द्वारा अनुमोदित/प्रायोजित अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/आयोजित मेलों के लिए आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित मर्दों के प्रदर्शनों की बिक्री प्रभावी सीमाशुल्क के भुगतान करने पर लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र बिना बाण्ड अवधि के भीतर पुनः निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि प्रत्येक प्रदर्शक के लिए ऐसे प्रदर्शनों की लागत बीमा भाड़ा मूल्य की निर्धारित सीमा 5 लाख रु. हो।

तथापि, जिन प्रदर्शित पदों का मुक्त आयात किया गया था उनकी भावी लागू सीमाशुल्क के भुगतान पर पुनः निर्यात की अनुमत बाण्ड अवधि के भीतर लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना बिक्री की जाएगी।

(2) यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण नुमाइश के लिए लाई गई वस्तुओं का बाण्ड अवधि के अंदर पुनः निर्यात या बिक्री नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी गुण-दोष आधार पर बाण्ड अवधि में वृद्धि कर सकते हैं।

विदेशी कार्यालय उपकरणों का आयात

2.45 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्थापित समुदयारीय कार्यालयों को बंद करने पर, कार्यालय उपकरणों और अन्य मर्दों का आयात लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना किया जा सकता है।

निर्यात उत्पादों के लिए लेबल, मूल्य टैग और इसी प्रकार का सामान

2.46 भारतीय निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं द्वारा दिए गए विशिष्ट आदेश के प्रति माल पर जो लेबल, मूल्य टैग, हैंगर्स, साइजर्स, पी वी सी बैग्स, इनले कार्ड्स प्रिंटेड बैग, स्टीकर्स और ट्रिमिंग सामग्री जैसे बटन और बैल्ट शोल्डर पैड्स, बकल्स, आइलेट्स, हुस्त और आइस और रिबेट्स लगाए जाते हैं, का आयात लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना किया जा सकता है।

प्रोटो टाइप्स

2.47 वास्तविक उपयोक्ता, नई/पुराने प्रोटोटाइप्स/पुराने नमूनों का आयात बिना लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र कर सकते हैं। जो उत्पादन कार्य में लगे हैं या उनके पास औद्योगिक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र/आशय पत्र है अथवा अनुसंधान में लगी है और उन्हें उत्पाद विकास या अनुसंधान, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रोटोटाइप/सम्पल की जरूरत है, वे सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुरूप स्व घोषणा करके आयात कर सकते हैं।

अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मर्दें

2.48 आर एण्ड डी प्रयोजन के लिए अपेक्षित, जीवित जानवरों को छोड़कर सभी प्रतिबंधित मर्दों का आयात सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के बिना किया जा सकता है।

निर्यात नीति

2.49 निर्यात से संबंधित नीति, इस नीति के अध्याय-2 में दी गई है। इसके अलावा, आई टी सी (एच एस) के परिशिष्ट 1 में उन मर्दों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका किसी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है, जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

2.50 आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 में उल्लिखित मर्दों के संबंध में निर्यात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, आयात-निर्यात फार्म में विदेश व्यापार महानिदेशक को दिया जाए और इसके साथ उसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। विदेश व्यापार सुविधा समिति, निर्यात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र जारी करने के लिए गुण-दोष के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय में स्थित अन्तर मंत्रालयीय कार्य दल नीचे दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2, परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट विशेष रसायनों, आर्गेनिजन, सामग्री, उपकरणों और प्रौद्योगिकी स्कोमेट के निर्यात के आवेदनों पर विचार करेगा।

स्कोमेट सूची पर निर्यात मर्दों या प्रौद्योगिकी के लाइसेंसों के आवेदनों पर मामला दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है जो अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित सामान्य मानदण्डों पर आधारित हैं :

I. स्कोमेट सूची पर निर्यात मर्दों के आवेदनों का मूल्यांकन करते समय अन्य कारकों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

क. अन्तिम प्रयोक्ता के व्यक्तिगत ब्यौरे, मद या प्रौद्योगिकी के अन्तिम प्रयोक्ता की घोषणाओं की विश्वसनियता,

अन्तिम प्रयोक्ता को आपूर्तिकर्ता से मद की सुपुर्दगी और मद या प्रौद्योगिकी क्षमता की निष्ठा जिसमें इसके निर्यात का समय शामिल है जो अन्तिम प्रयोग के लिए योगदान देता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों वैश्विक गैर निरस्तीकरण के उद्देश्यों या उन उद्देश्यों जिन, संघियों के लिए यह अनुरूप नहीं है।

- ख. इसमें यह भी देखा गया है कि निर्यातित मदें आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं।
- ख. मूल्यांकित खतरे कि निर्यातित मदें, आतंकवादी, आतंकवादी समूहों और देशद्रोहियों के हाथों में जा सकती हैं।
- ग. प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा स्थापित निर्यात नियंत्रण उपाय,
- घ. हथियारों और उनकी सुपुर्दगी से संबंधित प्राप्तकर्ता राज्य के कार्यक्रमों की क्षमताएं और उद्देश्य,
- ड. मदों के अन्तिम प्रयोग का मूल्यांकन,
- च. संगत द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौतों जिसमें भारत एक पक्ष हो, के निर्यात लाइसेंस आवेदनों की उपयुक्तता।

II. निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन पर विचार किए जाने की एक शर्त अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि उससे संबंधित निर्धारित प्रमाणन प्रस्तुत किया जाए, कि :

- क. मद का प्रयोग सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोग को भारत सरकार की मंजूरी के बिना बदला नहीं जाएगा, न ही मदों को संशोधित अथवा दुहराया जाएगा।
- ख. भारत सरकार की मंजूरी के बिना न ही मदों को न ही उनकी प्रतिकृति अथवा व्युत्पन्न को पुनर्हस्तांतरित किया जाएगा।
- ग. अन्तिम प्रयोक्ता, भारत सरकार द्वारा जैसा भी आवश्यक होगा वैसे प्रमाणन उपलब्ध कराएगा।

प्राप्तकर्ता के राज्य से, अन्तिम प्रयोग और गैर-पुनर्हस्तांतरण सहित, जैसा भी ठीक हो, भारत सरकार को अतिरिक्त औपचारिक आश्वासन की भी आवश्यकता हो सकती है।

III. नीचे श्रेणी 0 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी परमाणु ऊर्जा विभाग है। लागू दिशानिर्देश उस विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित हैं। श्रेणी 0 की कुछ मदों के लिए प्राप्तकर्ता राज्य से औपचारिक आश्वासनों में किसी नाभकीय विस्फोट उपकरण में न प्रयोग किया जाना भी शामिल है। श्रेणी 0 की कुछ मदों के निर्यात के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक की हस्तांतरण अतिरिक्त रूप से उचित संरक्षण के तहत और उचित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) रक्षोपाय

अथवा हस्तांतरणीय मदों के किसी भी अन्य पारस्परिक सहमति नियंत्रणों के तहत नहीं होगी।

- IV. मदों अथवा तकनीक के निर्यात के लिए लाइसेंसों में अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग शर्तें निर्धारित की जाएं, जो दिशा परिवर्तन की संभावना रखती हों। अथवा उसके विकास अथवा विनिर्माण में प्रयोग हों अथवा व्यापक विध्वंस के हथियारों की सुपुर्दगी में सक्षम प्रक्रिया के रूप में प्रयोग हों।
- V. सूची में दी गई किसी मद के लिए "तकनीक" के हस्तांतरण के लिए आवेदनों पर स्वयं मद के निर्यात के लिए आवेदन के रूप में विचार किया जाएगा।
- VI. सिर्फ प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के उद्देश्य के लिए इस सूची (श्रेणी 0, 1 और 2 को छोड़कर) में दिए मदों के निर्यात के लिए लाइसेंसों हेतु किसी अन्तिम प्रयोग अथवा अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। (किसी भी श्रेणी में 'तकनीक' के लिए, प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु निर्यात लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा। श्रेणी 0, 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले मदों के लिए प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा)।

VII. स्कोमेट सूची में जो मदें नहीं हैं उनका निर्यात भी व्यापक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों की निषिद्धता) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित होगा।

टिप्पणी 1 :—निर्यात अथवा निर्यात के प्रयास में लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन, दीवानी और/अथवा फौजदारी अभियोजन को आमंत्रित करेगा।

टिप्पणी 2 :—विदेश में प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के लिए इस सूची की मदों के निर्यात के लिए लाइसेंस छः माह के भीतर की अवधि में पुनः आयात शर्त के अधीन है। विदेश में प्रदर्शनी के दौरान यदि प्रदर्शनीकर्ता ने मद को बिक्री के लिए रखा हो, तो विदेश में प्रदर्शित ऐसी मदों के लिए निर्यातक निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन करने का हकदार है। ऐसी बिक्री बिना वैध लाइसेंस के नहीं होगी।

टिप्पणी 3 :—इस सूची की श्रेणी-2 में निर्यात की मदें, समय-समय पर जारी अन्य लागू दिशानिर्देशों द्वारा भी नियंत्रित होंगी। इस श्रेणी में मदों के निर्यातकों को विदेश व्यापार महानिदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

टिप्पणी 4 :—देशों और/अथवा देशों के समूहों को निर्यात के लिए "गंतव्य लाइसेंस" हेतु निर्यातक, आवेदन के हकदार हैं जहां सिर्फ पुनर्हस्तांतरण शर्तें लागू किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी 5 :—निर्यातक यह अनुरोध कर सकते हैं कि केवल ऐसी शर्तें ही लगाई जाएं जो स्कोमेट सूची

की मदों के निर्यात पर सरकार से सरकार समझौते के अधीन है।

टिप्पणी 6 :—‘तकनीक’ (आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 की शब्दावली में प्रविष्टि ‘तकनीक’ को भी देखें)। स्कोमेट सूची की मद के निर्यात का अनुमोदन, मद की स्थापना, संचलान, रख-रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक न्यूनतम ‘तकनीक’ के लिए उसी अन्तिम प्रयोक्ता को निर्यात के लिए प्राधिकृत करता है।

डीजीएफटी कार्यालय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों व व्यापार ऐसोसिएशनों के सहयोग से व्यापार से संबंधित आयातक/निर्यातक के मध्य विशेष रूप से एससीओ एमईटी मदों के संबंध में प्रभावी जागरूकता के लिए इन्डस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम का नियमित आधार पर आयोजन करेंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय, आवेदन करने पर, अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक आदि में प्रयोग होने वाले चिकित्सीय और शल्य उपकरणों के लिए, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत न आने वाली निर्यात की मदों के लिए और जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र भी जारी कर सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

राज्य व्यापार व्यवस्था के तहत मदों का निर्यात

2.51 राज्य व्यापार व्यवस्था के अधीन आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित मदों के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएं।

नमूनों/नुमाइशी वस्तुओं का निर्यात

2.52 ऐसे नमूनों या नुमाइशी वस्तुएँ, जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हों, के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाए।

निःशुल्क निर्यात

2.52.1 स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे जोकि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 10 लाख रुपये या 2 प्रतिशत की वार्षिक सीमा, जो भी ज्यादा हो, के अधीन होगा।

उपहार/पुर्जे/प्रतिस्थापन माल

2.53 नीति के पैराग्राफ 2.32, 2.33 और 2.37 में निर्धारित सीमा/अवधि से अधिक में देशी/आयातित वारण्टी स्पेयरस और प्रतिस्थापन माल, उपहार के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाए।

गैर-वास्तविक रूप में निर्यात संबंधी रिटर्न भेजना

2.54 हार्ड स्पीड डाटा कम्यूनिकेशन लिक्स, इन्टरनेट, टेलीफोन लाईन और कोई अन्य चैनल जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकरण शामिल

नहीं होता, सहित कम्यूनिकेशन लिंक का उपयोग करके, गैर-वास्तविक रूप में किए जाने वाले सभी निर्यातों के बारे में अनिवार्य रूप से परिशिष्ट 19ग में उल्लिखित फार्म में इलैक्ट्रॉनिक और साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् को तिमाही आधार पर सूचना भेजनी होगी।

यह प्रावधान सभी निर्यात करने वाले यूनिटों पर लागू होंगे चाहे देश में कहीं भी स्थित हों इनमें एम टी पी, एस ई जैड, ई एच टी पी और 100% ई ओ यू स्कीम के अधीन स्थित यूनिटें भी शामिल हैं।

भेषज और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास उपकरण का शुल्क मुक्त आयात

2.55 उन विनिर्माता निर्यातकों को (समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 1-3-2002 की सूची 28 में यथा निर्दिष्ट) पिछले लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी जिनका अपना अनुसंधान और विकास यूनिट है तथा यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत है, यह अनुमति उक्त अधिसूचना की शर्त सं. 53(2) को पूरा करने के अधीन होगी।

पात्र यूनिट परिशिष्ट-15क में दिए गए आवेदन-पत्र क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय या फर्म का मुख्यालय स्थित है।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी यूनिट द्वारा की गई घोषणा और जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा काउंटर साइन किया गया है, के आधार पर आवेदन की जांच करेगा।

2.55.1 कृषि रसायन क्षेत्र यूनिट को सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 1-3-2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) की सूची 28(क) में यथा निर्दिष्ट पिछले लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी कृषि रसायन क्षेत्र यूनिट जिनका वित्त वर्ष में सालाना कारोबार 20 करोड़ या इससे ऊपर है। ऐसी सुविधा सिर्फ उसी विनिर्माता को उपलब्ध होगी, जिनका अपना अनुसंधान और विकास यूनिट है तथा यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत है। यह अनुमति उक्त अधिसूचना की शर्त सं. 53(क) को पूरा करने के अधीन होगी।

पात्र यूनिट परिशिष्ट-15ख में दिए गए आवेदन-पत्र क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय या फर्म का मुख्यालय स्थित है।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी यूनिट द्वारा की गई घोषणा और जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा काउंटर साइन किया गया है, के आधार पर आवेदन की जांच करेगा।

एक योजना से दूसरी योजना में शिपिंग बिल की डुप्ली प्रति में परिवर्तन

2.56 यदि सीमाशुल्क प्राधिकारी, लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद, किसी स्कीम पोत बिल की डुप्ली प्रति के परिवर्तन की अनुमति देते हैं जिस पर उस योजना का लाभ नहीं लिया गया है, निर्यात उस योजना के तहत लाभ पाने का पात्र हो जिसे शिपमेंट को बाद में परिवर्तित किया गया है।

उद्योगों की पुनर्स्थापना

2.57 लाइसेंस के बिना संयंत्र और मशीनों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते ऐसे पुनर्स्थापित संयंत्र का मूल्य ह्रास 25 करोड़ रुपये से अधिक हो।

निर्यात आय की ऑफ सेटिंग

2.58 किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत लाइसेंस धारण किसी देय या इक्विटी निवेश के मद्दे निर्यात आय को ऑफसेट प्राप्तिओं के रूप में प्रयोग कर सकता है बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अनुमोदन लिया गया हो। ऐसे मामलों में, यदि निर्यातक निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऑफ सेटिंग निर्यात आय की प्राप्ति के बराबर होगी :—

(क) बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र की एवज में परिशिष्ट-22 घ

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति।

गुणवत्ता प्रमाणन

2.59 यह निरन्तर कोशिश रहनी चाहिए कि निर्यात उत्पादन का विनिर्माण करने वाले एककों/निर्यात उत्पाद के गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा दिया जाएगा।

2.59.1 गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्राफ 3.5.2 टिप्पणी-1 के अनुसार विदेश व्यापार नीति में शामिल की गई मुख्य-मुख्य बातों में से एक यह है कि आई एस ओ-9000 (श्रृंखला), आई एस ओ-14000 (श्रृंखला) या एच ए सी सी पी प्रमाणन या डब्ल्यू एच ओ जी एम पी या एस ई आई सी एम एम स्तर-2 और उपर्युक्त स्तर/प्रमाणन वाले एककों के लिए न्यूनतम प्रारम्भिक सीमा प्राप्त करने पर स्तर निर्यात सदन स्तर की मंजूरी दी जाए।

2.59.2 गुणवत्ता प्रमाणन देने के लिए जिन्हें प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अभिकरणों की सूची परिशिष्ट-6 में दी गई है।

परिशिष्ट-6 में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण परिशिष्ट-6 के अनुलग्नक-1 के अनुसार परिशिष्ट-1 में दिए गए संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिससे क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है, को अपना आवेदन कर सकता है।

2.59.3 हटा दिया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र

2.60 शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित उपबन्ध विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.49 में दिया गया है।

2.61 प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के तहत आयात की प्रक्रिया।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में, नीचे दी गई मात्रा के साथ-साथ दर्शाई गई सीमाशुल्क की रियायती दरों पर, चार मदों अर्थात् (1) स्किम्ड और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बच्चों के लिए दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ आदि (0402.10 अथवा 0402.21) (2) मक्का (कार्न); आदि (1005.90) (3) कच्चा सूरजमुखी बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (1512.11) और (4) रेप,

कोल्जा अथवा सरसों का रिफाइनड तेल, आदि (1514.19 अथवा 1514.99) के आयात की अनुमति है :—

क्रम सं. और मद	आईटीसी कोड संख्या	कोटा की मात्रा	रियायती शुल्क
1.	प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21 स्किम्ड और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बच्चों के लिए दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ आदि	10,000 मी.टन	15%
2.	प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90 मक्का (कार्न) : अन्य	5,00,000 मी.टन	15%
3.	प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11 कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग	1,50,000 मी.टन	15%
4.	प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 और 1514.99 रेप, कोल्जा अथवा सरसों का तेल अन्य (रिफाइनड)	1,50,000 मी.टन	45%

कोटे के आवंटन के लिए पात्र कंपनियाँ

2.61.1(क) दुग्ध चूर्ण (प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21) : राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ (एनसीडीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी) और मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) मक्का (कार्न) (प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90) : भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और राज्य सहकारी विपणन संघ कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा कुसुम्भ अथवा उनके भाग (प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11) : राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सीडब्लूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) रेप, कोल्जा अथवा सरसों के रिफाइनड तेल, अन्य (प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 अथवा 1514.99) : राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सीडब्लूसी) राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।

सभी पात्र कंपनियों प्राप्त आवेदनों की दरखास्त के अनुसार कोटा पात्र कंपनियों कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।

ऊपर उल्लिखित के अनुसार कोटा प्राप्त करने की इच्छुक सभी पात्र कंपनियों, विदेश व्यापार महानिदेशालय, के कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में, प्रक्रिया पुस्तक के आयात-निर्यात फार्म में निर्यात आयात सुविधा समिति को आवेदन कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक/निर्धारित दस्तावेजों सहित कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 1 मार्च, 2007 तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। उदाहरणतः टी आर क्यू के लिए वर्ष 2007-2008 के लिए आवेदन 1 मार्च, 2007 तक विदेश व्यापार महानिदेशालय पहुँच जाने चाहिए।

आयात वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् इस तारीख से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खेप की निकासी कर दी जानी चाहिए।

चूँकि, मक्के (कॉर्न) का आयात राज्य व्यापार व्यवस्था (एसपीआर) के तहत है, कोटे के आवंटन अर्थात् इस मद के लिए पैरा 1 (ख) में नामित एजेंसियों को भी, विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैरा 2.11 के अनुसार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 दिनांक 1/3/2002 की क्रम संख्या 21 (ख) में दर्शाई आवंटित मात्रा के लिए आयात लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, यदि वे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से आयात नहीं करना चाहते।

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I, 2004—2009 के परिशिष्ट 21 ख में शामिल प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात आयात सुविधा समिति (ईएफसी) मूल्यांकन करेगी और कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से आवेदकों के मध्य कोटा आवंटित करेगी अर्थात् 2007-08 के लिए ईएफसी 31 मार्च, 2007 से कोटा आवंटित करेगी।

अध्याय - 3

संवर्धनात्मक उपाय

स्तर प्रमाण-पत्र 3.1

नीति के अध्याय-3 में स्तर धारकों से संबंधित नीति दी गई है।

स्तर प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र 3.2

किसी की स्तर की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र 31 मार्च से पहले प्रस्तुत करना होगा। एक से पांच स्तर व्यापार सदन के लिए आवेदन पत्र माल व सेवाओं के निर्यातकों द्वारा 'आयात निर्यात फार्म' में देना होगा।

नीचे दी गयी तालिका के अनुसार मौजूदा स्तरधारक को स्वतः ही स्तर निर्यात सदन के बराबर माना जाएगा :-

निर्यात आयात नीति	विदेश व्यापार नीति
2002-07 के तहत	2004-09 के अनुसार
पूर्व स्तर	परिवर्तित स्तर
निर्यात सदन	एक स्तर निर्यात सदन
व्यापार सदन	तीन स्तर निर्यात सदन
स्तर व्यापार सदन	चार स्तर निर्यात सदन
सुपर स्तर व्यापार सदन	पांच स्तर निर्यात सदन

तथापि, कोई भी निर्यातक चाहे वह स्तरधारक है या नहीं वह स्तर की मंजूरी या अपने मौजूदा स्तर को बढ़ाने के लिए 'आयात निर्यात फार्म' में दुबारा आवेदन कर सकता है।

3.2.1 एक से पांच निर्यात सदन प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसका प्रमुख संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार है। बशर्ते कि आगे ई ओ यू/एस ई जैड ईकाइयों के सम्बन्ध में स्तर प्रमाणपत्र की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जाएंगे यदि इसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इसकी मूल कंपनी के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की क्लबिंग शामिल न हो। फिर भी क्लबिंग के मामले में, आवेदन संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत किया जाएगा।

3.2.2 किसी कंपनी के मामले में ऐसे आवेदन पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/निगम कार्यालय द्वारा और अन्य के मामले में उनके मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कंपनी के मामले में जहाँ आवेदन पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/निगम कार्यालय है तो उसे (क) वैध आर सी एम सी की स्व प्रमाणित प्रति जिसमें पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या निगम कार्यालय का नाम दिया गया हो और (ख) मुख्यालय और निगम कार्यालय और पंजीकृत कार्यालय और निगम कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय (जैसा भी मामला हो) से इस आशय की प्रविष्टि करवानी होगी कि स्तर प्रमाण पत्र के लिए हकदारी की अवधि के मद्दे कंपनी द्वारा पहले कोई ऐसा आवेदन नहीं किया गया है।

3.2.3 हटा दिया गया है।

3.2.4 हटा दिया गया है।

लक्ष्योपरि योजना (टारगेट प्लस स्कीम) 3.2.5

हटा दिया गया है।

खातों का रख-रखाव 3.3

स्तर धारक ने जो निर्यात और आयात किया है और जिससे उसे यह मान्यता दी गई है तथा मान्य प्रमाण-पत्र की वैध अवधि के भीतर उसने जो निर्यात और आयात किया है के खाते का सही और उचित लेखा रखेगा। यह रिकार्ड ऐसे प्रमाण-पत्र की वैध तारीख की समाप्ति से कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये लेखे लाइसेंसिंग प्राधिकारी या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रमाण-पत्र की अस्वीकृति/निलंबन/रद्द करना 3.4

यदि प्रमाण-पत्र धारक/आवेदक या कोई एजेंट अथवा कर्मचारी जो उनकी ओर से कार्य करता हो, निम्नलिखित कार्य करने में असफल रहता है तो उस प्राधिकारी द्वारा स्तर प्रमाण पत्र की मान्यता अस्वीकृत अथवा निलम्बित या रद्द की जा सकती है जो ऐसे प्रमाण पत्र जारी/नवीकृत करने के लिए सक्षम है :

(क) लगाए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है;

(ख) लाइसेंसों में रद्दोबदल करता है;

- (ग) किसी लाइसेंस को प्राप्त करने में अन्यथा विवरण देने, या भ्रष्ट या छल कपट करने में एक पक्ष बनता है;
- (घ) विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992 अथवा उसके अधीन बने नियमों या आदेशों का उल्लंघन करना है; या
- (ङ.) विदेश व्यापार महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है;

3.4.1 प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 3.4 (खण्ड-I) के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व आवेदक या स्तर धारक को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

अपील 3.5

जो आवेदक प्रमाण-पत्र के निलंबन या रद्द के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वह उक्त निर्णय की तारीख से 45 दिनों के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार को अपील कर सकता है। महानिदेशक, विदेश व्यापार का निर्णय अन्तिम होगा।

निर्यात संवर्धन परिषद् 3.6

निर्यात संवर्धन परिषदों से संबंधित सामान्य नीति, नीति के अध्याय-2 में दी गई है। निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों की सूची और उत्पाद वर्ग परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

3.7 निर्यात संवर्धन परिषदों का मुख्य कार्य इस प्रकार है:—

- (क) अपने सदस्यों को उनके निर्यात के विकास और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक उपयोगी सूचना और सहायता देना;
- (ख) तकनालॉजी में उन्नति, गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार, मानक और विनिर्देशन, उत्पाद में विकास, नवीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को व्यावसायिक सलाह देना;
- (ग) विदेशी बाजार अवसरों का पता लगाने के लिए अपने सदस्यों के शिष्टमण्डल के लिए विदेशी-दौरो का आयोजन करना;
- (घ) देश और विदेश में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता विक्रेता बैठकों में भाग लेने की व्यवस्था करना;
- (ङ.) केन्द्रीय और राज्य सरकार के स्तर पर निर्यातक समुदाय और सरकार के बीच आपसी बातचीत को बढ़ावा देना; और
- (च) अपने सदस्यों के निर्यात और आयात के संबंध में डाटा बेस तैयार करना।

अलाभकारी स्वशासी और व्यावसायिक निकाय 3.8

निर्यात संवर्धन परिषदें, कम्पनी अधिनियम या सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के अधीन पंजीकृत अलाभकारी संगठन हैं।

3.9 निर्यात संवर्धन परिषदें स्वशासी होंगी और अपने सारे कार्य विनियमित करेंगी। तथापि, यदि केन्द्रीय सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों के संगठन और/अथवा व्यापार कारोबार के लिए समान उपनियम बनाती है तो वे ऐसे संशोधनों के साथ उसे अपनाएँगी जो केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्यात संवर्धन परिषद् के विशेष किस्म या कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित करती है।

निर्यात संवर्धन परिषदों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने और विदेशों में विक्रय दल/प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/वस्त्र मंत्रालय जैसा भी मामला हो संबंधित परिषद् की प्रबंध समिति के साथ वर्ष में दो बार बैठक करेगा, पहली बार उनके वार्षिक योजना और बजट के अनुमोदन के लिए और दूसरी बार उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा और मध्य वर्ष मूल्यांकन के लिए।

3.10 निर्यात की तीव्र गति को बढ़ाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निर्यात संवर्धन परिषदें व्यावसायिक निकायों के रूप में कार्य करें। इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य, प्रबंधन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में व्यावसायिक अनुभव, सरकार और उद्योग में अनुभवी प्रशासकों को निर्यात संवर्धन परिषदों में लाना चाहिए।

सरकारी सहायता 3.11

निर्यात संवर्धन परिषदों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी 3.12

जो निर्यातक पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आर सी एम सी) प्राप्त करना चाहता है उसे आवेदन में अपने मुख्य व्यापार की घोषणा करनी होगी, यह आवेदन व्यापार से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् (ई पी सी) को प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, एक स्तर धारक के पास भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ (फियो) से आर सी एम सी प्राप्त करने का विकल्प होगा।

उपर्युक्त के बावजूद औषध और भेषज निर्यातक फार्मेक्सिल से पंजीकरण सदस्यता प्रमाण पत्र-प्राप्त कर सकते हैं।

तथा लघु वन्य पैदावार एवं उनके मूल्य आधारित उत्पादों के निर्यातक पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र शैलेक निर्यात संवर्धन परिषद् से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सेवा निर्यातकों (साफ्टवेयर सेवा निर्यातकों को छोड़कर) के लिए एफ आई ई ओ से आर.सी.एम.सी. लेना आवश्यक है।

जिन निर्यातकों का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में है, उन्हें आरसीएमसी भुवनेश्वर स्थित फियो कार्यालय से प्राप्त करना होगा चाहे वे उत्पाद का निर्यात कर रहे हों या नहीं।

सेवा क्षेत्र को उचित सलाह देने और बढ़ावा देने के लिए केवल सेवा क्षेत्र के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद् गठित की जायेगी।

3.12.1 इसके अलावा निर्यातक के सामने यह भी विकल्प रहेगा कि वह भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ या अन्य किसी निर्यात संवर्धन परिषद् से आर सी एम सी प्राप्त कर सकता है यदि उसका निर्यात उत्पाद उन परिषदों के अन्तर्गत आता है।

3.12.1.1 यदि निर्यात उत्पाद ऐसा है कि वह किसी ई पी सी के अन्तर्गत नहीं आता है तो इनके बारे में आर सी एम सी भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ द्वारा जारी किया जाएगा।

पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र

3.12.2 निर्यातक परिशिष्ट-19क में दिए गए आवेदन पर पंजीकृत हो सकता है और किसी निर्यात संवर्धन परिषद् का सदस्य हो सकता है। निर्यात संवर्धन परिषद् की सदस्यता स्वीकार हो जाने पर आवेदक को परिशिष्ट 19 (ख) में दिए गए प्रपत्र में उसी समय संबंधित संवर्धन परिषद् का पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाएगा बशर्ते कि इस संबंध में यथा विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हो। यदि कोई निर्यातक विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण करना चाहता है तो उसे इस आशय का प्रमाण पेश करना होगा।

भावी/संभावित निर्यातक आवेदन करने पर पंजीकरण करा सकते हैं और निर्यात संवर्धन परिषद् का संबंध सदस्य बन सकते हैं।

आर सी एम सी की वैधता अवधि

3.12.3 लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से आर सी एम सी की वैधता मानी जाएगी जिसके तहत इसे जारी किया गया था, और यह 31 मार्च को समाप्त लाइसेंसिंग वर्ष से 5 वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

संरचना में परिवर्तन के संबंध में सूचना

3.12.4 किसी निर्यातक के मालिकाना, संरचना, नाम और पते में परिवर्तन होने के मामले में यह निर्यातक आर सी एम सी धारक के लिए अनिवार्य होगा कि वह ऐसे परिवर्तन की तिथि से एक महीने की अवधि में पंजीकरण प्राधिकारी को इस संबंध में सूचित करेगा। तथापि, गुण दोष के आधार पर पंजीकरण प्राधिकारी देरी को माफ कर सकते हैं।

रिटर्न प्रस्तुत करना

3.13 निर्यातक अपने संचालन के क्षेत्र के अनुसार संबंधित प्राधिकारी को अपने निर्यात की विभिन्न आवश्यकताओं तिमाही रिटर्न/ब्यौरे प्रस्तुत करेगा। यह पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किन्हीं अन्य रिटर्न के अतिरिक्त होगी तथापि स्तर धारक फिओ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में फिओ को तिमाही रिटर्न भी भेजेंगे।

विपंजीकरण

3.14 पंजीकरण प्राधिकारी किसी आर सी एम सी धारक को पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए विपंजीकृत कर सकता है। आर सी एम सी धारक को विपंजीकृत करने से पूर्व पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसे एक कारण बताओ नोटिस

जारी किया जाएगा और इसे प्रस्तावित विपंजीकरण के विरुद्ध प्रत्यावेदन देने के लिए उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। विपंजीकरण होने पर संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचित करेगा।

विपंजीकरण के विरुद्ध अपील

3.15 यदि कोई आवेदक आर सी एम सी जारी करने से संबंधित मामलों में पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उक्त निर्णय के विरुद्ध 45 दिन के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा इस पक्ष में पदनामित अधिकारी को अपील कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

महानिदेशक, विदेश व्यापार के निर्देश

3.16 महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी को किसी निर्यातक का पंजीकरण अथवा विपंजीकरण करने का निर्देश दे सकते हैं तथा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों और आदेशों के प्रावधानों को लागू करने, नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक से संबंधित अन्य निर्देश दे सकते हैं।

3.17 इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज

3.17.1 नीति के पैरा 2.45 में ई डी आई की भूमिका एवं कार्यों को परिभाषित किया गया है। ई डी आई पहलों का मूलभूत उद्देश्य विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ता समुदाय के लिए सेवाओं का सुधार है जिससे कार्यों में उच्च पारदर्शिता प्राप्त हो तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस/आज्ञापत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके लेनदेन के व्यय में कमी प्राप्त हो। इन ई डी आई पहलों ने हमारे निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया है।

पात्रता

3.17.2 इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा सभी निर्यातकों को उपलब्ध होगी।

प्रक्रिया

3.17.3 इस योजना के अन्तर्गत निर्यातक अपना आवेदन डी जी एफ टी के वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर फाइल कर सकता है। तब संबंधित लागू नियम और विनियमों के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक को आवेदन फीस सहित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन की मूल प्रति देने के लिए संबंधित कार्यालय जाना होगा। प्रक्रिया पुस्तक में यथानिर्धारित पूरी छानबीन के बाद उल्लिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ प्राप्त होने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

ई डी आई हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

3.17.4 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आवेदनों अथवा/और ई एफ टी (इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) के जरिये इलैक्ट्रॉनिक रूप से दिये गये आवेदन शुल्क में से निम्नलिखित कटौती अनुमत होगी।

क्रम सं.	आवेदन का माध्यम	कटौती शुल्क (सामान्य आवेदन शुल्क के प्रतिशत के रूप में)
1.	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित	25 प्रतिशत
2.	ईएफटी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान	25 प्रतिशत
3.	दोनों डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित तथा ईएफटी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान	50 प्रतिशत

लाभ

3.17.5 यह सुविधा विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ गैर-जरूरी व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क को कम करेगी। इसे तीव्रगति से कार्यवाही होगी, कमियाँ यदि कोई हों उसकी सूचना शीघ्र प्राप्त हो जायेगी तथा आवेदन पर कार्यवाही करने की स्थिति ऑन-लाइन उपलब्ध होगी।

3.17.6 विदेश व्यापार महानिदेशालय इलैक्ट्रॉनिक आवेदन प्रणाली का प्रयोग करते हुए जारी लाइसेंस सीमाशुल्क को ई डी आई मोड के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे क्लियरेंस की अनुमति देने से पूर्व लाइसेंसों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

नई ई डी आई पहले

3.17.7 सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कुछ नई ई डी आई पहले की गई हैं।

- दस्तावेजों को कम करने के लिए एक बहुदेशीय साझा आवेदन प्रपत्र "आयात निर्यात फार्म" प्रारम्भ किया जा रहा है।

3.18 भारत से सेवित स्कीम

(क) भारत से सेवित स्कीम हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

(ख) शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र हेतु अकेला समेकित आवेदन 'आयात निर्यात फार्म' के अनुसार कम्पनी के मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य के मामले में मुख्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर होगी।

(ग) हटा दिया गया है।

(घ) प्रत्येक शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र हेतु न्यूनतम 5 लाख रुपए मूल्य के आंशिक प्रमाणपत्र अथवा उतने मूल्य के अलग-अलग प्रमाणपत्र भी जारी किए जा सकते हैं। प्रत्येक आंशिक प्रमाणपत्र के लिए 1000/- रु. का शुल्क देना होगा। तथापि, आंशिक प्रमाणपत्र (पत्रों) को जारी करने हेतु अनुरोध केवल आवेदन के समय किया जा सकता है और उस पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।

शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र सामान्यतः केवल पंजीकरण के एक पत्तन पर ही जारी किए जाएंगे तथापि, आवेदक प्रत्येक आंशिक प्रमाणपत्र हेतु पंजीकरण के विभिन्न पत्तनों हेतु चुनाव कर सकता है।

(ङ) हटा दिया गया है।

(च) हकदारी को विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.28 के प्रावधान तथा निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना की शर्तों की पूर्ति के मद्दे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों से आयात हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

(छ) शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र 24 महीनों की अवधि हेतु वैध होगा।

शुल्क क्रेडिट प्रमाण-पत्र की पुनर्वैधता अनुमेय नहीं होगी।

सेवा प्रदायक किए गए आयातों को पूरा करने के एक महीने के भीतर अथवा शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, 'आयात निर्यात फार्म' के अनुसार प्रमाणपत्र के तहत किए गए आयातों की विवरणिका क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति क्षेत्राधिकारी उत्पाद शुल्क प्राधिकारी (सेवा कर प्रकोष्ठ को देगा।) जहाँ भी लागू होगा।

(ज) इस स्कीम के तहत सभी आवेदक जो (1 स्टार और उससे अधिक, हेरिटेज होटल) तथा विशिष्ट रेसटोरेंट हैं यह सुनिश्चित करेंगे कि वे शुल्क क्रेडिट हकदारी का पूरा फायदा उपभोक्ता को देंगे।

(झ) केवल वह विदेशी मुद्रा प्राप्तियां जो कि सेवा निर्यातक द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के बदले में कमाई गयीं रकमों को इस स्कीम के तहत हकदारी की गुणना हेतु गिना जाएगा।

विदेशी मुद्रा अर्जनों के अन्य स्रोतों जैसे कि इक्विटी अथवा ऋण भागीदारी, चंदे, कर्जों का पुनः भुगतान तथा प्रदान की गई सेवा से असम्बद्ध विदेशी मुद्रा की अन्य आवकों को इस स्कीम के तहत गणना हेतु गिना जायेगा।

अपात्र प्रेषित धन एवं सेवाएं

3.18.1 (क) निम्नलिखित प्राप्त विदेशी मुद्रा इस स्कीम के अन्तर्गत हकदारी के लिए योग्य नहीं होगी :

I वित्तीय सेवा क्षेत्र से संबंधित प्राप्त की गई रकम

1. सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना
2. ग्राहकों को निर्यात आय की प्राप्ति
3. ए डी आर/जी डी आर अथवा वैसे अन्य जरिए से विदेशी मुद्रा को जारी करना
4. विदेशी मुद्रा बांड को जारी करना

5. प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उपायों की बिक्री
6. अन्य प्राप्तियाँ जो वित्तीय संस्थानों द्वारा चलाई जा रही सेवाओं से जुड़ी नहीं हैं

II. करार/विदेशों में नियमित रोजगार के जरिए प्राप्त धन (जैसे मजदूरी से प्राप्त धन)

(ख) ई ई एफ सी खाते से प्राप्त भुगतान का आकलन स्कीम के तहत लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों जैसे इक्विटी भागीदारी, अनुदान आदि के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार (तथापि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया चिकित्सा उपचार शल्य चिकित्सा, जाँच सलाह और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए प्राप्त प्रेषण अपात्र नहीं होगा)

(घ) शैक्षिक संस्थानों जैसे इक्विटी भागीदारी, अनुदान आदि (तथापि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया पाठ्यक्रम शुल्क और सलाह के लिए प्राप्त प्रेषण अपात्र नहीं होगा)

(ङ) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी स्कीम के अधीन कार्य कर रही यूनिटों का निर्यात कारोबार या ऐसी यूनिटों को की गई आपूर्ति या उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद तथा डीटीए यूनिटों के माध्यम से किया गया निर्यात।

(च) इसके अतिरिक्त इन यूनिटों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारोबार को डीटीए यूनिटों के कारोबार के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

योजना के अधीन आयातित माल का पुनः निर्यात

3.18.2 योजना के अधीन आयातित माल जोकि खराब पाया जाता है या उपयोग के लिए अनुपयुक्त है जो उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी निदेशानिर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यात हेतु स्क्रिप के मद्दे नामे डाली गई क्रेडिट धनराशि का 98 प्रतिशत संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र के रूप में जिसमें सृजित धनराशि और मूल स्क्रिप का ब्यौरा हो सृजित की जाएगी। प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा एक स्वच्छ स्क्रिप जारी की जाएगी। इस प्रकार जारी स्वच्छ स्क्रिप पर पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेष अवधि के बराबर के लिए वैध होगा।

विशेष कृषि और ग्राम उपज योजना

3.19 विशेष कृषि और ग्राम उपज योजना से संबंधित नीति का विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में उल्लेख किया गया है।

3.19.1 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अधीन 1-4-2006 के बाद किए गए निर्यात के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए आवेदन आयात-निर्यात प्रपत्र में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किए जाएंगे। आवेदक एक या अधिक आवेदन इस शर्त पर दाखिल कर सकता है कि प्रत्येक आवेदन में 25 से अधिक शिपिंग बिल केवल एक सीमाशुल्क सदन से किए गए निर्यात से संबंधित होने चाहिए। विशेष कृषि उपज योजना के अधीन 1-4-2005

से 31-3-2006 तक किए गए निर्यात पर यह प्रक्रिया समान रूप से लागू होगी।

शिपमेन्ट्स के संबंध में, जिसके लिए दावा किया गया है, क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यात की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर या वसूली की तारीख से 6 महीने के भीतर या मुद्रण की तारीख/पोतलदान बिल जारी होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किए जाएंगे।

तथापि, 1-4-2005 से 31-3-2006 तक किए गए निर्यात के संबंध में, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अधीन पात्र उत्पादों हेतु क्रेडिट प्रदान करने के लिए ऐसे आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर, 2006 या वसूली की तारीख से 6 महीने के भीतर या मुद्रण की तारीख/पोतलदान बिल के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, होगी।

3.19.2 'आयात निर्यात फार्म', में आवेदन के साथ परिशिष्ट-22 के अनुसार शिपिंग बिल की निर्यात संवर्धन प्रति और बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3.19.3 सीधे साथ-साथ तीसरे पक्ष के द्वारा निर्यातों हेतु, निर्यात दस्तावेज यानी निर्यात आदेश, वीजक, जी आर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र केवल आवेदक के नाम में होना चाहिए।

3.19.4 उन मामलों में जहाँ प्राप्ति के बाद आवेदक ने क्रेडिट हकदारी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया हो अथवा अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र के मद्दे किए गए पोत लदानों अथवा बैंक द्वारा विनिमय बिल का बिना शर्त लाभ उठाया गया हो/साथ-साथ स्वीकार्य/गारंटी दी गयी हो तथा निर्यातक के बैंक द्वारा उसकी पुष्टि की गयी हो तथा निर्यात और प्राप्ति के संगत बैंक प्रमाणपत्र में बैंक द्वारा प्रमाणित हो, क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जाएगी। अन्य मामलों में, क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र शुरू में गैर-हस्तांतरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाएगा। निर्यात आय की प्राप्ति के बाद ऐसे क्रेडिट हकदारी प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय के तौर पर पृष्ठांकित हो सकते हैं यदि आवेदक चाहे तो।

3.19.5 शुल्क क्रेडिट प्रमाण-पत्र पंजीकरण के एकल पत्तन के लिए जारी किया जाएगा और यह वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया हो। तथापि, आवेदक पंजीकरण के पत्तन से टी आर ए प्राप्त करने के बाद किसी अन्य पत्तन से इस शुल्क क्रेडिट को आयात हेतु प्राप्त कर सकता है। जिसमें आईसीडी/एलसीएस शामिल है।

3.19.6 प्रत्येक ड्यूटी क्रेडिट प्रमाणपत्र हेतु, प्रत्येक 5 लाख रुपए के न्यूनतम के मद्दे टुकड़ों में प्रमाणपत्र तथा उनके गुणकों में भी जारी किए जा सकते हैं। प्रत्येक टुकड़ों में प्रमाणपत्र हेतु 1000 रुपए का शुल्क अदा किया जाएगा। तथापि, टुकड़ों में प्रमाणपत्र (प्रमाण-पत्रों) को जारी करने हेतु अनुरोध केवल आवेदन देते समय किया जाएगा तथा बाद में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। टुकड़े में प्रमाणपत्र पर आयातों के प्रयोजनों हेतु पंजीकरण का वही पत्तन होगा जो मुख्य प्रमाण-पत्र में उल्लिखित हो।

3.19.7 निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों के मामले में समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों और विदेश

व्यापार नीति के पैरा 2.28 के प्रावधान की पूर्ति के मद्दे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों से आयात हेतु हकदारी इस्तेमाल की जा सकती है।

3.19.8 शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र 24 महीनों की अवधि हेतु वैध होगा।

शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र के पुनर्विधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

योजना के अधीन आयातित माल का पुनः निर्यात

3.19.9 योजना के अधीन आयातित माल जोकि खराब पाया जाता है या उपयोग के लिए अनुपयुक्त है तो उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी निदेशानिर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यात हेतु स्क्रिप के मद्दे नामे डाली गई क्रेडिट धनराशि का 98 प्रतिशत संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र के रूप में जिसमें सृजित धनराशि और मूल स्क्रिप का ब्यौरा हो सृजित की जाएगी। प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा एक स्वच्छ स्क्रिप जारी की जाएगी। इस प्रकार जारी स्वच्छ स्क्रिप पर पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेष अवधि के बराबर के लिए वैध होगा।

फोकस मार्केट स्कीम

3.20 फोकस मार्केट स्कीम से संबंधित स्कीम विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में दी गयी हैं।

3.20.1 फोकस मार्केट स्कीम के तहत क्रेडिट प्रदान करने हेतु आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र में उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन छह महीनों के आधार पर यानी अप्रैल-सितम्बर और अक्टूबर-मार्च को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तथापि, छह महीनों की अवधि के भीतर प्रत्येक आवेदन में उसी सीमाशुल्क पत्तन से शिपिंग बिल शामिल होंगे तथा विभिन्न सीमाशुल्क पत्तनों से निर्यातों हेतु अलग से आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट का दावा करने हेतु आवेदक को आवेदन की अवधि के अंत से छह महीनों की अवधि के भीतर अथवा उक्त आवेदन द्वारा शामिल विगत निर्यात की प्राप्ति की तारीख के छह महीनों की अवधि के भीतर, जो भी बाद में, प्रस्तुत करना होगा।

3.20.2 सीधे के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा निर्यातों हेतु, निर्यात दस्तावेज यानी निर्यात आदेश, बीजक, जी आर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र केवल आवेदक के नाम में होने चाहिए।

3.20.3 उन मामलों में, जहाँ प्राप्ति के बाद आवेदक ने क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया हो अथवा अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र के मद्दे किए गए पोत लदानों अथवा बैंक द्वारा विनिमय बिल का बिना शर्त लाभ उठाया गया हो/सह-स्वीकार्य/गारंटी दी गयी हो तथा निर्यातक के बैंक द्वारा उसकी पुष्टि की गयी हो तथा निर्यात और प्राप्ति के संगत बैंक प्रमाणपत्र में बैंक द्वारा प्रमाणित हो, क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जाएगी। अन्य मामलों में, क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र शुरू में गैर-हस्तांतरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाएगा। निर्यात आय की प्राप्ति के बाद ऐसे क्रेडिट

हकदारी प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय के तौर पर पृष्ठांकित हो सकते हैं, यदि आवेदक चाहे तो।

पंजीकरण का पत्तन

3.20.4 शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाण-पत्र पंजीकरण के एकल पत्तन के लिए जारी किया जाएगा और यह वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया हो। तथापि, आवेदक पंजीकरण के पत्तन से जिसमें आईसीडी/एलसीएस शामिल है। टी आर ए प्राप्त करने के बाद किसी अन्य पत्तन से इस शुल्क क्रेडिट को आयात हेतु प्राप्त कर सकता है।

टुकड़ों में रिक्वैस्ट हेतु सुविधाएँ

3.20.5 प्रत्येक इयूटी क्रेडिट प्रमाणपत्र हेतु, प्रत्येक 5 लाख रुपये के न्यूनतम के मद्दे टुकड़ों में प्रमाणपत्र तथा उनके गुणकों में भी जारी किए जा सकते हैं। प्रत्येक टुकड़े में प्रमाण पत्र हेतु 1000 रुपये का शुल्क अदा किया जाएगा। तथापि, टुकड़ों में प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) को जारी करने हेतु अनुरोध केवल आवेदन देते समय किया जाएगा तथा बाद में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। टुकड़े में प्रमाण-पत्र पर आयातों के प्रयोजनों हेतु पंजीकरण का वही पत्तन होगा जो मुख्य पत्र में उल्लिखित हो।

निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों से आयात

3.20.6 निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों के मामले में समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों और विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.28 के प्रावधान की पूर्ति के मद्दे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों से आयात हेतु हकदारी इस्तेमाल की जा सकती है।

स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

3.20.7 स्कीम के तहत आयातित माल का जो कि खराब पाया जाता है या उपयोग के लिए अनुपयुक्त है तो उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी निदेशानिर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यात हेतु स्क्रिप के मद्दे नामे डाली गई क्रेडिट धनराशि का 98 प्रतिशत संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र के रूप में जिसमें सृजित धनराशि और मूल स्क्रिप का ब्यौरा हो सृजित की जाएगी। प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा एक स्वच्छ स्क्रिप जारी की जाएगी। इस प्रकार जारी स्वच्छ स्क्रिप पर पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेष अवधि के बराबर के लिए वैध होगा।

वैधता अवधि

3.20.8 शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र 24 महीनों की अवधि हेतु वैध होगा।

शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र के पुनर्विधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

फोकस उत्पाद स्कीम

3.21 फोकस उत्पाद स्कीम से संबंधित स्कीम विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में दी गयी हैं।

3.21.1 फोकस उत्पाद स्कीम के तहत क्रेडिट प्रदान करने हेतु आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र में उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन छह महीनों के अन्तर पर यानी अप्रैल-सितम्बर और अक्टूबर-मार्च को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तथापि, छह महीनों की अवधि के भीतर प्रत्येक आवेदन में उसी सीमाशुल्क पत्तन से शिपिंग बिल शामिल होंगे तथा विभिन्न सीमाशुल्क पत्तनों से निर्यातों हेतु अलग से आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट का दावा करने हेतु आवेदक को आवेदन की अवधि के अंत से छह महीनों की अवधि के भीतर अथवा उक्त आवेदन द्वारा शामिल विगत निर्यात की प्राप्ति की तारीख के छह महीनों की अवधि के भीतर, जो भी बाद में, प्रस्तुत करना होगा।

3.21.2 सीधे के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा निर्यातों हेतु, निर्यात दस्तावेज निर्यात आदेश, बीजक, जी आर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र केवल आवेदक के नाम में होने चाहिए।

3.21.3 उन मामलों में, जहां प्राप्ति के बाद आवेदक के क्रेडिट हकदारी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया हो अथवा अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र के मद्दे किए गए पोत लदानों अथवा बैंक द्वारा विनिमय बिल का बिना शर्त लाभ उठाया गया हो/सह-स्वीकार्य/गारंटी दी गयी हो तथा निर्यातक के बैंक द्वारा उसकी पुष्टि की गयी हो तथा निर्यात और प्राप्ति के संगत बैंक प्रमाणपत्र में बैंक द्वारा प्रमाणित हो, क्रेडिट हकदारी प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जाएगी। अन्य मामलों में, क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र शुरू में गैर-हस्तांतरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाएगा। निर्यात आय की प्राप्ति के बाद ऐसे क्रेडिट हकदारी प्रमाण-पत्र हस्तांतरणीय के तौर पर पृष्ठांकित हो सकते हैं, यदि आवेदक चाहे तो।

पंजीकरण का पत्तन

3.21.4 शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र पंजीकरण के एकल पत्तन के लिए जारी किया जाएगा और यह वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया हो। तथापि, आवेदक पंजीकरण के पत्तन से जिसमें आईसीडी/एलसीएस शामिल है। टी आर ए प्राप्त करने के बाद किसी अन्य पत्तन से इस शुल्क क्रेडिट को आयात हेतु प्राप्त कर सकता है।

टुकड़ों में स्क्रिप्स हेतु सुविधाएँ

3.21.5 प्रत्येक ड्यूटी क्रेडिट प्रमाणपत्र हेतु, प्रत्येक 5 लाख रुपए के न्यूनतम के मद्दे टुकड़ों में प्रमाणपत्र तथा उनके गुणकों में भी जारी किए जा सकते हैं। प्रत्येक टुकड़ों में प्रमाणपत्र हेतु 1000 रुपए का शुल्क अदा किया जाएगा। तथापि, टुकड़ों में प्रमाणपत्र (प्रमाण-पत्रों) को जारी करने हेतु अनुरोध केवल आवेदन देते समय किया जाएगा तथा बाद में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। टुकड़े में प्रमाण-पत्र पर आयातों के प्रयोजनों हेतु पंजीकरण का वही पत्तन होगा जो मुख्य प्रमाणपत्र में उल्लिखित हो।

निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों से आयात

3.21.6 निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों के मामले में समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों और विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.28 के प्रावधान की पूर्ति के मद्दे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों से आयात हेतु हकदारी इस्तेमाल की जा सकती है।

स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

3.21.7 स्कीम के अधीन आयातित माल का जो कि खराब पाया जाता है या उपयोग के लिए अनुपयुक्त है तो उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी निदेशानिर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यात हेतु स्क्रिम के मद्दे नामे डाली गई क्रेडिट धनराशि का 98 प्रतिशत संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र के रूप में जिसमें सृजित धनराशि और मूल स्क्रिप का ब्यौरा हो सृजित की जाएगी। प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा एक स्वच्छ स्क्रिप जारी की जाएगी। इस प्रकार जारी स्वच्छ स्क्रिप पर पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेप अवधि के बराबर के लिए वैध होगा।

वैधता अवधि

3.21.8 शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र 24 महीनों की अवधि हेतु वैध होगा।

शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र के पुनर्विधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

अध्याय-चार

शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम

नीति

4.1 नीति के अध्याय-4 में विनिर्दिष्ट शुल्क मुक्त/शुल्क छूट स्कीम संबंधी नीति दी गई है।

सामान्य प्रावधान

4.2 अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र डी एफ आर सी/डी ई पी बी/बी एफ आई ए हेतु आवेदन, पात्र निर्यातक के पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जा सकता है।

4.3 जहाँ निर्यातक, शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट (यूनिटें) का आवेदक है, वह वैध आर सी एम सी की स्वतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा (क) जहाँ शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट का नाम दिया गया है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र

4.4 जहाँ मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड प्रकाशित कर दिए गए हैं, 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में आवेदन निर्धारित दस्तावेज, सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

4.4.1 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा इनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के मामले में, मात्रा, अपशिष्ट तथा मूल्य संवर्धन मानदण्ड, नीति और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय 4 के अनुसार होंगे।

4.4.2 उन मामलों में, जहाँ मानदण्ड प्रकाशित नहीं किए गए हैं, मानदंडों के निर्धारण के लिए आयात निर्यात प्रपत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) में संबंधित अग्रिम प्राधिकार पत्र समिति को प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे मामलों में, आवेदन की मूल प्रति के साथ निर्धारित शुल्क संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को देना होगा जिसकी एक स्व सत्यापित प्रति ए एल सी को देनी होगी। ऐसे मामलों में ए एल सी की सिफारिश के आधार पर आर एल ए द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएँगे।

कमेटी निवेश-उत्पादन मानदण्डों हेतु सिफारिशी प्राधिकारी के तौर पर भी कार्य करेंगी। अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार महानिदेशक, विदेश व्यापार इन मानदंडों को अधिसूचित करेंगे।

4.4.3 ऐसे आवेदन पत्र, जहाँ आयात के लिए लिए निविष्टि के रूप में एसेटिक एनहाइड्राइड, इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन की अपेक्षा है, ऐसे मामलों में जहाँ मानदण्ड निर्धारित है अथवा मानदण्ड निर्धारित नहीं है संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाएँगी।

ऐसे आवेदनों की प्रतियाँ भारत के औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर और स्वापक नियंत्रण संबंधित ब्यूरो जोनल निदेशक को भी पृष्ठांकित करनी होगी जिसके साथ यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक रिकार्डों का रखरखाव करेगा और निर्धारित रिकार्ड/विवरणियाँ भी प्रस्तुत करेगा।

निर्यात के लिए मसालों [निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-2009 के अध्याय 9 के अंतर्गत] का एक शुल्क मुक्त आयात, अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत अनुमत होगा, यह अनुमति सिर्फ मूल्यवर्द्धित उद्देश्य जैसे क्रशिंग/ग्राउण्डिंग/स्टेराइजेशन अथवा तेल और आले ओरेगैन्स के लिए है, सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, री-पैकिंग आदि के लिए यह अनुमति नहीं है।

4.4.4 लाइसेंसिंग प्राधिकारी जब एसेटिक एनहाइड्राइड, इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करेगा तो वह यह शर्त पृष्ठांकित करेंगे कि आयात करने से पूर्व, भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली और संबंधित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक को भी पृष्ठांकित करेगा।

4.4.5 भारत सरकार/एगिजम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के मद्दे किए गए निर्यात अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत लाभों के पात्र होंगे। आगे, स्कीम के तहत ई सी जी सी द्वारा किए गए स्थगित भुगतान/सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट काट्रैक्ट के तहत किए गए निर्यात भी लाभ के पात्र होंगे।

1057 GI/2006—4

अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

4.5 विनिर्माण प्रयोजन हेतु एक कंपनी की यूनिट से दूसरी कंपनी को अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे प्राप्त या आयातित किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना के तहत, स्पष्ट करते हुए कि ऐसे हस्तांतरित निविष्टियों पर कोई सेनवेट लाभ का दावा नहीं किया जाएगा, हस्तांतरण किया जाएगा। उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त कम्पनी/उत्पाद के मामले में, यूनिट को इसका सही रिकार्ड रखना होगा। तथापि, सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसी सभी यूनिटें आई ई सी प्रमाण-पत्र में उपलब्ध होनी चाहिए और जब वर्क के लिए केन्द्रीय उत्पाद के नियमों और विनियमों का पालन करेगी।

निःशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

4.6 नीति के पैरा 4.1.8 के अनुसार निर्यातक नीति के पैरा 4.1.3 में उल्लिखित मर्चों के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, जिनमें से कुछ अथवा सभी मर्चें निःशुल्क सप्लाय की गई हों।

ऐसे मामलों में, अग्रिम प्राधिकार पत्र के विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति कर विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा जिसमें निःशुल्क सप्लाय किए गए माल के प्रति शुल्क वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी आयातित निवेशों को वेस्टेज के अलावा उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा।

ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में मूल्य संवर्धन की गणना, आयातों के लागत बीमाभाड़ा मूल्य तथा निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, दोनों में निःशुल्क माल के नोशनल मूल्य को जोड़कर किया जाएगा।

जहाँ मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड विद्यमान नहीं है वहाँ स्वधोषित प्राधिकार पत्र

4.7 जहाँ मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, वहाँ ए एल सी द्वारा निर्धारित तदर्थ/मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्डों के अनुसार अंतिम समायोजन के लिए आवेदक के स्वधोषणा और वचनबद्धता के आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र भी जारी कर सकता है। तथापि निम्नलिखित उत्पादों के आयात के लिए इस पैराग्राफ के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

- (i) अध्याय-15 के तहत वर्गीकृत सभी सब्जियाँ/खाद्य तेल और आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-12 के तहत वर्गीकृत बीजों के तेल की सभी किस्में;
- (ii) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के तहत वर्गीकृत अनाजों की सभी किस्में;
- (iii) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-9 और 12 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क वाले सभी मसाले, हल्की काली मिर्च (लाइट बैरिज) को छोड़कर;

(iv) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-7 और 8 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क वाले फलों/सब्जियों की सभी किस्में;

(v) सींग, खुर और जानवर का कोई अन्य अंग।

निर्यात के लिए इत्र, इत्र संयोजकों और विभिन्न भोज्य अवयवों जिनमें विटामिन निहित हों, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस पैराग्राफ के तहत कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आवेदक इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.4.2 के तहत आवेदन कर सकता है। जहाँ जैव तकनीकी मदों का निर्यात और/या आयात शामिल है, इस पैराग्राफ के तहत केवल जैव तकनीकी विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

इससे आगे निर्यात के लिए मामलों [निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-2009 के अध्याय 9 के अंतर्गत] का एक शुल्क मुक्त आयात, अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत अनुमति होगा, यह अनुमति सिर्फ मूल्यवर्द्धित उद्देश्य जैसे क्रबिंग/ग्राउण्डिंग/स्टेरेलाइजेशन अथवा तेल और आले ओरेन्सिन्स के लिए है, सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, री-पैकिंग आदि के लिए यह अनुमति नहीं है।

हकदारी

4.7.1 एक या अधिक ऐसे लाइसेंसों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य स्तर धारकों के मामले में पिछले वर्ष के निर्यात/या आपूर्ति का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/अथवा रेल पर्यन्त शुल्क मूल्य का 500 प्रतिशत होना चाहिए और अन्यो के लिए पिछले वर्ष निर्यात और/या आपूर्ति के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/या रेल पर्यन्त निःशुल्क का 5 करोड़ रुपये अथवा 500 प्रतिशत होना चाहिए, जो भी ज्यादा है।

तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ एएलसी ने पैरा 4.7 के तहत प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में उसी निर्यात और आयात उत्पाद हेतु मानदंडों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, ऐसे मानदंड अनुमोदन की तारीख से छः महीनों की अवधि हेतु वैध होंगे।

ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक एएलसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार और अधिक प्राधिकार पत्रों हेतु पात्र होगा और एएलसी द्वारा बाद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में आवेदक तदर्थ मानदंड निर्धारित श्रेणी के तहत आवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि एएलसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे तदर्थ मानदंड, यदि पहले से अधिसूचित नहीं है तो, ऐसे तदर्थ मानदंडों, के अनुमोदन के छः माह के बाद एक माह की अवधि के भीतर अधिसूचित हो।

“तदर्थ मानदंड निर्धारित” श्रेणी के तहत संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे तथा ऐसे मामलों में आवेदन प्रतिशत मानदंडों के निर्धारण/अनुमोदन हेतु एएलसी को भेजने की जरूरत नहीं होगी।

4.7.2 एएलसी द्वारा मानदंड निर्धारित करने के बाद उप-पैरा 4.7.1 में उल्लिखित मूल्य सीमाएं इस पैरा के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर लागू नहीं होंगी। ऐसे प्राधिकार पत्र, ए एल सी द्वारा मानदंडों के निर्धारण के बाद तक बढ़ाए जा सकते हैं।

मानदंड निर्धारित करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ईपीसी द्वारा जैसा आवश्यक हो, उद्योग के लिए उत्पादन डाटा आदि प्रदान करना अनिवार्य है। अन्यथा, आवेदक को स्वघोषणा आधार पर पुनः अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र

4.7.3 आवेदक सीमाशुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्रस्तुत करके पैरा 4.7.1 में उल्लिखित हकदारी के अलावा उस पैरा के तहत प्राधिकार पत्र हेतु हकदार होगा। प्राधिकार पत्र पर इस आशय का विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा।

आवेदन

4.7.4 निर्धारित दस्तावेजों सहित मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर, मानदंडों के निर्धारण के लिए एस ए एल सी को आवेदन पत्र की एक प्रति ऐसे प्राधिकार पत्र के जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर भेजेगा।

वचनबद्धता

4.7.5 आवेदक यह वचनबद्धता देगा कि वह ए एल सी द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा तथा तदनुसार एएलसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयोग में न लाए गए निविष्टियों पर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करेगा। तथापि प्राधिकार पत्र धारी के पास अतिरिक्त अनुयुक्त निविष्टि के अनुपात में अतिरिक्त निर्यात दायित्व का विकल्प होगा। यदि एएलसी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो प्राधिकार पत्र धारक आयातित निविष्टियों पर बचाए गए सीमा शुल्क का 15 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त अप्रयुक्त आयातित सामान के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर की रकम, “हेड एकाउंट : 1453 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन और माइनर हेड 102” दर्शाते हुए सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में टी आर के माध्यम से जमा करनी होगी। प्राधिकार पत्र धारक को, बढ़ी हुई आयातित प्रतिबंधित निविष्टि को नियमित करने के लिए एक अलग आयात लाइसेंस प्राप्त करना भी आवश्यक है। तथापि, इस उप पैरा के प्रावधान, लागू नहीं होंगे, यदि आयात की तारीख को अप्रयुक्त आयातित सामानमुक्त रूप से आयात योग्य है।

4.7.6 ऐसे मामलों में, जहाँ ए एल सी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी की तारीख से 4 माह के भीतर मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहाँ यथा आवेदित मानदंडों को अंतिम माना जाएगा और कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। तथापि जिन मामलों में अपेक्षित दस्तावेज/सूचना न देने के कारण तदर्थ/मानक मानदंडों के निर्धारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ प्राधिकार पत्र धारी को उपर्युक्त पैरा के दर्शाए गए अनुसार अर्थदण्ड देना होगा। यदि कथित उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड अधिसूचित है, तो मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड, अपशिष्ट मानदंड और निर्यात दायित्व निश्चित करने के प्रयोजन हेतु लागू कर दिए जाएंगे।

ए एल सी द्वारा मानदण्डों के निर्धारण से पूर्व पूरे किए गए निर्यात दायित्व के मामलों में, पैराग्राफ 4.7.1 में यथा उल्लिखित प्राधिकार पत्र की हकदारी विगत लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (शिपिंग बिल/निर्यात बिल की प्रतियों/बीजकों की केन्द्रीय उत्पाद प्रमाणित प्रतियाँ) प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएंगी। तथापि, ऐसे मामलों में मानदण्डों के निर्धारित होने तक बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वित्तीय शक्तियाँ

4.8 वित्तीय शक्तियाँ नीचे सारणी में दी गई हैं :—

आवेदन की श्रेणी	प्रकाशित मानदण्डों और इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.7 के तहत	
	क्षेत्रीय प्राधिकारी	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन पर क्षेत्रीय प्राधिकारी
	पेट्रोलियम/ अन्य	पेट्रोलियम/ अन्य
	पेट्रो रसायन	पेट्रो रसायन
	उत्पाद और	उत्पाद और
	वार्षिक	वार्षिक
	आवश्यकताओं	आवश्यकताओं हेतु
	हेतु अग्रिम	अग्रिम प्राधिकार
	प्राधिकार पत्र	पत्र
प्राधिकार	500 करोड़	100 करोड़
पत्र का लागत रुपए से कम	रुपए से कम	रुपए या अधिक रुपए या अधिक
(बीमा भाड़ा मूल्य)		

तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण

4.9 मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, सहायक विनिर्माता से जुड़े व्यापार-निर्यातक अथवा विनिर्माता निर्यातक द्वारा बाकायदा सम्पूर्ण आंकड़ों सहित आवेदन किया जा सकता है। ऐसे आवेदन 'आयात निर्यात प्रपत्र' में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति (ए एल सी) को किए जा सकते हैं।

ए एल सी द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत भी ईंधन के आयात की अनुमति भी दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :—

- (क) ईंधन के आयात की सुविधा केवल कैप्टिव पावर प्लांट वाले विनिर्माताओं को दी जायेगी।
- (ख) उन मामलों में जहाँ ईंधन को विशिष्ट तौर पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत अनुमति है, उसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी। तथापि, मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड के तहत यदि ईंधन की अनुमति नहीं है, मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए सामान्य ईंधन नीति के अनुसार ईंधन की अनुमति दी जाएगी या पैरा 4.7 के तहत अनुमति दी जाएगी।
- (ग) ईंधन की केवल वास्तविक प्रयोक्ता प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमति होनी चाहिए। तथापि डी एफ आर सी के मामले में, ईंधन केवल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मार्केटिंग अधिकार प्राप्त एजेंसियों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

(घ) जहाँ कहीं ईंधन को मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड के तहत एक निविष्टि के रूप में शामिल किया गया हो, ऐसे उत्पाद हेतु डीईपीबी दर निर्धारित करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जिसके प्रति ईंधन को निवेश के तौर पर अनुमति दी गई है।

(ङ) नये क्षेत्रों के लिए ईंधन हकदारी के निर्धारण के लिए तथा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) में ईंधन हेतु सामान्य टिप्पणी के अनुसार मौजूदा हकदारी के संशोधन के लिए आवेदन, "ईंधन दर के लिए डाटा शीट" से सम्बन्धित आयात निर्यात प्रपत्र में अपेक्षित डाटा सहित अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को किया जाएगा।

अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक जो स्वदेशी रूप से ईंधन प्राप्त करना चाहते हैं वे अग्रिम मुक्त आदेश अथवा बैंक टू बैंक अन्तरदेशीय साखपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईंधन आपूर्ति करने वाले देशी संभरक, नीति के पैराग्राफ 8.3 (क), (ख) और (ग) में दिए गए मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे। यदि देशी संभरक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक को ऐसी ईंधन आपूर्तियों के तहत मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं हो, तो, वह उसे एक डिसक्लेमर जारी कर सकता है इस पर पृष्ठांकित आई ई सी संख्या सहित जिसके आधार पर प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय-8 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त कर सकता है।

मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड का संशोधन

4.10 सहायक विनिर्माता से जुड़े विनिर्माता निर्यातक और व्यापार-निर्यातक द्वारा ए एल सी के समक्ष "आयात निर्यात प्रपत्र" में मौजूदा मानक निविष्टि-उत्पादन मानकों में संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

निर्यात मद और निविष्टि का संशोधन

4.10.1 सिओन अथवा तदर्थ मानदण्ड के अन्तर्गत निर्यात मद अथवा निवेशों के संशोधन हेतु कोई भी विनिर्माता अथवा व्यापारी निर्यातक इस प्रक्रिया पुस्तक के "आयात निर्यात प्रपत्र" के अनुसार आवेदन कर सकता है।

आवेदक को संशोधन हेतु औचित्य भी बताना होगा तथा क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय के पास विचार हेतु कार्यालय प्रमुख के विशेष अनुमोदन के साथ भेजेगा। निविष्टि में किसी मुख्य परिवर्तन अथवा तदर्थ मानदण्ड अथवा सियोन के तहत अनुमत अधिक वेस्टेज के लिए आवेदन के मामले में इसे पुष्टि के लिए ए एल सी को भेजा जाएगा।

एन.सी. द्वारा सिओन का संशोधन

4.10.2 वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अथवा ए. एल. सी. द्वारा जिस समय भी जरूरी समझा जाए, ए. एल. सी. ऐसे सिओन की पहचान करेगी, जिसमें उसके विचार से पुनरीक्षण की आवश्यकता है। निर्यातकों को ऐसे पुनरीक्षण के लिए दिए गए आयात निर्यात फार्म में संशोधित डाटा देना होगा। उद्योग/निर्यातक के लिए यह अनिवार्य है कि सिओन के पुनरीक्षण के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ईपीसी को आवश्यक उत्पादन और खपत के आँकड़े आदि उपलब्ध करवाएँ। अन्यथा, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

अग्रिम प्राधिकार पत्र का विवरण

4.11 अग्रिम प्राधिकार पत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जायेगा :—

- (क) आयात और निर्यात/आपूर्ति की जाने वाली मर्दों का नाम और विवरण
- (ख) आयात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा जहाँ कहीं मात्रा नहीं बताई जा सकती, मद का मूल्य बताया जाएगा। तथापि, यदि मानक निवेश उत्पादन मानदंड में प्रत्येक निवेशों की मात्रा और मूल्य सीमित कारक है तो वह स्वीकार्य होगा।
- (ग) आयातों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य और
- (घ) निर्यात/आपूर्तियों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा।

प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में निर्यात

4.12 अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ई डी आई द्वारा तैयार फाइल संख्या करने की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार की जाएगी। जारी प्राधिकार पत्र के साथ निर्यात/आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोत/आपूर्ति दस्तावेज पृष्ठांकित करना चाहिए। यदि आवेदन अनुमोदित हो तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रारम्भिक निवेश/उत्पादन मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा, जो कि मानदंडों में किसी भी संशोधन के अधिसूचित होने तक किए गए अन्तरिम निर्यात/आपूर्तियों के अनुपात में होगा। निर्यात के लिए निर्यात के लिए, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति प्रक्रिया लागू होगी।

4.12.1 अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलने की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियों पूर्णतः निर्यातक की जिम्मेवारी और जोखिम होगी।

4.12.2 लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन का मामला संशोधित अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा शुल्क मुक्त शिपिंग बिलों से शुल्क वापसी बिलों में परिवर्तन की भी अनुमति दी जा सकती है।

अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआर/डीएफआईए

4.13 अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआरसी अथवा डीएफआईए की मंजूरी के लिए आवेदन, डीएफआरसी अथवा डीएफआईए अग्रिम लाइसेंसधारी, निर्यातक (वास्तविक/मान्य) के साथ पारस्परिक करार के आधार पर दिया जा सकता है। ऐसे अनुरोध पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस, अथवा डीएफआरसी अथवा डीएफआईए अन्तरवर्ती निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई मदों के सीधे आयात के लिए प्राधिकार पत्र को अवैध घोषित करने के बाद जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र धारक को अवैधोक्ति पत्र की एक प्रति दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मध्यवर्ती संभरक के साथ-साथ मध्यवर्ती संभरक के क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी

को भी भेजी जाएगी। ऐसे मामले में, लाइसेंसधारक के पास अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए धारक को अन्तरवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करने अथवा सीधे निर्यात करने का विकल्प होगा। तथापि, क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में इलेक्ट्रॉनिक सन्देश हस्तांतरण की सुविधा पूर्णतया संचालित होने के बाद क्षेत्राधिकार प्राप्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी अवैधोक्ति पत्र/एआरओ की प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार की सुविधा उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए वाले निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने पर सामग्री की आपूर्ति कर दी है या करना चाहता है जहाँ से अवैधोक्ति पत्र जारी किया गया था।

अग्रिम रिलीज आदेश

4.14 स्वदेशी स्रोतों/राज्य व्यापार उद्यमों से निविष्टियों की प्राप्ति के लिए अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.14.1 आवेदन पत्र में (1) मद का नाम, विवरण और मात्रा, और (2) खरीद की जाने वाली मर्दों के अलग-अलग मूल्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए के साथ अथवा बाद में एक एआरओ जारी किया जा सकता है और इसकी वैधता प्रक्रिया पुस्तक में यथा विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए की वैधता के साथ होगी।

अलग-अलग मद की खरीद के लिए जारी अग्रिम रिलीज आदेश स्वतः एक या अधिक स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए भी वैध होगा।

बैंक टू बैंक अन्तरदेशीय साखपत्र (एल सी)

4.15 निर्यातक, बैंक से प्राप्त बैंक टू बैंक अन्तरदेशीय साख पत्र की सुविधा का बारी-बारी से लाभ उठा सकता है। अग्रिम लाइसेंस धारक/डीएफआरसी/डीएफआईए धारक, स्वदेशी संभरक के पक्ष में अन्तरदेशीय (एल सी) साखपत्र खोलने हेतु बैंक के पास जा सकता है।

4.15.1 एल.सी. खोलने से पूर्व, बैंक सुनिश्चित करेगा कि अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए के वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा आवश्यक बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन कर दिया गया है तथा प्राधिकार पत्र पर उसका पृष्ठांकन कर दिया गया है।

तथापि, डीएफआरसी या हस्तांतरणीय या डीएफआईए के प्रति बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता आवश्यक नहीं होगा। अन्तरदेशीय साखपत्र खोलने के बाद, बैंक प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए के इक्विवैलेंट कन्ट्रोल और सीमाशुल्क की प्रति पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा :—

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए मूल्य रुपये कम हो गया है, क्योंकि लाइसेंसधारक ने मैसर्स (स्वदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) के पक्ष में आज इतने ही मूल्य पर अन्तरदेशीय साखपत्र संख्या खोल दिया है।”

4.15.2 स्वदेशी रूप में प्राप्त की जा रही मद की मात्रा और मूल्य के संबंध में केवल सीधी आयात हेतु बैंक द्वारा प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र को अवैध किया जायेगा।

4.15.3 बैंक द्वारा परक्रामण के लिए मूल साखपत्र रख लिया जाएगा तथा साखपत्र की केवल गैर-परक्रामण प्रति स्वदेशी संभ्रक को दी जायेगी।

4.15.4 पृष्ठांकन करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। जब लाइसेंसधारी बैंक से पृष्ठांकन के लिए अनुरोध करता है तो उसके द्वारा दिया गया कोई गलत विवरण या मिथ्या कथन के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में बैंक द्वारा खोला गया अन्तरदेशीय साख पत्र चाहे कुछ भी कारण हो, रद्द नहीं किया जाएगा।

4.15.5 बैंक द्वारा विधिवत पृष्ठांकित अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए की फोटो प्रति सहित अन्तरदेशीय साख पत्र की गैर परक्रामण प्रति स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के लिए मान्य निर्यात लाभों के दावे के लिए पर्याप्त होंगी। तथापि, डीएफआरसी के मद्दे जारी साख पत्र नीति के पैरा 8.3 (ख) में निर्दिष्ट लाभ पाने का पात्र होंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के साख पत्र नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग) में निर्दिष्ट लाभ पाने के पात्र होंगे।

4.15.6 जहाँ इस स्कीम के अधीन, निविष्ट के रूप में स्वर्ण/चाँदी की आयात अनुमति है, वहाँ ऐसी स्वर्ण/चाँदी को इस कार्य के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए के मद्दे आपूर्ति के लिए नीति के अध्याय-4 में पैराग्राफ 4क के बाद उल्लिखित नामित एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सामग्री की आपूर्ति से पूर्व, नामित एजेंसियों उपर्युक्त पैरा 4.15.1 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगी।

सह-विनिर्माताओं/जाबकर्ता/सह प्राधिकार पत्र की सुविधा

4.16 आयातित माल अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या डी एफ आई ई प्रमाण पत्र धारक या जाबकर्ता सह विनिर्माता के किसी भी एकक में प्रयुक्त हो सकता है बशर्ते कि उसका पृष्ठांकन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र में किया गया है। यदि आवेदक किसी विनिर्माता अथवा जाबकर्ता का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ना चाहता है, वह ऐसे पृष्ठांकन के लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ अग्रिम लिए निर्यात से पहले पूर्व निर्यात एक शर्त है प्राधिकार/डीएफआईए स्कीम और प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य विनिर्माता अथवा जाबकर्ता के जरिए सामग्री संसाधित करवाना चाहता है, वहाँ ऐसा पृष्ठांकन अनिवार्य होगा।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किए गए पृष्ठांकन पर, प्राधिकार पत्र धारक और प्राधिकार पत्र धारक संयुक्त रूप से और भिन्न रूप से निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सह-प्राधिकार पत्र धारक में से कोई एक माल का आयात अपने नाम अथवा संयुक्त नाम से कर सकता है। उनके संयुक्त नाम में बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता भी प्रस्तुत की जाएगी।

तथापि, यदि प्राधिकार पत्र धारक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र के पृष्ठांकन के बदले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा जाबकर्ता के नामों को प्राप्त करने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता निर्यातक केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं है/पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन के बिना जाब वर्क की अनुमति होगी। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक आयातित मर्दों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

यदि बैंक गारंटी/विधिक वचन बद्धता विमुक्त कर दी गयी है, तो अग्रिम प्राधिकार प्रमाणपत्र धारक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के तहत निर्धारित जाब कार्य विनियमन के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किसी विनिर्माता से शुल्क मुक्त निविष्टियों का संसाधन करा सकता है। तथापि, हस्तान्तरणीय डी एफ आई ई प्रमाणपत्र के मामले में ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

सह-लाइसेंसधारक की सुविधा

4.17 हटा दिया गया है।

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकार्यता

4.18 प्राधिकार पत्र जारी करते समय, आवेदक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को "आयात निर्यात प्रपत्र" में उल्लिखित फार्म में दी गई वचनबद्धता की स्वीकार्यता को अग्रिम प्राधिकार पत्र के पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा।

टिप्पणी :

(क) कोई आयात करने से पूर्व विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने पर कोई बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता देने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई निर्यात करने से पूर्व निर्यात दायित्व की आंशिक पूर्ति करने के मामले में बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता उसी अनुपात में घटा दी जाएगी।

प्राधिकार पत्र धारक संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को, जहाजरानी बिल की ई पी प्रति और निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र व निर्यात का विवरण जिसमें शिपिंग बिल के अनुसार शिपिंग बिल नम्बर, दिनांक, शिपिंग बिल के अनुसार पोत पर्यन्त मूल्य का ब्यौरा, दिया गया हो, और निर्यात उत्पाद के विवरण का निर्यात दायित्व की सम्पूर्ण अथवा आंशिक पूर्ति को प्रस्तुत करना होगा।

तथापि, निर्यात कारोबार की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि पुष्ट अपरिवर्तनीय साख पत्र अथवा विनिमय के बिल पर बैंक द्वारा, बिना शर्त उपयोग किया हुआ/सह-स्वीकार्यता/गारन्टी के मद्दे पोत लदान किया गया है और उसकी निर्यातक बैंक द्वारा पुष्टि की गई है। इन दोनों ही मामलों में इसका, परिशिष्ट 22क के कॉलम 14/15 में, बैंक द्वारा प्रमाणन किया जाएगा।

(ख) उस अग्रिम प्राधिकार पत्र जिसमें "नो बैंक गारंटी/एल यू टी" सुविधा दी गई हो, उनके मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी "नो बांड प्रमाणपत्र" की प्रतिलिपि उसमें निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए ध्यान में रखे गए पोत लदान के संबंध में, शिपिंग बिल की संख्या, तारीख तथा शिपिंग बिल के अनुसार एफ ओ बी मूल्य और निर्यात उत्पाद के विवरण को दर्शाते हुए उसे संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी जहाँ प्राधिकार पत्र पंजीकृत होना है, को भेजेगा। सीमा शुल्क हेतु "नो बांड प्रमाणपत्र" या निर्यात दायित्व पूर्ति प्रमाण पत्र के जारी होने के तुरन्त मासिक आधार पर बाद क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ऐसे ब्यौरों को डी जी एफ टी वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा।

ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्र में आयात अनुमत करने से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारी "नो बांड प्रमाणपत्र" में दिए गए निर्यात के विवरण की जाँच अपने रिकार्ड से करेंगे।

- (ग) सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा बैंक गारण्टी/विधिक बचन बढ़ता के निरस्तीकरण/विमुक्ति क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय द्वारा निर्यात दायित्व पूर्ति प्रमाणपत्र ई ओ डी सी/बाण्ड खेवर जारी करने के 30 दिन के अन्दर करना होगा।

पंजीकरण का पत्तन

4.19 अग्रिम प्राधिकार प्रमाण पत्र नीचे विनिर्दिष्ट किसी एक बंदरगाह या वायुपत्तन अथवा आई सी डी अथवा एल सी सी के माध्यम से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा। प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार में विनिर्दिष्ट पत्तन के साथ प्राधिकार पत्र को पंजीकृत करेगा और उसके बाद उस प्राधिकार पत्र के प्रति सभी आयातों को तब तक केवल उसी पत्तन से करेगा जब तक कि वह उस पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी से किसी दूसरे विशिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने की अनुमति नहीं ले लेता। तथापि, निर्यात किसी भी एक विनिर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है।

समुद्र पत्तन : मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, काकीनाडा, कांदला, मंगलौर, मरमागौंध, चैन्नई, न्हावशेवा, पाराद्वीप, पिपवाव, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, दहेज, नागपत्तनम, ओखा, मुंद्रा और सूरत (मगडाला) जामनगर, न्हावशेवा।

वायु पत्तन : अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर एयर कार्गो परिसर, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर और चेन्नई।

आई सी डी : आगरा, बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहाटी (अमीनगाँव), गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पित्तमपुर (इंदौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रुद्रपुर (नैनीताल), दिधी (पूणे), बड़ोदरा, दौलताबाद (बंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वलूज (औरंगाबाद), अनापार्थी, सलेम मल्लनपुर, सिंगनालूर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाडी, मदुरई, भोलवाड़ा, पाण्डिचेरी, गद्दी हरसरू, भटिण्डा, दप्पर, छैहराता (अमृतसर), करूर, मिराज, रेवाडी, भूसावल, जमशेदपुर, सूरजपुर, दादरी और तूतीकोरिन।

एल सी एस: रानाघाट हिसंहाबाद और रक्सोल, जोगबनी, नवतनवा (सोनौली), पेटरापोल, महादीपुर, दाबकी।

एस ई जैड : केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई एस ई जैड भी इस पैरा के तहत आयात एवं निर्यात के लिए निर्दिष्ट पत्तनों में से एक होगी।

4.19.1 सार्वजनिक सूचना द्वारा अथवा प्राधिकारपत्र धारक के लिखित अनुरोध पर सीमाशुल्क आयुक्त, विशेष आदेश द्वारा और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित के अतिरिक्त किसी पोत पत्तन/वायु पत्तन/आई सी डी या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन से भी आयात-निर्यात की अनुमति दे सकता है।

4.19.2 उन मामलों में, जहाँ प्राधिकार पत्र का प्राधिकार में निर्दिष्ट पत्तन पर पंजीकरण नहीं हुआ है और आयात नहीं हुआ है, तो पत्तन में परिवर्तन हेतु आवेदन पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा बशर्ते प्राधिकार को विमुक्त न किया गया हो।

4.19.3 पंजीकरण पत्तन के अलावा किसी वायु पत्तन/पोतपत्तन/आई सी डी से आयात के लिए पंजीकरण के पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी को टेलीग्राफिक रिलीज सलाह (टी आर ए) भी जारी किया जाएगा।

मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा

4.20 मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा सिर्फ मामलों की विमुक्ति/विनियमन के लिए उपलब्ध होगी और आगे कोई आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं होगी। इस सुविधा के लिए विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए भी सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता है। तथापि, 2004-2009 अवधि में जारी प्राधिकार पत्र के मामले में, विभिन्न सीमाशुल्क अधिसूचना के अग्रिम प्राधिकार पत्र सहित अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलाने जा सकते हैं।

4.20.1 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जिनके कार्यक्षेत्र के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया है अथवा अन्य मामलों में ए एल सी, एक से अधिक शुल्क मुक्त, अग्रिम प्राधिकार पत्र के आयात और निर्यात को मिलाने के अनुरोध पर भी विचार कर सकती है बशर्ते कि आयातित निवेश का उचित आकलन मानदण्डों के अनुसार किया गया है। इस प्रकार मिलाए गए प्राधिकारों का मूल्य संवर्धन अलग-अलग प्राधिकारों पर लगाए गए मूल्य संवर्धन का औसत होगा। मिलाने के बाद सभी प्रयोजनों के लिए इन प्राधिकारों को एक प्राधिकार माना जाएगा।

4.20.2 इस योजना के तहत जारी वार्षिक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्राधिकार सहित अग्रिम प्राधिकार की अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित आयातों और निर्यातों के उत्तरदायित्व को प्रतिबंधित किया जाएगा।

4.20.3 सिर्फ अग्रिम प्राधिकार के लिए सुविधा उपलब्ध होगी जहाँ निर्यात दायित्व के पूरा करने में कमी है और जो आयात के लिए वैध अग्रिम प्राधिकार के साथ जोड़ा जाना अपेक्षित है। निर्यात दायित्व की कमी के साथ समाप्त प्राधिकार के लिए और आयात के लिए वैध अग्रिम प्राधिकार के साथ जोड़े जाने के लिए आवेदक पैराग्राफ 4.22 के प्रावधानों के अनुसार निर्यात दायित्व की अवधि विस्तार के लिए संयोजन शुल्क अदा करेगा।

4.20.4 ऐसे मामलों में, पहले प्राधिकार के जारी किए जाने के निर्यात दायित्व विस्तार अवधि के (पैरा 4.22 के अनुसार अनुमत) बाद किंग गए निर्यातों, को मिलाने (क्लबिंग) पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.20.5 उपर्युक्त पैरा 4.20.3 और 4.20.4 के प्रावधानों के बावजूद, सभी समाप्त प्राधिकारों को मिलाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी समाप्त प्राधिकार एक्जिम नीति 1992-1997, 1997-2002 अर्थात् 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 2002 के मध्य जारी किए गए हों। तथापि, पूर्व मूल्य आधारित अग्रिम प्राधिकारों के क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्राधिकार के मूल्य में वृद्धि/कमी

4.21 अग्रिम प्राधिकार के संबंध में संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी (उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार), प्राधिकार के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी

वृद्धि के बाद मूल्य वृद्धि में अनुमानित न्यूनतम मूल्य वृद्धि से अधिक की कमी न आए तथा निविष्टि उत्पाद मानदण्डों और नीति जिसके अनुसार प्राधिकार जारी किया गया था, में कोई परिवर्तन नहीं आया हो।

4.21.1 संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी (उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) किसी अग्रिम प्राधिकार के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य निविष्टि की मात्रा, निर्यात दायित्व का पोत पर्यंत मूल्य तथा निर्यात की मात्रा में वृद्धि/गिरावट के अनुरोध पर भी विचार कर सकता है बशर्ते कि निविष्टि उत्पादन, मानदण्डों में कोई परिवर्तन न हो तथा ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य परिवर्धन नीति और प्रक्रिया में निर्धारित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन से कम न हो।

4.21.2 मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन से पूर्व या बाद में किया जा सकता है। उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों में परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएगी।

4.21.3 प्राधिकार पत्र के मूल्य में वृद्धि/कमी के लिए, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के 'आयात निर्यात प्रपत्र' में आवेदन किया जाएगा।

वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क

4.21.4 वृद्धि के लिए लगने वाले आवेदन शुल्क पर मूल और अन्तिम प्राधिकार के लागत बीमा मूल्य के अन्तर पर लगेगी। तथापि, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि प्राधिकार पत्र के मूल्य को कम किया जाए अथवा आवेदक ने अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए मूल आवेदन के साथ अधिकतम शुल्क क्रमशः 150,000 रुपये (व्यक्तिगत तौर पर आवेदन के लिए) और 75,000 रुपये (डिजिटली हस्ताक्षरित आवेदनों के लिए) जमा किए हैं।

निर्यात दायित्व अवधि और इसका विस्तार

4.22 अग्रिम प्राधिकार के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार जारी करने की तारीख से आरम्भ होगी। भारत/विदेश में मान्य निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत परियोजना/टर्नकी को आपूर्तियों के मामले को छोड़कर 24 महीनों की अवधि के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा, जहाँ प्रोजेक्ट/टर्नकी परियोजना के निष्पादन की संविदा अवधि के दौरान निर्यात दायित्व पूरा किया जाए।

इसके अलावा अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत निर्यात के लिए निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण आई टी सी (एच एस) 2004-09 के अध्याय 9 में शामिल मसालों का शुल्क मुक्त आयात केवल मूल्य संबंधित प्रयोजनों जैसे क्रशिंग/ग्राउंडिंग/स्टरलाइजेशन या तेल और ओलिवोरेजिस के लिए न कि सामान्य साफ सफाई, ग्रेडिंग, री-पैकिंग आदि के लिए अनुमत होगा।

तथापि, इस के लिए अग्रिम प्राधिकार के मामले में, जो एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मदों जारी किया गया है और पूर्व आयात शर्त के तहत निर्यात दायित्व की पूर्णावधि पहली खेप के आयात की तारीख से आरम्भ होगी और 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार चाय के लिए अग्रिम प्राधिकार के मामले में, निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि पहले प्रेषण की आयात की तारीख से शुरू होगी और इसे छः महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

4.22.1 निर्यात दायित्व में बढ़ोतरी हेतु आवेदन, 'आयात निर्यात प्रपत्र' में दिए प्रपत्र के अनुसार किया जा सकता है। क्षेत्रीय लाइसेंसिंग

प्राधिकारी प्राधिकार पत्र पर मूल निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए एक वृद्धि प्रदान करेगा बशर्ते प्राधिकार पत्र के अनुसार सभी अपूर्ण आयातित मदों पर बचाए गए संयोजन शुल्क का 2 प्रतिशत भुगतान हो।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा छः महीने के और विस्तार के आवेदन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि लाइसेंस के अनुसार सभी अपूर्ण आयातित मदों पर आधारित शुल्क के 5 प्रतिशत संयोजन शुल्क का भुगतान है।

उपर्युक्त निर्यात दायित्व विस्तार के सभी तीन मामलों के लिए, उपयोग में न लाई गई सभी आयातित मदों पर बचाए गए शुल्क पर मिश्रित शुल्क प्राधिकार पत्र धारक द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात और आयात के सन्दर्भ में परिकलित की जाएगी।

तथापि, पूर्व मूल्य आधारित अग्रिम प्राधिकार (वी ए बी ए एल एस) और वार्षिक आवश्यकता के लिए आग्रिम प्राधिकार के मामले में ऐसे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके अलावा उन प्राधिकारों के संबंध में जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की जानकारी में गलत बयानी/धोखाधड़ी देखने में आई है, निर्यात दायित्व की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन प्राधिकारों के संबंध में जहाँ न्याय निर्णय आदेश पहले से ही जारी कर दिया गया है निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी।

4.22.2 सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यात प्रेषण की अस्थायी निकासी की अनुमति दे सकता है जब प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्यात दायित्व बढ़ाने के लिए आवेदन किये जाने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

प्राधिकार पत्र का पुनर्विधीकरण

4.23 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी मूल प्राधिकार पत्र धारक के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं और मूल प्राधिकार की समाप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए पुनर्विधीकरण कर सकते हैं। प्राधिकार के पुनर्विधीकरण के लिए आवेदन, आयात-निर्यात फार्म में उल्लिखित फार्म में देना होगा।

दायित्व की मानीटरिंग

4.24 लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जिसके साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, निर्यात दायित्व की मानीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा।

दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारक, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.25 के अनुसार निर्यात दायित्व को पूरा करने के संबंध में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

तथापि जहाँ शिपमेंट की विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए छः महीने (स्तर प्रमाण-पत्र धारक के मामले में एक वर्ष) देय नहीं है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्यातों के बैंक प्रमाण-पत्र को जमा न करने और वसूली के लिए कार्यवाही नहीं करेगा बशर्ते कि निर्यात दायित्व को पूरा करने के अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।

4.24.1 यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्राधिकार पत्र धारक असफल रहता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी आगे प्राधिकार देने की मनाही, प्राधिकार की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर सकता है तथा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।

वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार

4.24 क (क) ऐसे प्राधिकारों के लिए पात्र निर्यातक लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 'आयात निर्यात फार्म' में आवेदन कर सकते हैं जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का विनिर्माण यूनिट स्थित है।

कंपनी का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय भी विनिर्माण यूनिट की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामलों में, मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय को उस कारखाने का पूरा पता बताना होगा जहाँ निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों में निविष्टियों का प्रयोग किया जायेगा।

व्यापारी निर्यातकों के मामले में, आवेदन मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक विनिर्माता जिसका नाम और पता इस प्राधिकार के साथ संलग्न शर्त शीट पर पृष्ठांकित किया जायेगा।

(ख) आवेदक प्राधिकार में उल्लिखित मदों के संबंध में किसी भी निविष्टि का आयात कर सकेगा। राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात के लिए आरक्षित मदों का आयात अग्रिम प्राधिकार के मद्दे नहीं किया जा सकता तथापि प्राधिकार पत्र धारक को इस संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्धारित सिसोन/अग्रिम प्राधिकार समिति द्वारा निर्धारित अलग-अलग मानदण्डों के अनुसार निविष्टियों का हिसाब देना होगा।

जिन निर्यात उत्पादों के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड मौजूद नहीं हैं उनके लिए प्राधिकार पत्र धारक को पोत लदान से पूर्व निर्धारित दस्तावेजों सहित 'आयात निर्यात फार्म' में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक आवेदन के व्याख्या पत्र में वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार की संख्या और तारीख तथा जिस फाइल से उक्त प्राधिकार जारी किया गया था, उसकी संख्या भी लिखेगा।

जिन मामलों में प्राधिकार की वैधता अवधि के दौरान अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्धारित सिसोन/अलग अलग मानदण्डों में परिवर्तन किया गया है, तो प्राधिकार पत्र धारक को संशोधन की तारीख से पहले किए संशोधन से पूर्व मानदण्डों के अनुसार किए गए निर्यात और संशोधित मानदण्डों के अनुसार संशोधन की तारीख को या उसके बाद किए गए निर्यात के संबंध में हिसाब देना होगा।

तथापि, निम्नलिखित निविष्टियों के सम्बन्ध में निर्यातक को शिपिंग बिल में वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम प्राधिकारों के लिए आवेदन में तकनीकी लक्षणों, गुणवत्ता और विनिर्दिष्टियों के संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकार जारी करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ऐसे निवेशों के संबंध में तकनीकी लक्षण गुणवत्ता और विनिर्देशन का उल्लेख करना होगा—

स्टेन लेस स्टील, कापर एलाय सिंथेटिक रबर बीयरिंग्स सॉल्वेंट्स परफ्यूम्स/आवश्यक तेल/एरोमैटिक्स रसायन, सरफेक्टेंट्स, सम्बद्ध फैब्रिक्स और संगमरमर सहित एलाय स्टील।

(ग) आयात करते समय, प्राधिकार पत्र धारक आयात कॉलम में प्रविष्टि करने के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को विशिष्ट

और तकनीकी विशेषताओं सहित निविष्टियों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा। प्राधिकार पत्र धारक आयातित निविष्टियों और परिणामी उत्पाद के बीच अंतर्संबंध रखेगा।

(घ) आवेदक निर्यात उत्पाद समूह, लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य और निर्यात दायित्व के पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। तथापि, छूट प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करने वाले निर्यात उत्पाद समूह के अन्तर्गत आने वाले किसी उत्पाद का निर्यात करने का प्राधिकार पत्र धारक को छूट प्राप्त होगी।

(ङ) जारी किए जाने की तारीख से प्राधिकार आयात और निर्यात के लिए 24 महीनों हेतु वैध होगा। निर्यात दायित्व अवधि का और विस्तार और पुनर्वैधीकरण इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.22 और 4.23 द्वारा अधिशासित किया जा सकता है। प्रत्येक प्राधिकार के लिए आयात हेतु पंजीकरण का एक पत्तन निश्चित है। निर्यात पैराग्राफ 4.19 में उल्लिखित किसी भी पत्तन से किया जा सकता है।

प्राधिकरण पत्र के पुनः वैधीकरण और/अथवा निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए आवेदन 'आयात निर्यात फार्म' में दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।

(च) पात्रता के भीतर, निर्यातक किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक या अधिक प्राधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते पंजीकरण के एक पत्तन के मद्दे, उसी उत्पाद समूह के लिए केवल एक प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है।

लाइसेंस वर्ष में एक अथवा अधिक प्राधिकारों के प्रति निर्यात दायित्व पूरा होने पर निर्यातक की हकदारी, उस लाइसेंसिंग वर्ष के लिए प्राधिकारों के मद्दे निर्यात दायित्व पूरा होने के बराबर राशि जितना पुनः जीवित मान लिया जाएगा।

(छ) विस्तारित निर्यात दायित्व की अवधि सहित निर्यात दायित्व की अवधि यदि कोई हो, समाप्त होने पर प्राधिकार पत्र धारक पैराग्राफ 4.25 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करके निर्यात दायित्व पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। निर्यात दायित्व की पूर्ति में वास्तविक चूक के मामले में प्राधिकार पत्र धारक पैरा 4.28 के अनुसार विनिमयन हेतु आवेदन कर सकता है।

4.24 ख पैराग्राफ 4.24 क में निहित उपबंध "अन्तरवर्ती आपूर्तियों" पर भी लागू होंगे जहाँ तक ये निम्नलिखित से असंबद्ध न हो :-

अन्तरवर्ती आपूर्तियों के लिए सुविधा उन मामलों के लिए उपलब्ध है जहाँ अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता प्राधिकार पत्र धारकों को जारी अवैधीकरण पत्रों के मद्दे सामग्री की आपूर्ति करना चाहता है। ऐसे मामलों में, अवैधीकरण पत्र की अन्तरवर्ती विनिर्माता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मदों के सीधे आयात के लिए प्राधिकार को अवैध बनाता है, की एक प्रति प्राधिकार पत्र धारक को दी जाए और इसकी एक प्रति अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता और अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथापि क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक संदेश हस्तांतरण की सुविधा पूर्णतः संचालित होने के बाद, क्षेत्राधिकार प्राप्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अवैधता पत्र/ए आर ओ की प्रति भेजने की

आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा अवैधीकरण पत्रों में वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र का प्राधिकार नम्बर और तारीख भी होनी चाहिए ताकि अवैधीकरण पत्रों को ठीक ढंग से गिना जा सके। प्राधिकार को बन्द करने के प्रयोजन के लिए इन्हें अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

निर्यात दायित्व की पूर्ति

4.25 प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व की पूर्ति के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—

वास्तविक निर्यातों के लिए:—

(1) परिशिष्ट-22क में दिए गए फार्म में प्राप्ति और निर्यात का बैंक प्रमाणपत्र या दस्तावेजों के सीधे लेन देन के मामले में (एफ आर सी) अथवा निर्यात आय को अप्रभावी करने के मामले में परिशिष्ट 22ख। तथापि, निर्यात आय की प्राप्ति पर बल नहीं दिया जायेगा यदि पोतलदान निम्नलिखित के मद्दे किया गया है:—

(क) पुष्ट अपरिवर्तनीय साख-पत्र या

(ख) विनिमय पत्र का बिना शर्त लाभ उठाना/सह-स्वीकृत/बैंक द्वारा गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्ट की गई है।

ऊपर बताए गए (क) और (ख) को बैंक द्वारा परिशिष्ट 22क के कालम 14/15 के अनुसार सत्यापित किया गया हो।

(2) एस ई जेड को निर्यात के मामले में शिपिंग बिल (बिलों) की ई पी प्रतियाँ जिनमें किए गए पोतलदान के विवरण दिए गए हों।

(3) पोतलदान बिलधार निर्यातों का ब्यौरा देते हुए निर्यातों का विवरण जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तारीख, जहाज प्रयन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात उत्पाद का ब्यौरा हो।

(4) बिल में प्रविष्टि कर, निर्यात की मर्दे, निर्यात की मात्रा और उनके लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित निर्यात का विवरण दें।

मान्य निर्यातों के लिए (मध्यवर्ती आपूर्तियों सहित)

(1) बीजक की एक प्रति या बीजक की एक विवरणी जो सामग्री प्राप्त करने वाले यूनिट द्वारा हस्ताक्षरित हो और उनके क्षेत्राधिकारी/उत्पाद प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मर्दों की आपूर्ति, उनकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तिथि को दर्शाने वाली एक प्रति।

तथापि उन मर्दों की प्रतिपूर्ति के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क देय नहीं है या उत्पाद शुल्क देय मर्दें जिन्हें उत्पाद शुल्क देय नहीं उत्पादों की इकाई के रूप में तैयार किया गया है, प्रोजेक्ट प्राधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें आपूर्ति की मद, उसकी मात्रा और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करने वाली उनके अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले उत्पाद प्राधिकारियों का उल्लेख हो।

तथापि ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी को आपूर्ति के संबंध में, क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बकायदा हस्ताक्षरित ए आर ई-3 की एक प्रति जिसमें आपूर्ति की मद इसकी मात्रा, मूल्य तथा ए सी आपूर्ति की तारीख प्रमाणित हो, प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

(2) परिशिष्ट 22-ग में दिए गए फार्म में परियोजना प्राधिकारी से भुगतान प्रमाण-पत्र/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी और

या मान्य निर्यातों (मध्यवर्ती आपूर्तियों सहित) को सप्लाई के लिए प्राधिकार पत्र धारक या ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी या परियोजना प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से माल की प्राप्ति का बैंक प्रमाण का दस्तावेजी प्रमाण परिशिष्ट-22 ख में उल्लिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। तथापि निर्यात आय की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जायेगा, यदि शिपमेंट निम्नलिखित के मद्दे किए गए है:—

(क) पुष्ट अपरिवर्तनीय अन्तरदेशीय साख-पत्र या

(ख) विनिमय पत्र का बिना शर्त लाभ उठाना/सह-स्वीकृत/बैंक द्वारा गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्ट की गई है।

ऊपर (क) या (ख) में निर्धारित शर्तों को परिशिष्ट-22ख के कालम 5/6/7 में बैंक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

(3) आपूर्ति बीजको के ब्यौरा तथा बीजक संख्या, दिनांक, रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, बीजक के अनुसार और उत्पाद के विवरण सूचित करते हुए एक ब्यौरा प्रस्तुत करें।

(4) निर्यात की मर्दे, निर्यात की मात्रा, और उनके लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित प्रविष्टि कर आयात का विवरण प्रस्तुत करें।

निष्क्रियता

4.26 यदि निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया हो तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी मामले को विमुक्त कर देगा।

निष्क्रियता के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निष्क्रियता पत्र की एक प्रति जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तिथि, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जो कि भारतीय रुपये में शिपिंग बिल (बिलों) के अनुसार हो और निर्यात उत्पाद का विवरण पैजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा। डीजीएफटी वेबसाइट पर प्राप्त करने के लिए निर्यात दायित्व पूर्तिप्रमाण पत्र या नो बांड प्रमाणपत्र को जारी होने के तुरन्त बाद क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी महीने के आधार पर इन ब्यौरों को डीजीएफटी वेबसाइट पर डालेगा। वास्तविक निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र के मद्दे बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को पूरा करने से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी अपने रिकार्ड के अनुसार विमुक्ति प्रमाणपत्र में दर्शाए निर्यात का ब्यौरा सत्यापित करेगा। तथापि इंटरमीडिएट लाइसेंस एवं मान्य निर्यात के लिए जारी अग्रिम लाइसेंस के मद्दे बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को पूरा करने से पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों/बोर्ड अधिकारी से आपूर्ति का विवरण सत्यापित करवाएगा।

सामान्यतः बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्क्रियकरण प्राधिकार पत्र धारक के किसी अनुपस्थिति, गलत घोषणा और गलत तथ्यों को बार-बार प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क द्वारा की गई कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी।

इसके अलावा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.30 में यथा निर्धारित विधिवत भरे गये परिशिष्ट 23 के प्रस्तुत न करने पर या परिशिष्ट 23 में प्रस्तुत और घोषित ब्यौरों के मिथ्या निरूपण, मिथ्या बयानी और गलत तथ्यों को बार-बार प्रस्तुत करने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस धारक के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। विमुक्ति प्रमाणपत्र में इससे सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी एक पृष्ठांकन करेगा।

31-8-2004 तक जारी किए गए लाइसेंसों के लिए संकमण प्रबन्ध

4.27 31-8-2004 तक जारी वार्षिक जरूरतों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र सहित अग्रिम प्राधिकारी पत्र प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड - 1) (आर ई 2001) एवं प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर ई 2001) का अध्याय-7 (2002-2007, 31-3-2002 को यथा अधिसूचित) के अध्याय-4 क्रमशः समय-समय पर यथा संशोधित, में निहित शर्तों के अनुसार अधिशासित किए जाएंगे। निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार और क्लबिंग से सम्बन्धित केवल उस प्रावधान को छोड़कर, जो डीजीएफटी द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रावधान और प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.20 और 4.22.1 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित किया जायेगा।

तथापि जिन मामलों में अप्रयुक्त माल पर सीमाशुल्क देय है, वह इस पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगा। यह सुविधा सभी वास्तविक चूक अग्रिम प्राधिकार पत्र के विनियम के लंबित मामलों में लागू होगी भले ही इसके जारी होने के तारीख जिसमें विगत अग्रिम प्राधिकार पत्र (वास्तविक निर्यातों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र) वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र (वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र), मान्य निर्यातों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्पेशल इम्प्रेस्ट प्राधिकार पत्र) अन्तर्वर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार या अंतर्वर्ती प्राधिकार पत्र।

वास्तविक चूक का विनियमन

4.28 निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है :-

(1) यदि निर्यात दायित्व मूल्य की शर्तों पर पूरा किया गया है लेकिन मात्रा की शर्तों के अनुसार उसमें कमी है तो प्राधिकार पत्र धारक को विनियमन के लिए

(क) सीमा शुल्क प्राधिकारी की प्रतिवर्ष 15% ब्याज दर के साथ आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क देगा और

(ख) "शीर्ष लेखा : 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन तथा लघुशीर्ष 102" बताते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में एक खजान रसीद के माध्यम से उपर्युक्त आयातित माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के समतुल्य राशि के 3% रकम। प्राधिकार पत्र धारक को बढ़े हुए आयातित निविष्ट के विनियमन के लिए एक अलग आयात लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। तथापि इस उप पैरा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि आयात का ताराख को उपर्युक्त आयातित माल मुक्त रूप से आयात योग्य हों।

(2) यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर नीति और प्रक्रिया में निर्धारित सकारात्मक मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि मूल्य संवर्धन सकारात्मक से नीचे आ जाता है तो लाइसेंसधारी खजाना रसीद के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में "मुख्य शीर्ष संख्या 1453—विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन उप शीर्ष-102" में प्रदर्शित करते हुए उस कमी के बराबर राशि जमा राशि का 100 गुणा और लागत बीमा

भाड़ा मूल्य के ऊपर संयोजन मूल्य संवर्धन के लिए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य भारतीय रुपये में साथ ही जमा करेगा।

इसकी गणना निर्यात की मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में यथा अनुपात की जायेगी। उदाहरण के लिए यदि निर्यात निष्पादन मात्रावार केवल 50% है लेकिन आयात अनुमत पूर्ण लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए है तो मूल्यवर्धन की यथानुपात आधार पर गणना की जाएगी अर्थात् आयात लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50% होगी। तदनुसार उसका यह मतलब होगा कि जहाँ प्राधिकार पत्र धारक निर्यात निष्पादन करने में असमर्थ हो वहाँ मूल्यवर्धन कमी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(3) यदि निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति मात्रात्मक और मूल्यात्मक दोनों ही शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होता है तो प्राधिकार पत्र धारक ऊपर उल्लिखित (1) और (2) के अनुसार विनियमन के लिए भुगतान करेगा।

(4) यदि निर्यातक, निर्यात दायित्व को पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ है और उसने प्राधिकार पत्र के अधीन कोई आयात नहीं किया है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास शिपिंग बिलों को शुल्क वापसी शिपिंग बिलों में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने और लाइसेंस रद्द करवाने का विकल्प होगा।

(5) लाइसेंसिंग प्राधिकारी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित और सत्यापित परिशिष्ट 23 के सम्बद्ध अंशों को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के शुरू में प्राधिकार (प्राधिकारों) के मदे आयातित वास्तविक मात्रा और प्राधिकार (प्राधिकारों) में अनुमत मानदण्डों से तुलना करेगा। इस सत्यापन प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकार पत्र धारक ने आयातित से कम मात्रा की खपत की है, तो प्राधिकार पत्र धारक आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज के दर से भुगतान करना होगा या निर्यात दायित्व की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करना होगा।

जुर्माना, सीमाशुल्क आदि जमा कराने हेतु समय अवधि

4.29 बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को विनियमित या लागू करने के संबंध में प्राधिकार पत्र धारक से वसूल किया जाने वाला ब्याज सहित सीमाशुल्क, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा की गई माँग के 30 दिनों के भीतर निर्धारित टी.आर. चालान में संबंधित सीमाशुल्क राजस्व के "मुख्य शीर्ष 0037—सीमाशुल्क उपशीर्ष 001 आयात शुल्क" में जमा करेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास तत्काल इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

प्राधिकार पत्र धारक से ऐसे दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की गई वसूली/जमा का ब्यौरा संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी पंजीकरण पत्तन को भेजेगा और उसकी सूचना संयुक्त सचिव (शुल्क वापसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप भवन, नई दिल्ली को देगा।

विनियमन के लिए शुल्क, ब्याज और किसी अन्य राशि का भुगतान अथवा विशेष आयात लाइसेंस को वापिस करना बिना इस पूर्वाग्रह के होना चाहिए कि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत किसी समय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी।

रक्षाओं का समुचित रख-रखाव

4.30 प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 23 में यथा निर्धारित प्राधिकार के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/घरेलु स्रोत से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल और खपत को सही और उचित हिसाब रखेगा। प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरू में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्ड्स को सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना होगा। तथापि, 13-5-2005 को या इसके बाद जारी प्राधिकारों हेतु इन रिकार्ड्स को उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। इन रिकार्ड्स को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र

4.31 शुल्क प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र संबंधी नीति के अध्याय 4 में दी गई है। डी एफ आर सी के तहत निर्यात करने वाले निर्यातकों को शिपिंग बिल की ई पी प्रति में एक घोषणा करनी होगी जिसमें क्रम संख्या और निर्यात उत्पाद के एस आई ओ एन के गुण उत्पाद को दर्शाया गया है।

स्वर्ण/चांदी/प्लेटीनम आभूषणों और उनकी वस्तुओं के मामले में प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, के पैरा 4क.2 की वेबस्टेज मानकों को शिपिंग बिल की ई पी प्रति में निर्दिष्ट करें।

तथापि निम्नलिखित मदों के संबंध में निर्यातकों से शिपिंग बिल में तकनीकी स्थिति, गुणवत्ता और विशिष्टिकरण की घोषणा करनी होगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी करते समय निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों की मात्रा, तकनीकी विशेषताओं और विशिष्टियों के संबंध में एक उल्लेख करेगा।

स्टेनलेस स्टील सहित एलॉय स्टील, कॉपर एलॉय, सिंथेटिक रबर, बिरिंग, सेलुलेंट, परफ्यूमस/इसेन्सियल आयल/इथेरेमेटिक रसायन, सरफैक्टेंट्स, रिलेवेक्ट कैबरिक्स, मारबल।

इसके मद्दे प्राप्त डी एफ आर सी और विशिष्ट निविष्टियों निम्नलिखित परिस्थितियों में वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन हैं :

- (i) निर्यात आय को प्राप्त कर लिया गया है और अपरिवर्तनीय साख पत्र के तहत निर्यात नहीं किया गया है या, विनिमय पत्र का लाभ नहीं उठाया गया है। सह-स्वीकृति नहीं दी गई है/गारंटी नहीं दी गई है, या
- (ii) डी एफ आर सी वास्तविक प्रयोक्ता शर्त सहित सियोन के मद्दे जारी किया गया है, या
- (iii) सियोन के तहत विशिष्ट निविष्टियां वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन हैं।

अन्य सभी परिस्थितियों में डी एफ आर सी के मद्दे प्राप्त निविष्टियां मुक्त रूप के हस्तांतरणिय हैं। तथापि, ईंधन के मामले में इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जिन एजेंसियों को विपणन अधिकार दिए गए हैं केवल उन्हें ही हस्तांतरण किया जा सकता है।

राज्य व्यापार उपक्रमों द्वारा आयात के लिए आरक्षित मदों को डी एफ आर सी के मदों को डी एफ आर सी के मद्दे आयात नहीं किया जा सकता। तथापि इन मदों को डी एफ आर सी धारक को जारी ए आर ओ के मद्दे राज्य व्यापार उपक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है।

4.31 क डीएफआरसी धारकों को की गई आपूर्ति को छोड़कर नीति के अध्याय-8 में उल्लिखित आपूर्ति के लिए भी डीएफआरसी उपलब्ध होगी। ऐसी डी एफ आर सी आवेदक के विकल्प के अनुसार प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.19 पर उल्लिखित किसी एकल पंजीकरण पत्तन के साथ जारी किया जाएगा।

डीएफआरसी का लागत बीमा भाड़ा मूल्य आपूर्ति के एफओआर मूल्य से 20% घटाने के बाद निर्धारित होगा। एफ ओ आर मूल्य की संगणना नीचे दिए गए उप पैरा (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे :

(1) सामग्री प्राप्त करने वाले एकक और उनके कार्य क्षेत्र वाले आपूर्ति की मद को अधिप्रमाणित करने वाले उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बीजक की एक प्रति, ऐसी आपूर्ति की मात्रा, मूल्य और तारीख। तथापि ऐसी मदों की आपूर्ति जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है अथवा उत्पाद शुल्क न लगने वाले उत्पादों का उत्पादन करने वाले यूनितों को की जाने वाले उत्पाद शुल्क वाले मदों की आपूर्ति के मामले में, उत्पाद प्रमाणपत्र के बदले में परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र जिसमें मात्रा प्रमाणित की गई हो, आपूर्ति का मूल्य और तारीख स्वीकार्य होगी।

उपर्युक्त बातों के होते हुए ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी आपूर्तिकर्ता को विकल्प होगा कि आपूर्तियों के संबंध में क्षेत्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों/बांड अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सीटी-3 ए आर ई 3 की एक प्रति जिसमें आपूर्ति के पद उनकी मात्रा मूल्य और तारीख प्रमाणित की गयी हो, प्रस्तुत की जाएगी।

(2) परियोजना प्राधिकारी से परिशिष्ट-22ग में उल्लिखित फार्म पर भुगतान प्रमाणपत्र अन्तर्वर्ती आपूर्तियों/मान्य निर्यातों के मामले में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी को आपूर्तियाँ सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राधिकार पत्र धारक या ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी जैसे भी मामला हो कारोबार से प्राप्तियों के संबंध में बैंक से दस्तावेजी प्रमाण परिशिष्ट 22-ख उल्लिखित फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा।

तथापि, यदि सुनिश्चित अपरिवर्तनीय अन्तरदेशीय साखपत्र के मद्दे पोतलदान किया गया हो और उसे परिशिष्ट 22ख के कॉलम 5/6/7 में अधिप्रमाणित किया गया है तो निर्यात कारोबार से प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा। निर्यात आय को प्राप्त करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए यदि पोतलदान पुष्ट किये गए अपरिवर्तनीय अन्तरदेशीय साख पत्र के मद्दे किया गया है या अन्तरदेशीय विनिमय पत्र का बिना शर्त लाभ उठाया गया है/सह-स्वीकृत है/बैंक द्वारा गारंटी दी गई है और इसकी निर्यात बैंक द्वारा पुष्टी की गई है। भारत सरकार/एजिम बैंक लाईन ऑफ क्रेडिट के मद्दे किया गया निर्यात और स्थगित भुगतान/ई सीजीसी कवर द्वारा समर्थित सप्लायर्स लाईन ऑफ क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट तहत किया निर्यात डी एफ आर सी स्कीम के तहत लाभ पाने के भी पात्र होंगे।

डी एफ आर सी/के तहत निर्यात/आयात

4.32 डी एफ आर सी के तहत प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.19 में उल्लिखित किसी भी बन्दरगाह से और किसी भी एस ई जेड को निर्यात पोतलदान किया जा सकता है। डी एफ आर सी एक मात्र पंजीकृत बन्दरगाह के लिए जारी की जायेगी जो वही बन्दरगाह होगा जिससे

निर्यात प्रभावी होगा। फिर भी निर्यात के बन्दरगाह के अलावा अन्य किसी बन्दरगाह से किए जाने वाले आयात के लिए टी आर ए निर्यात के बन्दरगाह पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयातक बन्दरगाह पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

आवेदन प्रस्तुत करना

4.33 डी एफ आर सी प्रदान के लिए आवेदन आयात-निर्यात प्रपत्र में उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। डी एफ आर सी के लिए आवेदन निर्यात/आपूर्ति आय प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्तुत किया जाएगा।

तथापि, इसके मद्दे निर्यात/आपूर्ति के मामले में—

- (क) अनुमोदित परिवर्तनीय साख पत्र या अनुमोदित अपरिवर्तनीय अन्तरदेशीय साख पत्र या
- (ख) विनिमय पत्र का बिना शर्त लाभ उठाना/सह-स्वीकृत बैंक द्वारा गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्टी की गई है।

निर्यात/आपूर्ति के बाद आवेदन भरा जायेगा।

पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर परिकलित किया जायेगा। तथापि, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण तथा उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के मामले में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से लागत बीमा भाड़ा मूल्य को आकलन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क 2.1 में उल्लिखित मूल्य संवर्धन के अनुसार किया जाएगा।

समय सीमा

4.34 डी एफ आर सी के लिए आवेदन छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसे शिपमेंट के संबंध में प्राप्ति की तारीख तक गिना जाएगा, जिसके संबंध में लिए डी एफ आर सी माँगा गया है।

4.34.1 अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे निर्यात/अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे आपूर्ति या विनिमय पत्र के मामले में बिना शर्त लाभ उठाना/सह-स्वीकृत बैंक द्वारा गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्टी की गई है। के तहत निर्यात के मामले में डी एफ आर सी छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसे शिपमेंट के संबंध में प्राप्ति की अन्तिम तारीख तक गिना जाएगा, जिसके लिए डी एफ आर सी माँगा गया है।

4.34.2 निर्यात के मद्दे अग्रिम भुगतान हेतु डी एफ आर सी निर्यात के मद्दे अग्रिम भुगतान की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर भरी जायेगी।

4.34.3 जहाँ कहीं सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम शिपमेंट की अनुमति दी गई है वहाँ ऐसे निर्यात के तहत डी एफ आर सी, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा शिपमेंट बिल रिलीज के पश्चात ही जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा शिपिंग बिल को जारी करने की तारीख से छः महीने अथवा प्राप्ति की तारीख से छः महीने, जो भी बाद में हो होगी।

आवेदन प्रस्तुत करने की बीच अवधि

4.35 आवेदक निर्यात के एक बन्दरगाह से एक निर्यात उत्पाद हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जिन मामलों में भिन्न-भिन्न पंजीकरण के बन्दरगाह से उसी उत्पाद का निर्यात किया गया है तो निर्यातक उसी निर्यात उत्पाद समूह के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

विखण्डित सुविधा

4.35.1 प्रत्येक शुल्क क्रेडिट प्रमाण-पत्र के लिए विखण्डित प्रमाण-पत्र न्यूनतम 5 लाख और इसके गुणकों की शर्त के अधीन जारी किए जायेंगे। प्रत्येक विखण्डित प्रमाण-पत्र के लिए 1000 रु. शुल्क का भुगतान करना होगा तथापि विखण्डित लाइसेंस जारी करने के लिए अनुरोध केवल आवेदन करते समय करना होगा और इस पर बाद में विचार नहीं किया जायेगा। शुल्क क्रेडिट प्रमाण-पत्र एक पत्तन पंजीकरण के लिए जारी किया जायेगा।

सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जाँच

4.36 क्षेत्रीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि डी एफ आर सी जारी करते समय शिपिंग बिल की संख्या व तारीख, निर्यात उत्पाद के विवरण और शिपिंग बिल के अनुसार भारतीय रुपये में एफ ओ बी मूल्य को डी एफ आर सी के पीछे पृष्ठांकित किया गया है। डी एफ आर सी के तहत आयात की अनुमति देने से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि डी एफ आर सी में दिए गए निर्यात के ब्यौरे उनके रिकार्ड के अनुसार हैं।

मान्य निर्यातों के लिए डी एफ आर सी जारी करते वक्त क्षेत्रीय प्राधिकारी इसकी एक प्रति पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क को तथा एक प्रति उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को जिनका क्षेत्राधिकार मान्य निर्यातों को पाने वाली यूनिट तक होगा, पृष्ठांकन करेगा और वह ऐसी आपूर्ति की मद, इसकी मात्रा, मूल्य और दिनांक सहित बीजक का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

जहाँ कहीं क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों तथा उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित रिकार्ड में कोई भिन्नता पायी जाती है तो उत्पाद शुल्क प्राधिकारी, पंजीकरण पत्तन पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी और सीमाशुल्क प्राधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी प्रमाणपत्र के प्रति आपूर्तियों की स्वीकृति से पहले क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से पंजीकरण के पत्तन पर आपूर्तियों के ब्यौरे की जाँच कराएगा।

डी एफ आर सी स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

4.36क डी एफ आर सी स्कीम के तहत आयातित वस्तुओं, जिन्हें खराब अथवा प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया है, का राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, ऐसी वस्तुओं के निर्यात हेतु डी एफ आर सी के मद्दे नामे डाले गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 95 प्रतिशत के बारे में प्रमाण-पत्र के रूप में संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा गारंटी देनी होगी, जिसमें गारंटी की राशि और मूल डी एफ आर सी के ब्यौरे दिए गए हों। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा

एक नया डी एफ आर सी जारी किया जायेगा। इस प्रकार जारी किए गए नये डी एफ आर सी में यही पंजी करण पत्तन होगा और यह ऐसे खराब/अनुपयुक्त वस्तुओं के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेष अवधि के बराबर अवधि के वैध होगा।

शुल्क पात्रता पासबुक योजना (डीईपीबी)

4.37 शुल्क पात्रता पासबुक योजना से संबंधित नीति, नीति के अध्याय-4 में दी गई है। इस योजना के अधीन शुल्क क्रेडिट, एस आई ओ एन के उपर्युक्त निर्यात उत्पादों के मान्य निर्यातों और ऐसे सिओन के अनुसार मान्य निर्यातों पर लगने वाले सीमा शुल्क के आधार पर परिकलित की जायेगी। इस योजना के अधीन, ऐसे उत्पादों के निर्यात के माध्यम से मूल्य संवर्धन शुल्क क्रेडिट की जो दर निर्धारित की गई है, के खाते में डाली जायेगी।

डी ई पी बी दर का निर्धारण

4.38 'आयात निर्यात फार्म' में डी ई पी बी दरों के निर्धारण से संबंधित है। डी ई पी बी दरों के निर्धारण के सभी आवेदन संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से भेजे जाएंगे जो निर्यात के पोत पर्याप्त निशुल्क मूल्य की निविदियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सहित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों के अनुसार जाँच करेगी।

अस्थायी डी ई पी बी दर

4.38क विविधता को उत्साहित करने और नये उत्पादों के निर्यात को तरक्की प्रदान करने के लिए, डी ई पी बी समिति को ऐसे उत्पादों को विशेष मामलों के तौर पर ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तथापि, ऐसी डी ई पी बी दरें कुछ निश्चित अवधि के लिए वैध रहेंगी जिसके दौरान दरों के नियमित निर्धारण के लिए निर्यातक, निर्यात और आयात डाटा प्रस्तुत करेगा।

डी ई पी बी प्रत्याशा में निर्यात

4.39 डी ई पी बी योजना के अधीन किसी निर्यात की अनुमति नहीं है। जब तक कि संबंधित निर्यात उत्पाद की डी ई पी बी दर अधिसूचित नहीं कर दी जाती है।

पंजीकरण का पत्तन

4.40 विशिष्ट पत्तनों से किए गए निर्यात/आयात डी ई पी बी के लिए पात्र होंगे।

समुद्र पत्तन : मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, दाहोज, काकीनाड़ा, कांदला, मंगलौर, मरमागौव, मुन्दरा, चेन्नई नावसेवा, पेराद्वीप, पिपानाव, सिक्का टूटीकोरिन विशाखापत्तनम सूरत (मगडाला), नागपट ओखा, धरमतार, जामनगर और नावा सेवा

वायु पत्तन : अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर एयर कार्गो काम्प्लेक्स, कोचीन दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर श्रीनगर त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर और चेन्नई।

अंतर्. सी. डी : आगरा, अहमदाबाद, बंगलौर, भिवन्डी, कोयम्बटूर दौलताबाद, (चंजरवाड़ी और भालीवाड़ा) दिल्ली, दिघी (पुणे), फरीदाबाद, गुन्डूर हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जोधपुर, कानपुर,

कोटा, लुधियाना, मदुरै और राजाघाट मल्लनपुर में लैण्ड कस्टम स्टेशन, मुरादाबाद, मेरठ, नागपुर, नासिक, गुवाहाटी (अमिनगाँव), पिम्परी (पुणे) पीतनपुर (इंदौर), रुद्रपुर (नैनीताल), सेलम, सिंगनलुर, सूरत, निरुपुर, उदयपुर, बदोदा, वाराणसी, बालुज भिलवाड़ा, पांडिचेरी और गहीहर्सर, भुसावल, जमशेदपुर, सुरजपुर दादरी और टूटीकोरिन

एल. सी. एस : रानाघाट और सिंहबाद, रक्तौल, जोगबनी, नौतनवा (सनोल) पैट्रपोल और महदीपुर और डाकी

एस. ई. जैड : भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोना (जोनो) को किये गये निर्यात डीईपीबी हकदारी के पात्र होंगे और ऐसे मामलों में संबंधित एसईजैड ही पंजीकरण के पत्तन होंगे।

बशर्ते कि सीमाशुल्क आयुक्त सार्वजनिक सूचना अथवा प्राधिकार पत्र धारी के लिखित अनुरोध पर विशेष आदेश से ओर ऐसी शर्तों के प्रति जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, किसी अन्य समुद्री पत्तन हवाई पत्तन इंग्लैंड कंटेनर डिपो अथवा भूमि सीमाशुल्क द्वारा आयात अथवा निर्यात की अनुमति दे सकता है।

4.40.1 डी ई पी बी केवल एकल पंजीकरण पोर्ट के लिए जारी की जायेगी। यह वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया है।

रिकार्ड का रख-रखाव

4.40.2 प्रत्येक सीमाशुल्क सदन डी ई पी बी जहाजरानी बिल के अधीन किए गए निर्यात के ब्यौरे का अलग रिकार्ड रखेगा।

डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट और मौजूदा बाजार मूल्य

4.41 जिन उत्पादों के संबंध में डी ई पी बी योजना के अधीन क्रेडिट हकदारी की दर 10 प्रतिशत या इससे ज्यादा है वहां ऐसे प्रत्येक निर्यात उत्पाद के प्रति क्रेडिट की राशि निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निर्यात के समय निर्यातक को जहाजरानी बिल पर यह घोषणा करनी चाहिए कि निर्यात उत्पाद के प्रति डी ई पी बी योजना के तहत लाभ निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

तथापि वर्तमान बाजार मूल्य घोषणा उन उत्पादों पर लागू नहीं होगी जिनके उत्पाद की डी ई पी बी दर के संबंध में वैल्यू कैप न हो।

डी ई पी बी क्रेडिट का उपयोग

4.42 डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट का इस्तेमाल पूंजीगत माल को छोड़कर आयातित किसी भी मद पर सीमाशुल्क का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

डी ई पी बी के लिए आवेदन

4.43 डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए आवेदन संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 'आयात निर्यात फार्म' में उल्लिखित फार्म में निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिया जा सकता है। सीमाशुल्क द्वारा (अनुमत निर्यात) पूर्व निर्यात आदेश की तारीख को लागू विधि को वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रा विनियम अधिसूचना के तहत मुक्त विदेशी मुद्रा में

पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है। डी. ई. पी. बी. हकदारी के लिए एजेंसी की कमीशन जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के केवल 12.5 प्रतिशत तक सीमित होगी।

4.43(क) परेषण निर्यात के संबंध में, जहाँ निर्यातक ने अनन्तिम आधार पर उत्पाद के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की घोषणा कर दी है तो निर्यातक ऐसे माल की मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में बिक्री से प्राप्त वास्तविक पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आधारित शिपिंग बिल का अन्तिम मूल्यांकन के लिए पात्र होगा। डीईपीबी हकदारी के लिए एजेंसी की कमीशन केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12.5 प्रतिशत तक सीमित है। तथापि, विदेशी मुद्रा के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को सीमाशुल्क द्वारा "अनुमत निर्यात" के आदेश की तारीख को यथा लागू विषय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्यात के लिए विनियम दर के अनुसार भारतीय रुपयों में परिवर्तन किया जाएगा।

4.43(ख) डी टी ए से एस ई जैड यूनिटों को आपूर्तियों हेतु क्रेडिट को प्रदान करने के लिए डीटीए यूनिट या एसईजैड यूनिट द्वारा आवेदन किया जा सकता है। यदि दावा लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास किया गया है तो डीटीए यूनिट लाभ का दावा या तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी या संबंधित विकास आयुक्त से कर सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी डीटीए यूनिट को लाभ अनुमत करने के साथ-साथ पत्र की एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को पृष्ठांकित करेगा। इसके साथ निर्यात दस्तावेजों का ब्यौरा होगा जिसके मद्दे शामिल लेन देन की पुष्टि हेतु लाभ अनुमत किए गए हैं। यदि डी टी ए सभरक विकास आयुक्त के पास दावा करना पसंद करता है तो विकास आयुक्त डी ई पी बी लाभ अनुमत करने से पहले डीजीएफटी की वेबसाइट से सभरक के निषिद्ध सूची स्तर (डीईएल) का सत्यापन करेगा। एसईजैड यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को आयात निर्यात फार्म में निम्न दस्तोवजों के साथ देना होगा।

- (1) बैंक रसीद (डुप्लिकेट में)/ डिमान्ड ड्राफ्ट परिशिष्ट 21ख के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में
- (2) एस ई जैड में सीमाशुल्क द्वारा जारी निर्यातों के बिल की एक प्रति
- (3) बीजक की एक प्रति जो आपूर्ति की एफ और आर मूल्य, ऐसी आपूर्ति पर डी ई पी बी हकदारी और ऐसी बिक्री से प्राप्त कुल मूल्य दर्शाती हो
- (4) परिशिष्ट 22ख के अनुसार प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र
- (5) यदि एसईजैड यूनिट ऐसी प्राप्त की गयी आपूर्ति के लिए डी ई पी बी लाभ प्राप्त करना चाहती है। उन्हें डीटीए यूनिट से डिसक्लेमर सर्टिफिकेट देना होगा कि डी टी ए यूनिट इन आपूर्तियों पर किसी लाभ का दावा नहीं करेगी तथा इन आपूर्तियों पर डी ई पी बी लाभ का दावा करने के लिए एस ई जैड यूनिटों को प्राधिकृत करेगी।

4.44 ऐसे मामलों में जहाँ आवेदनक प्राप्ति के बाद डी ई पी बी के लिए आवेदन करता है या निर्यात और निकासी के संबंधित बैंक प्रमाण-पत्र में बैंक द्वारा प्रमाणित अपरिवर्तनीय साखपत्र अथवा विनियम पत्र का लाभ उठाना/सह-स्वीकृत/बैंक गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्टि की गई के मद्दे शिपमेंट हुआ है तो डी ई पी बी हस्तान्तरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जायेगी। अन्य मामलों में शुरू में डी ई पी बी निर्यात कारोबार की प्राप्ति के बाद अहस्तान्तरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जायेगी। निर्यात आय प्राप्त होने पर ऐसे डी ई पी बी को हस्तान्तरित के तौर पर पृष्ठांकित किया जा सकता है।

निकासी की मोनिटरिंग

4.45 क्षेत्रीय प्राधिकारी उन मामलों को मानिटर करेगा जहाँ निर्यात कारोबार की आय से पूर्व डी ई पी बी मंजूर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वसूली निर्धारित समय के भीतर हो जाएगी। (ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ शिपमेंट का माध्यम शाख पत्र अथवा विनियम पत्र का लाभ उठाना/सह-स्वीकृत/बैंक गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्टि की गई। के माध्यम से हुआ है) ऐसे करने में असफल रहने पर वे 15 प्रतिशत ब्याज के साथ डी ई पी बी शाख के बराबर राशि की वसूली के मामलों में वसूली की राशि पर 4.29 में बताए गये सीमा शुल्क के मुख्य लेखा शीर्ष खाते में जमा की जायेगी।

4.45.1 यदि निर्यात आय छः महीने के भीतर या भारत में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत बढ़ाई गई अवधि के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता तो डी ई पी बी धारक ऐसे निर्यात के प्रति प्राप्त क्रेडिट की राशि पर डी ई पी बी जारी होने की तारीख से जमा करने की तारीख तक 15 प्रतिशत ब्याज देना होगा। जहाँ विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई राशि उस राशि से कम है जिस पर डी ई पी बी क्रेडिट प्राप्त किया गया है तो डी ई पी बी धारक एस ए डी सहित आयात पर उपयोग किए गए शुल्क मुक्त के अनुपातिक राशि (डी ई पी बी के अधीन केवल आयात के लिए एस ए डी की छूट हो) पर आयात की तारीख से जमा करने की तारीख तक 15 प्रतिशत तक नकद ब्याज देगा।

समय-अवधि

4.46 क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर या वसूली की तारीख से तीन माह के भीतर शिपिंग बिल के प्रिंटिंग/रिलीज होने के तीन महीने के भीतर जो भी बाद में हो, किए जाएँगे। शिपमेंट जिसके लिए दावा किया गया है उसका हिसाब वसूली/निर्यात की अंतिम तारीख से लगाया जाएगा।

4.47 जहाँ कहीं सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनन्तिम पोतलदान की अनुमति दी गयी है वहाँ ऐसे निर्यात के प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जहाजरानी बिल रिलीज करने के बाद ही डी ई पी बी जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में, डी ई पी बी के लिए आवेदन ऐसे जहाजरानी बिल के रिलीज की तारीख से छः महीनों के भीतर या वसूली की तारीख से छः महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, किए जाएँगे।

आवेदनों की संख्या

4.48 किसी एक आवेदन में सभी जहाजरानी बिल केवल एक सीमाशुल्क सदन से किए गए निर्यात से संबंधित होने चाहिए। जहाजरानी

बिलों की संख्या पर कोई समय सीमा नहीं है जिन्हें एक आवेदन में ई डी आई के तरीके जारी किया जा सकता है।

सीमाशुल्क द्वारा सत्यापन

4ड49 1-10-2005 से पहले के ई डी आई शिपिंग बिलों और गैर ई डी आई शिपिंग बिलों के मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी डी ई पी बी जारी करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजरानी बिल संख्या और तारीख, जहाजरानी बिल (बिलों) के अनुसार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य भारतीय रुपयों में और निर्यात उत्पाद का ब्यौरा डी ई पी बी पर पृष्ठांकित है। डी ई पी बी के प्रति आयात अनुमत करने से पहले, सीमाशुल्क यह सत्यापित करेगा कि डी ई पी बी पर दिए गए निर्यात का ब्यौरा उनके लेख के अनुसार है। तथापि, ई डी आई पत्रों से 1-10-2005 को या उसके बाद जारी ई डी आई शिपिंग बिलों के मामले में जिन्हें सीमाशुल्क द्वारा डी जी एफ टी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है तो जारी डी ई पी बी को इलेक्ट्रॉनिक मैसेजी एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से पंजीकरण के पतन पर सीमाशुल्क को भेजा जाएगा तथा डी ई पी बी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण के पतन पर पंजीकरण किया जाएगा। शिपिंग बिलों का कोई सत्यापन, जिसके मद्दे ऐसी डी ई पी बी जारी की गई है, इन डी ई पी बी के मद्दे आयात अनुमत करने से पहले, की आवश्यकता नहीं होगी।

पुनः वैधीकरण

4.50 कोई पुनः वैधीकरण डी ई पी बी की मूल वैधता अवधि के बाद प्रदान नहीं किया जाएगा। जब तक कि प्रक्रिया पुस्तक पैरा 2.13 के तहत प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय/सीमाशुल्क की सुरक्षा में यह समाप्त नहीं हो जाता।

डी ई पी बी स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

4.51 राजस्व विभाग द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार डी ई पी बी स्कीम के तहत आयातित माल जो खराब अथवा उपयोग हेतु उचित न पाया जाए, का पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, ऐसे माल के निर्यात हेतु डी ई पी बी के प्रति क्रेडिट राशि को 98 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। प्रमाण-पत्र के रूप में संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा ऐसा किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र में राशि और मूल डी ई पी बी के ब्यौरे शामिल होंगे। प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नया डी ई पी बी जारी किया जाएगा। इस प्रकार जारी डी ई पी बी के पंजीकरण का पतन वही रहेगा और डी ई पी बी की वैधता की शेष अवधि के बराबर की अवधि हेतु वैध होगा जिसके प्रति इन वस्तुओं का आयात किया गया था।

जहाजरानी बिलों की खो गई ई पी प्रतिलिपि के मद्दे डी ई पी बी और अन्य शुल्क क्रेडिट प्रमाण-पत्र /डी एफ आर सी जारी करना

4.52 जिन मामलों में जहाजरानी बिलों की ई पी प्रतिलिपि खो गई है, वहाँ डी ई पी बी और अन्य ड्यूटी क्रेडिट प्रमाण-पत्र/डी एफ आर सी के दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाएं।

(क) खो गए मूल जहाजरानी बिल के स्थान पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट/सत्यापित प्रतिलिपि।

(ख) खो गए जहाजरानी बिल के संबंध में डी ई पी बी/डी एफ आर सी हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क या डी एफ आर सी हकदारी 1 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो। तथापि, सरकारी एजेंसियों द्वारा शिपिंग बिल खोने पर दस्तावेजी प्रमाण देने से शुल्क नहीं लगेगा।

(ग) खो गए जहाजरानी बिलों के संबंध में निर्यातक द्वारा एक शपथ-पत्र और यह आश्वासन कि यदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा।

(घ) इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बांड निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि खो गए जहाजरानी बिल के बदले जारी किए गए डी ई पी बी/डी एफ आर सी के कारण सरकार को यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

निकासी करने से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसी शिपिंग बिल के प्रति डी ई पी बी/डी एफ आर सी का लाभ नहीं लिया गया है।

4.52.1 खोए हुए जहाजरानी बिल का दावा जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट प्रतिलिपि की वसूली की तिथि के छः महीने के भीतर होना चाहिए तथा इस प्रकार के किसी आवेदन पर इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। तथापि यदि कोई अनंतिम मूल्यांकित डी ई पी बी जहाजरानी बिल खो जाता है तो इस प्रकार के मामले में डी ई पी बी के आवेदन की तारीख अंतिम मूल्यांकित जहाजरानी बिल की वसूली की तिथि से छः महीने के भीतर होगी।

मूल बैंक प्रमाणपत्र का खो जाना

4.53 जिन मामलों में मूल बैंक प्रमाणपत्र खो जाता है उन मामलों में डी ई पी बी/डी एफ आर सी दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ—

(क) खाए हुए मूल प्रमाणपत्र के बदले बैंक प्राधिकारी द्वारा जारी बैंक प्रमाण-पत्र की अनुलिपि।

(ख) खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के संबंध में डी ई पी बी पात्रता के 2% या डी एफ आर सी के 1% के बराबर आवेदन फीस, जैसा भी मामला हो।

(ग) बैंक प्रमाणपत्र के खो जाने के संबंध में निर्यातक द्वारा एक हलफनामा जिसमें यह वचन दिया गया हो कि यदि

वह प्रमाण बाद में मिल जाता है तो उसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को लौटा दिया जाएगा।

- (घ) निर्यातक द्वारा इस आशय का एक इन्डैमैनिटी बान्ड प्रस्तुत किया जाएगा कि वह खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति जारी डी ई पी बी/डी एफ आर सी के मद में यदि सरकार को कोई क्षति होती है तो वह उस क्षति की पूर्ति करेगा।

खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति दावों निर्यात की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाए कि उसके बाद प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहाँ दोनों दस्तावेज खो जाते हैं तो निर्यातक पैराग्राफ 4.51 व 4.52 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएगा।

शुल्क मुक्त आयात हकदारी स्कीम (डी एफ आई ए)

4.54 शुल्क मुक्त आयात हकदारी स्कीम से सम्बंधित नीति, नीति के अध्याय 4 में दी गई है

आवेदन

4.55 सिओन के अनुसार आयात हकदारी के साथ 'आयात निर्यात फार्म' में एक आवेदन, आवेदन पत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.55.1 सोने/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उसकी वस्तुओं के निर्यात के मामले में गुणवत्ता, छीजन और मूल्यवर्धन मानदण्ड नीति और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क में निर्धारित अनुसार होंगे।

4.55.2 आवेदन जिनमें एसिटिक एनहाईड्राइड, इफेड्राइन और स्यूडो इफेड्रिन की आयात के लिए निविष्टि के रूप में आवश्यकता है और सिओन में निर्धारित है तो वे सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के पास दाखिल किए जाएंगे।

ऐसे आवेदनों की प्रतियाँ, भारत के औषध नियन्त्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, स्वापक आयुक्त केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर, और स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो के सम्बन्धित क्षेत्रीय निदेशक को एक घोषणा के साथ-साथ पृष्ठांकित करेगा कि आवेदक निर्धारित रिकार्ड रखेगा और निर्धारित विवरणी भी प्रस्तुत करेगा।

डी एफ आई ए स्कीम के अधीन निर्यात के लिए मसालों का शुल्क मुक्त आयात (निर्यात और आयात मदों, 2004-09 के आई टी सी (एच एन) वर्गीकरण के अध्याय 9 में शामिल) केवल मूल्यवर्धन प्रयोजनों जैसे क्रसिंग/ग्राउंडिंग/स्टेरीलाइजेशन या तेलों और ओलियोरेजिंस बनाने के लिए अनुमत है न कि केवल क्लोनिंग, ग्रेडिंग, री-पैकिंग आदि के लिए।

क्षेत्रीय प्राधिकारी जब एसिटिक एनहाईड्राइड, इफेड्राइन और स्यूडो इफेड्रिन के आयात के लिए डी एफ आई ए प्रमाण पत्र जारी करेंगे तो वह यह शर्त पृष्ठांकित करेंगे कि आयात करने से पूर्व, भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण

पत्र प्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति औषध नियन्त्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली और संबंधित स्वापक ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक को भी पृष्ठांकित करेगा।

4.55.3 तथापि निम्नलिखित मदों के संबंध में निर्यातकों से शिपिंग बिल में तकनीकी स्थिति, मात्रा और विशिष्टकरण की घोषणा करनी होगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी करते समय निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों की मात्रा, तकनीकी विशेषताओं और विशिष्टियों के संबंध में एक उल्लेख करेगा।

स्टेनलेस स्टील सहित एलॉय स्टील, कॉपर एलॉय, सिंथेटिक रबर, बिरिंग, सोल्वेंट, परफ्यूमस/एसेंम्येयल आयल/एरोमेटिक रसायन, सरफैस्टेंट्स, रिलेवेन्ट फैबरिक्स, मारबल पोलीप्रोपीन से बनी वस्तुएं, पेपर और बोर्ड से बनी वस्तुएं, इन्सेक्टीसाइड्स, लेडइन्गोट्स, जिंक इन्गोट्स साइट्रिक एसिड, रेलिवेंट ग्लास फाइबर, चोपड/स्ट्रेन्डिड मैट्रोविंग वूवन सेफेंसिंग मैट, रेलिवेंट सिंथेटिक रेजिन (अनसेचुरेटिड, विनाइल ईस्टर रेजिन, हाइड्रोक्सी इथिलसेल्यूलोज), लाइनिंग मैटिरियल

भारत सरकार/निर्यात आयात बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के मदों किए गये निर्यात डी एफ आई ए स्कीम के अधीन लाभों के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त स्थापित भुगतान/आपूर्तिकर्ता लाइन ऑफ क्रेडिट ठेका जिसके लिए ई सी जी सी कवर उपलब्ध है के अन्तर्गत किए निर्यात इस स्कीम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।

बहु यूनिटों वाले आवेदकों हेतु डी एफ आई ए प्रमाणपत्र

4.56 अधिक यूनिटों वाली कम्पनियों के मामले में डी एफ आई ए प्रमाणपत्र जारी करते समय आरएलए को कम्पनी की यूनिट विशेष हेतु आयातित सामग्री के प्रयोग को पृष्ठांकित करना होगा तथा इस स्पष्ट समझौते के साथ कि ऐसे स्थानांतरित निवेशों पर सेनवैट के लाभ का दावा नहीं किया जाएगा, कम्पनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से किसी भी सामग्री की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को स्थानांतरित किया जा सकता है। उत्पाद शुल्क से छुट प्राप्त कम्पनी/उत्पाद के मामले में, यूनिट को इसका सही रिकार्ड बनाना होगा। तथापि, सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी यूनिटें आई ई सी प्रमाण-पत्र में उपलब्ध होनी चाहिए और जाँव वर्क के लिए केन्द्रीय उत्पाद के नियमों और विनियमों का पालन करेगी।

निःशुल्क और प्रदत्त माल हेतु डीएफआईए प्रमाण पत्र

4.57 निःशुल्क और भुगतान किये गये माल हेतु डीएफआईए प्रमाण पत्र निर्यातक सिओन के अनुसार मदों के आयात के लिए डीएफआईए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

इनमें से कुछ या सभी मदों जिनकी आपूर्ति की जानी है निःशुल्क हो सकती है। ऐसे मामलों में मूल्य संवर्धन के परिकलन हेतु अन्य निःशुल्क निविष्टियों के नोशनल मूल्य को भी ध्यान में रखा जाए। तथापि यदि सभी निविष्टियों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है तो निर्यातक को नीति के पैरा 4.2.7 में दिये गये उपबंधों को अपनाने का विकल्प रहेगा।

ऐसे डीएफआईए के मामले में मूल्य संवर्धन की गणना, आयातों के लागत बीमाभाड़ा मूल्य तथा निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, दोनों में निःशुल्क माल के नोशनल मूल्य को जोड़कर किया जाएगा।

ऐसे मामलों में अग्रिम लाइसेंस के निदेशों द्वारा निम्नलिखित प्रति पर विशिष्ट प्रमाणन किया जाएगा कि निर्गत निर्यात/आपूर्ति के लिए मूल्य का अभाव के प्रति शुल्क वापसी की अनुमति नहीं दी जायेगी। वापसी के लिए निदेशों को पोस्टेज के अलावा उत्पाद के निर्यात में प्रयुक्त किया जायेगा।

ऐसे डीएफआईए के मामले में मूल्य संबंधित की गणना, आयातों के लगत बीमाभाड़ा मूल्य तथा निर्यातों के पोस्ट पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, दोनों में निःशुल्क माल के नोशनल मूल्य को जोड़कर किया जाएगा।

विविध शक्तियाँ

4.58 वितीय शक्तियाँ प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.9 के अनुसार होंगी।

डीएफआईए का विवरण

4.59 डीएफआईए में निम्नलिखित की विनिर्दिष्ट किया अन्वेष।

- (क) आयात-निर्यात/आपूर्ति की जाने वाली वस्तु का नाम और विवरण
- (ख) आयात की जानेवाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा वहाँ काई मात्रा नहीं बताई जा सकती मद का मूल्य बताया जायेगा। तथापि यदि मानक निवेश उत्पादन मानदंड में संबंधित निवेशों की मात्रा और मूल्य सीमित करक है तो वह स्वीकार्य होगा।
- (ग) अन्वेषों का कुल लगत बीमा भाड़ा मूल्य और
- (घ) निर्यात/आपूर्ति का पोस्ट पर्यन्त मूल्य/रेल पर्यन्त मूल्य और मात्रा।

डीएफआईए की प्रत्याशा में निर्यात

4.60 डीएफआईए के लिए आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार की जाएगी। तथापि, ई-कमर्स आवेदन के मामले में, डीएफआईए हेतु ई डी आई से तैयार फाइल सं. की तारीख से की गई निर्यात आपूर्तियाँ स्वीकार की जा सकती हैं। यदि आवेदन अनुपस्थित हो तो द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निवेश/उत्पादन मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा जो कि मानदंडों में किसी भी संशोधन के अधिसूचित होने तक किए गए अन्तरिम निर्यात/आपूर्तियों के अनुपात में होगा। निर्यात के सेब हिस्से के लिए प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/प्रक्रिया लागू होगी।

4.60.1 डीएफआईए मिलाने की प्रत्याशा में शीघ्र नए निर्यात/आपूर्तियों पूर्णतः निर्यात/आपूर्ति की विनियमों और शर्तों के अंतर्गत।

4.60.2 लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा डीएफआईए के आवेदन का मामला संशोधित अथवा अस्वीकृत होने की तिथि में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा शुल्क मुक्त विनिर्देशों से शुल्क वापसी विलों में परिवर्तन की भी अनुमति दी जा सकती है।

पंजीकरण का पतन

4.61 प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.19 में विनिर्दिष्ट किसी एक वायु पतन या आईसीडी या एलसीडी के जरिये आयात और निर्यात के प्रयोग के लिए डीएफआईए जारी किए जाएंगे।

बैंक गारंटी/विविधक वचनबद्धता की स्वीकृति

4.62 लाइसेंस जारी करते समय, आवेदक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में उल्लिखित फार्म में दी गई वचनबद्धता की स्वीकार्यता को डीएफआईए के पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा।

टिप्पणी : कोई आयात करने से पूर्व विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने पर कोई बैंक गारंटी/विविधक वचनबद्धता देने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई निर्यात करने से पूर्व निर्यात दायित्व की आंशिक पूर्ति करने के मामले में बैंक गारंटी/विविधक वचनबद्धता उसी अनुपात में घटा दी जाएगी।

डी.एफ.आई.ए. लाइसेंस मूल्य में वृद्धि/कमी

4.63 डी.एफ.आई.ए. के संबंध में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (उनकी वितीय शक्तियों के अनुसार), डीएफआईए के आयात या निर्यात की मात्रा, के लगत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य वृद्धि में अनुमानित न्यूनतम मूल्य वृद्धि से अधिक की कमी न आए तथा निविष्टि उत्पाद मानदंडों और नीति जिसके अनुसार प्राधिकार पत्र जारी किया गया था, में कोई परिवर्तन नहीं आया हो।

मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन निर्यात से पूर्व या बाद में किया जा सकता है। उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निवेश उत्पादन मानदंडों में परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएगी।

प्रमाणपत्र के मूल्य में वृद्धि/कमी के लिए, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के 'आयात निर्यात प्रपत्र' में आवेदन किया जाएगा।

निर्यात दायित्व अवधि और इसमें वृद्धि

4.64 निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि और इसमें वृद्धि इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.22 में दिये गये उपबंधों के अनुसार शासित होगी।

डी.एफ.आई.ए. प्रमाण पत्र की पुनर्विधीकरण

4.65 डी.एफ.आई.ए. धारक को पुनर्विधीकरण की सुविधा इस पुस्तक के पैराग्राफ 4.23 में दिये गये उपबंध के अनुसार उपलब्ध होगी।

डीएफआईए स्कीम के तहत आयतित माल का पुनः निर्यात

4.66 हस्तांतरणीय डीएफआईए के मदे आयतित माल, जिसे खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यात हेतु डीएफआईए के मदे डेबिट किया गया लगत-बीमा-भाड़ा मूल्य का 95 प्रतिशत स्मबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक प्रमाण पत्र के रूप में जिसमें सृजित धनराशि और मूल डीएफआईए का ब्यौरा शामिल हो,

प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक स्वच्छ डीएफआईए जारी किया जाएगा।

इस प्रकार जारी किया स्वच्छ डीएफआईए प्राधिकरण का समान पतन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त सामान के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेष अवधि के समकक्ष अवधि के लिए वैध होगा।

दायित्व की मॉनीटरिंग

4.67 क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके साथ डी.एफ.आई.ए. लाइसेंसधारी द्वारा विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा।

दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारी, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.25 के अनुसार निर्यात दायित्व को पूरा करने के संबंध में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

तथापि जहाँ शिपमेंट की विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए छः महीने (स्तर प्रमाण-पत्र धारक के मामले में एक वर्ष) देय नहीं है, क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यातों के बैंक प्रमाण-पत्र को जमा न करने और वसूली के लिए कार्यवाही नहीं करेगा बशर्ते कि निर्यात दायित्व को पूरा करने के अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।

यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्राधिकार पत्र धारक असफल रहता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आगे लाइसेंस देने की मनाही, लाइसेंस की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर सकता है तथा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।

निर्यात दायित्व की पूर्ति

4.68 प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व की पूर्ति के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—

क्रास्तविक निर्यातों के लिए :—

(1) परिशिष्ट-22 क में दिए गए फार्म में "निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र या दस्तावेजों के सीधे लेन देन के मामले में (एफ आई आर सी) प्रत्यक्ष निर्यात आय को अप्रभावी करने के मामले में परिशिष्ट 22 ख। तथापि, निर्यात आय की प्राप्ति पर बल नहीं दिया जायेगा यदि कर्ज के पुष्ट अपरिवर्तनीय पत्र के प्रति पोतलदान दिए गए हैं।

(क) अनुमोदित अपरिवर्तनीय साख-पत्र या

(ख) विनिमय पत्र का बिना शर्त लाभ उठाना/सह-स्वीकृत/ बैंक द्वारा गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्टि की गई है

ऊपर बताए गए (क) और (ख) को बैंक द्वारा परिशिष्ट 22 क के कालम 14/15 के अनुसार सत्यापित किया गया हो।

(2) एस ई जेड को निर्यात के मामले में शिपिंग बिल की ई पी प्रतियाँ जिनमें किए गए पोतलदान के विवरण दिए गए हों।

(3) पोतलदान बिलवार निर्यातों का ब्यौरा देते हुए निर्यातों का विवरण जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तारीख, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात उत्पाद का ब्यौरा हो।

(4) बिल में प्रविष्टि अनुसार, निर्यात की मर्दे, निर्यात की मात्रा और उनके लगाने बीमा भाड़ा मूल्य सहित निर्यात का विवरण दें।

मान्य निर्यातों के लिए (मध्यवर्ती आपूर्तियों सहित)

(1) बीजक की एक प्रति या बीजकों की एक विवरणी जो सामग्री प्राप्त करने वाले यूनिट द्वारा हस्ताक्षरित हो और उनके क्षेत्राधिकार वाले उत्पाद प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मर्दों की आपूर्ति, उनकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तिथि को दर्शाने वाली एक प्रति।

तथापि, उन मर्दों की प्रतिपूर्ति के मामले में जिनमें उत्पाद शुल्क देय नहीं है या उत्पाद शुल्क हेतु देय मर्द जिन पर उत्पाद शुल्क देय नहीं उत्पादों की इकाई के रूप में तैयार किया गया है, प्रोजेक्ट प्राधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें आपूर्ति की मद, उसकी मात्रा और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करने वाली उनके अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले उत्पाद प्राधिकारियों का उल्लेख हो।

तथापि, के बावजूद ई ओ यू/ई एच टी पी/बी टी पी/एस टी पी/को आपूर्ति के संबंध में, क्षेत्राधिकारी उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बाकायदा हस्ताक्षरित सीटी-3 की एक प्रति जिसमें आपूर्ति की मद इसकी मात्रा, मूल्य तथा ए सी आपूर्ति की तारीख प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।

(2) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/मान्य निर्यात (मध्यवर्ती आपूर्तियों सहित) के मामले में परिशिष्ट 22-ग में दिए गए फार्म में परियोजना प्राधिकारी से भुगतान प्रमाण-पत्र ई ओ यू/ई एच पी टी/एस टी पी/बी टी पी या प्रोजेक्ट प्राधिकारी से सप्लाइ के लिए मध्यवर्ती आपूर्तियों/मान्य निर्यातों के अग्रिम लाइसेंस के मामले में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से माल की प्राप्ति के बैंक प्रमाण का दस्तावेजी प्रमाण परिशिष्ट-22 ख में उल्लिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। तथापि, निर्यात आय की प्राप्ति पर

कोर नहीं दिया जायेगा यदि शिपमेंट निम्नलिखित के मद्दे किए गए हैं :—

- (क) पुष्ट अपरिवर्तनीय साख-पत्र या
- (ख) देशीय बिल का बिना सर्व लाभ उठाना/सह-स्वीकृत/ बैंक द्वारा गारंटी दी गई है और इसकी निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्टि की गई है। ऊपर (क) या (ख) में निर्धारित शर्तों को परिशिष्ट-22 के कलम 5/6/7 में बैंक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- (3) आपूर्ति बीजकों के ब्यौरे तथा बीजक संख्या, दिनांक रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, बीजक के अनुसार और उत्पाद के विवरण सूचित करते हुए एक ब्यौरा प्रस्तुत करें।
- (4) बिल में प्रविष्टि के अनुसार, आयात की मर्दे आयात की मात्रा और उनके संगत बीमा भाड़ा मूल्य सहित आयात का विवरण दें।

निवेशों के लेखा का ठीक रख-रखाव

4.69 मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट-23 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकार-पत्र के मद्दे फ्रेल् खरीद/पुस्तक आयातित माल की खपत और उपयोग का सच्य और सही लेखा रखेगा। ये रिकार्ड बांड मुक्ति/निर्यात दायित्व/हस्तांतरणीयता की निष्क्रियता/पूर्ति हेतु आवेदन सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी (यों) को भेजना आवश्यक है। ये रिकार्ड निष्क्रियता की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु सुरक्षित रखे जाने चाहिए।

निष्क्रियता

4.70 यदि निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया हो तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी मामले को निष्क्रिय कर देगा।

निष्क्रियता के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निष्क्रियता पत्र की एक प्रति जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तिथि, पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जो कि भारतीय रुपये में शिपिंग बिल (बिलों) के अनुसार हो और निर्यात उत्पाद का विवरण बैंक/कारक के कलम पर सील शुल्क प्राधिकारी को भेजना। निर्यात दायित्व प्रति प्रमाणपत्र अथवा बांड प्रमाणपत्र नहीं को जारी करने के बाद तुरंत क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा डीजीएफटी वेबसाइट पर भी ऐसे ब्यौरे रखे जाएं जहाँ सील शुल्क तक कार्यालय डीजीएफटी वेबसाइट से देख सके।

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की पूरा करने से पूर्व, सीमाशुल्क प्राधिकारी अपने रिकार्ड के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणपत्र में दर्शाए निर्यात का ब्यौरा सत्यापित करेगा। इसमें इंटरनैशियल लाइसेंस एवं मान्य निर्यात के लिए जारी अग्रिम लाइसेंस के मद्दे बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को पूरा करने से पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों/बोर्ड अधिकारी से आपूर्ति का विवरण सत्यापित करवाएगा।

सामान्यतः एल वू टी के निष्क्रियता लाइसेंस धारक के किसी अनुपरिवर्ति, गलत घोषणा और गलत ब्यौरे को धार-धार प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क द्वारा की गई कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी।

इसके अलावा, परिशिष्ट-23 में उल्लिखित ब्यौरों में बाद में पता लगी गलत घोषणाओं और गलत तथ्यों हेतु अथवा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4.69 में यथा विनिर्दिष्ट, बाक्यदा उल्लिखित, परिशिष्ट-23 को प्रस्तुत न करने के मामलों में लाइसेंस धारक के विरुद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही भी की जाएगी। इस बारे में निष्क्रियता प्रमाणपत्र में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा एक प्रवृत्तकन किया जाएगा।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी/बांड छूट को रा करने के 30 दिनों के भीतर सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को रद्द/निष्क्रिय करेगा।

वास्तविक चूक का विनियमन

4.71 निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.28 में निर्धारित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है।

डी एफ आई ए प्रमाण पत्र के मद्दे आयातित निवेशों की हस्तांतरणीयता

4.70 पैरा में यथा निर्धारित निर्यात दायित्व की पूर्ति और दस्तावेजों की प्रस्तुति प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.68 में विनिर्दिष्ट के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रमाणपत्र को हस्तांतरणीय बनाएगा बशर्ते कि इस स्कीम हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो।

तथापि, प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकित प्रतिबंधित मद को विदेश व्यापार नीति और उसमें निर्धारित व्यापार नीति प्रक्रिया के अनुसार केवल अलग से जारी आयात लाइसेंस/अनुज्ञापत्र के मद्दे अनुमत होगी।

रत्न और आभूषण

4क. रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र और स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम जेवरार के लिए स्कीम निर्यात एवं आयात नीति के अध्याय-4 के पैरा 4क में दी गई है।

प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

4क.1 प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन पत्र, निर्धारित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-1 क में उल्लिखित "आयात निर्यात फार्म" के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास जमा किया जाए।

4क.1.1 आवेदन पत्र उस माह से छः माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस माह/तिमाही के दौरान निर्यात आय प्राप्त की गई है। माह/तिमाही के दौरान निर्यात से प्राप्त आय के लिए पूरे महीने/तिमाही के लिए समेकित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

तथापि, यदि कोई पूरा आवेदन करना होगा तो, यह 10 प्रतिशत हकदारी कम करके स्वीकार किया जाएगा। तीसरे पक्ष के मामले में, प्रतिपूर्ति लाभ ग्राह्य होंगे बशर्ते कि जहाजरानी बिल की ई पी प्रति में विनिर्माता और तीसरे पक्ष दोनों का नाम दिया गया हो और ऐसे निर्यात के लिए दूसरे पक्ष द्वारा दावा न करने का पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी एक पक्ष द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस को प्रस्तुत किया गया हो। प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र हस्तांतरणीय होगा।

4क.1.2 जिन मामलों में बीजक के प्रति आंशिक भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान आंशिक भुगतान प्राप्त किया गया था उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए बशर्ते कि,

(क) ऐसी प्रत्येक ऐसे बीजक के लिए दो से अधिक ऐसे आवेदन प्रस्तुत न किए गए हों, और

(ख) बीजक की प्राप्ति के 50% वसूल करने के बाद ही ऐसे प्रथम आवेदन पत्र को जमा किया जाएगा।

4क.1.3 जिन मामलों में भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त हो गया है और निर्यात बाद में किया जाता है तो प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान निर्यात किया गया है, उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4क.1.4 स्पष्टता के प्रयोजन के लिए, यह पुनः दोहराया गया है कि अग्रिम भुगतान मामले में, जिस माह निर्यात किया गया है और निर्यात करने के बाद जिस माह निर्यात आय आंशिक रूप से या पूरी तरह प्राप्त की जाती है उस माह को प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र दाखिल करने के प्रयोजन के लिए छः माह की अवधि को गिना नहीं जाएगा।

छीजन मानदंड

4क.2 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए छीजन या विनिर्माण हानि नीचे दी गई है :—

निर्यात की मद	निर्यात मद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के अंश के संबंध में भार के रूप में छीजन का प्रतिशत	स्वर्ण/प्लेटिनम	चांदी
क. सादा आभूषण और वस्तुएँ और आभूषण जैसे मंगल सूत्र जिसमें स्वर्ण और ब्लैक मोती/कृत्रिम स्टोन्स, क्यूबिक जिरालोनिया	3.5 प्रतिशत	4.5 %	
ख. जड़ित आभूषण और उसकी वस्तुएँ	9.0 प्रतिशत	10 %	
ग. स्वदेशी रूप से (गैर-मशीनी कृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित) मार्कटिंग और फाइंडिंग	3.5 प्रतिशत	4.5 %	
घ. पूर्णतः मशीनी प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित और अजड़ित कोई भी आभूषण/वस्तुएँ	1.25 प्रतिशत	1.25 %	
ङ. जड़ित जेवरों में प्रयुक्त मार्कटिंग या तो आयातित हो या स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए/विनिर्मित हों	2.5 प्रतिशत	2.5 %	
च. स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम मैडलायन्स (कानूनी प्रकृति के सिक्कों को छोड़कर)	0.25 प्रतिशत	0.25 %	
छ. मशीनी तकनीक तरीके द्वारा तैयार किए गए फाइंडिंग व	1.25 प्रतिशत	1.25 %	

मूल्य संवर्धन

4क.2.1 आभूषण निर्यात स्कीम के तहत मूल्य संवर्धन का परिकल्पित विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.6 के अनुसार किया जाएगा।

क्र.सं. निर्यात मद	न्यूनतम मूल्य संवर्धन
क. सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी के आभूषण और मंगल सूत्र जिसमें स्वर्ण और ब्लैक बीड्स/इमटेशन स्टोन्स, कीमती पत्थर और अर्ध-कीमती पत्थर क्यूबिक जिरि-कोनिया हीरे, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर आदि लगे हों।	4.5 प्रतिशत
ख. सभी स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी के आभूषण और वस्तुएँ	15 प्रतिशत
ग. पूर्णतः मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई भी आभूषण/वस्तुएँ	3 प्रतिशत
घ. स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के मैडलायन्स और सिक्के (कानूनी निविदा के स्वरूप के सिक्कों को छोड़कर)	3 प्रतिशत
ङ. मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम फाइंडिंग/मार्कटिंग।	5 प्रतिशत

4क.2.2 निर्यात के प्रति स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की मात्रा की हकदारी में अनुमत छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की मात्रा होगी।

रत्न और आभूषण खो जाना

4क.3 देश के बाहर निर्यातित रत्न और आभूषण मदों के खेप, जो निर्यात के बाद रास्ते में खो गए हैं तथा ऐसे निर्यातों के मद जहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी हो अथवा बीमा दावा कर लिया गया हो, वे भी प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे।

रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

4क.4 रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र, अपरिष्कृत हीरों, बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध-बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक स्टोन और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा। इसके अलावा, यह प्राधिकार पत्र समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के मूल्य के भीतर 5% तक आभूषणों के खाली बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा। जड़ित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों/सामग्री के आयात के प्रति जारी रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र, समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालिश किए गए बहुमूल्य/अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होगा।

4क.4.1 रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकरण पत्र परिशिष्ट-12ख में दिए गए मापदण्ड पर उपलब्ध होगा।

आवेदन प्रस्तुत करना

4क.4.2 (1) रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को परिशिष्ट-1क में दिए गए प्रपत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित परिशिष्ट-22ख के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) यदि जहाजरानी बिल की ई पी प्रति और नामित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बीजक नामित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है तो निर्यातक इसकी स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा और इसके साथ नामित अधिकरण से यह प्रमाण पत्र भी होगा जिसमें उद्धृत आभूषणों के मामले में स्टडिंग के कैरेट/मूल्य और सादे आभूषणों तथा वस्तुओं के मामले में प्राप्त किए गए अधिक मूल्य परिवर्धन को प्रमाणित किया गया हो।

(3) रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकरण पत्र के लिए पैरा 4क.1.1 से 4क.1.4 के प्रावधान भी लागू होंगे।

अधिकरण कमीशन

4क.5 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण स्कीम का उपयोग करने वाले निर्यातक को अधिकरण कमीशन देने की अनुमति है। मूल्य परिवर्धन का परिकल्पन अधिकरण कमीशन को बटा कर किया जाएगा। जहाँ कोई ऐसा अधिकरण कमीशन दिया जाता है तो मूल्य परिवर्धन अधिकरण कमीशन प्रतिशत द्वारा पदनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

जहाजरानी बिल और बीजक पर पृष्ठांकन

4क.6 आभूषणों के निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का भार, इस पर दावा किए गए वेस्टेज, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का कुल भार, जमा दावा किए गए वेस्टेज तथा स्वर्ण/चाँदी के लिए 0.995/0.999 शुद्धता और प्लेटिनम के लिए 0.9999 शुद्धता में इसकी समकक्ष मात्रा तथा इसका मूल्य, निर्यात का एक ओ की मूल्य, प्राप्त मूल्य परिवर्धन के ब्यौरे होने चाहिए। निर्यात के लिए इन प्रत्येक धातुओं से निर्मित सभी का कुल मदों के संबंध में इस्तेमाल किए गए स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की शुद्धता यदि वही है तो निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कुल भार और ऐसी ही मदों, जिनकी शुद्धता वही है, के अन्य ब्यौरे भी देने होंगे। उद्धृत मदों के माबल्लों में, जहाजरानी बिल में विनिर्माण में इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य/अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों/हीरों/जोतियों का भार और मूल्य तथा स्वर्ण/चाँदी के मिश्रण में इस्तेमाल की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य के ब्यौरे भी होने चाहिए।

निर्यात की शर्तें

4क.7 सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि जहाजरानी बिल और बीजक में पृष्ठांकन ठीक किया गया हो तथा प्राप्त किया गया मूल्य परिवर्धन नीति में निर्धारित मूल्य संवर्धन से कम न हो।

निर्यात का सबूत

4क.8 निर्यातक को जहाँ कहीं अपेक्षित हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण देना होगा :—

- (क) जहाजरानी बिल की ई पी प्रति,
- (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बीजक, और
- (ग) परिशिष्ट 22क में दिए गए प्रपत्र में निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दस्तावेज लेन देन/संचयन के लिए भेजे गए हैं।

(घ) निम्नानुसार एक घोषणा :—

“मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि 180 दिनों के बाद की निर्यात आय विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों के औसत निर्यात के 10% से ज्यादा नहीं होगी। मैं/हम आगे घोषणा करता हूँ/करते हैं कि कोई भी निर्यात आय एक वर्ष या ऐसी बढी हुई अवधि जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की गई हो, से ज्यादा बकाया नहीं है।”

विदेशी क्रेता द्वारा आभूषणों की व्यक्तिगत सामान के मामले में निर्यात हकदारियों का दावा करने के लिए निर्यात के सबूत के तौर पर निर्यातक/विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—

- (क) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए शिपिंग बिल की प्रति
- (ख) विदेशी क्रेता के आगमन के समय सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत किए गए मुद्रा घोषणा प्रपत्र की एक प्रति; और
- (ग) बैंक से विदेशी मुद्रा नकदी प्रमाण पत्र।

इसके अतिरिक्त, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डी ए)/सुपुर्दगी पर नकद आधार पर व्यक्तिगत सामान की भी अनुमति है। निर्यात हकदारी का दावा करने हेतु निर्यातक को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे :—

- (i) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल की प्रति
- (ii) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण- पत्र

इस संबंध में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी निर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन किया जायेगा।

शुद्धता/परिशुद्धता का परिवर्तन

4क.9 परिशुद्धता के रूप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाया जाएगा:—

- (i) जहाँ स्वर्ण वस्तुओं का कैरेट में निर्यात किया गया है, वहाँ स्वर्ण अंश को 24 से भाग दिया जाएगा और इसके बाद 0.995/0.999/0.900 से गुणा किया जाएगा ताकि क्रमशः 0.995/0.999/0.900 परिशुद्धता के रूप में स्वर्ण की समकक्ष मात्रा तक पहुँचा जा सके, और
- (ii) जहाँ कहीं निर्यात की वस्तु की शुद्धता, परिशुद्धता के रूप में व्यक्त की गई है, वहाँ स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम मात्रा को 0.995/0.999/0.900 से भाग दिया जाएगा ताकि स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम क्रमशः 0.995/0.999/0.900 परिशुद्धता की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके, और

नामित अधिकरण द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की रिलीज

4क.10 नामित अधिकरणों/भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत बैंकों द्वारा आभूषणों के निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम केवल 10 ग्राम या स्वर्ण के संबंध में दस तोला छड़ों के गुणकों में रिलीज किया जाएगा। तथापि, निर्यातकों को चाँदी केवल 1 किग्रा गुणकों में रिलीज किया जाएगा। स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कोई भी शेष निर्यातक को उसकी भावी हकदारी सहित उपलब्ध रहेगा। नामित प्राधिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/0.995 परिशुद्धता में और प्लेटिनम 0.900 या इससे अधिक परिशुद्धता में रिलीज की जाएगी।

भुगतान की शर्तें

4क.11 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साख-पत्र, के आधार पर नकद भुगतान या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान के तहत होगी। सुपुर्दगी के आधार पर दी जाएगी (स्वीकृति के प्रति दस्तावेज)

निर्यात बन्दरगाह

4क.12 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, कोची, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एअरपोर्ट, गोवा और हैदराबाद स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी। प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद के स्थित सीमाशुल्क सदनों माध्यम से कूरियर द्वारा निर्यात भी अनुमत होगा।

डाक द्वारा निर्यात

4क.13 विदेशी डाक घर के जरिए रत्न और आभूषण निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.17 में दी गयी है। निर्यात के समय, निर्यातक की निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:—

- (i) विदेशी डाक घर में प्रस्तुत किया गया जहाजरानी बिल या बीजक।

- (ii) नामित अधिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था।

- (iii) बीजक की तीन प्रतियाँ।

4क.14 हटा दिया गया है।

विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के तहत निर्यात

4क.15 विदेशी क्रेता द्वारा की गई आपूर्ति के प्रत्येक आयात परेषण की निकासी से पहले, नामित अधिकरण इस आशय के एक बॉण्ड का सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निष्पादन करेगा कि वह करार में निर्धारित अवधि के भीतर ग्राह्य वेस्टेज को छोड़कर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम मार्केटिंग और फाइंडिंग आदि के सम्पूर्ण आयात के बराबर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेगा।

सोना/चाँदी/प्लेटिनम, अयस्क, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और मार्केटिंग्स और सादा अर्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों की स्तर धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष पूर्ति के मामले में शुल्क प्राधिकरण आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, एलॉयस, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और मार्केटिंग्स और सादा अर्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगाने वाले सीमा शुल्क की बैंक गारंटी सीमाशुल्क के पास जमा करानी होगी।

सीमा शुल्क विभाग के पास निष्पादित बैंक गारंटी एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। स्तर-धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष आपूर्ति के संबंध में, निर्यात 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। निर्यात दायित्व को पूरा न करने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त न करने की स्थिति में सीमा शुल्क विभाग और ब्याज की वसूली कर सकता है जिसमें बैंक गारंटी को लागू भी सम्मिलित है। इसके अलावा आयातक सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है।

4क.15.1 नामित अधिकरण स्तर धारक/निर्यातक को उस मात्रा पर लगाने वाला सीमा शुल्क देना होगा जिसके बारे में यह साबित हो गया है कि निर्यात नहीं किया गया है।

4क.15.2 सीमाशुल्क प्राधिकारी के जरिए नामित अधिकरण स्तर धारक/निर्यातक द्वारा माल के निकासी करायी जाएगी। उन मामलों में भी जहाँ सहायक कम्पनियों द्वारा निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है नामित अधिकरण द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा माल निकासी करायी जाएगी। न कि सहायक द्वारा/एसे मामलों में, सहायक कम्पनी नामित अधिकरण को आगम पत्र और जहाजरानी बिल प्रस्तुत करने के लिए इसके एजेंट के रूप में प्राधिकृत करेगी।

4क.15.3 निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल में निम्नलिखित ब्यौरे भी होने चाहिए:—

- (i) सहायक/स्तर धारक/निर्यातक का नाम और पता।
- (ii) नामित एजेन्सी द्वारा स्वीकृति कि सम्बद्ध साझेदार द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे निर्यात किया गया है, नामित एजेन्सी के पास इसके पंजीकरण की तिथि स्तर धारक/निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में, इस संबंध में स्वघोषणापत्र दिया जाएगा।

- (iii) सीमाशुल्क सदन का नाम बिलके माध्यम से सोना/चाँदी/प्लेटिनम सादा अर्थ निर्मित सोना/सिल्वर/प्लेटिनम आभूषण का आयात किया गया है और आगम पत्र संख्या एवं तारीख तथा आयात की तारीख।

4क.15.4 प्रत्येक शिपिंग बिल निर्यात हेतु केवल उस सीमाशुल्क सदन के माध्यम से वैध होगा जहाँ संबंधित नामित अधिकरण स्तर धारक/निर्यातक का कार्यालय स्थित है। यह पोत रवाना हेतु 7 दिन की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस दिन नामित अधिकरण द्वारा पृष्ठांकन किया गया था। यदि निर्यात इस समयवधि में नहीं किया जाता है, तो निर्यातक एक नया पोतलदान बिल दाखिल करेगा।

4क.15.5 निर्यात के समय, निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

- (1) सीमाशुल्क सदन बिलके माध्यम से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम सादा अर्थ-निर्मित सोना/सिल्वर/प्लेटिनम आभूषण का तदनु रूप आयात हुआ है, के अतिरिक्त सीमाशुल्क सदन जहाँ निर्यात किया गया है, के पोतलदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियाँ सहित। अन्य मामलों में पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति;
- (2) बीजक की तीन प्रतियाँ;
- (3) विदेशी खरीददारों द्वारा भेजी गई मर्दों की मात्रा और मूल्य को इंगित करने वाला नामित एजेन्सी का प्रमाण पत्र।

4क.15.6 सीमाशुल्क प्राधिकरण पोतलदान बिल और सम्बद्ध बीजक की विधिवत सत्यापित दो प्रतियाँ वापिस लौटाएगा। एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नामित एजेन्सी स्तर धारक/निर्यातक के कार्यालय को भेजी जाएगी।

4क.15.7 निर्यात की तिथि से 15 दिन के भीतर उस नामित एजेन्सी को जिसने निर्यात किया है, निर्यातक, निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात् निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि की अनुमत मात्रा जारी करेगा।

4क.15.8 निर्यातक अग्रिम रूप से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। उन मर्दों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत जोड़कर उन पर लगने वाले सीमाशुल्क के बराबर राशि विदेशी खरीददार द्वारा बैंक गारन्टी की अदायगी की जाएगी। बैंक गारन्टी की राशि तभी वापिस की जाएगी। जब निर्यातक, नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत और निर्यात उत्पाद में मर्दों की अग्रिम आपूर्ति के उपयोग के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

4क.15.9 सीमाशुल्क कार्यालय से निष्पादित बॉन्ड/बैंक गारन्टी को छुड़ाने के उद्देश्य हेतु नामित अधिकरण स्तर धारक/निर्यातक विदेशी

खरीददार द्वारा प्रतिपूर्ति मर्दों की मात्रा और मूल्य, तदनु रूप आगम बिल संख्या और तिथि, तदनु रूप किए गए निर्यात संबंधी प्रत्येक शिपिंग बिल की संख्या को बताएगा।

खर्चों का रखरखाव-

4क.16 नामित अधिकरण प्रत्येक निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित सोना, चाँदी, मार्केटिंग्स, फाइंडिंग्स सादा अर्थ निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण इत्यादि किए गए निर्यात और ऐसे निर्यात के लिए जारी सोना/चाँदी, मार्केटिंग्स, फाइंडिंग्स इत्यादि का प्रेषण वार पूर्ण लेखा जोखा रखेगा तथा सीधे निर्यातों के मामले में ऐसा लेखा-जोखा स्वरूपक द्वारा रखा जाएगा। इस लेखा जोखा का रख-रखाव निर्यात की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

प्रदर्शनियों/निर्यात संवर्धन दौरो/ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात जरिए निर्यात

4क.17 नामित अधिकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शनी लगाने ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट सरकारी अनुमोदन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। अन्य कोई व्यक्ति सहायक, सीमाशुल्क के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शनी लगाने निर्यात संवर्धन दौरे/ब्राण्डेड आभूषण के विनिर्दिष्ट जी जे ई पी सी के निर्यात उन्नयन की प्रमाणित प्रति प्रेषित करेगा।

पुनः आयात के मामले में, ऐसी मर्दों के पहुँचने पर निकासी से पहले निर्यात दस्तावेजों के साथ जाँच की जाएगी।

4क.18 (क) इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्यात के तरीके के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

- (i) विदेशी प्रदर्शनी में आयोजित/भाग लेने के लिए रत्नों और आभूषणों का निर्यात।

इस योजना के तहत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होंगे :

विदेशों में न बेची गई मर्दें प्रदर्शनी के बन्द होने के 60 दिनों के भीतर पुनः आयातित की जाएगी। तथापि यदि निर्यातक पहली प्रदर्शनी के बन्द होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है तो दूसरी प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 60 दिन गिने जाएंगे। विदेश प्रदर्शनी में आयोजन/भाग लेने के लिए रत्न और आभूषण के व्यक्तिगत सामान के मामले में, ऐसे रत्न और आभूषण का मूल्य 2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी। ऐसी प्रदर्शनियों में बेची गई मर्दों पर सोना/चाँदी/प्लेटिनम अंश प्रतिपूर्ति के रूप में आयातित किए

जा सकते हैं। निर्यातक को प्रदर्शनी में विदेश में बेचे गए माल के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए सोना/चाँदी/प्लेटिनम के बन्द होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी से प्रतिपूर्ति ले सकता है।

(ii) निर्यात संवर्धन दौरे के लिए रत्न और आभूषणों का व्यक्तिगत सामान।

सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कट पॉलिशड डायमण्ड, कीमती अर्ध-कीमती पत्थर, मोती और नमूनों के रूप में वस्तुएँ 100,000 अमरीकी डालर तक निर्यात प्रमोशन टूर और अस्थायी डिस्पले/विदेश में बिक्री के लिए भी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन के साथ अनुमति है बशर्ते कि प्रमोटर सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर आभूषण/सामान या बिक्री से प्राप्त आय को वापिस लाएगा। निर्यात संवर्धन दौरे के लिए पर्सनल कैरिज के मामले में, निर्यातक देश को छोड़ते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को ऐसे नमूनों की पर्सनल कैरिज घोषित करेगा और सीमाशुल्क के आभूषण मूल्यांकन कर्ता द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में निर्यातक निर्यात प्रमोशन दौरे के बाद 120 दिनों के भीतर या 45 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, सोना, चाँदी, प्लेटिनम विदेश में बेची गई मर्चों के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए नामित एजेंसी के साथ बुक करेगा।

(iii) ब्रॉन्डेड आभूषणों का निर्यात

ब्रॉन्डेड आभूषण का निर्यात भी विदेशों में स्थापित अनुमत दुकानों या उनके वितरकों/एजेंटों के शोरूम में डिस्पले/बिक्री के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन से अनुमत है। 180 दिनों के भीतर विदेश में न बेची गई मर्चें 45 दिनों के भीतर पुनः आयातित की जाएंगी। विदेशों में बेची गई मर्चों के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के उद्देश्य हेतु स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम को 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी को बुक करेगा।

(ख) ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

(1) सीमाशुल्क सत्यापित बीजक।

(2) सरकार/जी जे ई पी सी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की प्राप्ति।

(3) परिशिष्ट-22च में दिए गए प्रपत्र नामित अभिकरण जी जे ई पी सी से प्रमाणपत्र।

(ग) नामित अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति के रूप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का आयात किया जाएगा।

4क.19 नामित अभिकरण किए गए निर्यात, विदेश में बेची गई वस्तुओं, वस्तुओं को पुनः आयात और विदेश में खरीदी गई और भारत में आयातित धातुओं का पूरा लेखा-जोखा रखेगा। ऐसा लेखा-जोखा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात

4क.20 इस स्कीम के तहत निर्यातक निम्नलिखित आधार पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है :—

(1) निर्यात पूरा करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति के आधार पर,

(2) अग्रिम रूप से तत्काल खरीद आधार पर,

(3) ऋण आधार पर

प्रतिपूर्ति आधार

4क.21 निर्यातक बहुमूल्य धातु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की बुकिंग के लिए नामित अभिकरण को आवेदन कर सकता है। नामित अभिकरण के पास बुक बहुमूल्य धातु की मात्रा निर्यात उत्पाद में बहुमूल्य धातु के अंश और स्वीकार्य वेस्टेज के बराबर होनी चाहिए।

4क.21.1 आवेदक बुकिंग के समय बहुमूल्य धातु के अनुमानित मूल्य का कम से कम 20% वयाना राशि जमा करेगा जिसे वास्तविक बिक्री के समय समायोजित कर लिया जाएगा।

4क.21.2 निर्यात बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के आधार पर जेबरात नोशनल दर पर निर्यात करेंगे। निर्यातक क्रेता के क्रेडिट शर्तों के अन्दर मूल्य निर्धारित करेगा तथा उसकी आय नियत समय अथवा 180 दिन जो भी पहले हो प्राप्त करे। निर्यातक जो प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुमान आधार पर निर्यात कर रहे हैं वो उसी दर पर तथा मात्रा के नामित एजेंसी से सोना बुक कर सकते हैं जा उन्होंने क्रेता के साथ बुक किया है। नामित अभिकरण बहुमूल्य धातु खरीदेंगे और इसके पश्चात् क्रम संख्या वाला एक खरीद प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य डालर में निर्दिष्ट होगा, साथ ही रुपये में मूल्य भी दर्शाया जाएगा। मूल्य वह वास्तविक मूल्य होगा जिस पर नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम

खरीद गया है इसमें अनुमत सेवा प्रभार शामिल होगा। नामित अधिकरणों द्वारा लंगाया गया सेवा प्रभार मूल्य परिवर्धन के प्रयोजन के लिए स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के मूल्य में शामिल किया जाएगा। नामित एजेंसियों द्वारा निर्यातक हेतु क्रय प्रमाणपत्र की प्रतियाँ सहित निर्यातक के आवेदन की दूसरी और तीसरी प्रतियाँ संबंधित सीमाशुल्क संवर्धन को तथा नेगोशियेटिंग बैंक को भेजी जाएंगी। जो सोने के क्रय की पुष्टि करेंगे। निर्यातक जो अनुमानित दर पर निर्यात कर रहे हैं वे प्रतिपूरक तभी लेंगे जब आय प्राप्त हो जाएगी।

4क.21.3 बुकिंग की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा और बुकिंग की तारीख से 150 दिन के अवधि के भीतर या निर्यात की तारीख से 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, बहुमूल्य धातु को निकाला जाएगा।

अग्रिम रूप से तत्काल खरीद आधार पर

4क.22 निर्यातक तत्काल खरीद आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अधिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अधिकरणों को बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अधिकरण बैंक गारंटी को लागू करेंगे।

4क.22.1 बहुमूल्य धातु की तत्काल खरीद की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा।

ऋण आधार पर

4क.23 निर्यातक ऋण आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अधिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अधिकरणों को बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हो। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अधिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को लागू करेंगे।

4क.23.1 निर्यातक को ऋण के आधार पर लिए गए स्वर्ण पर यथानिर्दिष्ट दर व्याज देना होगा।

4क.23.2 सोने को ऋण आधार पर प्राप्त होने के अधिकतम 90 दिन के अन्दर निर्यात पूर्ण करना है। निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4क.23.3 निर्यातक को नामित अधिकरणों रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी जे ई पी सी) द्वारा जारी किए गए अनुमानित दर प्रमाण पत्र के आधार पर किए गए रत्न निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी। यह दरें मौजूदा स्वर्ण/अमेरिकी डालर तथा अमेरिकी/भारतीय रुपया अनुमानित प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। नामित एजेंसियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोत लदान के दिन से 7 कार्य दिवसों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

मूल्य संयोजन, खरीददार और नामित अधिकरणों के साथ निर्धारित किए गए मूल्यों के आधार पर होगा।

निर्यातक की तिथि से 180 दिनों के अन्दर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण की वापसी की मान्यता होगी। इस मूल्य

के बारे में नामजद अधिकरणों को सूचित किया जाएगा जो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों को दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि इस दर पर निर्यात आय को सुनिश्चित किया जाएगा।

4क.24 नामित एजेंसी निर्यातक के ई ई एफ सी खाते से बहुमूल्य धातु के आयात की लागत का डालर में भुगतान स्वीकार कर सकती है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात

4क.25 मूल्य संवर्धन निर्यात दायित्व अवधि और चूक के विनियमन को छोड़कर इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया इस स्कीम हेतु भी लागू होगी।

4क.25.1 निर्यात दायित्व को लाइसेंस के तहत पहले प्रेषण के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा तथापि निर्यात दायित्व अवधि फाइनिंग, स्वर्ण के बने हुए माउन्टिंग, प्लेटिनम और चाँदी और आभूषणों के निर्यात के आयात होने के 180 दिन के भीतर होगी। इसके पश्चात् निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। अग्रिम लाइसेंसधारक निर्यात पूरा होने के पश्चात् प्रतिपूर्ति के रूप में स्वर्ण का आयात कर सकता है।

4क.25.2 अग्रिम प्राधिकार पत्र सीधे आयात के बदले नामित अधिकरणों से स्वर्ण/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में, नामित अधिकरण प्राधिकार पत्र की विनियमन नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा।

हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र

4क.26 हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र हेतु नीति को विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.14 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

आवेदन पत्र

4क.26.1 इस स्कीम के प्रयोजन हेतु एक आवेदन प्रपत्र 'आयात निर्यात फार्म' के विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

निर्यात दायित्व

4क.26.2 प्रत्येक खेप के प्रति निर्यात दायित्व की, सीमाशुल्क के माध्यम से ऐसी खेप की निकासी की तारीख से 5 महीने की अवधि के भीतर पूर्ति करनी होगी, तथापि आयातक को किसी भी समय न तो प्रत्येक आयात खेप के रिकार्ड रखने की आवश्यकता और न ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रति तुलनात्मक आयात खेपों के साथ निर्यात खेपों का सह संबंध रखने की आवश्यकता होगी।

वास्तविक चूक का विनियमन

4क.27 निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में उन बहुमूल्य धातुओं को जिन्हें उसने नामित अधिकरणों से प्राप्त किया है, को नियमित करेगा बशर्ते निर्यातक ने सीमाशुल्क

प्राधिकारी को 15% ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान किया हो। तथापि अधिम लाइसेंस के मामले में इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4.28 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे। यह किसी भी ऐसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, तथा इसके अधीन जारी आदेश या नियमों के तहत निर्यातक के विरुद्ध की जा सकती है।

उपभोक्त्यों के आयात हेतु प्रतिपूर्ति लाइसेंस

4क.28 सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र जिसमें निर्यात निष्पादन दर्शाया हो के प्रस्तुत करने पर पिछले वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य का 2% का शुल्क मुक्त आपात के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। यह प्राधिकार पत्र अहस्तान्तरणीय तथा वास्तविक उपयोगकर्ता के मोह होगा। वह प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र शुल्क मुक्त उपभोक्त्यों की आयात के लिए होगा जैसा कि सीमा शुल्क ने अधिसूचित किया है।

यद्यपि उपभोक्त्यों के आयात अथवा प्लेन/जड़ित आभूषणों के आयात के लिए आवेदन पत्र 'आयात निर्यात प्रपत्र' में संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

रत्न और आभूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर से ले जाना

4क.29 सभी ई ओ यू/एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर और में स्थित डी टी ए यूनिटों से भी विदेशी क्रेताओं द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। पर्सनल कैरिज निर्यात की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी तथापि निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाएगा। विदेश जाने वाले यात्री द्वारा निर्यात के व्यक्तिगत लाने व ले जाने के मामले में प्रतिपूर्ति दावे के लिए दस्तावेज वही होंगे जो प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4क.21.2 में दिये गये हैं। प्राधिकृत कारियर कम्पनी भी इन लाइनों में काम कर सकते हैं।

हीरा और आभूषणों के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

4क.30 सभी ई ओर यू और एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर स्थित डी टी ए यूनिटों से भी भारतीय आयातक विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सल को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल की दुलाई प्रक्रिया के समान होगी लेकिन सीमाशुल्क की जाँच और सील करने के पार्सलों को आयातक/नागरिक विदेशी के देश छोड़ने के समय सौंपा जाएगा। इस स्वयं के अन्तर्गत आयातों की निकासी नीति पुस्तक के अध्याय 4 में दी गयी सामान्य लाइसेंसिंग पद्धति के अनुसार होगी।

नमूनों का शुल्क मुक्त आयात

4क.31 रत्न और आभूषण में के विगत तीन वर्ष के कारोबार के औसत के 0.25 प्रतिशत अथवा 03 लाख रुपए तक रत्न और आभूषण नमूनों के शुल्क मुक्त आयात, जो भी कम हो सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष में अनुमत होगा।

अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

4क.32 सादे/बहुमूल्य पत्थर जड़ित आभूषणों के निर्यातक को, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक, अस्वीकृत और खरीदार द्वारा लौटाए गए आभूषण के शुल्क मुक्त पुनः आयात की अनुमति होगी।

4क.32.1 सादे/बहुमूल्य पत्थर जड़ित आभूषण के पुनः आयात के इच्छुक निर्यातक को, पुनः आयात के 60 दिनों के भीतर, क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उसके पिछले वर्ष के निर्यात की, चार्टर्ड लेखाकर से सत्यापित प्रति जमा करनी होगी और उसी मात्रा (पुनः आयातित सोने और बहुमूल्य पत्थर जड़ने के मूल्य के बराबर) में सादे/जड़ित आभूषणों की मात्रा के बराबर उसके साथ पुनः निर्यात के बांड भी पुनः आयात के 60 दिन के अन्दर निष्पादित करेगा।

रत्न और आभूषण डालर लेखा

4क.33 रत्न और आभूषण डालर लेखा हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.19 में उल्लेख किया गया है। इसके संचालन की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय -5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

नीति

5.1 नीति के अध्याय 5 में निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम से संबंधित नीति, दी गई है।

आवेदन प्रपत्र

5.2 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजे जा सकते हैं।

आवेदनों पर विचार

5.3 आयात निर्यात प्रपत्र में संलग्न प्रपत्र में, निर्यात दायित्व के लिए प्रयुक्त उत्पादों के लिए, पूर्व उत्पादन, उत्पादन अथवा उत्पादन के बाद इसमें इस्तेमाल के लिए आयात हेतु पूंजीगत माल के अन्तिम प्रयोग को सत्यापित करते हुए स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से प्राप्त प्रमाणपत्र सहित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ईपीसीजी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है जहाँ, बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रुपये हो।

ऐसे मामलों के लिए जहाँ, बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रुपये से अधिक है, आवेदक, संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुख्यालय में सीधे आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, मुख्यालय की ईपीसीजी समिति/सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सिफारिश के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा तदनुसार ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया जाएगा।

5.3.1 सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट 32क में दिए गए स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर (सीईसी) के नेक्सस प्रमाणपत्र के

आधार पर ई पी सी जी लाइसेंस जारी करेगा तथा इसके बाद ई पी सी जी लाइसेंस की एक प्रति सम्बंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा।

5.3.2 प्राधिकार पत्र धारक संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आयात करने के 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि पूंजीगत माल प्राधिकार पत्र धारक या सहायक विनिर्माता/वैन्डर की फैक्टरी परिसर में स्थापित कर दी गयी है।

तथापि प्राधिकार पत्र धारक जो किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं है तथा सेवा प्रदायक संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी के या स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर के समक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि चल और अचल पूंजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक/सहायक विनिर्माता के परिसर में स्थापित कर दिया गया है।

5.3.3 आयातों के प्रयोजन के लिए प्रसिद्ध पुस्तक के पैरा 4.19 में निर्दिष्ट एक मात्र पंजीकरण फोट के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। सभी आयात इस एक-ही पतन से किए जाएंगे जब तक की सीमाशुल्क प्राधिकरण से विशेष अनुमति न ली गई हो। तथापि, पैराग्राफ 4.19 में निर्दिष्ट किसी पतन से निर्यात किया जा सकता है।

5.3.4 (1) ईपीसीजी स्कीम के तहत, आयातित/जिन्हें आयात करना है ऐसे पूंजीगत माल के रख-रखाव और अधिष्ठापन के लिए आवश्यक, रिफ्रेक्टरी, कैटालिस्ट और उपभोग्य सहित स्पेयरस के आयात के लिए भी आवेदक आवेदन कर सकता है।

आवेदन में चार्टर्ड इंजीनियर अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदक की फैक्टरी/प्रांगण में अधिष्ठापित प्लांट/मशीनरी की सूची, संलग्न होनी चाहिए, जिसमें स्पेयरस की आवश्यकता है।

ऐसे मामलों में, ईपीसीजी लाइसेंस स्पेयरस की सूची को विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दर्शाएगा :

- (क) प्लांट/मशीनरी का नाम, जिसके लिए स्पेयरस की आवश्यकता है।
- (ख) लाइसेंस के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य
- (ग) नीति के अनुसार निर्गत दायित्व के मूल्य सहित निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण

(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी स्पेयरस के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने के पश्चात् संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को प्राधिकार पत्र की एक प्रति भेजेगा।

(3) इसके अलावा निर्यात दायित्व को अग्रिम रूप से पूरा करते समय प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्राधिकार पत्र धारक द्वारा रखे गए स्टॉक और खपत रजिस्टर के आधार पर अधिष्ठापित पूंजीगत वस्तुओं में इस प्रकार आयोजित स्पेयरस का प्रयोग किया गया।

ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन ईओयू/एस ई जेड यूनिटें

5.4 एक ई.ओ.यू/एस.ई.जेड एकक, नीति के पैरा 6.18(घ) की शर्तों के अनुसार, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन "आयात-निर्यात प्रपत्र" में दिए गए प्रपत्र में, निर्धारित दस्तावेजों सहित, प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा, आवेदक विकास आयुक्त से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा जिसमें आवेदक द्वारा आयातित/आवेदक द्वारा स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए पूंजीगत माल का ब्यौरा, आयात प्राप्त करते समय उसका मूल्य और स्कीम के अधीन शुल्क मूल्यांकन के लिए मूल्यहास का विवरण होगा।

ऐसे मामलों को मुख्यालय की ई पी सी जी स्कीम समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, संबंधित विकास आयुक्त के "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" के आधार पर ई पी सी जी प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

पूंजीगत माल की स्वदेशी स्रोतों से प्राप्ति

5.5 स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल को प्राप्त करने के इच्छुक ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक, सीधे आयात के लिए ई पी सी जी लाइसेंस को अमान्य कराने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अनुरोध भेजेगा। ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक उस व्यक्ति का नाम और पता भी देगा जिससे वह पूंजीगत माल प्राप्त करना चाहता है।

5.5.1 ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर कि प्राधिकार पत्र जारी होने के समय या उसके पश्चात, लाइसेंसिंग प्राधिकारी सीधे आयात के प्राधिकार पत्र को अवैध करेगा और ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक को, दो प्रतियों में, एक अवैधीकरण पत्र जारी करेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी साथ-ही-साथ सीधे आयात के बदले में स्वदेशी रूप में पूंजीगत माल प्राप्त करने के लिए ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को अनुमति प्रदान करेगा।

5.5.2 ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति करने के इच्छुक स्वदेशी विनिर्माता, "आयात-निर्यात प्रपत्र" में दिए गए प्रपत्र में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए यथा अपेक्षित ऐसी निविष्टियों के आयात के लिए मान्य निर्यातों हेतु अग्रिम लाइसेंस को जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ता को लाभ

5.5.3 मान्य निर्यात के लाभ का दावा करने के प्रयोजन के लिए पूंजीगत माल का स्वदेशी आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

- (क) विनिर्मित पूंजीगत माल की आपूर्ति/अर्जन के प्रमाण के रूप में, फैक्टरी/प्रांगण पर क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित सहायक सीमाशुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों का प्रमाण पत्र और सेवा प्रदायक के मामले में, स्वतंत्र सनदी इंजीनियर पूंजीगत माल की आपूर्तियों/प्राप्तियों की पुष्टि करने से संबंधित प्रमाणपत्र देना होगा।

- (ख) परिशिष्ट - 22ख में उल्लिखित प्रपत्र में ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का प्रमाण।

पूँजीगत माल को पट्टे पर देना

5.6 ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक, पार्टियों के बीच पक्की संविदा के आधार पर, नीति के पैराग्राफ 2.25 के अनुसार पूँजीगत माल को घरेलू लीजिंग कम्पनी से प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में, आयातित पूँजीगत माल का प्रविष्टि बिल या स्वदेशी रूप से प्राप्त वाणिज्यिक बीजक, जैसी भी मामला हो, आयात/स्थानीय आपूर्ति के समय ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक और लीजिंग कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। तथापि, ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्तें

5.7 नीति के पैराग्राफ 5.4 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त स्कीम के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :—

5.7.1 ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक के नाम से निर्यात सीधा निर्यात होगा। तथापि, तीसरी पार्टी (पार्टियों) के माध्यम से निर्यात, जैसाकि नीति के अध्याय 9 में परिभाषित किया गया है, की भी अनुमति ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत होगी। यदि व्यापारी निर्यातक, आयातक हैं तो सहायक विनिर्माता का नाम जहाजरानी बिल में दर्शाया जाएगा। निर्यात के समय, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र सं. और तारीख जहाजरानी बिल पर पृष्ठांकित किया जाएगा जिसे निर्यात दायित्व के निष्पादन के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

5.7.2 पैराग्राफ 5.7.3 के तहत मान्य निर्यात के अलावा निर्यात आय, मुक्त रूप से मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी। तथापि, मुक्त विदेशी मुद्रा में अपरिवर्तनीय साख-पत्र के मुद्दे निर्यात के मामले में अथवा यदि विनिमय बिल बिना शर्त एवेलाइज्ड/संयुक्त रूप से स्वीकार्य बैंक द्वारा गारन्टी दी गई हो और इसकी निर्यातक बैंक द्वारा पुष्टि की गई हो तो निर्यात दायित्व को पूरा करने पर जोर नहीं दिया जाएगा।

5.7.3 भारत सरकार/निर्यात आयात बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के मुद्दे किए गए निर्यात तथा स्थगित भुगतान/आपूर्तिकर्ता लाइन ऑफ क्रेडिट ठेका जिसके लिए ई.पी.सी.जी. कवर उपलब्ध है के अन्तर्गत किए गए निर्यातों को इस स्कीम के तहत निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए गिना जाएगा।

5.7.3.1 तेल और गैस क्षेत्र को की गई आपूर्तियों को ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के मुद्दे निर्यात दायित्व को पूरा किया गया समझा जाएगा बशर्ते लाइसेंस 31-3-2000 को या उससे पहले जारी किया गया हो और ऐसी आपूर्तियों के लिए नीति के पैरा 8.3 के तहत कोई लाभ न लिया गया हो।

5.7.4 जहाँ निर्यात दायित्व का औसत स्तर पूर्व यूएसएसआर या सहानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य देश को किये गये निर्यातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया हो, ऐसे मामलों में निर्यात के औसत स्तर को ऐसे देशों को किये गये निर्यात से घटा दिया

जाएगा। ऐसा अधित्याग सभी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर लागू माना जाएगा, जो निष्क्रिय/नियमित न किये गये हों।

तथापि बाद में दिये जाने वाले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के उद्देश्य हेतु औसत निर्यात निष्पादन का परिकलन करने के लिए निष्क्रिय ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत किए गए निर्यात को नहीं जोड़ा जाएगा।

5.7.5 नीति के पैरा 5.7.3 में इस योजना के तहत दर्शाए वास्तविक या मान्य निर्यात के लिए जहाँ विनिर्माता निर्यातक ने उसी निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए ई.पी.सी.जी. और शुल्क मुक्त स्कीम या हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र के तहत लाइसेंस प्राप्त किए हैं या डीईपीबी/अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किया गया तो इन योजनाओं के अधीन किए गए निर्यात दायित्व के रूप में भी गिना जाएगा।

5.7.6 हस्तशिल्प, कुटीर, हथकरघा, लघु उद्योग, कृषि, जल कृषि, पशु-पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगुरोत्पादन, मुर्गीपालन, रेश्मोत्पाद और सेवाओं, से संबंधित वस्तुओं के निर्यात के मामले में, निर्यात दायित्व का निर्धारण इस नीति के पैराग्राफ 5.1 के अनुसार किया जाएगा किन्तु प्राधिकार पत्र धारक के लिए नीति के उपर्युक्त पैराग्राफ 5.4 (1) और 5.9 में यथानिर्धारित निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

इन क्षेत्रों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत औजारों को छोड़कर आयातित माल को निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद की आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे मामलों में भी जहाँ निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया है, हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तथापि पूँजीगत माल के हस्तांतरण की अनुमति समूह कम्पनियों या प्रबंधित होटलों के भीतर दी जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी और विनिर्माता/व्यापारी निर्यातकों के मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी और सेवा प्रदायकों के मामले में केवल क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दी जाएगी।

इसके अलावा, जिन मामलों में सेवा प्रदायक वस्तुओं का निर्यात करके निर्यात दायित्व को पूरा करना चाहते हैं तो उसे निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं के संबंध में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा के अर्जन के औसत स्तर को बनाए रखना होगा।

5.7.7 निर्यात दायित्व को नीति के पैरा 5.4 में दी गई शर्तों के अनुसार पूरा करना होगा।

निर्यात दायित्व की पूर्ति

5.8 ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन प्राधिकार पत्र धारक निम्नलिखित अनुपातों में निर्दिष्ट अवधि में निर्यात दायित्व पूरा करेगा :

प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से अवधि	न्यूनतम निर्यात दायित्व जिसे पूरा किया जाना है
प्रथम से षष्ठम वर्ष का ब्लाक	50%
सप्तम और अष्टम वर्ष का ब्लाक	50%

5.8.1 ऐसे प्राधिकार पत्र जिन पर बचाए गए शुल्क का मूल्य 100 करोड़ या इससे अधिक है, के संबंध में निर्यात दायित्व निम्नलिखित अनुपात में 12 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा :-

प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से अवधि	न्यूनतम निर्यात दायित्व जिसे पूरा किया जाना है
1 से 10 वर्ष का ब्लाक	50%
11 और 12 वर्ष का ब्लाक	50%

5.8.2 तथापि, विशिष्ट ब्लाक वर्ष के निर्यात दायित्व को, पूर्ववर्ती ब्लाक वर्ष में किए गए अधिक निर्यात द्वारा समंजित किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक निर्यात दायित्व को पूरा करने और डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन सुनिश्चित करके वार्षिक रूप से औसत निर्यात के बारे में क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा।

5.8.3 जहाँ वर्ष के विशेष ब्लॉक का निर्यात दायित्व, उपर्युक्त अनुपातों की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं हुआ है ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ वर्ष के विशेष ब्लॉक के लिए निर्धारित निर्यात दायित्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया गया हो तो ऐसे प्राधिकार पत्र धारक उक्त वर्ष/ब्लाक वर्ष की समाप्ति से 3 महीनों के भीतर उस सामान, जिसमें कुल निर्यात दायित्व का अपूर्ण निर्यात दायित्व के भाग के रूप में समान अनुपात शामिल है, पर देय शुल्क के अनुपात के समकक्ष राशि का सीमाशुल्क और प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत व्याज अदा करेगा।

5.8.4 तथापि, 31-3-2000 तक स्कीम के तहत जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर ई-99) के पैरा 6.11 में दी गई शर्तों द्वारा अधिशोधित किए जाएंगे। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर ई-99) के प्रावधानों के बावजूद मूल्यवार कमी के मामले में लाइसेंसधारक को विशेष आयात प्राधिकार पत्र वापिस नहीं करना होगा।

1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2002 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-01) के उपबन्धों द्वारा अधिशोधित किए जाएंगे।

1 अप्रैल, 2002 से 31 अगस्त, 2004 तक जारी प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-02) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशोधित किए जाएंगे। तथापि पुराने लाइसेंसों के मामले में भी क्लबिंग की शर्त इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.18 की मौजूदा शर्त के अनुसार होगी।

औसत को बनाये रखना

5.8.5 ईपीसीजी लाइसेंस के तहत औसत निर्यात की नीति के पैरा 5.4 (1) और 5.9 के उपबन्धों के अनुसार बनाये रखा जाएगा।

निर्यात दायित्व की निगरानी

5.9.1 प्राधिकार पत्र धारक, जारी किए गए प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व को पूरा करने में की गई प्रगति के बारे में तथा किए गए निर्यातों के वार्षिक औसत स्तर के बारे में क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट डीजीएफटी

की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जावेगी। क्षेत्रीय प्राधिकारी विशेष वर्ष में पूरे किए गए निर्यात दायित्व के लिए आंशिक निर्यात दायित्व पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10 प्रतिशत सी आई एफ मूल्य तक स्वचालित कमी/स्वचालित वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि

5.10 यदि स्कीम के तहत जारी प्राधिकार पत्र लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत के अधिक/कम मूल्य के आयात के लिए उपयोग किया गया है तो प्राधिकार पत्र को बचा-अनुपात आधार पर बढ़ा दिया जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी क्षेत्रीय प्राधिकारी के पुष्टीकरण के बिना ही प्राधिकार पत्र के 10 प्रतिशत अधिक में माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा।

ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक बाद में आयातों के अधिक लागत बीमा भाड़ा मूल्य/बचाई गई राशि को कवर करने के लिए अतिरिक्त आयातों के एक महीने के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अतिरिक्त फीस देगा, निर्यात दायित्व में यथानुपात वृद्धि हो जाएगी।

5.10.1 इसी प्रकार यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक ने लाइसेंस में दिए गए मूल्य से कम लाइसेंस का प्रयोग किया है तो उसका निर्यात दायित्व लाइसेंस के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ में यथानुपात आधार पर कम हो जाएगा।

निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार

5.11 संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, लाइसेंस के तहत लागू कुल निर्यात दायित्व के 10 प्रतिशत तक लागू निर्यात दायित्व में वृद्धि अथवा प्राधिकार पत्र के तहत बचाये गये कुल शुल्क के 2 प्रतिशत के संयोजन शुल्क को भुगतान करके निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की बंबूरी हेतु एक अथवा अधिक आवेदनों पर विचार कर सकता है। जैसा भी मामला हो वह माँगे गये विस्तार के प्रत्येक वर्ष हेतु निर्यातक की इच्छा पर आधारित होगा।

तथापि उपर उपलब्ध 2 वर्षों से अधिक की अवधि हेतु निर्यात दायित्व विस्तार पर 50 प्रतिशत तक बढ़ाने निर्यात दायित्व पर 2 वर्षों तक के विस्तार हेतु इस शर्त पर विचार किया जाएगा कि प्राधिकार पत्र धारक द्वारा आपूर्ति निर्यात दायित्व का 50 प्रतिशत शुल्क सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भुगतान करना होगा। यह ईपीसीजी प्राधिकार पत्र में विस्तार करने को पुष्टीकरण करने से पहले करना होगा ऐसे मामलों में संयोजन प्रशुल्क का भुगतान नहीं करना होगा या अतिरिक्त निर्यात दायित्व लगाया जाएगा। यदि फर्म अभी भी निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर सकी है तो पहले से जमा किए शुल्क को कुल शुल्क और निर्यात दायित्व में घूँक करने के लिए दिये जाने वाले ब्याज में से काट लिया जाएगा।

निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार उन शर्तों के तहत दिया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो। जहाँ निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाई गई है, प्राधिकार पत्र धारक को बढ़ाई अवधि के दौरान औसत दायित्व बनाए रखना होगा। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद का ही निर्यात निर्यात, दायित्व के लिए योग्य होगा।

5.11.1 बाइफर के साथ वास्तविक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पंजीकृत फर्म/कम्पनी अथवा समूह कम्पनी अथवा रुग्ण ईकाई के रूप में एसएसआई यूनिट के लिए राज्य पुनर्वास स्कीम अथवा यूनिट प्राप्त कोई फर्म/कम्पनी, जो कि बाइफर के अधीन है, महानिदेशक, विदेश व्यापार का निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार के लिए आवेदन कर सकती है।

फर्म/कम्पनी जो कि बाइफर/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर रही है, संबंधित एजेन्सी द्वारा आवेदन की रसीद के 30 दिनों के भीतर ईपीसीजी लाइसेंस के लिए छूट के संबंध में, यदि कोई हो, महानिदेशक, विदेश व्यापार को सूचित करेगी।

बाइफर/आप्रेटिंग एजेन्सी/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग से प्राप्त सूचना की प्राप्ति पर महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसी फर्म द्वारा प्राप्त किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर लगाए गए निर्यात दायित्व की पूर्ति में चूक के संबंध में संबंधित एजेन्सी से मामले पर विचार करेंगे।

महानिदेशक, विदेश व्यापार विस्तार की अनुमति के लिए ऐसे आवेदन पर 12 वर्ष तक निर्यात दायित्व की अवधि में अथवा आप्रेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार पुनर्वास पैकेज अथवा बाइफर बोर्ड/राज्य प्राधिकरण द्वारा गुणदोष के आधार पर विचार करेंगे।

निर्यात दायित्व में कमी

5.12 क्षेत्रीय प्राधिकारी, निर्यात दायित्व अवधि की वैधता के भीतर निर्यात दायित्व में 5 प्रतिशत तक की कमी को उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन माफ भी कर सकता है।

विमुक्ति

5.13 निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रूप में, प्राधिकार पत्र धारक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :

(क) वास्तविक निर्यात के लिए :

सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए प्रपत्र में, किए गए निर्यात का सन्निहित विवरण और बैंक द्वारा निर्यात और मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय मुद्रा में वसूली या सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित बैंकों के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए प्रपत्र में निर्यातों का विवरण।

तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ अपरिवर्तनीय साख पत्र अथवा विनियम बिल बैंक द्वारा बिना शर्तों के अवेलाइण्ड/को-एक्सेटेड/गारण्टी प्राप्त है और निर्यातक बैंक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, तो निर्यात आय की वसूली आवश्यक नहीं होगी।

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक ईपीसीजी के लाभ प्राप्त करने के लिए अपरिवर्तनीय साख-पत्र अथवा विनियम बिल की एक प्रति प्रस्तुत करेगा जो कि बैंक द्वारा बिना शर्तों के अवेलाइण्ड/को-एक्सेटेड/गारण्टी प्राप्त तथा जिसकी निर्यातक बैंक द्वारा पुष्टि की गई हो।

(ख) मान्य निर्यात के लिए :

(1) मध्यवर्ती आपूर्तियों के लिए अग्रिम रिलीज आदेश/बैंक-टू-बैंक अन्तर्देशीय साखपत्र या अग्रिम प्राधिकार पत्र आपूर्ति प्राप्त हो गई हैं को दर्शाने वाला संबंधित ई.ओ.यू. कार्यालय के बंध पत्र द्वारा विधिवत् प्रमाणित आपूर्ति बीजक या एआरई-3,

(2) प्राधिकार पत्र धारक, सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान की प्राप्ति का प्रमाण या परिशष्ट-22ख में दिए गए प्रपत्र अथवा परिशष्ट-22ग में दिए गए प्रपत्र में संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाणपत्र की स्वतः प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ अपरिवर्तनीय साख पत्र अथवा विनियम बिल बैंक द्वारा बिना शर्तों के अवेलाइण्ड/को-एक्सेटेड/गारण्टी प्राप्त है और निर्यातक बैंक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, तो निर्यात आय की वसूली आवश्यक नहीं होगी।

(ग) की गई सेवाओं के लिए :

'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखापाल तथा बैंक/प्राधिकृत डीलर द्वारा विधिवत् प्रमाणित की गई सेवाओं का समेकित विवरण अथवा व्यक्तिगत विवरण (बैंक/प्राधिकृत डीलर वार) जिसमें सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा का प्रमाण दिया गया है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व के निष्पादन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों जिनके साथ बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित की है, को भेजेगा।

वास्तविक चूक का विनियमन

5.14 यदि ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारी निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह पैरा 5.8.3 के अनुसार सीमाशुल्क प्राधिकारी को सीमाशुल्क तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा। 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान की यह सुविधा इसे जारी करने की तारीख के बावजूद ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के विनयमीकरण के सभी लम्बित मामलों के लिए उपलब्ध होगी।

लेखों का रख-रखाव

5.15 प्रत्येक ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक विमुक्ति की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए निर्यात/ की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं का सही और उचित लेखा रखेगा।

ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का पुनः निर्यात

5.16 ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जो खराब अथवा अप्रयुक्त पाया गया हो अपने आयात के शुल्क के भुगतान की तारीख से 3 वर्षों के भीतर विदेशी सप्लायर को पुनः निर्यात कर दिया जाए जिसकी अनुमति लाइसेंसिंग/सीमाशुल्क प्राधिकारी से ली जाए।

तथापि, ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक एकान्तर उत्पादों/सेवाओं के निर्यात से प्राधिकार पत्र के अधीन शेष निर्यात दायित्व पूरा करेगा अथवा प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र के अधीन न पूरे न किए गए निर्यात दायित्व से बचाए गए शुल्क की अनुपातिक राशि के बराबर शुल्क अदा करेगा।

पूँजीगत माल की प्रतिस्थापन

5.16.1 स्कीम के तहत आयातित और खराब पाया गया अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त पूँजीगत माल को निर्यात किया जाएगा तथा इस स्कीम के तहत उसके बदले में आयात किया जाएगा। ऐसे मामलों में, निर्यात की अनुमति देते समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को ऐसे स्थापित पूँजीगत माल के आयात के समय घटा दिया जाएगा।

दण्डात्मक कार्यवाही

5.17 निर्यात दायित्व या प्राधिकार पत्र की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, लाइसेंस धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं नीति तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाई की जा सकती है।

ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग

5.18 उसी प्राधिकार पत्र धारक के दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की क्लबिंग इसमें दिये उपबन्धों के अनुसार होगी। इस पैरा के उप पैरा में उल्लिखित समाप्ति की अवधि ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात दायित्व अवधि के सन्दर्भ से होगी।

5.18.1 आयातों और निर्यातों का उत्तरादायित्व क्लब किए जाने वाले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र में उल्लिखित मर्दों को प्रतिबन्धित होगा।

5.18.2 क्लबिंग के लिए आवेदन में केवल क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के मामले में क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी केवल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर क्लबिंग के आवेदन पर विचार करेगा :

- (क) ई पी सी जी प्राधिकार पत्र उसी लाइसेंसिंग वर्ष के लिए जारी किया गया है।
- (ख) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र उसी सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं।
- (ग) ई पी सी जी प्राधिकार पत्र उसी उत्पाद (उत्पादों) या उसी सेवाओं के निर्यात के लिए है।

5.18.3 इस तरह क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए कुल निर्यात दायित्व बचाए गए कुल शुल्क अथवा आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य, क्लब किए गए प्राधिकार पत्र का जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए, पुनः नियत किया जाएगा।

क्लब किए गए प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि क्लब किए गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/क्लब किए गए शुल्क पर बचाई गई राशि, जैसा भी मामला हो, के लिए लागू नीति के अनुसार होगी। दो

प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि में किसी विसंगति के मामले में, क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी।

5.18.4 क्लबिंग पर, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र उक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत जारी एकल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र माना जाएगा और क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए निर्यात दायित्व अवधि पहले प्राधिकार पत्र को जारी करने की तारीख से मानी जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ क्लब किए गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/बचाया गया शुल्क मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक हो, निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि में लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

5.18.5 क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए बनाए रखे जाने वाले औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा।

5.18.6 समाप्त हो गए प्राधिकार पत्र के मामले में क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए कोई विशेष (पैरा 5.11 के तहत सामान्य विस्तारण के अन्तर्गत) निर्यात दायित्व विस्तारण दिया गया हो, तो इस लाइसेंस पर क्लबिंग के लिए विचार विमर्श नहीं किया जाएगा।

निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण

5.19(क) ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक नीति के पैरा 5.4

(1) में दिए गए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए प्रपत्र में निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है।

(ख) हटा दिया गया है।

(ग) अन्य सभी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए प्राधिकार पत्र धारक आवेदन किए गए ब्लाक के अन्त में अनिवार्य (वास्तविक अथवा संशोधित जैसा भी मामला हो) ब्लाकवार निर्यात दायित्व को पूरा करे। यह सुविधा बढ़ाई गई निर्यात दायित्व अवधि में दिए गए आवेदनों को दी जाती है। तथापि ऐसे मामलों में, बढ़ाई गई निर्यात दायित्व अवधि निर्यात दायित्व पुनः निर्धारण के प्रयोजन के लिए पिछले ब्लाक के अनुसार मानी जाएगी। ऐसे सभी मामलों में, पुनः निर्धारित निर्यात दायित्व का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :

(पूरा न किया गया प्रतिशत निर्यात दायित्व) × (8) × (प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से बचाया गया शुल्क)

(घ) ऐसे मामलों में, जहाँ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की शेष वास्तविक निर्यात दायित्व अवधि (और बढ़ाई गई निर्यात दायित्व अवधि नहीं) पुनः निर्धारण के लिए आवेदन की तारीख को 2 वर्ष से कम है, और अनिवार्य (मूल अथवा संशोधित, जैसा भी मामला हो) ब्लाकवार निर्यात दायित्व पूरा कर लिया है, वहाँ निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख को बचाए गए शुल्क के दुगुणे पर पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(ङ) निर्धारित किए गए औसत निर्यात दायित्व और वास्तविक प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में परिवर्तन नहीं होगा।

(च) 'आयात-निर्यात प्रपत्र' के तहत भी आवेदन किए जा सकते हैं यदि प्राधिकार पत्र धारक ने उसकी औसत प्राप्त कर ली है और नीति के पैरा 5.4 (1) की शर्तों के अनुसार उत्पादों/सेवाओं में परिवर्तन पर ईपीसीजी निर्यात दायित्व को पुनः निर्धारित किया गया है।

पूँजीगत माल का तकनीकी उन्नयन

5.20 ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक नीति की पैरा 5.10 के उपबन्धों के अनुसार ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूँजीगत माल के तकनीकी उन्नयन का विकल्प चुन सकते हैं।

यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित मौजूदा पूँजीगत माल का उन्नयन करना चाहता है, तो वह निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तकनीकी उन्नयन का विकल्प चुन सकता है :

- (1) आयात किया जाने वाला पूँजीगत माल नया और पहले के पूँजीगत माल से तकनीकी रूप से बढ़िया होना चाहिए। यह उसी उत्पाद के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया गया हो, जिसके लिए वास्तविक ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया गया था।
- (2) नए पूँजीगत माल के लिए निर्यात दायित्व पूँजीगत माल और पुराने पूँजीगत माल के तहत पहले ही किए गए निर्यातों दोनों पर बचाए गए शुल्क की छः गुणा कुल राशि का अन्तर होगा।
- (3) निर्यात-दायित्व अवधि नए प्राधिकार पत्र को जारी करने की तारीख से 8 वर्ष होगी।
- (4) ब्लॉक वार निर्यात दायित्व पूर्ति इस प्रक्रिया के पैरा 5.8 के अनुसार होगी।
- (5) उन्नत पूँजीगत माल के लिए औसत निर्यात दायित्व पुनः स्थापित किए जाने वाले पूँजीगत माल के बराबर होगा।

पूँजीगत माल के तकनीकी उन्नयन के लिए आवेदन "आयात-निर्यात प्रपत्र" में किया जाएगा।

रिफरबिशड/रिकंडीशंड पुर्जों और औजार का तकनीकी उन्नयन

5.21 नीति के पैरा 5.1 और 5.1क में उल्लिखित रिफरबिशड पुर्जों का आयात ईपीसीजी योजना के तहत अनुमत किया जाएगा।

तथापि, इस प्रकार रिफरबिशड/रिकंडीशंड पुर्जों की शेष अवधि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा प्रमाणित मूल पुर्जों की कम से कम कालावधि, कम से कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

ईपीसीजी योजना के तहत आयातित औजार आवेदक की समूह कंपनियों या किसी भी एक्क को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

5.22 ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्रों के पुनर्विधोकरण की अनुमति नहीं होगी।

अध्याय-6

निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) स्कीम और बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बी टी पी)

स्कीम

6.1 निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी) और साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) व जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 6 में दी गयी है।

परिभाषाएँ

6.2 निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू) और इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) और बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बी टी पी) के उद्देश्य हेतु जब तक सन्दर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, शब्द और अभिव्यक्तियों का नीति में यथा उल्लिखित निम्नलिखित तात्पर्य समझा जाएगा।

अनुमोदन/आवेदन और आवेदन का नवीनीकरण

6.3.1 ई ओ यू स्थापित करने हेतु परिशिष्ट-14-1क में दिए प्रपत्र में आवेदन की तीन प्रतियाँ विकास आयुक्त को देनी होंगी।

6.3.2 सेवा क्षेत्रों में (आर एंड डी, साफ्टवेयर और आई टी सेवाएं, या बी ओ ए द्वारा सौंपी गयी कोई अन्य सेवा कार्यकलाप में यूनिट की स्थापना हेतु प्रस्तावों के अलावा) ई ओ यू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना हेतु आवेदन परिशिष्ट-14-1ग में दिए अनुमोदन संबंधित क्षेत्र विशिष्ट शर्तों तथा परिशिष्ट 14-1ख में उल्लिखित मापदण्डों के अनुसार 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा रद्द किया जाएगा। अन्य मामलों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निकासी के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

6.3.3 औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ई ओ यू स्थापित करने वाले प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड (परिशिष्ट-14-1घ के अनुसार) और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा गुण दोष के आधार पर 45 दिनों के भीतर प्रस्ताव की निकासी के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

6.3.4.1 साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी)/इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई एच टी पी) काम्प्लेक्सों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उद्यमों अथवा उनके किसी संयोजन के द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अन्तर मंत्रालय स्थायी समिति (आईएमएससी) द्वारा बाकायदा अनुमोदित होगा। ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट स्थापित करने हेतु आवेदन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.3.4.2 बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी) यूनिट केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र ढांचों अथवा इनके किसी भी संयोजन द्वारा स्थापित किया जाएगा। बीटीपी स्थापित करने हेतु आवेदन जैव टेक्नोलॉजी विभाग को देना होगा और ऐसे आवेदन जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों पर पूरा उतरता हो जिसे डीसीएफटी को अधिसूचना हेतु सिफारिश और अनुमोदित किया जायेगा। बीटीपी यूनिट को स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.3.6 एल ओ पी/एल ओ आई में विनिर्माण मंद्/सेवा गतिविधियों वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए अपेक्षित वार्षिक निर्यात, शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन, तैयार माल उप-उत्पाद और डीटीए में बेकार माल की बिक्री, यदि कोई हो तथा ऐसे कोई अन्य मामले जो आवश्यक हों तथा ऐसी शर्तें भी लगा सकते हैं जो अपेक्षित हैं का उल्लेख होगा।

6.3.7 संबंधित प्राधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई सभी उद्देश्यों हेतु प्राधिकार पत्र माने जाएंगे। ई ओ यू यूनिटों हेतु एल ओ पी का मानक प्रपत्र परिशिष्ट 14-1ड में दिया गया है।

6.3.8 ई ओ यू का अलग एल ओ पी हेतु अलग निर्धारित परिसर होंगे। ई ओ यू लीजड परिसरों पर अनुमोदित की जा सकती है बशर्ते कि लीज सरकारी विभाग/उपक्रम/एजेंसी से प्राप्त की गयी हो। तथापि, यदि लीज निजी पक्षों से प्राप्त की गयी हो तो इसकी वैधता एल यू टी की तारीख से 5 वर्षों की अवधि हेतु होगी तथा विकास आयुक्त लीज की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

6.3.9 नीति के पैरा 6.6 में उल्लिखित अनुमोदित अवधि के पूरा होने पर, स्कीम में बने रहने अथवा उससे बाहर चले जाने का विकल्प यूनिट को होगा। यदि अनुमोदित अवधि की समाप्ति के छह महीनों की अवधि के भीतर यूनिट से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती तो विकास आयुक्त ई ओ यू स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदन को स्वयं रद्द करने की कार्यवाही करेगा और इस संबंध में आगे की कार्यवाही करेगा। जहाँ यूनिट स्कीम के तहत बने रहना चाहती है, विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को आगे बढ़ा देगा।

विधिक वचनबद्धता

6.4.1 अनुमोदित ई ओ यू/ईएचटीपी/एस टी पी/बीटीपी यूनिट परिशिष्ट-14.1 च में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी।

6.4.2 सभी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी का स्थायी ई. मेल पता होना चाहिए। यूनिट का स्थायी ई. मेल पता तथा डिजिटल हस्ताक्षर करने की स्थिति में यूनिटों को एल्यूटी नहीं दिया जाएगा। ईओयू का स्थायी ई. मेल पता तथा डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में आगे आयात और डीटीए बिक्री की विकास आयुक्त द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

माल और सेवाओं का निर्यात

6.5.1 सॉफ्टवेयर यूनिट, प्रोफेशनल सेवाओं के सहित निर्यात समेत डाटासंचार लिंकों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक निर्यात (जो कूरियर सेवा के माध्यम से भी) कर सकती हैं।

6.5.2 ईओयू नामित एजेंसी के द्वारा जारी नेशनल रेट सर्टीफिकेट के आधार पर आभूषणों का निर्यात करने हेतु अनुमत होगी। यह रेट नेशनल रेट सर्टीफिकेट में प्रचलित स्वर्ण/अमेरिकी डालर/भारतीय रुपया दर पर आधारित होगा। नामित एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोत लदान की तारीख के 3 कार्य दिवसों से पुराना नहीं होना चाहिए।

6.5.3 निर्यातक को निर्यात करने की तारीख से 180 दिन के भीतर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करने और स्वर्ण खण चुकाने की छूट होगी। नामित एजेंसियों को मूल्य की सूचनाएं दी जाएंगी, जो प्रमाणपत्र जारी करेंगी जिसमें निर्यात व्याप इस दर पर प्राप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज तैयार करने वाले बैंक की दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाता हो।

6.5.4 रत्न और आभूषण ईओयू आयातित माल का पुनः निर्यात और घरेलू खरीद माल का निर्यात कर सकती हैं इनमें आंशिक संसाधन/विनिर्माण से पैदा हुई वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके यथा लागू वैध रत्न प्रतिपूर्ति के प्रति डीटीए में आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे माल के मूल्य के 5% तक उपयुक्त/टूटे कटे और पालिशड हीरों, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों की आपूर्ति भी अनुमत होगी।

आयात/वस्तुओं की घरेलू खरीद

6.6.1 घरेलू टेरिफ क्षेत्र से पूंजीगत माल के आयात/खरीद की अनुमति निम्नलिखित के लिए होगी :—

- (क) कच्चा माल, संघटक, उपभोग्य, अन्तरवर्ती, कल-पूजें और पैकिंग सामग्रियाँ।
- (ख) पूंजीगत माल, चाहे नया या पुराना हो, जिसमें अब तक के परिवर्तनों सहित निम्नलिखित और उनके कल-पूजें :
 - (i) डी जी सैट्स, कैपटिव पावर प्लांट्स, ट्रांसफार्मर्स तथा सहायक उपकरण और उपयुक्त सभी के लिए अतिरिक्त पुर्जे।
 - (ii) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।
 - (iii) गुणवत्ता आश्वासन उपकरण।
 - (iv) सामग्री पकड़ने का उपकरण जैसे फोर्क लिफ्टर्स तथा ओवरहेड क्रेन्स/मोबाइल क्रेन्स, क्रालर क्रेन्स, हाईस्टस और स्टैकर।
 - (v) बिना व्यवधान बिजली आपूर्ति प्रणाली (यू पी एस) संचयन के लिए विशेष बैक्स, संचयन प्रणाली, मोइलर फर्नीचर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, एंटी स्टैरिक कारपेट, टेली कन्फ्रेंसिंग उपकरण, सर्वो कन्ट्रोल प्रणाली, एयर-कंडीशनर्स, विद्युत उपकरण के लिए पैनेल।

- (vi) सुरक्षा प्रणाली।
- (vii) टूलस, जिग्स, फिक्चर्स, गेजों, मोल्ड्स, डाइस, उपकरण तथा अनुषांगिक मर्दे।
- (ग) यूनिट के भीतर पूंजीगत माल बनाने के लिए कच्चा माल।
- (घ) अन्य जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (i) उत्पाद की विविधता विकास अथवा मूल्यांकन के लिए प्रोटोटाइप तथा तकनीकी नमूने।
 - (ii) ड्राइंग्स, वैल्यू प्रिन्टर्स, चार्ट्स, माइक्रो फिल्म और तकनीकी डाटा।
 - (iii) पी ए बी एक्स, फैक्स मशीनें, वीडियो प्रोजेक्शन प्रणाली, कम्प्यूटर्स लैप टॉप, सर्वर सहित कार्यालय उपकरण।
- (ङ) उक्त मर्दों के लिए कल-पुर्जे तथा उपभोग।
- (च) अनुमोदन बांड के अनुमोदन से अन्य कोई मर्द।

6.6.2. ईओयू/मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात हेतु सादा/ऑडिट स्वर्ण/प्लेटिनम अथवा चाँदी आभूषणों का आयात कर सकती है।

आयात की शर्तें

6.7. ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों द्वारा आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

- (क) माल का ईओयू/ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी परिसर में आयात किया जाएगा। तथापि, ईओयू में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के एकक सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारिक सहायक आयुक्त को पहले ही सूचित करके फार्मों/खदानों में पूंजीगत वस्तुओं और निविष्टियों की आपूर्ति/हस्तांतरण कर सकते हैं बशर्ते माल का स्वामित्व ईओयू एकक का हो। सेनार्डट सैक्टर को खदान स्थल को पूंजीगत माल के मूल्य के 5 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों को ले जाने की भी अनुमति होगी।
- (ख) ईओयू एककों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में एककों के लिए सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों के अधीन यथा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया अपनाई जायेगी और सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के पास उचित बॉण्ड प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ग) पूंजीगत वस्तुओं और कल-पुर्जों को छोड़कर वस्तुओं का ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा उपयोग सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा तीन वर्ष या बढ़ाई गई अवधि के भीतर नीति के अनुसार किया जायेगा। तथापि आयातित माल का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार मर्दों के आयात के मर्दे निर्यात दायित्व आई.टी.सी. (एच.एस.) निर्यात एवं आयात मर्दों के वर्गीकरण, 2004-2009 के अध्याय-9 में शामिल की प्रतिपूर्ति आयात की प्रथम खेप की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा तथा

आयात की प्रथम खेप की तिथि को सीमा शुल्क प्राधिकरण स्पष्ट करेगा।

- (घ) अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व आयातित/जहाज से भेजी गई/पहुँच चुकी वस्तुएँ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम के तहत शुल्क मुक्त निकासी हेतु पात्र होंगी बशर्ते सीमा-शुल्क का भुगतान न किया गया हो और वस्तुओं की सीमा शुल्क प्राधिकारी से निकासी न कराई गई हो।

अनुमोदित परिसरों के बाहर फैक्स मशीनों/लैपटाप कम्प्यूटर

6.8.1. ओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट पर एक फैक्स मशीन लगा सकते हैं बशर्ते कि इसके कार्य स्थल के बारे में गोमा शुल्क/उत्पाद शुल्क के संबंधित सहायक आयुक्त को सूचित किया जाएगा।

6.8.2. ओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट आयातित लैपटाप कम्प्यूटर और वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम को बांडेड कार्य स्थल से अस्थायी रूप से बाहर ले जा सकते हैं ताकि इन पर प्राधिकृत कर्मचारी कार्य कर सकें।

6.8.3. ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय में शुल्क मुक्त आयातित/प्राप्त निजी कम्प्यूटर, जो दो से ज्यादा न हो लगा सकते हैं बशर्ते कि वे इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो।

6.8.4. सॉफ्टवेयर यूनिटों द्वारा प्राधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सेवाएँ और व्यक्ति संचार लिंकों के माध्यम से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में स्थापित सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

पूँजीगत माल की लीजिंग

6.9. लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वित्तपोषित मुफ्त प्राप्त और/अथवा ऋण आधार पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य को भी नीति में यथा परिभाषित नेट विदेशी मुद्रा के परिकलन के उद्देश्य हेतु गिना जाएगा।

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई)

6.10.1. विशेष आर्थिक जोन स्कीम के अधीन ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें निवल विदेशी मुद्रा अर्जन होंगी। शुद्ध विदेशी मुद्रा की संगणना पांच वर्षों के बराबर हेतु निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जाएगी। केवल एलओपी/एलओआई में विनिर्दिष्ट निर्यात हेतु विनिर्माण की मर्दे निवल विदेशी मुद्रा की संगणना हेतु ध्यान में रखी जाएंगी।

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) = ए - बी > 0 जबकि

'ए' विशेष आर्थिक जोन ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है। और 'बी' सभी आयातित व निविष्टि का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, सभी आयातित माल का लागत

बीमा भाड़ा मूल्य और पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाह्य उधार पर व्याज के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतान का मूल्य या कोई अन्य प्रभार का समग्र योग है। निविष्टि का तात्पर्य कच्चे माल, अन्तरवर्ती, संघटक, उपभोग्य, कलपुर्जे और पैकिंग सामग्री से है।

6.10.2 यदि कोई निविष्टि अन्य एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट या भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से प्राप्त होती है तो ऐसी निविष्टि का मूल्य बी के अधीन शामिल किया जाएगा।

6.10.3 यदि किसी लीजिंग कम्पनी से मुफ्त आयातित किसी पंजीगत माल को लीज किया जाता है, मुफ्त और/अथवा ऋण आधार पर या हस्तांतरण आधार पर प्राप्त किया जाता है तो उसको प्रत्येक यूनिट के पास जिस शेष अवधि के लिए बी के अधीन यथानुपात जैसा भी मामला हो, शामिल किया अथवा नहीं किया जाएगा।

6.10.4 निवल विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना के लिए आयातित पंजीगत माल के मूल्य का भुगतान इस प्रकार किया जाएगा—

प्रथम—दस वर्ष—10 प्रतिशत

खातों का रखरखाव

6.11.1 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने खातों को नियमित रखें और परिशिष्ट-14 1—च में दर्शाएँ गए नियमों के अनुसार विकास आयुक्त/सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय/जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6.11.2 यूनिट डीटीए में निर्यात और बिक्री/आपूर्ति या अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को हस्तांतरित और अपने स्टॉक के शेष माल के माध्यम से प्रमुख मालों के प्रत्येक श्रेणी के आयात/प्राप्त माल का हिसाब लगा सकेगी। तथापि किसी भी समय यूनिटों को अपने निर्यातों के साथ प्रत्येक आयात खेप को सम्बद्ध करना, अन्य एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को हस्तांतरण करने, डीटीए में बिक्री करने और शेष वस्तुओं को स्टॉक में रखना अपेक्षित है। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा तय नहीं किये गये माल के मामले में स्पष्टीकरण देना होगा।

निवल विदेशी मुद्रा की निगरानी

6.12.1 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14.1 छ में उल्लिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के निष्पादन की निगरानी को सूचना व तकनालों/मंत्रालय/जैव प्रौद्योगिकी विभाग संबंधित केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से करेगा।

6.12.2 सकारात्मक एन एफ टी सुनिश्चित न कर पाने और एलओपी/एलओआई/आईएल/एलपूटी की शर्तों का अनुसरण न कर पाने पर इस एकक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन किसी अन्य कानून/नियमों और एलओपी/एलओआई/आई एल को रद्द करके या मंजूर करके बिना किसी पूर्वाग्रह के दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/स्वीपिंग का

6.13 सोना/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/स्वीपिंग ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी से गर्वन्मेंट ऑफ इण्डिया मिण्ट/प्राइवेट मिण्ट को भेजी जा सकती है।

मानक छड़ों में परिवर्तन

और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानक रोध में उन्हें लौटाई जा सकती है अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित सोना/चाँदी/प्लेटिनम काप्टेन्ट के आधार पर लागू सीमाशुल्क के भुगतान पर डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

डीटीए आपूर्तियाँ

6.14 नीति के पैरा 6.8 में डी टी ए बिक्री के प्रावधान के बावजूद ऐसी डी टी ए बिक्री उस समय में आयात के समय लागू नियमों एवं अन्य प्रतिबंधों को भी ध्यान में लाना होगा ऐसा करने से आयातक किसी अन्य लागू नियम/विनियम की छूट के लिए अधिकृत नहीं होगा। आयातक को कानूनों अथवा नियमों के सहित किन्हीं आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्धता अथवा अनुपालन से किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत भी प्राप्त नहीं होगी।

अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी यूनिटों को आपूर्ति

6.15 अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी यूनिटों को आपूर्ति निवल विदेशी मुद्रा से गिनी जाएगी बशर्ते कि ऐसा माल इन यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हो।

एक एकक से दूसरे एकक को ऊर्जा का हस्तांतरण

6.16 एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से दूसरे यूनिट को कैपिटिव पावर प्लान्टो (डी जी सैट) से ऊर्जा का स्थानान्तरण परिशिष्ट 14 1ग में क्षेत्र विशिष्ट शर्त में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमति होगी।

डीटीए से बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/सिंथेटिक पत्थरों की आपूर्ति

6.17 डीटीए से ईओयू एकको को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मर्दों और दरों पर प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र पाने के पात्र होंगे। प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के संगत अध्याय में है। तथापि, आवेदन संबंधित के विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए। ईओयू को ऐसी आपूर्तियों को मान्य निर्यात लाभों के किसी भी प्रयोजन के लिए मान्य निर्यातों के रूप में नहीं माना जाता है।

हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

6.18 सभी हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जाएं।

अन्य निर्यातकों के जरिए निर्यात

6.19 कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बीटीपी की यूनिट अपने विनिर्मित माल/इसके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का निर्यात किसी निर्यातक या किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बीटीपी यूनिट के जरिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है :—

- (क) माल संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड/बीटीपी में तैयार किया जाएगा।
- (ख) निवल विदेशी मुद्रा का स्तर अथवा यथानिर्धारित आयातों और निर्यातों से संबंधित अन्य शर्तें संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी द्वारा विनियमित की जाएगी।
- (ग) इस प्रकार से प्राप्त निर्यात आदेश ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम के अन्तर्गत ही निष्पादित किए जाएंगे और माल यूनिट से सीधे ही पोत लदान के पत्तन पर भेज दिया जाएगा।
- (घ) इस प्रकार के निर्यात ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों द्वारा एन एफ ई को पूरा करने के लिए अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजेड यूनिट से या अन्य निर्यातक से ईओयू द्वारा आपूर्ति किए गए मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी।
- (ङ) सभी निर्यात पात्रताएं जिसमें स्तरधारक की मान्यता भी शामिल हैं भी निर्यातक के खाते में जोड़े जाएंगे जिसके नाम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है तथापि ऐसा निर्यात ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार को पूरा करने के लिए गिना जाएगा।

अन्य प्रावधान

6.20.1 स्टार व्यापार सदन स्तर प्रदान करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट डीटीए में की मुख्य कंपनी अथवा पंजीकृत: के निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा।

6.20.2 भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेवा गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्षेत्रीय मानदण्ड लागू होंगे।

6.20.3 प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए सॉफ्टवेयर यूनिटों को कम्प्यूटर पद्धति के उपयोग की भी अनुमति है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए बाण्डेड परिसर से बाहर कोई कम्प्यूटर नहीं चले।

6.21 ईओयू विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार प्रणाली लागू नहीं होगी। ईओयू का निर्यात भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निश्चय के अधीन होगा। आई टी सी (एच एस) के अनुसार निर्यात को अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/उपभोक्ता रकम आदि में

निर्यात की अपेक्षा डीटीएस खरीदे गए कच्चे माल और प्रसंस्करण/विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी। वसा मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आएगा। काष्ठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/अन्य काष्ठ के उपयोग के संबंध में 1996 के रिट याचिका संख्या 171 टीएन गोडावर्तन थिरुमुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य—1995 के रिट (सिविल) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12-12-1996 के आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

उप-ठेके

6.21.1 अन्य ईओयू या एसईजेड यूनिट अथवा डीटीए की यूनिट के माध्यम से ईओयू रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा उप-ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा :—

- (क) उप-ठेके पर दिया गया तैयार या अर्ध तैयार माल जिसमें जड़ित आभूषण भी शामिल हैं, की 90 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा।
- (ख) बिना कटे और पालिस किए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों (जिन पर शून्य शुल्क हो, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य और सिंथेटिक पत्थर को छोड़कर) उप-ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी
- (ग) डीटीए/ईओयू/एसईजेड यूनिटों से सादे स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बराबर मात्रा के बदले प्राप्त सोना/चांदी/प्लेटिनम के आभूषण, जैसा भी मामला हो, उक्त आभूषण शामिल हैं।
- (घ) ईओयू प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4-क.2 के अनुसार उप-ठेके हेतु अदला-बदली के मुद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा।
- (ङ) डीटीए यूनिट जो सोना/चांदी/प्लेटिनम के बदले में फुटकर ठेका या आभूषण आपूर्ति का कार्य करती हैं वे मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगे।

6.21.2 डीटीए यूनिट से जॉब वर्क करवाने की सुविधा तब भी उपलब्ध होगी चाहे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण में जॉब वर्कर को पंजीकृत न भी कराया गया हो। यह इस शर्त के अधीन होगा कि जॉब वर्क पूरा होने पर वस्तुओं को यूनिट के प्रांगण में वापस लाया जाएगा।

6.21.3 फुटकर ठेकेदार के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हों। जहां जॉब वर्कर एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट हैं, ऐसे मामलों में उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और निर्यात या जो जॉब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है। जॉब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृतीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि नीति में उल्लेख किया गया है।

6.21.4 ईओयू को उप-ठेकेदारों के परिसर से माडलड किंग्स, टूल्स, फिक्चर्स, टेकल्स, उपकरण हैंगर्स और पैटर्न और ड्राइंग को बनाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर फुटकर

ठेका कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाने की अनुमति होगी। इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भेजा जाएगा।

6.21.5 विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उप-ठेके के मामले में माल का उप-ठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि जैव चक्र परिसरों का, निर्यात घोषणा फार्मों, बीजकों आदि में घोषणा की जाए और पूरी विदेशी मुद्रा देश में वापस लाई जाए।

ठेका कृषि

6.22 कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के उत्पादन/संसाधन में संलग्न ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो समान निकाल सकती है (परिशिष्ट-14 आई जे)

- (क) ठेके फार्मों से ईओयू द्वारा निवेशों की आपूर्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिसूचित निवेश-उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगी।
- (ख) ईओयू और डीटीए किसानों के बीच खेती संबंधी ठेका होगा।
- (ग) ईकाई कृषि/बागवानी जल कृषि/उत्पादों के निर्यात में संलग्न रहनी चाहिए अन्यथा तक उस यूनिट को उप/सहायक आयुक्त सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास बाहर ले जाने वाले पूंजीगत माल/निविष्टियों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रदर्शनी के माध्यम से निर्यात/निर्यात संबंधन दौर

6.23 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी विक्रय आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का निर्यात कर सकती है :—

- (क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल का पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा। रत्न और आभूषण मदों के लिए, उत्पाद की एक स्व-प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- (ख) पुनः आयात के मामले में, आने पर ऐसे मदों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा।
- (ग) जो मद विदेश में बिक्री न हों, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसका आयात किया जाएगा। तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की राणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी।

- (घ) वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से ले जाने और विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए ऐसे रत्नों और आभूषणों का मूल्य 2 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए।

निर्यात संबंधन दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों का व्यक्तिगत रूप से ले जाना

6.24 ईओयू द्वारा निर्यात संबंधन दौरों और विदेशों में अस्थायी प्रदर्शन/बिक्री के लिए 100,000 अमेरिकी डालर तक के सोना/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पालिश किए हुए हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, मानकों और नमूनों के रूप में सामग्री के व्यक्तिगत असबाब की निम्नलिखित शर्तों पर विकास आयुक्त की अनुमति है :—

- (क) ईओयू, प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल को वापस लाएगा अथवा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से बिक्री आय को वापस लाएगा।
- (ख) यूनिट ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असबाब की सीमाशुल्क को देश छोड़ने से पहले घोषणा करेगा/आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।

विदेशों में शोरूम/शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से निर्यात

6.25 विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोरूम में प्रदर्शन/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है। जो मद 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा।

अन्तराष्ट्रीय वायु पत्तनों में शोरूम/फुटकर दुकानों से बिक्री

6.26 ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तराष्ट्रीय वायु-पत्तनों में शोरूम/फुटकर दुकान स्थापित कर सकते हैं, जो मद 60 दिन के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे निर्यात किया जायेगा या संबंधित ईओयू को लौटा दिया जाएगा।

आयात/निर्यात पार्सलों के व्यक्तिगत असबाब जिनमें विदेश जाने वाले यात्रियों का असबाब भी शामिल है।

6.27.1 रत्न और आभूषण मदों के पर्सनल कैरेज के माध्यम से आयात/निर्यात, सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तथापि निर्यात आय सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। रत्न और आभूषण यूनिटों के अलावा, पर्सनल कैरेज यूनिटों के माध्यम से आयात/निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते की माल वाणिज्यिक मात्रा में न हो।

6.27.2 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत कैरेज के लिए ईओयू यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :—

(क) ईओयू द्वारा फाईल की गई पोत लदान बिल की प्रति।

(ख) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की प्रति।

(ग) बैंक से विदेशी मुद्रा प्रति/नकदीकरण प्रमाण-पत्र।

6.27.3 इसके अलावा, विदेश जाने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत कैरेज की डाक्यूमेंट अगेन्स्ट एक्सटैन्स (डी ए) कैश आन डिलीवरी (सीओडी) आधार पर अनुमति होगी। ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(क) जहाज रानी बिल की प्रति

(ख) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण-पत्र।

6.27.4 आयात पार्सलों का व्यक्तिगत कैरेज के लिए वही प्रक्रिया जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है इसमें वह पार्सल शामिल नहीं है जिसे ईओयू/विदेशी नागरिक द्वारा जांच और निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता है। इस संबंध में कस्टम प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा।

6.27.5 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा पार्स को व्यक्तिगत समान के तौर पर ले जाने की अनुमति होगी यदि ग्राहक के स्थान पर निर्धारित माल की मरम्मत हेतु उनकी आवश्यकता हो। निर्यातों के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—

(क) निर्यातों हेतु सीमाशुल्क कार्यालय से अनुज्ञा पत्र।

(ख) मूल्य सहित बीजक (भुगतान करने पर अथवा निःशुल्क)।

आयातित/स्वदेशी माल का प्रतिस्थापन/मरम्मत

6.28.1 यूनिट पूंजीगत माल की मरम्मत के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचना दिए जाने पर विदेश भेजा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए किसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति भी होगी। तथापि, देश के भीतर पूंजीगत माल को मरम्मत के लिए भेजने हेतु अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6.28.2 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट अपने रिकार्ड के अनुसार और सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(क) माल के मरम्मत/प्रतिस्थापन/जांच या केलिब्रेसन तथा रिटर्न के लिए डीटी ए/विदेश को स्थानान्तरित करेगा।

(ख) माल के वापसी के लिए सीमाशुल्क के उपयुक्त बचनबद्धता देते हुए शुल्क का भुगतान किए बिना प्रतिवर्ष रु. 5 लाख तक के माल का किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला/संस्थान को गुणवत्ता जांच/धार एण्ड डी प्रयोजन के लिए स्थानान्तरण किया जा सकता है। तथापि, यदि माल का उपभोग कर लिया जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो इस आशय का प्रमाण प्रयोगशाला/संस्थान से सीमा शुल्क की एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नमूने

6.29.1 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिट अपने रिकार्ड के अनुसार तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर डी टी ए में नमूनों की आपूर्ति या विक्रय कर सकता है। वे यथा लागू शुल्क का भुगतान करके प्रदर्शन/बाजार संवर्धन कर सकते हैं।

6.29.2 निर्धारित अवधि के भीतर नमूनों की वापसी सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उपयुक्त बचनबद्धता प्रस्तुत करके शुल्क का भुगतान किए बिना हटाया जा सकता है।

6.29.3 ई ओ यू कुरियर एजेंसियों/डाकघर के माध्यम सहित निर्यात के सभी अनुमत तरीकों से किसी सीमा के बिना मुक्त निर्यात कर सकता है जिनमें वैक्स मोल्ड, सिल्वर मोल्ड और रबर मोल्ड के नमूने शामिल हैं।

6.29.4 अपने पास रखे रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व सूचना देकर कोई ई.ओ.यू. अन्य ई.ओ.यू. को 30 दिनों के भीतर वापसी आधार पर प्रदर्शन हेतु नमूने भेज सकता है।

कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पैरिफेरिस् के दान

6.30 संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वह अनुमति दी गई है वह आयातित/स्वदेश से खरीदे गए/उधार किए गए कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पैरिफेरिकल्स जिनमें प्रिन्टर्स, प्लौटर, स्कैनर, मानिटर, की बोर्ड और स्टोरेज यूनिट शामिल हैं उनको आयात/खरीद और यूनिट द्वारा उपयोग की गई दो वर्ष के बाद शुल्क का भुगतान किसी मान्यताप्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थाओं, पंजीकृत खैराती अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों स्थानीय निकाय, केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को इस संबंध में जारी सीमा/उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार दान स्वरूप दे सकता है।

माल को नष्ट करना

6.31 सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सूचना देकर या यूनिट के बाहर पूंजीगत माल, कच्चा माल, उपभोग्य, कलपुर्जे, विनिर्मित माल/प्रसंस्कृत या पैकड और स्क्रैप/अवशिष्ट/अवशेष/रद्दीमाल को नष्ट करने के मामले में कोई शुल्क देय नहीं होगा। नष्ट करना जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है, सोना, चाँदी, प्लेटिनियम, हीरा बहुमूल्य अर्द्धमूल्य पत्थरों पर लागू नहीं होगा।

पृथक पहचान

6.32 यदि औद्योगिक उद्यम घरेलू यूनिट पहचान के साथ-साथ ई ओ यू/ई एचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट दोनों रूप में कार्य कर रहा है तो उसकी दो पृथक पहचान होगी और पृथक-पृथक बैंक खाते होंगे। तथापि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी कोई पृथक कानूनी पहचान हो लेकिन ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा प्रभावी आयात और निर्यात अथवा आपूर्तियों की प्रतिष्ठान के अन्य पूंजियों द्वारा किये गये कार्य से पृथक करना संभव हो।

ईओयू के लिए यूनिट अनुमोदन समिति

6.33.1 ईओयू की एकक अनुमोदन समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार होंगे :—

- (क) सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और आई. टी. संबंधी सेवाएं या बी ओ ए द्वारा सौंपी गई कोई अन्य सेवा को छोड़कर) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस वाली मद के लिए यूनिट स्थापित करने हेतु कोई अन्य प्रस्ताव के अलावा ई ओ यू स्थापित करने के लिए आवेदन पर बी ओ ए द्वारा विचार किया जाएगा।
- (ख) एस ई जैड से ई ओ यू में यूनिट के परिवर्तन पर विचार और अनुमति।
- (ग) यूनिट के कार्य निष्पादन की मानिट्रिंग
- (घ) यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी, लाइसेंस का पर्यवेक्षण और मानिट्रिंग तथा विधि के अनुसार समुचित कारवाई करेगी।
- (ङ) यूनिट को दी गयी अनुमति, निकासी, प्राधिकर पत्र के अधीन उसके कार्य निष्पादन का मानिट्रिंग करने के लिए आवश्यक सूचना मांगना।
- (च) केन्द्रीय सरकार या उसकी ऐजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निष्पादन।
- (छ) राज्य सरकार या उसकी ऐजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निष्पादन।
- (ज) ई ओ यू की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन और निकासी देना।

ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन

6.33.2 ईएचटीपी/एसटीपी योजना के तहत यूनिटों के मामले में, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग/निदेशक (एसटीपीआई) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। एस टी पी/ई एच टी पी के मामले में राजपत्र में दिनांक 30-1-2006 को जारी अधिसूचना सं. एस. ओ. 106 (ई) में उल्लिखित के अनुसार नामित अधिकारी को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 खण्ड-13 जो खण्ड-11 के साथ पठनीय है के अधीन निर्णय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार बीटीपी के तहत यूनिटों के मामले में, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, परिशिष्ट 14-1-ख में दिए अनुसार, नए यूनिटों के स्वतः अनुमोदन देने के लिए मनोनीत अधिकारी इसके निर्धारित मानदण्डों को अपनाएंगे। ई ओ यू का प्रशासन/ विकास आयुक्त/ नामित अधिकारी की शक्ति

6.34 यूनिट के संबंध में विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। विकास आयुक्त का क्षेत्राधिकार परिशिष्ट 14-1(ट) में दिया गया है।

1. रुग्ण/बन्द डीटीए यूनिट को ई ओ यू में बदलना।
2. ई ओ यू को एस टी पी/ ई एच टी पी/ बी टी पी तथा विलोमतः में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन करना।
3. विदेशी मुद्रा विनियम दर के घटने-बढ़ने के कारण भारतीय रुपये में पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति।
4. केवल बिना लाइसेंस वाले उद्योगों के मामले में सीमा से परे क्षमता वृद्धि अनुमत करना।
5. एलओपी में उल्लिखित समान वस्तुओं और गतिविधियों के लिए ब्रोड बैंडिंग की अनुमति देना अथवा विनिर्माण की मौजूदा पद्धति को बैकवर्ड या फारवर्ड लिंकेज प्रदान करना।
6. कार्यान्वयन समिति या कम्पनी के नाम परिवर्तन को अधिकृत करना तथा एक कम्पनी से दूसरे में परिवर्तन करना बशर्ते कि नयी कार्यान्वयन समिति/कम्पनी, मौजूदा यूनिट की सम्पत्ति और जिम्मेवारी लेने का वचन देती है।
7. एल ओ पी में उल्लिखित स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन अनुमत करना और/या अतिरिक्त स्थान सम्मिलित करना बशर्ते कि अनुमोदन की अन्य शर्तों तथा समझौतों में किसी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नया स्थान विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है।
8. एल ओ पी को वैधता अवधि को एल ओ पी की शुरुआती वैधता अवधि से 3 वर्ष बढ़ाना (अनुमोदन के शुरुआती अवधि पर जहां कहीं भी प्रतिबंधिता है वैसे मामलों के अलावा, जैसे तेल परिसोधन परियोजना की स्थापना करना)।
9. जहां कहीं भी न्याय संगत हो, एल ओ पी को निरस्त करना।
10. दो या अधिक यूनिटों को एक यूनिट में विलय करना बशर्ते की यूनिटें उसी विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती हैं, इस शर्त पर किया जायेगा कि यूनिटों का कार्यकलाप ब्रोड बैंडिंग के प्रावधानों के तहत शामिल हैं।
11. राजपत्र अधिसूचना संख्या का. आ. 194(अ) दिनांक 6-3-2000 में यथा उल्लिखित निर्यात अभिमुख यूनिटों के संबंध में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत अधिनियम शक्तियों का प्रयोग करना।
12. भारतीय रिज़र्व बैंक ए. डी. (एम ए शृंखला) परिपत्र ए वी (डी आई आर शृंखला) परिपत्र संख्या 9 दिनांक

25-10-2001) के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा साफ्टवेक्स फार्म पर घोषित निर्यातों का मूल्यांकन करना।

13. गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 25022/7/99-एफ-1 दिनांक 20-9-1999 के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा निम्न स्तर के विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाने के लिए रोजगार वीसा प्रदान करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना।

पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण पत्र

14. निर्यातोंमुख इकाई/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में काम करना। मसालों के मामलों की छोड़कर, नीति के पैरा 2.44 में उनके मामलों में अलग पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मसालों के मामले में, इकाईयों की मसाला बोर्ड के पास स्वयं की पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य होगा।

आयातक निर्यातक कोड संख्या

15. फर्म को यदि पहले आयातक निर्यातक कोड संख्या आबंटित नहीं की गयी है तो निर्यात अभिमुख यूनिटों को उसे आबंटित करना।

ग्रीन कार्ड

16. विधिक वचन बद्धता निष्पादन के बाद अपने आप ग्रीन कार्ड जारी करना।
17. निर्यातोन्मुखी यूनिटों के संबंध में स्तर प्रमाण पत्र की स्वीकृति/नवीनीकरण बशर्ते कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में इसके उद्गम कम्पनी के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मिलाना शामिल नहीं है।
18. निर्यातोन्मुखी यूनिट ईओयू/ईएचटीपी/एस टी पी/ बीटीपी स्कीम का उसके क्षेत्राधिकार में प्रचार।

डीटीए में पूंजीगत माल की निकासी

6.35 पुराने पूंजीगत माल के आयात की निकासी की अनुमति ई पी सी जी स्कीम के तहत नीति के अनुसार दी जायेगी। अन्य मामलों में, ऐसी निकासी की तारीख को लागू आयात नीति और लागू शुल्क के भुगतान पर डी टी ए में निकासी की अनुमति होगी।

ह्रास मानदंड

6.36.1 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर संबंधी मदों के मामले में 5 वर्षों में पूंजीगत माल के लिए ह्रास 100 प्रतिशत तक अनुमत है तथा अन्य मदों के मामले में यह 10 वर्ष होगा।

कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरिफेरियल्स के लिए मूल्यह्रास मानदण्ड

6.36.2 कम्प्यूटर पेरिफेरियल्स तथा कम्प्यूटर के लिए ह्रास निम्नवत होगा :—

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 10 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 8 प्रतिशत
तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 5 प्रतिशत
चौथे और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु 1 प्रतिशत

पूँजीगत माल के लिए मूल्यह्रास मानदण्ड

6.36.3 उपरोक्त के अलावा, पूंजीगत माल के लिए तय की गई ह्रास दर निम्नवत होगी :—

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत

चतुर्थ और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत

असके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत

परिवर्तन

6.37.1 मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/ बी टी पी में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन पूर्वस्थापित प्लान्ट, मशीनरी और उपकरण के लिए स्कीम के तहत शुल्क और करों में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। परिवर्तन के बाद विनिर्माण के प्रारम्भ होने की मूल तारीख से आयात से अधिकतम 10 वर्ष के लिए छूट होगी अथवा आयात अधिनियम की धारा-10 के तहत निर्धारित छूट प्राप्त होगी, जो भी पहले हो। इस प्रयोजन के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र एकक संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को उसी तरह आवेदन कर सकता है जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू होगा। यदि यूनिट अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम पूर्व में अग्रिम क्षेत्रीय स्कीम के तहत बकाया निर्यात निष्पादन रखता है तो यह अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को उत्पादन के लिए वास्तविक तौर पर प्रयुक्त शुल्क मुक्त सामग्री की मात्रा के अनुपात में निर्यात वचन बद्धता को कम करने के लिए आवेदन करेगी तथा अग्रिम प्राधिकार पत्र के मदे आयातित अप्रयुक्त सामग्री ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/ बी टी पी स्कीम के तहत यदि कोई हो, को आगे ले जाने की अनुमति है।

6.37.2 मौजूदा ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिटें ई ओ यू में परिवर्तन/विलय होने के लिए आवेदन कर सकती हैं तथा ई ओ यू भी ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों में परिवर्तन/विलय होने के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें सम्बद्ध स्कीम के तहत लागू शुल्कों और करों की छूट की अनुमति प्राप्त करना जारी रखेंगी। ई ओ यू के रूप में परिवर्तन इच्छुक ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें संबंधित विकास आयुक्त को सूचना तकनीकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू है, उसी तरह आवेदन कर सकती हैं। वैसे ही ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी में परिवर्तन को इच्छुक ई ओ यू संबंधित विकास आयुक्त के माध्यम से सूचना तकनीकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

6.37.3 विकास आयुक्त के अनुमोदन से एक निर्यातोन्मुख यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यातोन्मुखी यूनिट, निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत यथानुपात दायित्व प्राप्त कर चुकी है।

रुग्ण यूनिट का पुनरुत्थान

6.38 उचित प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित किए जाने की शर्त पर यूनिट के पुनरुत्थान के प्रस्ताव या अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है। रुग्ण यूनिट के पुनरुत्थान पर दिशा निर्देश परिशिष्ट 14.1 35 में दिये गये हैं।

6.39 शीघ्र निपटान संबंधी प्रक्रिया**पात्रता**

6.39.1 विदेश व्यापार नीति के तहत स्तरधारक प्रमाणपत्र रखने वाले ई ओ यू शीघ्र निपटान हेतु पात्र होंगे।

आयात कार्गो की जांच

6.39.2 स्तरधारक यूनिटों को आयात के पत्तन पर आयात कार्गो के परीक्षण से छूट दी जाएगी। तथापि, क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त यादृच्छिक आधार पर ईकाई के स्थान पर जाकर भी खेप की परीक्षा कर सकता है।

माल की घरेलू खरीद व आयात

6.39.4 विगत वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये और उससे अधिक का वास्तविक निर्यात कारोबार करने वाली यूनिटों को सीमा-शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त द्वारा जारी किये पूर्व साक्ष्यांकित खरीद प्रमाणपत्र के आधार पर शुल्क के भुगतान के बिना माल के आयात की अनुमति होगी।

फैक्स मशीन/कम्प्यूटरों की स्थापना

6.39.4 क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमाशुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को पूर्व सूचना के तहत बाण्डेड परिसरों के बाहर अपने प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालय में एक फैक्स मशीन और 2 कम्प्यूटरों को स्थापित करने हेतु निर्यातोन्मुख यूनिट पात्र होगी।

डी जी सैटों को प्राप्त करना

6.39.5 यूनिट की वास्तविक आवश्यकता के साथ क्षमता के अनुकूल डी जी सैट प्राप्त करने की अनुमति विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचित करते हुए दी जाएगी।

पूँजीगत माल को अस्थायी रूप से हटाना

6.39.6 पात्र निर्यातोन्मुख यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को पूर्व सूचना के तहत मरम्मत हेतु अपने पूँजीगत माल अथवा उनके हिस्सों को हटा सकती हैं।

डीटीए में रिजैक्ट्स की निकासी

6.39.7 डीटीए में रिजैक्ट्स की निकासी की अनुमति हेतु आवेदन पर क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारी अग्रता आधार पर विचार करेगा।

नमूनों को वैयक्तिक रूप से लाना ले जाना

6.39.8 स्तर धारक निर्यातोन्मुख यूनिटों द्वारा रत्न और आभूषणों के नमूनों को वैयक्तिक तौर पर लाने ले जाने की अनुमति

पैरा 6.24 में निर्धारित के सीमा के मदे होगी। विकास आयुक्त/सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्यकलाप जिनके लिए अनुमति आवश्यक नहीं

6.39.9 स्तरधारक के निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में विकास आयुक्त क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

तैयार उत्पादों की विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(क) के अनुसार डीटीए में बिक्री, प्रदर्शनियों में भाग लेना और निर्यात संवर्धक दौरो के लिए रत्नों और आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से लाना ले जाना प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 6.24 की शर्तों की पूर्ति के मदे। तथापि, उसकी पूर्व सूचना देनी होगी।

आवेदनों का समयबद्ध निपटान

6.40 विकास आयुक्त आवेदनों को शीघ्रता से निपटारेंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सीमा को अपनाया जाता है बशर्ते आवेदन हर तरह से पूरे हो और उनके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हों।

क्र. सं.	आवेदन की श्रेणी	निपटान के लिए समय सीमा
1	2	3
1.	अनुमति पत्र जारी करना	15 दिन
2.	अनुमति पत्र/आशय पत्र का परिवर्तन	15 दिन
3.	विधिक वचन बढ़ता को स्वीकृति	3 दिन
4.	विधिक वचन बढ़ता नवीकरण	3 दिन
5.	ब्रांड बैन्डिंग/डाइवर्सिफिकेशन की अनुमति	3 दिन
6.	स्थापना स्थल में परिवर्तन की अनुमति	7 दिन
7.	अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति	2 दिन
8.	यूनिटों के विलयन की अनुमति	7 दिन
9.	उत्पादन क्षमता की वृद्धि की अनुमति	3 दिन
10.	अनुमति पत्र को रद्द करना	3 दिन
11.	डिबान्डिंग/एक्जिट की अनुमति	7 दिन
12.	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति	2 दिन
13.	निम्नस्तरीय टेक्नीशियन के लिए रोजगार वीजा हेतु पात्रता प्रमाण पत्र	2 दिन
14.	ग्रीन कार्ड जारी करना	2 दिन
15.	ग्रीन कार्ड का नवीकरण	उसी दिन
16.	पूँजीगत वस्तुओं को लीज पर देने की अनुमति	1 दिन
17.	स्केप/वेस्ट के निपटान की अनुमति	2 दिन
18.	नाम में परिवर्तन की अनुमति	2 दिन
19.	अन्तर यूनिट स्थानान्तरण	2 दिन

1	2	3
20.	वेस्टेज संबंधी मापदण्ड, तदर्थ	2 दिन
21.	पुनः आयात करने की अनुमति	उसी दिन
22.	पुनः निर्यात करने की अनुमति	उसी दिन
23.	वस्तुओं के प्रतिस्थापन/मरम्मत की अनुमति	उसी दिन
24.	आई.ई.कोड का आवंटन	1 दिन
25.	साफ्टवेक्स फार्म का प्राधिकार पत्र	1 दिन
26.	सी.एस.टी. दावों की प्रतिपूर्ति	7 दिन
27.	जी.एस.पी. प्रमाण पत्र जारी करना	उसी दिन
28.	एस.टी.पी.आई, ई.पी.सी.जी. को ई.ओ.यू. के परिवर्तन की अनुमति	5 दिन
29.	ई.ओ. यू. की अन्तिम निकासी की अनुमति	5 दिन
30.	ई.ओ.यू. में विस्तार की अनुमति	2 दिन
31.	पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की अनुमति	2 दिन
32.	प्रदर्शनी/दौरो के जरिये निर्यात की अनुमति	2 दिन
33.	शुल्क/वापसी/टी.ई.डी. की प्रतिपूर्ति	7 दिन

अध्याय-7

विशेष आर्थिक जोन

विशेष आर्थिक जोन से सम्बंधित नीति और प्रक्रिया, विशेष आर्थिक अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 में शामिल है।

अध्याय-8

मान्य निर्यात

नीति

8.1 मान्य निर्यात संबंधी नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-8 में दी गई है।

मान्य निर्यात के लाभों का दावा करने के लिए मानदण्ड

8.2.1 नीति के पैरा 8.2 (क) के तहत आपूर्तियों के सम्बंध में ए आर ओ तथा बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख-पत्र को जारी करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.14 और 4.15 में दी गई है।

8.2.2 नीति और डी एफ आर सी के पैरा 8.2 (ख) के अन्तर्गत आपूर्तियों के सम्बंध में, विकास आयुक्त अथवा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से मान्य निर्यात लाभों का दावा किया जा सकता है। अग्रिम प्राधिकार पत्र, डी एफ आई ए और डी एफ आर सी के लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से दावा किया जा सकता है। ऐसी आपूर्तियों को प्राप्त करने वाली एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

8.2.3 नीति के पैरा 8.2(ग) के अन्तर्गत पूँजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के सम्बंध में, आपूर्तिकर्ता ई पी सी जे. प्राधिकार पत्र धारक से उस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि आपूर्ति/विनिर्मित पूँजीगत माल प्राप्त हो गया है।

8.2.4 नीति के पैरा 8.2(घ), (ड.), (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत आपूर्ति के सम्बंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन के साथ परिशिष्ट-27 में दिए परियोजना प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न होगा। ऐसी आपूर्तियों के मद्दे भुगतान परिशिष्ट 22-ग में दिए गए फार्म के अनुसार संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

मान्य निर्यात शुल्क वापसी और अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी/अंतिम उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट पर दावे की प्रक्रिया

8.3.1 नीति के पैरा 8.3(ख) और (ग) के तहत लाभों का दावा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है :—

1. आयात निर्यात प्रपत्र में, उसमें बताए गए दस्तावेजों सहित आपूर्तिकर्ता द्वारा आवेदन संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्राप्तिकर्ता निर्धारित दस्तावेजों के अलावा सेनवेट क्रेडिट न लेने सम्बंधी प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-22ग में स्व-घोषणा के साथ आपूर्तिकर्ता के उपयुक्त दावेदारी छोड़ने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके भी लाभ की दावेदारी कर सकता है।

2. पैरा 8.2 (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत आपूर्तियों के मामले में दावा परिशिष्ट-22ख में दिए प्रपत्र में सामान्य बैंकिंग चैनल के द्वारा भुगतान की प्राप्ति के मद्दे किया जायेगा। ऐसे दावे आवेदक के विकल्प के अनुसार भुगतान की तिथि से आकलन करके मासिक/तिमाही/छमाही अवधि के अन्त से 6 महीने के अन्दर दर्ज किये जायेंगे। उन मामलों में जहाँ अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है, आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि भुगतान प्राप्त करने की तिथि भुगतान प्राप्त करने की तिथि के बदले, आपूर्ति करने की तिथि से सह सम्पन्न होगी।

पैरा 8.2 (क) और (ख) के तहत आपूर्तियों के मामले में ऐसे दावे भुगतान प्राप्ति के महीने की आखिरी तारीख के 6 महीनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। पैरा 8.2 (ग) के तहत आपूर्तियों के मामले में आवेदन मासिक/त्रिमासिक/अर्ध-वार्षिक अवधि के अन्त से 6 महीनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है, जिसे आवेदक के विकल्प के अनुसार भुगतान की तारीख से गिना जायेगा। जिन मामलों में भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त हुआ है आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख भुगतान प्राप्ति की तारीख के बजाय आपूर्ति की तारीख होगी।

3. नीति के पैरा 8.2 (ख) के अन्तर्गत आपूर्तियों के सम्बंध में जहाँ आपूर्तिकर्ता लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लाभ का दावा करना चाहता है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी डी टी ए आपूर्तिकर्ता को मान्य निर्यात के लाभ की अनुमति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रमाणित प्रतियाँ, की गई आपूर्ति के प्रमाण के रूप में शुल्क को प्रमाणित बीजक की सत्यापित प्रतियाँ और/या उत्पाद शुल्क सत्यापित सीटी-3 फार्म और अनुमति-पत्र की वैधता के प्रमाण के रूप सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त होने पर देगा।

4. नीति के पैरा 8.2 (घ), (ड.), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) में उल्लिखित श्रेणियों के तहत आपूर्तियों के सम्बंध में प्राप्त भुगतान/हुई आपूर्ति हेतु दावा, हुई आपूर्ति अथवा प्राप्त भुगतान के साक्ष्य के आधार पर आवेदक के विकल्पानुसार किसी विशेष महा/तिमाही/छमाही आधार पर किया जा सकता है। दावा किसी विशेष परियोजना अथवा सभी

परियोजनाओं के मद्दे किया जा सकता है। ऐसे दावे आवेदक के विकल्प के अनुसार मासिक/तिमाही/छमाही अवधि की समाप्ति से परियोजना अधिकारी द्वारा आपूर्ति की प्राप्ति की तारीख से गिने गए अथवा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे दावे जहाँ खण्डों में भुगतान प्राप्त हो वहाँ भी किए जा सकते हैं।

8.3.2 अंतिम उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

8.3.3 जहाँ ड्रा बैंक की कोई समग्र उद्योग दर उपलब्ध नहीं है या यह उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या उपकरणों पर शुल्क के 4/5 से कम है तो निर्यातक/आपूर्तिकर्ता क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा विकास आयुक्त को जैसा भी मामला हो, आयात निर्यात प्रपत्र में दिए गए प्रपत्र में ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है।

8.3.4 अगर ब्रांड दर के निर्धारण की आवश्यकता है तो शुल्क वापसी के ब्रांड रेट के निर्धारण के लिए आवेदन के साथ दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पैरा 9.3 के अन्तर्गत विलम्ब कटौती के प्रावधान और पैरा 9.4 के अन्तर्गत पूरक दावे भी इस उप पैरा के अन्तर्गत लागू होंगे।

8.3.5 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी निजी कम्पनियों के मामले में शुल्क वापसी के दावे 75 प्रतिशत तक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 90 प्रतिशत तक अन्तिम भुगतान पर विचार करेगा जोकि ब्रांड दर के निर्धारण के लिए लम्बित हैं।

8.3.6 इस प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अधीन, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 मान्य निर्यात के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

उप ठेकेदारों द्वारा मान्य निर्यात लाभों का दावा करने की प्रक्रिया

8.4 पैरा 8.2 (घ), (ङ), (च), (छ), (झ) और (ञ) के तहत उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को की गई आपूर्तियों के संबंध में, मुख्य ठेकेदार उप ठेकेदार को भुगतान कर सकता है और परिशिष्ट 22ग में दिए गए फर्म 1-ग के रूप में भुगतान प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। तथापि, पैरा 8.2 (घ), (ङ), (च), (छ), (झ) और (ञ) के तहत की गई आपूर्तियों के लिए, अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए मुख्य ठेकेदार से भुगतान प्रमाण-पत्र लेने पर जोर नहीं दिया जायेगा। उप-ठेकेदार को मान्य निर्यात के लाभ वस्तुओं की उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जिस सीमा तक उप-ठेकेदार द्वारा वस्तुओं का विनिर्माण किया गया है और इनकी आपूर्ति की गई है या अन्य विनिर्माताओं से इन्हें प्राप्त किया गया है, वस्तुओं का मूल्य प्रक्रिया-पुस्तक के परिशिष्ट-22ग में यथा निर्दिष्टनुसार होगा।

अध्याय-9

विविध मामले

नाम और संरचना में परिवर्तन

9.1 यदि बिना प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/मान्यताप्राप्त स्तर धारक के बिना आयात के पात्र आई ई सी धारक/लाइसेंस धारक/प्राधिकार

पत्र/वास्तविक उपयोक्ता के नाम/पते या संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो संबंधित आई ई सी धारक/लाइसेंस धारक/प्राधिकार पत्र/वास्तविक उपयोक्ता/स्तर धारक जो भी मामला हो, यदि वह इस बीच निम्नलिखित कार्रवाई नहीं करता है तो नाम या पता या संरचना में परिवर्तन की तारीख से 90 दिन की समाप्ति के पश्चात उक्त लाइसेंस/आई ई सी संख्या के तहत या नीति और इस प्रक्रिया पुस्तक के अधीन अनुमत आयात या निर्यात या अन्य सुविधा का पात्र नहीं रहेगा :-

(क) आई ई सी धारक/लाइसेंस धारक/प्राधिकार पत्र धारक/स्तर धारक, आई ई सी संख्या/प्राधिकार पत्र/लाइसेंस या मान्यता प्रमाण-पत्र में जो भी मामला हो, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त परिवर्तन करवा लेता है;

(ख) वास्तविक उपयोक्ता ने औद्योगिक सहायता सचिवालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा जारी औद्योगिक लाइसेंस में या राज्य सरकार के उद्योग निदेशक द्वारा जारी वास्तविक उपयोक्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त परिवर्तन करवा लिए हैं या औद्योगिक सहायता सचिवालय में ज्ञापन प्रस्तुत करने की पावती की सूचना प्राप्त कर ली है।

तथापि, बशर्ते कि आई. ई. कोड नम्बर जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 1000/- रुपये के जुर्माने के भुगतान पर देरी को माफ कर सकता है।

तथापि, उक्त जुर्माने के भुगतान के उद्देश्य के लिए एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के निदेशक को बदलना कम्पनी के ढाँचागत परिवर्तन की स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आई ई सी में संशोधन के प्रयोजन हेतु गठन तथा उपरोक्त जुर्माने के भुगतान का आशय है कि साझेदारी फर्म में साझेदार बदलने से ट्रस्ट के ट्रस्टी, सोसायटी बोर्ड के सदस्य तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के निदेशक बदल जाएंगे।

आयात प्राधिकार पत्र/लाइसेंसों/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र का नामकरण

9.2 नीति के तहत जारी आयात प्राधिकार पत्र/लाइसेंसों/प्रमाण पत्रों/अनुमति पत्रों पर मूल्य प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र जारी करने की तारीख पर मौजूद विनिमय दर पर रुपयों में और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा दोनों में निर्दिष्ट किया जाएगा। जिन प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों/प्रमाण-पत्रों/अनुमति पत्रों पर निर्यात दायित्व लगाया गया है, वहाँ निर्यात दायित्व का मूल्य प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र जारी करने की तारीख पर मौजूद विनिमय दर पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और रुपया दोनों निर्दिष्ट किया जाएगा। यह विनिमय दर आयात प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र पर भी निर्दिष्ट की जाएगी।

9.2.1 तथापि, प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के तहत विदेशी मुद्रा के प्रेषण और निर्यात दायित्व का निष्पादन मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा। रुपयों के मूल्य में कोई वृद्धि आवश्यक नहीं होगी यदि विदेशी मुद्रा का प्रेषण मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में निर्दिष्ट प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के मूल्य में शामिल होता है।

9.2.2 यथापि, ए सी यू देशों को निर्यात के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र पर निर्यात दायित्व ए सी यू डॉलरों में लगाया और निष्पादित किया जाएगा।

9.2.3 जहां आपूर्तियाँ देश के भीतर की जानी हों, वहां अन्तर्वर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र और मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व भारतीय रुपयों में लगाया जाएगा और निर्यात दायित्व का निष्पादन भारतीय रुपयों में, प्राधिकार पत्र पर अंकित लागत बीमा भाड़ा मूल्य को ध्यान में रखे बिना आयातों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के संदर्भ के अनुसार भारतीय रुपयों में किया जाएगा।

प्राप्ति की निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदन

9.3 जब कभी प्राप्ति की तारीख समाप्त होने के पश्चात कोई आवेदन प्राप्त होता है, किन्तु अंतिम तारीख से छह माह के भीतर यह प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 10% विलम्ब कटौती लगा कर इन पर विचार किया जा सकता है।

अनुपूरक दावे

9.4 यदि निर्धारित समयावधि के भीतर, अनुपूरक दावे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 10% कटौती करके ऐसे आवेदन पर विचार किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

9.5 प्रत्येक आयातक/निर्यातक महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा सिधित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना देगा।

नीति/प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण

9.6 नीति के किसी भी प्रावधान या प्रक्रिया पुस्तक, आई टी सी (एच एस) के तहत मदों की आयातीयता या निर्यातीयता के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण महानिदेशक, विदेश व्यापार से परिशिष्ट-28 में दिए गए प्रपत्र में माँगा जा सकता है। ई-मेल के माध्यम से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है।

उपभोग का रजिस्टर

9.7 आयातक, प्राधिकार पत्र/लाइसेंस के आयातित मदों और इसके उपयोग के बारे में एक रजिस्टर रखेगा। आयातक, प्राधिकार पत्र/लाइसेंस के बिना आयातित मदों और इसके उपयोग के संबंध में एक रजिस्टर भी रखेगा बशर्ते ऐसी मदों का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के तहत किया गया हो।

उन स्कीमों को छोड़कर जिनमें उपयोग रजिस्टर को सुरक्षित रखने हेतु अवधि को विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, रजिस्टर, परिशिष्ट 23 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार होगा। अन्य सभी मामलों में, रजिस्टर आयात की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक बनाए रखा जायेगा।

निर्यात सुविधा

9.8 निर्यातकों की समस्याओं को समन्वित रूप से समाधान के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यात सुविधा केन्द्र का कार्य करेंगे। ये कार्यालय निर्यातकों की समस्याओं, शिकायतों के समाधान के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेगी तथा उनके व्यापार और निर्यात संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करेगी।

इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी नामंकित किए गए हैं और निर्यातकों को सहयोग देने के लिए नामित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 17 में दी गई है।

विभिन्न विभागों से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिए सुविधा कमेटी का गठन प्रत्येक विभाग में किया जाएगा जिसको विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थायी शिकायत समितियाँ

9.9 शिकायत निवारण तंत्र का व्यौरा नीति के पैरा 2.49 में दिया गया है।

नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

इन शिकायत समितियों के अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) अलग-अलग लाइसेंसिंग कार्यालयों में संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ आई ई ओ), निर्यात संवर्धन परिषद/वस्तु बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी, सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

9.9.1 अलग-अलग शिकायत समिति का अध्यक्ष किसी सदस्य को शामिल कर सकता है। ऐसी समितियों की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी।

9.9.2 प्रत्येक निर्यातक/आयातक को शिकायत समिति में अभ्यावेदन देने तथा यदि वह चाहे तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अधिकार होगा। इस प्रयोजन के लिए, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

9.9.3 शिकायत समिति को अभ्यावेदन परिशिष्ट-26 में दिए गए प्रपत्र में भेजा जाएगा।

काउंटर सहायता

9.10 आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में 'काउंटर सहायता' प्रकोष्ठ कार्य करेगा।

प्रत्येक कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी काउंटर का प्रभारी होगा। काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदक को एक टोकन दिया जाएगा और टोकन को उसी दिन लौटाने की सलाह दी जाएगी जब उसे यह बताया जाएगा कि उसका आवेदन पूर्ण है और इसे

कार्यालय द्वारा आगे की कार्यवाई के लिए रख लिया गया है या इसमें कोई कमी है जिसे आवेदक को पूरा करना है।

9.10.1 काउंटर सहायता प्रकोष्ठ आवेदन को आवश्यक संवीक्षा के लिए उसी दिन संबंधित अनुभाग को भेजेगा। यदि इसमें कोई कमी होगी तो इसे संबंधित अनुभाग द्वारा नोट किया जाएगा और इसे उसी दिन काउंटर सहायता प्रकोष्ठ को लौटा दिया जाएगा। पूर्ण आवेदन के मामले में, आवेदन को औपचारिक रसीद दी जाएगी जिसमें आगे संदर्भ के लिए फाइल नम्बर दिया जाएगा।

अपूर्ण आवेदनों के मामले में, संबंधित अनुभाग द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए इसे आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

पूर्ण आवेदनों पर पैरा-9.10 के अधीन दी गई समय-सीमा के भीतर संबंधित अनुभाग द्वारा कार्यवाई की जाएगी।

यदि और कोई कमी नोट की जाती है तो कार्यालय के अध्यक्ष के अनुमोदन से इसे बताया जाएगा जो काउंटर सहायता के प्रभावी संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।

9.10.2 छोटी प्रकृति के संशोधन/पूछताछ के लिए भी काउंटर सहायता का उपयोग किया जाएगा। ऐसे मामलों में, आवेदन, उपयुक्त रसीद के प्रति काउंटर पर लाइसेंसिंग कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे और प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/सूची/पूछताछ जैसा भी मामला हो, को काउंटर पर ही उसी दिन संशोधित करके/आवश्यक जवाब दे कर वापिस कर दिया जाएगा।

आवेदनों का समयबद्ध निपटान

9.11 लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सारणी को अपनाया जाएगा बशर्ते आवेदन हर तरह से पूर्ण हो और उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हों :

क्र. आवेदन की श्रेणी सं.	निपटान के लिए समय सीमा
1	2
क. आयातक निर्यातक कोड संख्या	2 कार्य दिवस
ख. अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड को अधिसूचित किया गया है या पैराग्राफ 4.7 के तहत डी एफ आई ए, जहाँ निविष्टि उत्पादन मानदण्ड अधिसूचित है और वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र	3 कार्य दिवस

1	2	3
	अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि उत्पादन 15 कार्य दिवस मानदण्डों को अधिसूचित किया गया है किन्तु आवेदनों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का अनुमोदन होना है।	
	अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि उत्पादन मानदंड अधिसूचित नहीं है।	45 कार्य दिवस
	निविष्टि-उत्पादन मानदंडों का निर्धारण	90 कार्य दिवस
ग. डी एफ आर सी/डी ई पी बी		3 कार्य दिवस
घ. (i) स्वधोषणा आधार पर ई पी सी जी प्राधिकार पत्र		3 कार्य दिवस
(ii) अन्तर्संबंध के निर्धारण हेतु ई पी सी जी प्राधिकार पत्र [ऊपर (1) को छोड़कर]		45 कार्य दिवस
ङ. रत्न और आभूषण स्कीम के तहत सभी प्राधिकार पत्र		3 कार्य दिवस
च. प्राधिकार पत्र की पुनर्विधता तथा क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि		3 कार्य दिवस
छ. बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति अग्रिम प्राधिकार पत्रों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को निष्क्रिय बनाना		3 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस
ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्क्रिय करना		30 कार्य दिवस
ज. स्तर प्रमाण पत्र जारी करना/नवीकरण करना		3 कार्य दिवस
झ. किसी भी श्रेणी के प्राधिकार पत्र का संशोधन		3 कार्य दिवस
ञ. मान्य निर्यात शुल्क वापसी दर का निर्धारण		45 कार्य दिवस
ट. विविध		10 कार्य दिवस
ठ. ई डी आई माध्यम से प्रस्तुत सभी आवेदन		1 कार्य दिवस

आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी के मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष की जानकारी में लिखित रूप से लाया जायेगा और शीघ्रता से इसकी जांच की जायेगी और उत्तर दिया जायेगा।

आयात के संबंध में शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

9.11 के आयात के उद्देश्य के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जाएगा :—

परिवहन का तरीका समुद्र मार्ग द्वारा**शिपमेंट/प्रेषण की तारीख**

लदान-पत्र पर लिखी तारीख।

वायु मार्ग द्वारा

सम्बद्ध एयरवे बिल की तारीख बशर्ते इससे उस तारीख का पता चलता हो जब माल अपने देश के अंतिम हवाई अड्डे को छोड़ा हो, जहाँ से आयात किया गया।

भूमि-रुद्ध देशों से

प्रेषण आधार के माध्यम से भारत में खेप भेजने वाले को रेल, सड़क या अन्य मान्यताप्राप्त परिवहन के साधन द्वारा प्रेषण की तारीख।

डाक पार्सल द्वारा

पैकेटों या प्रेषण नोट पर प्रेषण कार्यालय की स्टैम्प की तारीख।

पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा

कुरियर रसीद/वे बिल पर अंकित तारीख।

बहु-आयामी परिवहन

लदान के संयुक्त परिवहन में पहले वाहन से सामान सौंपने की तारीख।

निर्यात के संबंध में शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

9.12 निर्यात के उद्देश्य के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा :—

परिवहन का तरीका समुद्र मार्ग द्वारा**शिपमेंट/प्रेषण की तारीख**

लदान-पत्र पर लिखी तारीख।

1. समुद्र मार्ग द्वारा

बल्क कार्गो के लिए, लदान-पत्र की तारीख या नेट रसीद की तारीख, जो भी बाद की हो।

(क) कंटेनर-युक्त कार्गो के लिए, 'जहाज पर लदान बिल' या 'लदान के जहाज-लदान-बिल के लिए प्राप्त' की तारीख जहाँ एल/सी में ऐसे लदान-पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी) से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए, सीमाशुल्क निकासी के पश्चात् आई सी डी में निर्यात माल के लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान-पत्र की तारीख।

(ख) लैंड बाजेंज के लिए, लदान-पत्र की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लदान का प्रमाण हो।

2. वायु मार्ग द्वारा

उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा शिपिंग बिल पर उल्लिखित तारीख, जिसमें लदान या वायु कार्गो का म्पलैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो।

3. डाक पार्सल द्वारा

डाक रसीद पर अंकित तारीख।

4. रेल द्वारा

रेलवे रसीद की तारीख।

5. पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा

कुरियर रसीद/माल-सूची पर अंकित तारीख।

6. सड़क मार्ग द्वारा

जैसा कि भूमि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख।

तथापि, जहाँ कहीं नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के हित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंप गए खेपों और बाद में निर्यात पर लागू नहीं होंगे।

इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व अवधि के समाप्ति से पहले माल सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता, किन्तु वास्तविक निर्यात, निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाएगी।

पुनरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया

9.13 महानिदेशक, विदेश व्यापार स्वयं या अन्यथा, ई पी सी/एफ आई ई ओ के किसी अधिकारी, जिसमें उसके द्वारा नामित व्यक्ति, नियुक्त या प्राधिकारियों का समूह/समिति शामिल है, के पास लम्बित पड़े किसी मामले या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तय किए गए मामले के रिकार्ड मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (2004—2009) का अभिन्न अंग हैं जो सार्वजनिक सूचना संख्या-1 (आर ई-2006/2004—09) दिनांक 7 अप्रैल, 2006 द्वारा यथा अधिसूचित वार्षिक परिशिष्ट में शामिल है।

परिशिष्ट विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर उपलब्ध है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 7th April, 2006

No. 1 (RE-2006)/2004-2009

F. No. 01/94/180/Handbook/AM 07/PC-I.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, the Director General of Foreign Trade hereby notifies annual supplement of the Handbook of Procedures (Volume I) incorporating Annual Supplement as updated on 7th April, 2006 as contained in Annexure to this Public Notice and the Appendices to the Handbook of Procedures (Vol. I) as available on the website of Directorate General of Foreign Trade at <http://dgft.gov.in>. This shall come into force from 1st April, 2006.

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade
and *ex-officio* Addl. Secy.

ANNEXURE**HANDBOOK OF PROCEDURES-
(VOL. I)**

1st September, 2004—31st March, 2009

w.e.f. 1-4-2006

CHAPTER-I**INTRODUCTION****NOTIFICATION:**

1.1 In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation Act), 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government has notified the Foreign Trade Policy for the period 2004—2009 incorporating the Export and Import Policy for the period 2002—2007 as modified.

This Policy shall come into force with effect from 1st September, 2004 and shall remain in force upto 31st March, 2009, unless as otherwise specified.

In pursuance of the provisions of paragraph 2.4 of the Policy, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the compilation known as Handbook of Procedures (Vol. 1), Handbook of Procedures (Vol. 2) and Schedule of DEPB rates.

These compilations, as amended from time to time, shall remain in force until 31st March, 2009.

Objective

1.2 The objective of this Handbook is to implement the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder the Foreign Trade Policy (2004-2009) incorporating the Export and Import Policy (2002-07) by laying down simple, transparent and EDI (Electronic Data Interchange) compatible procedures which are easy to

comply with the administer for efficacious management of foreign trade.

Definition :

1.3 For the purpose of this Handbook, the definitions contained in the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder and the Foreign Trade Policy (2004—2009) shall apply.

CHAPTER-2**GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS
AND IMPORTS****POLICY:**

2.1 The Policy relating to the general provisions regarding exports and imports is given in Chapter-2 of the Policy.

Countries of Imports/Exports :

2.2 Unless otherwise specifically provided, import/export will be valid from/to any country. However, import/exports of arms and related material from/to Iraq shall be prohibited.

The above provisions shall, however, be subject to all conditionality, or requirement of licence/Authorisation, or permission, as may be required under Schedule II of ITC (HS).

Application Fee :

2.3 Unless otherwise exempted, specified fee shall be paid for making an application under any provision of the Policy and this Handbook. The scale of fee, mode of payment, procedure for refund of fee and the categories of persons exempted from the payment of fee are contained in Appendix-21B.

Territorial Jurisdiction of Regional Authorities :

2.4 Every application, unless otherwise specified, shall be submitted to the Regional Authority concerned, as per the territorial jurisdiction of the Regional Authorities indicated in Appendix-1.

Filing of Application :

2.5 Every application for an Import/Export licence/certificate/Authorisation/permission or any other purpose should be complete in all respects as required under the relevant provisions of the Policy/Procedures and shall be signed by the applicant as defined in paragraph 9.9 of the Policy.

An incomplete application is liable to be rejected giving specific reason for rejection. However, in case of manual applications, the applicant would furnish as soft comply of the application in MS word format.

Profile of Importer/Exporter :

2.6 Each importer/exporter shall be required to file importer/exporter profile once with the Regional Authority

in Part I of 'Aayaat Niryaat Form'. Regional Authority shall enter the information furnished in Part I of 'Aayaat Niryaat Form' in their database so as to dispense with the need for asking the repetitive information. In case of any change in the information given in Part I of 'Aayaat Niryaat Form', importer/exporter shall intimate the same to the Regional Authority.

Self-Addressed Stamped Envelope :

2.7 The applicant shall furnish a self addressed envelope of 40x15cm with postal stamp affixed on the envelope as follows for all documents required to be sent by Speed Post :

- (a) Within local area Rs. 20.00
- (b) Upto 200 Kms. Rs. 25.00
- (c) Between 200 to 1000 Kms. Rs. 30.00
- (d) Beyond 1000 Kms. Rs. 50.00

IEC No : Exempted Categories :

2.8 The following categories of importers or exporters are exempted from obtaining Importer-Exporter Code (IEC) number :

- (i) Importers covered by clause 3(1) [except sub-clauses (e) and (1)] and exporters covered by clause 3(2) [except sub-clauses(i) and (k)] of the Foreign Trade (Exemption from application of Rules in certain cases) Order, 1993.
- (ii) Ministries/Departments of the Central or State Government.
- (iii) Persons importing or exporting goods for personal use not connected with trade or manufacture or agriculture.
- (iv) Persons importing/exporting goods from/to Nepal provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rs. 25,000.
- (v) Persons importing/exporting goods from/to Myanmar through Indo-Myanmar border areas provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rs. 25,000.

However, the exemption from obtaining Importer-Exporter Code (IEC) number shall not be applicable for the export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipments and Technologies (SCOMET) as listed in Appendix 3, Schedule 2 of the ITC (HS) except in the case of exports by category (II) above.

- (vi) The following permanent IEC numbers shall be used by the categories of importers/exporters mentioned against them for import/export purposes.

Sl. No.	Code Number	Categories of Importers/Exporters
1.	0100000011	All Ministries/Departments of the Central Government and agencies wholly or partially owned by them.
2.	0100000029	All Ministries/Departments of the State Government and agencies wholly or partially owned by them.
3.	0100000037	Diplomatic personnel, Counsel or officers in India and the officials of the UNO and its specialised agencies.
4.	0100000045	Indians returning from/going abroad and claiming benefit under the Baggage Rules.
5.	0100000053	Persons/Institutions/Hospitals importing or exporting goods for personnel use, not connected with trade or manufacture or agriculture.
6.	0100000061	Persons importing/exporting goods from/to Nepal provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rupees 25000/-.
7.	0100000070	Persons importing/exporting goods from/to Myanmar through Indo-Myanmar border areas provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rupees 25000/-.
8.	0100000088	Ford Foundation
9.	0100000096	Importers importing goods for display or use in fairs/exhibitions or similar events under the provisions of ATA carnet.
10.	0100000100	Director, National Blood Group Reference Laboratory, Bombay or their authorized offices.
11.	0100000126	Individuals/Charitable Institutions/Registered NGOs Importing goods, which have been exempted from Customs duty under the Notification issued by Ministry of Finance for <i>bona fide</i> use by the victims affected by natural calamity.

Note : Commercial Public Sector Undertaking (PSU) who have obtained PAN will however be required to obtain Importer Exporter Code number. The permanent IEC number as mentioned above, shall be used by non-commercial PSUs.

Application for Grant of IEC Number

2.9 An application for grant of IEC number shall be made by the Registered/Head Office of the applicant to the Regional Authority under whose jurisdiction, the Registered office in case of company and Head Office in case of others, falls in the 'Aayaat Niryaat Form' and shall be accompanied by documents prescribed therein. In case of STPI/EHTP/BTP units, the Regional Offices of the DGFT having jurisdiction over the district in which the Registered/Head Office of the STPI unit is located shall issue or amend the IECs.

Only one IEC would be issued against a single PAN number. Any proprietor can have only one IEC number and in case there are more than one IECs allotted to a proprietor, the same may be surrendered to the Regional Office for cancellation.

IEC Format and Statements

2.9.1 The Regional Authority concerned shall issue an IEC number in the format as given in Appendix-18B. A copy of such IEC number shall be endorsed to the concerned banker (as per the details given in the IEC application form).

A consolidated statement of IEC numbers issued by the Regional Authority shall be sent to the offices of the Exchange Control Department of the RBI as given in Appendix-18D as per the statement given in Appendix-18C.

Validity of IEC No.

2.9.2 An IEC number allotted to an applicant shall be valid for all its branches/divisions/units/factories as indicated in the format of IEC given in Appendix-18B.

Duplicate Copy of IEC Number

2.9.3 Where an IEC Number is lost or misplaced, the issuing authority may consider requests for grant of a duplicate copy of IEC number, if accompanied by an affidavit.

Surrender of IEC Number

2.9.4 If an IEC holder does not wish to operate the allotted IEC number, he may surrender the same by informing the issuing authority. On receipt of such intimation, the issuing authority shall immediately cancel the same and electronically transmit it to DGFT for onward transmission to the Customs and Regional Authorities.

Mandatory returns

2.9.5 Deleted.

Application for Import and Export of Restricted Items

2.10 An application for grant of a licence/certificate/permission for import or export of items mentioned as restricted in ITC (HS) may be made in the form and to the Regional authorities specified under the relevant chapters of this Handbook.

Imports under Indo-US Memorandum of Understanding

2.11 Import of specified capital goods, raw materials, components, etc. from the United States of America is subject to US Export Control Regulations.

US suppliers of such items are required to obtain an export licence/certificate/Authorisation/permission based on the import certificate furnished by the Indian Importer to the US supplier. The following are the designated Import Certificate Issuing Authorities (ICIA) :

- (i) The Department of Electronics, for import of computer and computer based systems ;
- (ii) The Department of Industrial Policy and Promotion, Technical Support Wing (TSW), for organised sector units registered under it, except for import of computers and computer based systems ;
- (iii) The Ministry of Defence, for defence related items,
- (iv) The Director General of Foreign Trade for small scale industries and entities not covered above as well as on behalf of any of the above;
- (v) The Embassy of India, Washington, DC, on behalf of any of the above.

A request for an import certificate shall be made in the 'Aayaat Niryaat Form'. The import certificate in Appendix-31 may be issued by the ICIA directly to the importer with a copy to (i) Ministry of External Affairs (AMS Section), New Delhi; (ii) Department of Electronics, New Delhi and (iii) Directorate General of Foreign Trade, New Delhi.

However, this import certificate will not be regarded as a substitute for an import licence/certificate/permission in respect of the items mentioned as restricted in ITC (HS) and an import licence/certificate/permission will have to be obtained wherever required for such items.

Validity of Import Licence/Certificate/Authorisation/Permissions/CCPs/Export licence

2.12 The validity of import licence/certificate/Authorisation/permission from the date of issue of licence/certificate/Authorisation/permission shall be as follows :

- (i) Advance Authorisation — 24 months
DFIA (including Advance Authorisation/DFIA for Annual Requirement), DFRC and Replenishment licence for Gem and Jewellery as per Chapter-4 of the Policy.
- (ii) EPCG Authorisation 36 months
(other than spares).

- | | |
|---|---|
| (iii) HPCG Authorisation for Spares, refractories, catalyst and consumables. | Co-terminus with the Export Obligation Period of the EPCG Authorisation. |
| (iv) Others including CCP and Duty Entitlement Passbook Scheme, unless otherwise specified. | 24 months |
| (v) Advance Authorisation/DFIA for deemed export (including Advance Authorisation/DFIA for Annual Requirement). | 24 months or Co-terminus with the contracted duration of execution of the project whichever is later. |

2.12.1 Where the date of expiry of the licence/certificate/Authorisation/permission/duty credit certificates falls before the last day of the month, the licence/certificate/Authorisation/permission/duty credit certificate shall be deemed to be valid until the last day of the month.

This proviso would be applicable even for a revalidated licence/certificate/Authorisation/permission/duty credit certificates.

2.12.2 "The period of validity means the period for shipment/dispatch of goods covered under the licence/certificate/Authorisation/permission. The validity of an import licence/certificate/Authorisation/permission is decided with reference to the date of shipment/dispatch of the goods from the supplying country as given in Paragraph 9.11 A of this Handbook and not the date of arrival of the goods at an Indian port."

2.12.3 The provisions of paragraph 2.12.2 above shall not be applicable to DEPB, Duty Free Entitlement Certificate for Service Providers, Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana and duty credit scrips issued under Focus Market scheme and Focus Product scheme. DEPB, Duty Free Entitlement Certificate for Service Providers, Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana and duty credit scrips issued under Focus Market scheme and Focus Product scheme which are in the nature of duty credit entitlement and must be valid on the date on which actual debit of duty is made.

2.12.4 Similarly, where the date of expiry of either original or extended export obligation period falls before the last day of the month, such export obligation period shall be deemed to be valid until the last day of the month. The original validity of export licence for restricted items shall be 12 months from the date of issuance unless otherwise specified.

Revalidation of Import/Export Licence/Certificate/Authorisation/Permissions

2.13 The licence/certificate/Authorisation/permission may be revalidated on merits by the Regional Authority concerned, which has issued the licence/

certificate/Authorisation/permission, for a period of six months reckoned from the date of expiry of the validity period.

2.13.1 However, revalidation of freely transferable licence/certificate/Authorisation/permissions and stock and sale licence/certificate/Authorisation/permission shall not be permitted unless the licence/certificate/Authorisation/permissions have expired while in custody of the Customs authority/Regional Authority.

2.13.2 In case the licence/certificate/Authorisation/permissions expires in the custody of the concerned Regional Authority, revalidation would be permitted under the specific orders of the Head of the Office for a period for which the Licence/Certificate/Authorisation/Permissions has remained in Custody with the concerned Regional Authority.

2.13.3 Notwithstanding the provisions of para 2.13 and in cases covered under paras 2.13.1 and 2.13.2 above, the revalidation would be for a period for which the Licence/Certificate/Authorisation/Permissions remains in the custody of the Customers of Regional Authority.

An application for revalidation, including application for revalidation of licence for import of restricted items, may be made to the Regional Authority concerned in the 'Aayaat Niryaat Form'. The Regional Authority would consider the application for revalidation of restricted list licence as per the Government rules/notifications governing the import of the items mentioned in the licence existing as on date of request for revalidation. However, in such cases where revalidation of the licence/certificate/Authorisation/permissions is to be considered by DGFT, the original application along with Treasury Receipt (TR)/Demand Draft shall be submitted to the Regional Authorities concerned and self attested copy of the same shall be submitted to DGFT.

Duplicate Copies of Export-Import Licence/Certificate/Authorisation/Permissions/CCPs

2.14 Where a licence/certificate/Authorisation/permission or an actual user duty credit certificate is lost or misplaced, an application for grant of a duplicate copy thereof may be made along with a copy of an affidavit, as given in Appendix-24, to the Regional Authority which has issued the original licence/certificate/Authorisation/permission.

The Regional Authority concerned may, or merits, issue a duplicate copy of the same after issuing an order for cancellation of the original licence/certificate/Authorisation/permission and after informing the customs authority where the original licence/certificate/Authorisation/permission was registered.

2.15 Duplicate copy of freely transferable licence/certificate/Authorisation/permissions, may be issued

against an application accompanied by the following documents :

- (a) An application with a fee equivalent to 10% of duty saved or duty credit.
- (b) A copy of FIR reporting the loss.
- (c) A copy of the original affidavit on notorised stamp paper.
- (d) Indemnity bond on a stamp paper undertaking to indemnify the revenue loss to the Government which may be caused on account of issue of duplicate licenses covering the duty saved/duty credit amount.

2.15.1 However, when the licence/certificate/Authorisation/permissions has been lost by the Government agency and a proof to this effect is submitted, the documents at serial Nos. (a) to (d) shall not be asked for.

In such cases, licence/certificate/Authorisation/permission shall be revalidated for a period for six months from the date of endorsement, notwithstanding anything stated below.

2.15.2 The Regional Authority, before issuing the licences/certificate/Authorisation/permission, shall obtain the report regarding utilization of the licence/certificate/Authorisation/permissions from the Custom authority at the port of registration mentioned in the original licence/certificate/Authorisation/permission.

The duplicate licence/certificate/Authorisation/permission shall be issued only for the balance, which remained unutilized as per the report furnished by the Customs authority at the port of registration.

2.15.3 The validity of duplicate licence/certificate/Authorisation/permission shall be co-terminus with the original licence and therefore no request shall be entertained if the validity of the original licence/certificate/Authorisation/permission has expired.

However, in case when DEPB/DFRC, Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana scrips/DFCE issued under Served from India/scrips issued under Focus Market scheme/scrips issued under Focus Product scheme/Transferable DFIA is lost by Customs/Regional Authority, duplicate licence/certificate/Authorisation/permission shall be issued for a validity of six months.

However, in the case of loss of DEPB/Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana scrips/DFCE issued under Served from India/scrips issued under Focus Market scheme/scrips issued under Focus Product scheme/Transferable DFIA not involving either the Customs or the Regional Authorities, the duplicate issued would have a validity equivalent to the balance period of validity of the original on the date of application for the duplicate.

2.15.4 The 10% duty saved as given in para 2.15(a) is applicable for DFRC/Transferable DFIA and would be

the duty saved amount for the balance quantity and proportionate CIF value as per information available in serial No. 6 of Sub-section V of 'Aayaat Niryaat Form'. However in case of duty credit certificates such as DEPB, Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana scrips/DFCE issued under Served from India/scrips issued under Focus Market scheme/scrips issued under Focus Product scheme/Transferable DFIA 10% duty credit as given in para 2.15(a) will be equivalent to 10% of the available credit balance on the lost duty credit certificate.

2.15.5 The provision of paragraphs 2.15.1 and 2.15.3 shall be applicable both for cases covered under paragraphs 2.14 and 2.15.

Identity Cards

2.16 To facilitate collection of licence/certificate/Authorisation/permissions and other documents from DGFT Headquarters and Regional Authorities, identity cards may be issued to the proprietor/partners/directors and the authorised employees (not more than three), of the importers and exporters.

However in case of limited companies, the Head of the Regional Office may approve the allotment of more than three identity cards per company. An application for issuance of an Identity Card may be made in the form given in Appendix 20A.

The documents/licence/certificate/Authorisation/permissions may be delivered to the identity card holder and the officials of the DGFT shall not be responsible for any loss etc. of the documents/licence/certificate/Authorisation/permissions thereafter.

In case of loss of an identity card, a duplicate card may be issued on the basis of an affidavit. The identity card shall be issued in the format as given in Appendix-20B and shall be valid for a period of three years from the date of issuance.

In the normal circumstances, one authorized employee is allotted one identity card pertaining to the company he represents. However, to take care of cases like common directors/partners, group company or any other similar issues, Head of the Regional Office may issue multiple identity cards to authorized employee after recording the reasons in writing.

Interviews with authorised Officers

2.17 Importer/Exporter and their employees shall have free access to the offices of the Regional authorities and to the officers authorised to grant interviews. Such officers may also grant interview at their discretion to authorised representative of the importer/exporter for making specific representation. Interviews/clarifications may also be sought through E-mails with the officer concerned.

Export of Items Reserved for SSI Sector

2.18 Units other than small scale units are permitted to expand or create new capacities in respect of items reserved for the small scale sector, subject to the condition

that they obtain an Industrial licence under the Industries (Development and Regulation), Act, 1951.

It is a condition of such licence that the manufacturer shall undertake export obligation as may be specified by the Ministry of Industry and the licensee is required to furnish a Legal Undertaking to the Directorate General of Foreign Trade in this behalf. The Directorate General of Foreign Trade shall monitor the export obligation.

Warehousing Facility

2.19 Public/Private Customs Bonded Warehouses may be set up in Domestic Tariff Area by following the procedure envisaged in Chapter-IX of the Customs Act, 1962. Such warehouses shall be permitted to import the items in terms of paragraph 2.28 of the Policy.

On receipt of goods, such warehouses shall keep the goods for a period of one year without payment of applicable customs duties. Goods can be cleared against the Bill of Entry for home consumption, on payment of applicable custom duty and on submission of licence/certificate/Authorisation/permission wherever required, provided the competent customs authorities have made an order for clearance of such goods for home consumption.

In case of clearance against duty free categories/concessional duty categories, exemption/concession from duty, as the case may be, allowed.

In case of clearance against DEPB, customs duty on imports may be adjusted against DEPB credit.

The goods can be re-exported without payment of customs duty provided (i) a shipping bill or a bill of export is presented in respect of such goods; and (ii) order for export of such goods has been made by competent customs authorities.

Import, storage, clearance or re-export are subject to the provisions of the Customs Act, 1962 and the Rules, Orders, Notifications or Instructions issued in respect of these provisions.

Execution of Bank Guarantee/Legal Undertaking for Advance Authorisation/DFIA and EPCG Authorisation

2.20 In cases of direct import before clearance of goods through customs, the licence/Authorisation holder shall execute a legal undertaking (LUT)/Bank Guarantee (BG) with the customs authorities in the manner as prescribed by them.

For cases of direct imports, the Regional Authority shall endorse the following condition on the licence/Authorisation :

"Bank Guarantee/LUT as applicable to be executed as per relevant Customs Notification/Circular"

However, in case of indigenous sourcing, the licence/certificate/Authorisation/permission holder shall furnish Bank Guarantee/LUT to the Regional Authority as

prescribed below before sourcing the material from the nominated agencies or indigenous supplier :—

Sl. No.	Category of Exporter	Relevant provisions of Bank Guarantee/LUT
1	2	3
1.	All Status holders (both merchandise exporter and service providers)/Public Sector Undertaking (PSUs).	Legal Undertaking (LUT).
2.	Manufacturer exporter (except Proprietorship and Partnership firms) (a) Registered with Central Excise authority and (b) Having a minimum export turn-over of Rs. 1 Crore and above in the preceding year, and (c) Having exported during the previous two financial years.	Legal Undertaking (LUT).
3.	Manufacturer Exporter (a) Registered with Central Excise Authority and (b) Having paid Central Excise Duty of Rs. 1 Crore or more during the preceding financial year. The exporter must submit a Certificate issued by Jurisdictional Superintendent of Central Excise where the factory is located validating clause (b) above.	Legal Undertaking (LUT).
4.	All exporters (a) having an export turnover of at least Rupees 5 crore in the preceding licensing year and (b) have a good track record and three years of export performance	Legal Undertaking (LUT).
5.	Other Manufacturer Exporter not covered under 1, 2, 3 and 4 above (except Proprietorships and Partnership firms)	Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 15% of duty saved on excise and education cess, if applicable.

1	2	3	1	2	3
	(a) exporting for last 3 years, or (b) exporting in any of the last 3 years and satisfying the following conditions: Registered with Excise Authorities, OR Registered with State Sales Tax Authorities; shall be required to furnish: (i) A Central Excise certificate certifying preceding years exports as per Customs Circular No. 74/2003 dated 21-8-2003, and (ii) Registration Certificate and Excise Control Code (E.C.C.) Number issued by Central Excise Authorities or Registration Certificate issued by State Sales Tax Authorities, as the case may be. This provision is not required for category (a) above.		(iii) The company furnishes copy of their audited balance sheet, and the minimum investment in plant and machinery must be Rs. 50 Lakhs.		
			7. Merchant Exporter, all types of Proprietorship and Partnership firms (Other than Status Holders/PSU and category 4 above)		Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved on excise and education cess, if applicable.
			8. Service providers other than those in category land 4 above.		Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved on excise and education cess, if applicable.
			However, Manufacturer/Merchant Exporters falling under any of the following two categories based on risk profile of the exporter are required to execute bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved amount on excise and education cess if applicable. This can be prescribed by the Head of the office not being below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade by recording the reasons in writing.		
			(a) Have come under the adverse notice of Customs/DGFT/Central Excise for serious irregularities;		
			(b) Having adverse track record in terms of fulfillment of pending export obligation.		
			In cases where the Excise Duty is nil on the items of indigenous procurement, the Bank Guarantee furnished would be for 25 % of the basic Customs Duty on the same product. The Bank Guarantee and LUT should be valid as per the terms and conditions incorporated in the Appendix-25A & 25B respectively. The validity of the Bank Guarantee/LUT is required to be extended in case of extension in export obligation period. Specific endorsement to this effect shall be made in the licence/Authorisation by the Regional Authority.		
			In respect of categories 3, 4 & 5 above, if the exporter has not exported for all the 3 preceding years, 15% Bank Guarantee condition shall be imposed on the duty saved amount provided the CIF value does not exceed 200% of the domestic turnover or 200% FOB/FOR value of supplies of the preceding licensing year, whichever is higher. Licence/Authorisation beyond 200% entitlement shall be subject to 100 % BG on the duty saved amount for the CIF value exceeding 200% entitlement. However the entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing fulfillment of export obligation and		
	6. Manufacturing companies (as distinguished from Proprietorship and Partnership firm, who may also be manufacturers) having not exported in each of the preceding three licensing years but fulfilled the following criterion :	Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 15% of duty saved on excise duty and education cess, if applicable.			
	(i) The company is registered with Central Excise Authorities and has paid Central Excise duty (unless exempted); and (ii) The company is registered with State Sales Tax Authorities and has paid sales tax (unless exempted); and				

realization of export/supply proceed. In respect of categories at S. No. 2 and 4, the licensee/ Authorisation holder would be required to submitted the Export Performance Certificate issued by a chartered accountant as per Appendix 26.

However, for import/domestic procurement of car under EPCG scheme. 100 % Bank Guarantee will be required to be furnished except in case of status holders/PSUs who will furnish Bank Guarantee/LUT as per aforesaid conditions.

Bank Guarantee exemption/relaxation as mentioned above shall also be available in respect of past licences/ Authorisations where licence/Authorisation holder had earlier filed Bank Guarantee but as on date the licence/ Authorisation holder is entitled for Bank Guarantee exemption.

In case, the firm has already executed BG/LUT for the full Value of the licence/certificate/Authorisation/ permission covering the items indigenously procured, to the Customs and furnished proof of the same, no BG/ LUT shall be required to be executed with the Regional Authority.

Corporate Guarantee.

2.20.1 A Status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of Bank Guarantee/LUT in terms of the provisions of relevant Customs Circular in this regard. In case of a Group company, if one company of a Group is a status holder, Corporate Guarantee may be given for another company by this company, which is not a status holder.

Certificate of Origin

2.21.1 Certificate of Origin is the instrument to establish evidence on the origin of goods imported into any country. There are two categories of Certificate of Origin viz. (1) Preferential and (2) Non preferential.

Preferential

2.21.1 The preferential arrangement/Schemes under which India is receiving tariff preferences for its exports are Generalised System of Preferences (GSP), Global System of Trade Preferences (GSTP), SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA), Bangkok Agreement, India—Sri Lanka—Free Trade Agreement (ISLFTA) and Indo-Thailand Free Trade Agreement. These arrangements/agreements prescribe Rules of origin which have to be fulfilled for the exports to be eligible for the tariff preference. The authorised agencies shall provide services relating to issuance of certificate of origin, including details regarding the rules of origin, list of items covered by an agreement, extent of tariff preference, verification and certification of eligibility etc. Export Inspection Council (EIC) is the sole agency authorised to print blank certificates. The authorised agencies may charge a fee, as approved by Ministry of Commerce and Industry, for the services rendered.

Generalised System of Preferences (GSP)

(a) GSP is a non by contractual instrument by which industrialized (developed) countries unilaterally and on the basis of non reciprocity extend tariff concessions developing countries. The following countries extend tariff preferences under their GSP Scheme.

- (i) United States (ii) New Zealand (iii) Belarus
- (iv) Eyriocab Union (v) Japan (vi) Russia
- (vii) Canada (viii) Norway (ix) Australia
- (only to LDCs)
- (x) Switzerland
- (xi) Bulgaria

GSP Schemes of these countries details the sectors/ products and tariff lines under which these benefits are available, besides the conditions and the procedures governing the benefits. These schemes are renewed and modified from time to time Normally the customs of GSP offering countries require information in Form 'A' (prescribed for GSP Rules of Origin) duly filled by the exporters of the beneficiary countries and certified by authorised agency. List of agencies authorised to issue GSP certificate of Origin is given in Appendix-4A.

Global Systems of Trade Preference (GSTP)

(b) Under the agreement establishing Global System of Trade Preference (GSTP) tariff concessions are exchanged among developing countries, who have signed the agreement. Presently, there are 46 members countries of GSTP and India has exchanged tariff concessions with 12 countries on a limited number of products. Export Inspection Council (EIC) is the sole agency authorised to issue Certificate of Origin under GSTP.

SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA)

(c) The Agreement establishing SAPTA was signed by seven SAARC members namely India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives in 1993 and came into operation in 1995. Four rounds of trade negotiations have been completed and more than 3000 tariff lines are under tariff concessions among the SAARC countries. The list of agencies, which are authorised to issue Certificate of Origin under SAPTA are notified under Appendix—4B.

Bangkok Agreement

(d) The Bangkok agreement is a preferential trading arrangement designed to liberalise and expand trade in goods progressively in the Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) region through liberalization of tariff and non tariff barriers. At present, Bangladesh, Sri Lanka, South Korea, Indian and China are exchanging tariff concessions. The agencies authorised to issue Certificate of Origin under Bangkok agreement are listed in Appendix—4B.

India-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISLFTA)

(e) A Free Trade Agreement (FTA) between India and Sri Lanka was signed on 20th December, 1998. The agreement was operationalised in March, 2000 following notification of the required Customs tariff concessions by the Government of Sri Lanka and India in February, and March, 2000 respectively. Export Inspection Council is the sole agency to issue the Certificate of Origin under ISLFTA.

India Afghanistan Preferential Trade Agreement

(f) A Preferential Trade Agreement between the Transitional Islamic State of Afghanistan and Republic of India was signed on 6th March, 2003 and was operationalised with the issuance of the Customs Notification No. 76/2003 dated 13th May, 2003. Export Inspection Council is the sole agency to issue the Certificate of Origin under India Afghanistan Preferential Trade Agreement.

Indo-Thailand Framework Agreement for Free Trade Area

(g) India and Thailand have signed the protocol to implement Early Harvest Scheme under India-Thailand Free Trade Agreement on 1st September, 2004. The tariff preferences for imports on the items of Early Harvest Scheme would be available only to those products, which satisfy the Rules of Origin Criteria, which have been notified by Department of Revenue, Ministry of Finance, vide notification No. 101/2004-Customs dated 31st August 2004. Export Inspection Council of India would be the sole agency to issue the Certificate of Origin under the Early Harvest Scheme of the Framework Agreement on the India-Thailand Free Trade Agreement.

Non-Preferential

2.21.2. The Government has also nominated certain authorised agencies to issue Non-Preferential Certificate of Origin in accordance with Article II of International Convention Relating to Simplification of customs formalities, 1923. These Certificates of Origin evidence the origin of goods and do not bestow any right to preferential tariffs. The list of these agencies is provided in Appendix—4C.

All the exporters who are required to submit Certificate of Origin (Non Preferential) would have to apply to any of the agencies enlisted in Appendix-4C with the following documents :

- (a) Details of quantum/origin of the inputs/consumable used in the export product.
- (b) Two copies of invoices.
- (c) Packing list in duplicate for the concerned invoice.
- (d) Fee not exceeding Rs. 100 per certificate as may be prescribed by the concerned agency.

The agency would ensure that the goods are of Indian origin as per the general principles governing the rules of origin before granting the Certificate of Origin (non preferential). The Certificate would be issued as per the Format

of Certificate of Origin (Non Preferential) given in Annexure-II to Appendix-4C. I should be ensured that no correction/re-type is made on the certificate.

Any of the agencies desirous of enlistment in Appendix-4C may submit their application as per Annexure I to Appendix 4C to the concerned Regional Authority under whose Jurisdiction the applicant falls as given in Appendix 1.

In case of tea, all exporters who are required to submit Certificate of Origin (Non-Preferential) shall apply to the Tea Board or any Inspection Agency authorized by the Tea Board and enlisted in Appendix-4C of the Handbook of Procedures, (Vol. I) with the documents listed above.

Automatic Licence/Certificate/Authorisation/Permission

2.22 The status holders shall be issued licence/certificate/Authorisation/permissions automatically with the stipulated time period. Deficiency, if any, shall be informed in the covering letter which shall be required to be rectified by the status holders within 10 days from the date of communication of deficiency.

Submission of Certified Copies of Documents

2.23 Wherever the original documents have been submitted to a different Regional Authority/nominated agencies or to a different division of the same Regional Authority, the applicant can furnish photocopy of the documents duly certified by him in lieu of the original.

Advance Payment

2.24 In case, payment is received in advance and export/deemed exports takes place subsequently, the application for salience/certificate/Authorisation/permission shall be filed within specific period following the month during the which the exports/deemed exports are made, unless otherwise specified.

Payment through ECGC cover

2.25. In cases where the export has been completed but the payment has not been realised from the buyer, such exports shall be taken into account for the purpose of benefits under the Policy provided the payment has been realised by the Indian exporter through ECGC cover.

Payment through General Insurance

2.25.2 In cases where exports have been made and payment realized through the General Insurance Cover on account of transit loss or other circumstances, the amount of the instance cover paid would be treated as payment realized on account of exports under the various export promotion schemes.

Export by post

2.26 In case of export by post, the exporter shall submit the following documents in lieu of documents prescribed for export by sea/air.

- (1) Bank Certificate of Export and Realisation as given in Appendix-22A.
- (2) Relevant postal receipt.

- (3) Invoice duly attested by the Customs.

Import/Export through Courier Service

2.26.1 Imports/Exports through a registered courier service is permitted as per the Notification issued by the Department of Revenue. However, importability/exportability of such items shall be regulated in accordance with the Policy.

Direct negotiation of export documents

2.26.2 In cases where the exporter directly negotiates the document (not through the authorised dealer) with the permission of the RBI, he is required to submit the following documents for availing of the benefits under the export promotion schemes:

- Permission from RBI allowing direct negotiation of documents (however this is not required for status holders who have been granted a general permission),
- Copy of the Foreign Inward Remittance certificate (FIRC) as per Form 10-H of the Income Tax department in lieu of the BRC, and
- Statement giving details of the shipping bills/invoice against which the FIRC was issued.

Import/Export of Samples

2.27 No licence/certificate/Authorisation/permission shall be required for Imports of bonafide technical and trade samples of items mentioned as restricted in ITC(HS) except vegetable seeds, bees and new drugs by any importer. However, samples of tea not exceeding Rs. 2000 (CIF) in one consignment shall be allowed without a licence/certificate/Authorisation/permission by any person connected with Tea industry.

Duty free import of samples upto Rs. 60000 for all exporters barring those in the gems and jewellery sector and Rs. 300,000 for those in the gems and jewellery sector shall be allowed as per the terms and conditions of Customs notification.

Exports of bonafide trade and technical samples of freely exportable item shall be allowed without any limit.

Import under Lease Financing

2.28 Permission of the Regional Authority is not required for import of capital goods under lease financing. However, the condition of actual user or licence/certificate/Authorisation/permission, wherever required under the Policy or this Handbook, shall be applicable in case of import of capital goods under such lease financing.

The facility shall also be available under EPCG Scheme, Eou/SEZ scheme. The domestic supplier of capital goods to eligible categories of deemed exports shall be eligible for the benefits of deemed exports as given in paragraph 8.3 of the Policy even in such cases where the supplies are under lease financing.

Exhibits Required for National and international Exhibitions or Fairs and Demonstration

2.29 Import/export of exhibits, including construction and decorative materials required for the temporary

stands of the foreign/Indian exhibitors at the exhibitions, fair or similar show or display for a period of six months on re-export/re-import basis, shall be allowed without a licence/certificate/Authorisation/permission on submission of a certificate from an officer of a rank not below that of an Under Secretary/Deputy Director General of Foreign Trade to the Government of India in the Department of Commerce/Directorate General of Foreign Trade or an officer of the Indian Trade Promotion Organization duly authorised by its Chairman in this behalf, to the effect that such exhibition, fair or similar show or display, as the case may be,

(i) has been approved or sponsored by the Government of India in the Department of Commerce or the India Trade Promotion Organization; and

(ii) is being held in public interest.

Extension beyond six months for re-export/re-import will be considered by the Customs Authorities on merits. Consumables such as paints, printed material, pamphlets, literature etc. pertaining to the exhibits need not be re-exported/re-imported.

Import Policy

2.30 The Policy relating to the general provisions regarding import of capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods is given in Chapter 2 of the Policy.

General Procedure for Licensing of Restricted Goods

2.31 Wherever an import licence/certificate/permission, including Customs Clearance Permit (CCP), is required under the Policy, the procedure contained in this chapter shall be applicable.

2.32 Import of Metallic Waste and Scrap

2.32.1 Import of any form of metallic waste, scrap will be subject to the condition that it will not contain hazardous, toxic waste, radioactive contaminated waste/scrap containing radioactive material, any type of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge or any other explosive material in any form either used or otherwise.

2.32.2 Import of the following types of metallic waste and scrap will be free subject to certain conditions detailed below :

Sl. No.	Exim Code	Item description
1	2	3
1.	72041000	Waste and scrap of cast iron
2.	72042190	Other
3.	72042920	Of High speed steel
4.	72042990	Other
5.	72043000	Waste and scrap of tinned iron or steel
6.	72044100	Turnings, shavings, chips, milling waste, saw dust, fillings, trimmings and stampings, whether or not in bundles

1	2	3
7.	72044900	Other
8.	72045000	Remelting scrap ingots
9.	74040010	Copper scrap
10.	74040022	Brass scrap
11.	75030010	Nickel scrap
12.	76020010	Aluminium scrap
13.	79020010	Zinc Scrap
14.	80020010	Tin scrap
15.	81042010	Magnesium scrap

Shredded form : Import of metallic waste and scrap listed in para 2.32.2 above in shredded form shall be permitted through all ports of India. Import from Hodaideh, Yemen and Bandar Abbas, Iran will be in shredded form only.

Unshredded compressed and loose form : Import of metallic waste, scrap listed in para 2.32.2 above in unshredded compressed and loose form shall be subject to the following conditions :

- Import will be allowed only from overseas suppliers who are registered with the Directorate General of Foreign Trade and are listed under Appendix-5B of the Handbook of Procedures. Registration will be required only for those suppliers that directly contract with suppliers located in India.
- All applications will be filed in Appendix—5A of the Handbook of Procedures, Vol. I along with supporting documents (wherever required). The details are available on the DGFT website.
- there will be no application fee for registration.
- The initial registration will be for a period of two years.
- Only direct imports from registered suppliers against letter of credit will be allowed. No high seas sale would be allowed.
- Import of scrap would take place only through the following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs :—

"1. Chennai, 2. Cochin, 3. Ennore, 4. JNPT, 5. Kandla, 6. Mormugao, 7. Mumbai, 8. New Mangalore, 9. Paradip, 10. Tuticorin, 11. Vishakhapatnam, 12. ICD Tughlakabad (New Delhi), 13. Pipava, 14. Mundra, 15. Kolkata, 16. ICD Ludhiana, 17. ICD Dadri (Greater Noida), 18. ICD Nagpur, 19. ICD Jodhpur, 20. ICD Jaipur, 21. ICD Udaipur, 22. CFS Mulund, 23. ICD Kanpur, 24. ICD Ahmedabad, 25. ICD Pitampur and 26. ICD Milanpur".

- In case of any violation, the overseas supplier would be de-registered. Action will also be taken against the Indian firm which is importing the scrap under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992.

The last date for filing the applications will be 30th April, 2006. Applications can be sent by e-mail, courier, or in person to the Directorate General of Foreign Trade, H-wing, Udyog Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011.

The new system of import from registered sources will come into effect from 1st April, 2006. However, upto 30th June, 2006 imports will also be allowed on the basis of the pre-shipment inspection certificate regime in terms of Para 2.32 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), notified vide Public Notice No. 1 dated 8th April, 2005 and as amended from time to time.

2.32.3. However, import of other kinds of metallic waste and scrap will be allowed in terms of the conditions of the ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2004—2009.

2.32.4 The import policy for seconds and defective, rags, PET bottles/waste, and ships is given in the ITC(HS) Classification of Export and Import items, 2004—2009.

Import of Second Hand Capital Goods

2.33 Import of second hand capital goods including refurbished/reconditioned spares, shall be allowed freely, subject to conditions for the following categories :

The Import of second hand computers including personal computers and laptops are restricted for imports.

The import of refurbished/reconditioned spares will be allowed on production of a Charter Engineer certificate that such spares have a residual life not less than 80% of the life of the original spare.

2.33.1 Notwithstanding the provisions of Para 2.33 above, second hand computers, laptops and computer peripherals including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage units can be imported freely as donations by the following category of donees :

- School run by Central or State Government or a local body
- Educational Institution run on non-commercial basis by any organization
- Registered Charitable Hospital
- Public Library
- Public funded Research and Development Establishment
- Community Information Centre run by the Central or State Government or local bodies.

- (vii) Adult Education Centre run by the Central or State Government of a local body.
- (viii) Organization of the Central or State Government or a Union Territory.

The imports under this sub para would be subject to the condition that the goods shall not be used for any commercial purpose, is non-transferable and complies with all the terms and conditions of the relevant Customs Rules and Regulations.

2.33A Customs or any other Central or State Government authority may avail of the services of the Inspection and Certification Agencies in Appendix 5 of the Handbook, for certifying both the residual life as well as the valuation/purchase price of the capital good.

Import of Ammunition by Licensed Arms Dealers

2.34 Import of following types of ammunition are allowed against a licence/certificate/permission by licensed arms dealers subject to the conditions as may be specified :

- (i) Shotgun Cartridges 28 bore;
- (ii) Revolver Cartridges of .450, .455 and .45 bores;
- (iii) Pistol Cartridges of .25, .30 Mauser, .450 and .45 bores;
- (iv) Rifle Cartridges of 6.5 mm, .22 savage, .22 Hornet, 300 Sherwood, 32/40, .256, .275, .280, 7 m/m Mauser, 7 m/m Man Schoener, 9 m/m Mauser, 9 m/m Man Schoener, 8×57, 8×57S, 9.3 m/m, 9.5 m/m, .375 Magnum, .405, .30.06, .270, .30/30 Winch, .318, .33 Winch, .275 Mag., .350 Mag., 400/350, .369 Pardey, .450/400, .470, .32 Win, .458 Win, .380 Rook, .220 Swift and .44 Win. bores.

An import licence/certificate/permission shall be issued at 5% of the value of the annual average sales turnover of ammunition (whether indigenous or imported) during the preceding three licensing years subject to a minimum of Rs. 2000.

An application for grant of a licence/certificate/permission for items listed above may be made to the Regional Authority in the 'Aayaat Niryaat Form' along with the documents prescribed therein.

Restricted Items Required by Hotels, Restaurants, Travel Agents, Tour Operators and Other Specified Categories.

2.35 Items mentioned as restricted for imports in ITC(HS) required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators may be allowed against a licence/certificate/permission. Import licence/certificate/permission shall be granted on the recommendation of the Director General, Tourism, Government of India.

2.35.1 Hotels, including tourist hotels, recognised by the Director General of Tourism, Government of India or a State Government shall be entitled to import licence/certificate/permissions upto a value of 25% of the foreign

exchange earned by them from foreign tourists during the preceding licensing year.

Such licence/certificate/permissions shall be granted for the import of essential goods related to the hotel and tourism industry.

2.35.2 Travel agents, tour operators, restaurants, and tourist transport operators and other units for tourism, like adventure/wildlife and convention units, recognized by the Director General of Tourism, Government of India, shall be entitled to import licence/certificate/permissions up to a value of 10% of the foreign exchange earned by them during the preceding licensing year.

Such licence/certificate/permissions shall be granted for the import of essential goods which are restricted for imports related to the travel and tourism industry, including office and other equipment required for their own professional use.

2.35.3 The import entitlement under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 of any one licensing year can be carried forward, either in full or in part, and added to the import entitlement of the two succeeding licensing years.

2.35.4 The import licence/certificate/permission granted under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 shall not be transferable. However, transferability of such licence/certificate/permission granted to hotels/restaurants/travel agents/tour operators may be allowed within their respective groups or to managed hotels as defined in Chapter 9 of Foreign Trade Policy.

2.35.5 The goods imported against such licence/certificate/permission shall not be transferred to anyone within a period of 2 years from the date of their import without the prior permission of the Directorate General of Foreign Trade.

No permission for transfer will be required in case the imported goods are re-exported. However the re-export shall be subject to all conditionality, or requirement of licence, or permission, as may be required under Schedule II of ITC (HS) Classification.

2.35.6 An application for grant of a licence/certificate/permission under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 may be made in the 'Aayaat Niryaat Form' to the Director General of Foreign Trade through Director of Tourism, Government of India who will forward the application to the Regional Authority concerned along with the recommendations on the import entitlement and the goods to be imported.

Import of Other Restricted Items

2.36 ITC (HS) contains the list of restricted items. An application for import of such items may be made, in the 'Aayaat Niryaat Form' along with the documents prescribed therein. Original application along with Treasury Receipt (TR)/Demand Draft shall be submitted to the regional authority concerned and self- attested copy of the same shall be submitted to DGFT in Duplicate along

with proof of submission of the application to concerned Regional Authority.

EXIM Facilitation Committee

2.37 Restricted item licence/certificate/permission may be granted by the Director General of Foreign Trade or any other Regional Authority authorised by him in this behalf. The DGFT/Regional Authority may take the assistance and advice of a Facilitation Committee.

The Facilitation Committee will consist of representatives of Technical Authorities and Departments/Ministries concerned.

Gifts of Consumer or Other Goods

2.38 In terms of the provisions contained in paragraph 2.19 of the Policy, an application for grant of Customs clearance Permit for import as gifts of items appearing as restricted for imports in ITC(HS) shall be made to the Director General of Foreign Trade in the form given 'Aayaat Niryaat Form' along with documents prescribed therein.

However, where the recipient of a gift is a charitable, religious or an educational institution registered under a law relating to the registration of societies or trusts or otherwise approved by the Central or a State Government and the gift sought to be imported has been exempted from payment of customs duty by the Ministry of Finance, such import shall be allowed by the customs authorities without a Customs Clearance Permit.

Import under Government to Government Agreements

2.39 Import of goods under Government to Government agreements may be allowed without a licence/certificate/permission or Customs Clearance Permit on production of necessary evidence to the satisfaction of the Customs authorities.

Import of Cheque Books/Ticket Forms etc.

2.40 Indian branches of foreign banks, insurance companies and travel agencies may import cheque books, bank draft forms and traveller cheque forms without a Customs Clearance Permit. Similarly, airlines/shipping companies operating in India, including persons authorised by such airlines/shipping companies may import passenger ticket forms without a Customs Clearance Permit.

Import of Reconditioned/Second Hand Aircraft Spares

2.41 Air India, Indian Airlines, Vayudoot, Pawan Hans Ltd. and scheduled domestic private airlines, private sector/public sector companies and State Governments operating executive/training aircraft or those engaged in the aerial spraying of crops and non scheduled airlines and charter service operators will be eligible to import, without a licence/certificate/permission, reconditioned/second hand aircraft spares on the recommendation of the Director General of Civil Aviation, Government of India.

Foreign airlines shall also be eligible to import without a licence/certificate/permission, reconditioned/second

hand aircraft spares on the recommendation of the Director General of Civil Aviation, Government of India.

Import of Replacement Goods

2.42 Goods or parts thereof on being imported and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged after import may be exported without a licence/certificate/Authorisation/permission, and goods in replacement thereof may be supplied free of charge by the foreign suppliers or imported against a marine insurance or marine-cum-erection insurance claim settled by an insurance company. Such goods shall be allowed clearance by the customs authorities without an import licence/certificate/Authorisation/permission provided that :

(a) The shipment of replacement goods is made within 24 months from the date of clearance of the previously imported goods, through the Customs or within the guarantee period in the case of machines or parts thereof where such period is more than 24 months; and

(b) No remittance shall be allowed except for payment of insurance and freight charges where the replacement of goods by foreign suppliers is subject to payment of insurance and/or freight by the importer and documentary evidence to this effect is produced at the time of making the remittance.

The importer shall also have the option to claim refund of payment, if any, already made to the foreign supplier, instead of obtaining replacement of goods referred to above.

2.42.1 In such cases where the goods have been found short-shipped, short-landed or lost in transit prior to actual import and/or detected as such at the time of customs clearance, import of replacement goods will be permitted on the strength of the certificate issued by the customs authorities without an import licence/certificate/Authorisation/permission.

This procedure shall also apply to cases in which short-shipment of goods is certified by the foreign supplier and he has agreed to replace the goods free of cost.

2.42.2 Cases not covered by the above provisions will be considered on merits by the DGFT for grant of licence/certificate/Authorisation/permissions for replacement of goods for which and application may be made in the 'Aayaat Niryaat Form'.

Transfer of Imported Goods

2.43 Goods, which are importable without restriction, can be transferred by sale or otherwise by the importer freely. Transfer of imported goods, which are subject to Actual User condition under the Policy and have become surplus to the needs of the Actual User, shall be made only with the prior permission of the Regional Authority concerned. The following information along with supporting documents shall be furnished with the request

for grant of permission for transfer, to the Regional Authority concerned :

- (i) Reasons for transfer of imported material;
- (ii) Name, address, IEC number and industrial licence/certificate/Authorisation/permission/registration, if any, of the transferee;
- (iii) Description, quantity and value of the goods imported and those sought to be transferred;
- (iv) Copies of import licence/certificate/Authorisation/permission and bills of entry relating to the imports made;
- (v) Terms and conditions of the transfer as agreed upon between buyer and the seller.

2.43.1 Prior permission of the Regional Authority shall not, however, be necessary for transfer or disposal of goods, which were imported with Actual User condition provided such goods are freely importable without Actual User condition on the date of transfer.

2.43.2 Prior permission of the Regional Authority shall also not be required for transfer or disposal of imported goods after a period of two years from the date of import. However, transfer of imported firearms by the importer/ licensee/ Authorisation holder shall be permitted only after 10 years of the date of import with the approval of the DGFT.

Sale of Exhibits

- 2.44 (i) Sale of exhibits of restricted items, mentioned in ITC(HS), imported for an international exhibition/fair organised/approved/sponsored by the India Trade Promotion Organisation (ITPO) may also be made, without a licence/certificate/Authorisation/permission, within the bond period allowed for re-export, on payment of the applicable customs duties, subject to a ceiling limit of Rs. 5 lakhs (CI) for such exhibits for each exhibitor.

However, sale of exhibits of items, which were freely imported shall be made, without a licence/certificate/Authorisation/permission, within the bond period allowed for re-export on payment of applicable customs duties.

- (ii) If goods brought for exhibition are not re-exported or sold within the bond period due to circumstances beyond the control of the importer, the customs authorities may allow extension of the beyond period on merits.

Import of Overseas Office Equipment

2.45 On the winding up of overseas offices, set up with the approval of the Reserve Bank of India, used office equipment and other items may be imported without a licence/certificate/permission.

Labels, Price Tags and like Articles for Export Products

2.46 Supplies, made by foreign buyers or procured by the exporters on the advice of foreign buyers, of labels,

price tags, hangers sizes, PVC boxes, inlay cards, printed bags, stickers and trimming material like buttons, belts shoulder pads, buckles, eyelets, hooks and eyes and rivets to be attached to the goods against specific orders placed by foreign buyers on Indian exporters, may be imported without a licence/certificate/Authorisation/permission.

Prototypes

2.47 Import of new/second hand prototypes/second hand samples may be allowed on payment of duty without a licence/certificate/Authorisation/permission to an Actual user (industrial) engaged in the production of or having industrial licence/letter of intent for research in the item for which prototype is sought for product development or research, as the case may be, upon a self-declaration to that effect, to the satisfaction of the Customs Authorities.

Restricted items for R&D

2.48 All restricted items and items permitted to be imported by State Trading Enterprises (STEs), except live animals, required for R&D purpose may be imported without a licence/certificate/Authorisation/permission by Government recognised Research and Development units.

Export Policy

2.49 The policy relating to Exports is given in Chapter-2 of the Policy. Further, Schedule 2, Appendix-1 of the ITC (HS) specifies the list of items which may be exported without a licence/certificate/Authorisation/permission but subject to terms and conditions specified in this behalf.

Application for Grant of Export Licence/Certificate/Permission

2.50 An application for grant of Export licence/certificate/permission in respect of items mentioned in Schedule 2 of ITC(HS) may be made in the "Aayaat Niryaat Form", to the Director General of Foreign Trade and shall be accompanied by the documents prescribed therein. The Foreign Trade Facilitation Committee shall consider applications on merits for issue of export licence/certificate/permissions.

An Inter-Ministerial Working Group in DGFT shall consider applications for export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and technologies (SCOMET) as specified in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC(HS) on the basis of guidelines given below.

Applications for licences to export items or technology on the SCOMET List are considered case-by-case, based inter alia on the following general criteria :—

I. The following factors, among others, are taken into account in the evaluation of applications for export of items on the SCOMET List :

- a. Credentials of the end-user, credibility of declarations of end-use of the item or technology, the integrity of the chain of transmission of the item from the supplier to the end-user, and on the potential of the item or technology, including the timing of its

- export, to contribute to end users that are not in conformity with India's national security or foreign policy goals and objectives, the objectives of global non-proliferation, or its obligations under treaties to which it is a State party.
- b. The assessed risk that the exported items will fall into the hands of terrorist groups, and non-State actors;
 - c. Export control measures instituted by the recipient State;
 - d. The capabilities and objectives of the programmes of the recipient State relating to weapons and their delivery;
 - e. The assessment of the end-uses of the item(s);
 - f. The applicability to an export licence application of relevant bilateral or multilateral agreements to which India is a party.
- II. A condition for the consideration of an application for an export licence is the submission of stipulated certifications to the effect, inter alia, that :
- a. The item will be used only for the purpose stated and that such use will not be changed, nor the items modified or replicated without the consent of the Government of India;
 - b. Neither the items nor derivatives thereof will re-transferred without the consent of the Government of India;
 - c. The end-user shall facilitate such verifications as are required by the Government of India.
- The Government of India may also require additional formal assurances, as appropriate, including on end-use and non-retransfer, from the State of the recipient.
- III. The Regional Authority for items in Category below is the Department of Atomic Energy. The applicable guidelines are notified by that Department under the Atomic Energy Act, 1962. For certain items in category 0, formal assurances from the recipient State will include non-use in any nuclear explosive device. Licences for export of certain items in category 0 will not be granted unless the transfer is additionally under adequate physical protection and is covered by appropriate International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, or any other mutually agreed controls on transferred items.
- IV. Additional end-use conditions may be stipulated in licences for the export of items or technology that bear the possibility of diversion to or use in the development or

manufacture of, or use as, systems capable of delivery of weapons of mass destruction.

- V. Applications for the transfer of "Technology" for any item on the List will be considered as an application for the export of the item itself.
- VI. Licences for the export of items in this List (other than those under Categories 0, 1 and 2) solely for the purposes of display or exhibition shall not require any end-use or end-user certifications. (No export licence for display or exhibition shall be issued for "Technology" in any category. No licence for display or exhibition shall be issued for items under Categories 0, 1 and 2.).
- VII. Export of items not on the SCOMET List may also be regulated under the provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery System (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005.

Note 1 : Export or attempt to export in violation of any of the conditions of licence shall invite civil and/or criminal prosecution.

Note 2 : Licences for export of items in this List for display or exhibition abroad are subject to a condition of re-import within a period not exceeding six months. Exporters are entitled to apply for an export licence for such items exhibited abroad if the exhibitor intends to offer that item for sale during the exhibition abroad. Such sale shall not take place without a valid licence.

Note 3 : The export of items in Category 2 of this list may also be controlled by other applicable guidelines issued from time to time. Exporters of items in this category are advised to seek guidance from the DGFT.

Note 4 : Exporters are entitled to apply for a "destination licence" for countries and/or groupings of countries for export to which only re-transfer conditions need be imposed.

Note 5 : Exporters are entitled to request that only such conditions need be imposed as are the subject of Government to Government instruments of accord over export of items on the SCOMET List.

Note 6 : "Technology" (see also entry "Technology" in the glossary in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC(HS)). The approval of export of an item on the SCOMET List also authorizes the export to the same end-user of the minimum "technology" required for the installation, operation, maintenance and repair of the item.

DGFT in association with the Administrative Ministries/Departments and the Trade

Associations will organize Industry Outreach Programme on regular basis for an effective awareness among the exporters/importers dealing with the trade in particular, in SCOMET items.

DGFT may also issue, on application, Free Sale and Commerce Certificate for export of items not covered under Drugs & Cosmetics Act, 1940, which have usage in hospitals, nursing homes and clinics, etc. for medical and surgical purposes and are not prohibited for export. The validity of such certificate shall be two years from the date of issue unless otherwise specified.

Export of Items under State Trading Regime (STR)

2.51 An application for export of items mentioned in ITC(HS) under STR regime may be made to the Director General of Foreign Trade.

Exports of Samples/Exhibits

2.52 An application for the export of samples or exhibits, which are restricted for export, may be made to the Director General of Foreign Trade.

Free of Cost Exports

2.52.1 The status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rs. 10 lakh or 2% of the average annual export realisation during the preceding three licensing years whichever is higher.

Gift/Spares/Replacement Goods

2.53 For export of gifts, indigenous/imported warranty spares and replacement goods in excess of the ceiling/period prescribed in paragraphs 2.32, 2.33 and 2.37 respectively of the Policy, an application may be made to the Director General of Foreign Trade.

Furnishing of Returns in respect of Exports in non physical form

2.54 All the exports made in non physical form by using communication links including high speed data communication links, internet, telephone line or any other channel which do not involve the Customs authorities has to be compulsorily reported on quarterly basis to the Electronic and Software Export Promotion Council in the proforma given in Appendix-19C.

These provisions shall be applicable to all the exporting units located anywhere in the country including those located in STP, SEZ, EHTP and under 100% EOU scheme.

Duty Free Import of R&D Equipment for Pharmaceuticals and Bio-technology Sector

2.55 Duty free import of goods (as specified in the list 28 of Customs notification No. 21/2002 dated 1-3-2002, as amended from time to time) upto 25% of the FOB value of exports during the preceding licensing year, shall be

allowed to the manufacturer exporters having Research and Development wing which is registered with the Department of Scientific and Industrial Research in the Ministry of Science and Technology subject to fulfilment of condition number 53(ii) of the said notification.

The eligible unit may furnish an application given in Appendix-15A to the Regional Authorities under whose jurisdiction the registered office of company or head office of the firm is located.

The Regional Authority shall verify the application on the basis of the declaration given by the unit and countersigned by Chartered Accountant.

2.55.1 Duty free imports of goods as specified in list 28A of Customs notification No. 21/2002 dated 1-3-2002, (as amended from time to time) upto 1% of the FOB value of exports made during the preceding licensing year, shall be allowed to agro chemicals sector unit having export turnover of Rs. 20 crore or above during preceding licensing year. Such facility shall be available only to a manufacturer having a research and development wing registered with Department of Scientific and Industrial Research in Ministry of Science and Technology subject to fulfilment of condition No. 53A of the said notification.

The eligible unit shall apply in the form given in Appendix-15B to the Regional Authorities under whose jurisdiction the registered office of company or head office of the firm is located.

The Regional authority shall verify the application on the basis of the declaration given by the unit and countersigned by Chartered Accountant.

Conversion of E.P. copy of shipping bill from one scheme to another

2.56 If the Customs Authorities, after recording reasons in writing, permit conversion of an E.P. copy of any scheme shipping bill on which the benefit of that scheme has not been availed, the exporter would be entitled to the benefit under the scheme in which shipment is subsequently converted.

Relocation of Industries

2.57 Plant and machineries would be permitted for import without a license provided the depreciated value of such relocation plant exceeds Rs. 25 crore.

Offsetting of Export Proceeds

2.58 Subject to the specific approval of the Reserve Bank of India, any payables, or equity investment made by a licence/Authorisation holder under any export promotion scheme, can be used to offset receipts of his export proceeds. In such cases, the offsetting would be equal to the realisation of the export proceeds and the export would have to submit the following additional documents :

- (a) Appendix-22D in lieu of the Bank Realisation Certificate.
- (b) Specific permission of the Reserve Bank of India.

Quality Certification

2.59 It has been a constant endeavor to promote quality standards in the export product/units manufacturing the export product.

2.59.1 One of the salient features incorporated in the Foreign Trade Policy as per paragraph 3.5.2 Note. 1 for the promotion of quality standards is the grant of Star Export House status on achievement of a lower threshold limit for units having ISO-9000 (Series), ISO-14000 (Series) or HACCP certification or WHO GMP or SEI CMM level-2 and above status/certification.

2.59.2 The list of such agencies authorised to grant quality certification is given in Appendix-6.

Any of the agencies desirous of enlistment in Appendix-6 may submit their application as per Annexure I to Appendix 6 to the concerned Regional Authority under whose Jurisdiction the applicant falls as given in Appendix 1.

2.59.3 Deleted.

Grievance Redressal Mechanism

2.60 The provisions pertaining to the Grievance Redressal Mechanism is given in para 2.49 of the Foreign Trade Policy.

Procedure for Import under the Tariff Rate Quota Scheme

2.61 Attention is invited to Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. 21/2002-Customs dated 1st March, 2002. As per the notification, import of four items viz., (1) Skimmed and whole milk powder, milk food for babies etc. (0402.10 or 0402.21) (2) Maize (corn) : other (1005.90) (3) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (1512.11) and (4) Refined rape, colza or mustard oil, other (1514.19 or 1514.99) is allowed in a financial year, up to the quantities as well as such concessional rates of customs duty as indicated below :

Sl. No.	ITC Code No. and Item	Quantity of Quota	Concessional duty
1.	Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21 Skimmed and whole Milk Powder. Milk Food for babies etc.	10,000 MTs	15%
2.	Tariff Code No. 1005.90 Maize (Corn) : other	5,00,000 MTs	15%
3.	Tariff Code No. 1512.11 Crude Sunflower seed or Safflower Oil or fractions thereof	150,000 MTs	50%
4.	Tariff Code No. 1514.19 and 1514.99 Rape, Colza or Mustard Oil (Refined)	150,000 MTs	45%

Eligible entities for allocation of quota :

2.61.1 (a) Milk Powder (Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21) : National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), National Cooperative Dairy Federation (NCDF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects and Equipment Corporation of India Limited (PEC) and Spices Trading Corporation Limited (STCL) are eligible to avail the quota.

(b) Maize (corn) (Tariff Code No. 1005.90) : National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), State Trading Corporation (STC), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects and Equipment Corporation of India Limited (PEC), Spices Trading Corporation Limited (STCL) and State Cooperative Marketing Federations are eligible to avail the quota.

(c) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (Tariff Code No. 1512.11) : National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), Spices Trading Corporation Limited (STCL) and Central Warehousing Corporation (CWC), State Cooperative Marketing Federations and State Cooperative Civil Supplies Corporation are eligible to avail the quota.

(d) Refined rape, colza or mustard oil, other (Tariff Code No. 1514.19 or 1514.99) : National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), Spices Trading Corporation Limited (STCL) and Central Warehousing Corporation (CWC), State Cooperative Marketing Federations and State Cooperative Civil Supplies Corporation are eligible to avail the quota.

All the eligible entities are eligible to avail the quotas as per the request of the applicants received.

All eligible entities desiring availment of the quota as mentioned above, may make application to Exim Facilitation Committee (EFC) in the Aayaat-Niryaat Form of the Handbook of Procedures in the office of Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Udyog Bhavan, New Delhi-110011. The completed application forms along with the required/prescribed documents must reach this office on or before 1st March of each financial year preceding to the year of the quota e.g. Applications for TRQ for 2007-2008 must reach DGFT by 1st March, 2007.

The imports have to be completed before 31 March of the financial year i.e. the consignments must be cleared by the customs authorities before this date.

Since import of maize (corn) is under State Trading Regime (STR), the allottees of quota i.e. designated agencies in para 1 (b) above for this item shall also be granted an import licence/Authorisation for the allotted quantities as indicated at Sl. No. 21(b) of Customs Notification No. 21/

2002 dated 1-3-2002 in terms of para 2.11 of Foreign Trade Policy, 2004—2009, if they do not wish to make the imports through Food Corporation of India (FCI).

The application fee for these applications shall be paid according to the procedure contained in Appendix 21 B to Handbook of Procedures, Vol. I, 2004-2009.

The Exim Facilitation Committee (EFC) in the DGFT will evaluate and allot the quota among the applicants by 31st March of each financial year preceding to the year of the quota e.g. For 2007-2008, EFC will allot quota by 31st March, 2007.

CHAPTER 3

PROMOTIONAL MEASURES

Status Certificates

3.1 The Policy relating to the status holder is given in Chapter-3 of the Policy.

Application for Grant of Status Certificate

3.2 For grant of any status, the application shall be filed before 31st March. The application by exporters of goods and services for grant of One to Five Star Export House status shall be filed in 'Aayaat Niryaat Form'.

An existing status holder shall be automatically treated to be an equivalent star export house as per the table given herein under :

Erstwhile status under Exim Policy 2002—2007	Converted Status as per the Foreign Trade Policy 2004-2009
Export House	One Star Export House
Trading House	Three Star Export House
Star Trading House	Four Star Export House
Super Star Trading House	Five Star Export House

However, any exporter irrespective of whether he is a status holder or not can apply afresh in 'Aayaat Niryaat Form' for grant of status or upgradation of his existing status.

3.2.1 Application for grant of certificate for One to Five Star Export House shall be filed with the concerned regional authority headed by Joint DGFT. Provided further that, application for grant of status certificate in respect of EOU/SEZ units, shall be filed with the concerned Development Commissioner if it does not involve clubbing of FOB value of exports of its other company(ies) in the DTA. However in case of clubbing, the application shall be filed with Joint DGFT.

3.2.2 Such application shall be made by the Registered Office/Head Office/Corporate Office in the case of a Company and Head Office in case of others. Where the applicant is the Registered Office/Head Office/Corporate Office in case of a Company, it shall furnish (a) Self certified copy of valid RCMC where the name of the Registered Office or Head Office or Corporate Office is given and (b) A disclaimer from the Head Office and

Corporate Office (or Registered Office and Corporate Office or Registered Office and Head Office as the case may be) that no such application has been filed by the Company earlier against the period of entitlement for the status certificate.

3.2.3 Deleted.

Target Plus Scheme

3.2.5 Deleted.

Maintenance of Accounts

3.3 The status holder shall maintain true and proper accounts of its exports and imports based on which such recognition has been granted and the exports and imports made during the validity period of such recognition certificate. The record shall be maintained for a minimum period of three years from the expiry of the validity of such certificate. These accounts shall be made available for inspection to the regional authority or any authority nominated by the Director General of Foreign Trade.

Refusal/Suspension/Cancellation of Certificate

3.4 The status certificate may be refused or suspended or cancelled by the authority which is competent to issue/renew such certificate, if the certificate holder/applicant or any agent or employee acting on his behalf :

- (a) Fails to discharge the export obligation imposed;
- (b) Tampers with authorisations/licences;
- (c) Misrepresents or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any authorisation/licence;
- (d) Commits a breach of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, or the Rules and Orders made there under; or
- (e) Fails to furnish the information required by the Director General of Foreign Trade or any person or authority authorized by him.

3.4.1 A reasonable opportunity shall be given to the status holder before taking any action under paragraph 3.4 of Handbook of Procedures (Vol. I).

Appeal

3.5 An applicant, who is not satisfied with the decision taken to suspend or cancel the certificate, may file an appeal to the Director General of Foreign Trade within 45 days of the date of the said decision. The decision of the DGFT shall be final.

Export Promotion Council

3.6 The general policy relating to the Export Promotion Councils (EPCs) is given in Chapter-2 of the Policy. A list and product category of Export Promotion Councils/Commodity Boards is given in Appendix-2.

3.7 The major functions of the EPCs are:

- (a) To provide commercially useful information and assistance to their members in developing and increasing their exports;
- (b) To offer professional advice to their members in areas such as technology up gradation, quality and design improvement, standards and specifications, product development, innovation, etc.;
- (c) To organise visits of delegations of its members abroad to explore overseas market opportunities;
- (d) To organise participation in trade fairs, exhibitions and buyer-seller meets in India and abroad;
- (e) To promote interaction between the exporting community and the Government both at the Central and State levels; and
- (f) To build a database on the exports and imports of their members.

Non-Profit, Autonomous and Professional Bodies

3.8 The EPCs are non-profit organizations registered under the Companies Act or the Societies Registration Act, as the case may be.

3.9 The EPCs shall be autonomous and regulate their own affairs. However, if the Central Government frames uniform bylaws for the constitution and/or for the transaction of business for EPCs, they shall adopt the same with such modifications as Central Government may approve having regard to the special nature or functioning of such EPC.

The EPCs shall not be required to obtain the approval of the Central Government for participation in trade fairs, exhibitions etc. and for sending sales teams/delegations abroad.

The Ministry of Commerce and Industry/Ministry of Textiles of the Government of India, as the case may be, would interact with the Managing Committee of the Council concerned, twice a year, once for approving their annual plans and budget and again for a mid-year appraisal and review of their performance.

3.10 In order to give a boost and impetus to exports, it is imperative that the EPCs function as professional bodies. For this purpose, executives with a professional background in commerce, management and international marketing and having experience in government and industry should be brought into the EPCs.

Government Support

3.11 The EPCs may be provided financial assistance by the Central Government.

Authorities Issuing RCMC

3.12 An exporter desiring to obtain a Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) shall declare his main line of business in the application, which shall be made to

the Export Promotion Council (EPC) relating to that line of business. However, a status holder has the option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization (FIEO).

Notwithstanding anything stated above, exporters of Drugs and Pharmaceuticals shall obtain RCMC from FIEO only.

Further, exporters of minor forest produce and their value added products shall obtain RCMC from Shellac Export Promotion Council.

The service exporters (except software service exporters) shall be required to obtain RCMC from FIEO.

In respect of exporters having their head office/registered office in the State of Orissa, RCMC may be obtained from FIEO office in Bhubaneswar irrespective of the product being exported by them.

In order to give proper guidance and encouragement to the Services Sector, an exclusive Export Promotion Council for Services shall be set up.

3.12.1 In addition, an exporter has the option to obtain an RCMC from FIEO or any other relevant EPC if the products exported by him relate to those EPC's.

3.12.1.1 If the export product is such that it is not covered by any EPC, RCMC in respect thereof may be issued by FIEO.

Registration-cum-Membership

3.12.2 An exporter may, on application given in Appendix-19A, register and become a member of an Export Promotion Council. On being admitted to membership, the applicant shall be granted forthwith Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) of the EPC concerned, in the format given in Appendix-19B subject to such terms and conditions as may be specified in this behalf. In case an exporter desires to get registration as a manufacturer exporter, he shall furnish evidence to that effect.

Prospective/potential exporters may also, on application, register and become an associate member of an export promotion council.

Validity Period of RCMC

3.12.3 The RCMC shall be deemed to be valid from 1st April of the licensing year in which it was issued and shall be valid for five years ending 31st March of the licensing year, unless otherwise specified.

Intimation Regarding Change in Constitution

3.12.4 In case of change in ownership, constitution, name or address of an exporter, it shall be obligatory on the part of RCMC holder to intimate such change to the registering authority within a period of one month from the date of such change. The registering authority, however, may condone delays on merits.

Furnishing of Returns

3.13 The exporter shall furnish quarterly returns/details of his exports of different commodities.

concerned registering authority. This will be in addition to any other returns as may be prescribed by the registering authority. However, status holders shall also send quarterly returns to FIEO in the format specified by FIEO.

De-Registration

3.14 The registering authority may de-register an RCMC holder for a specified period for violation of the conditions of registration. Before such de-registration, the RCMC holder shall be given a show cause notice by the registering authority, and an adequate and reasonable opportunity to make a representation against the proposed de-registration. Upon de-registration, the concerned export promotion council shall intimate the same to all the regional authorities.

Appeal against De-registration

3.15 A person aggrieved by a decision of the registering authority in respect of any matter connected with the issue of RCMC may prefer an appeal to the Director General of Foreign Trade or an officer designated in this behalf within 45 days against the said decision and the decision of the appellate authority shall be final.

Directives of DGFT

3.16 The Director General of Foreign Trade may direct any registering authority to register or de-register an exporter or otherwise issue such other directions to them consistent with and in order to implement the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder, the Policy or this Handbook.

3.17 ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

3.17.1 The role and functions of EDI are defined in Para 2.45 of the Foreign Trade Policy. The basic purpose of EDI Initiatives is to improve the services for DGFT user community thereby achieving greater transparency of operations and reducing transaction costs by decreasing the processing time for obtaining authorisation/licences/permission/certificate from the DGFT. These EDI initiatives have made our exports competitive in international markets.

Eligibility

3.17.2 The facility of electronic filing of applications shall be available to all exporters.

Procedure

3.17.3 Under this scheme, an exporter would be able to file his application on the DGFT website at <http://dgft.gov.in>. The application will then be processed in accordance with the prevalent rules and regulations.

The applicant will have to visit the concerned office to handover the hard copy of the application along with the requisite documents including the application fee. The authorisation/license shall be issued on receipt of the hard copies of the documents as mentioned above after due scrutiny as prescribed in this Handbook.

Fiscal Incentives for EDI

3.17.4 The following deductions in Application Fee would be admissible for applications signed digitally or/ and where application fee is paid electronically through EFT (electronic fund transfer)

Sl. No.	Mode of Application	Fee Deduction (as a % of normal application fee)
1.	Digitally signed	25%
2.	Application fee payment vide EFT	25%
3.	Both digitally signed as well as use of EFT for payment of application fee	50%

Benefits

3.17.5 The facility will reduce unnecessary physical interface with DGFT. It will enable faster processing, speedier communication of deficiencies, if any, and on-line availability of application processing status.

3.17.6 Authorisation license issued using DGFT Electronic Application System shall be transmitted electronically to the Customs through EDI Mode. This shall also obviate the need for verification of authorisation/licences before allowing clearance.

New EDI Initiatives

3.17.7 To further improve the quality of services some new EDI Initiatives are being taken by DGFT.

In order to reduce documentation, a multiple purpose common application form 'Aayaat Niryaat Form' has been introduced.

3.18 SERVED FROM INDIA SCHEME

(a) The Policy for the Served From India Scheme is given in Chapter 3 of Foreign Trade Policy.

(b) A single consolidated application for the duty credit entitlement certificate shall be filed with the jurisdictional regional authority in 'Aayaat Niryaat Form' by the Registered Office in case of a company and Head Office in case of others. The last date for filing of such application shall be 31st December.

(c) deleted.

(d) For each duty credit certificate, split certificates subject to a minimum of Rs. 5 lakh each and multiples thereof may, also be issued. A fee of Rs. 1000 each shall be paid for each split certificate. However, a request for issuance of split certificate(s) shall be made at the time of application only and shall not be considered at a later stage.

The duty credit certificate shall normally be issued with a single port of registration. However the applicant may choose different ports of registration for each split certificate.

(e) deleted

(f) The entitlement can be used for import from private/public bonded warehouses subject to the fulfillment of provision of paragraph 2.28 of Foreign Trade Policy and the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue from time to time in respect of private/public bonded warehouses.

(g) The duty credit entitlement certificate shall be valid for a period of 24 months.

Revalidation of duty credit certificate shall not be allowed.

The service provider shall within one month of the completion of imports made or the expiry of the validity of the duty credit entitlement certificate whichever is earlier, submit a statement of imports made under the certificate as per 'Aayaat Niryaat Form' to the Jurisdictional Regional Authority with a copy to the Jurisdictional Excise Authorities (service tax cell) whether applicable.

(h) All the applicants under this scheme who are hotels (1 star and above, heritage hotels) and stand alone restaurants would ensure that they pass on the benefit of the duty credit entitlement to the consumer.

(i) Only such foreign exchange remittances as are earned as amounts in lieu of the services rendered by the service exporter would be counted for computation of the entitlement under this scheme.

Other sources of foreign exchange earnings such as equity or debt participation, donations, repayment of loans and any other inflow of foreign exchange unrelated to the service rendered would not be counted for the computation of entitlement under the scheme.

Ineligible Remittances and Services

3.18.1 (a) The following Foreign Exchange remittances shall not be eligible for entitlement under this scheme:

I. Remittances related to Financial Services Sector

1. Raising of all types of foreign currency Loans.
2. Export proceeds realisation of clients.
3. Issuance of Foreign Equity through ADRs/GDRs or other similar instruments.
4. Issuance of foreign currency Bonds.
5. Sale of securities and other financial instruments.
6. Other receivables not connected with the services rendered by the financial institutions.

II. Remittances earned through contract/regular employment abroad (e.g. labour remittances).

(b) Payments received from Export Earners Foreign Currency (EEFC) Account shall not be counted for benefits under the scheme.

(c) The foreign exchange turnover for Healthcare Institutions like equity participation, donations etc. (However remittances received on account of medical

treatment, surgery, testing, consultancy and health care provided by the institution shall not be ineligible).

(d) The foreign exchange turnover for Educational Institutions like equity participation, donations etc. (However remittances received on account of the course fees and consultancy provided by the institution shall not be ineligible).

(e) Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI/BTP Schemes or supplies made to such units or products manufactured by them and exported through DTA units

(f) Moreover, the clubbing of turnover of services rendered by these units with the turnover of the DTA units shall also not be allowed.

Re-export of goods imported under the Scheme

3.18.2 Goods imported under the scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases, 98% of the credit amount debited against the scrip for the export of such goods, shall be generated by the concerned Commissioner of Customs in the form of a Certificate, containing the amount generated and the details of the original Scrip. Based on the certificate, a fresh Scrip shall be issued by the concerned Regional Authority. The fresh Scrip, so issued, shall have the same port of registration and shall be valid for a period equivalent to the balance period available on the date of import of such defective/unfit goods.

Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana

3.19 The Policy pertaining to the Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana is given in Chapter 3 of the Foreign Trade Policy.

3.19.1 The application for grant of credit under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana for export made from 01-04-2006 onwards shall be made to the regional authority concerned in the Aayaat Niryaat Form along with the documents prescribed therein. The applicant may file one or more applications subject to the condition that each application shall contain not more than 25 shipping bills. All the shipping bills in any one application must relate to exports made from one Customs House only. This procedure will equally apply to the exports made from 01-04-2005 till 31-03-2006 under the then Vishesh Krishi Upaj Yojana.

The application for obtaining credit shall be filed within a period of twelve months from the date of exports or within six months from the date of realization or within three months from the date of printing/release of shipping bill, whichever is later, in respect of shipments for which the claim have been filed.

However, in respect of the exports made from 01-04-2005 till 31-03-2006, application for grant of credit for products eligible under the Vishesh Krishi Upaj Yojana,

the last date for filing such applications shall be 30th September, 2006 or within six months from the date of realization or within three months from the date of printing/release of shipping bill, whichever is later.

3.19.2 The application in the 'Aayaat Nirvaat Form' shall be accompanied by Export Promotion copy of the shipping bill and bank realization certificate as per Appendix-22A.

3.19.3 For direct as well as third party exports, the Export documents viz Export Order, Invoice, GR Form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

3.19.4 In cases where the applicant applies for the credit entitlement certificate after realization or shipments are made against irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co-Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank and certified by the bank in the relevant Bank certificate of export and realization, the credit entitlement certificate shall be issued with transferable endorsement. In other cases, the credit entitlement certificate shall be initially issued with non-transferable endorsement. Upon realization of export proceeds, such credit entitlement certificates can be endorsed as transferable, if the applicant so desires.

3.19.5 The duty credit certificate shall be issued with a single port of registration and this will be the port from which the exports have been made. However, the applicant may use this duty credit for imports from any other port after obtaining TRA from the port of registration that includes ICD/LCS.

3.19.6 For each duty credit certificate, split certificates subject to a minimum of Rs. 5 lakh each and multiples thereof may also be issued. A fee of Rs. 1000 each shall be paid for each split certificate. However, a request for issuance of split certificate(s) shall be made at the time of application only and shall not be considered at a later stage. The split certificate will have the same port of registration for the purposes of imports as appearing in the main certificate.

3.19.7 The entitlement can be used for import from private/public bonded warehouses subject to the fulfilment of provision of paragraph 2.28 of Foreign Trade Policy and the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue from time to time in respect of private/public bonded warehouses.

3.19.8 The duty credit entitlement certificate shall be valid for a period of 12 months.

Realization of duty credit entitlement certificate shall not be allowed.

Re-export of goods imported under the Scheme

3.19.9 Goods imported under the scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases, 98% of the credit amount debited against the scrip for the export of such goods, shall be generated by

the concerned Customs Officer of Customs in the form of a Certificate, containing the amount generated and the details of the original Scrip. Based on the certificate, a fresh Scrip shall be issued by the concerned Regional Authority. The fresh Scrip, so issued, shall have the same port of registration as the original Scrip for a period equivalent to the balance period remaining from the date of import of such defective/unfit goods.

Focus Market Scheme

3.20 The policy pertaining to Focus Market Scheme is given in Chapter 2 of the Foreign Trade Policy.

3.20.1 The application for grant of credit under Focus Market Scheme shall be made to the regional authority concerned in the Aayaat Nirvaat Form along with the documents prescribed therein. The application shall be filed on a six monthly basis i.e. April-September and October-March. However, each application within the same six monthly period shall include shipping bills from the same customs port only and separate applications shall be made for exports made from different custom ports.

The application for obtaining duty credit under the scheme shall be submitted within a period of six months from the end of the period of the application or within a period of six months of the date of realization of the last export covered by the application, whichever is later.

3.20.2 For direct as well as third party exports, the Export documents viz Export Order, Invoice, GR Form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

3.20.3 In cases where the applicant applies for the credit entitlement certificate after realization or shipments are made against irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank and certified by the bank in the relevant Bank Certificate of Export and Realization, the credit entitlement certificate shall be issued with transferable endorsement. In other cases, the credit entitlement certificate shall be initially issued with non-transferable endorsement. Upon realization of export proceeds, such credit entitlement certificates can be endorsed as transferable, if the applicant so desires.

Port of Registration

The credit entitlement certificate shall be issued with a single port of registration and this will be the port from where the exports have been made. However, the applicant may use this duty credit for imports from any other port after obtaining TRA from the port of registration that includes ICD/LCS.

Facility for Split Scrips

3.20.5 For each duty credit certificate, split certificates subject to a minimum of Rs. 5 lakh each and multiples thereof may also be issued. A fee of Rs. 1000 each shall be

paid for each split certificate. However, a request for issuance of split certificate(s) shall be made at the time of application only and shall not be considered at a later stage. The split certificate will have the same port of registration for the purposes of imports as appearing in the main certificate.

Import from private/public bonded warehouses

3.20.6 The entitlement can be used for import from private/public bonded warehouses subject to the fulfilment of provision of paragraph 2.28 of Foreign Trade Policy and the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue from time to time in respect of private/public bonded warehouses.

Re-export of goods imported under the Scheme

3.20.7 Goods imported under the scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases, 98% of the credit amount debited against the scrip for the export of such goods, shall be generated by the concerned Commissioner of Customs in the form of a Certificate, containing the amount generated and the details of the original Scrip. Based on the certificate, a fresh Scrip shall be issued by the concerned Regional Authority. The fresh Scrip, so issued, shall have the same port of registration and shall be valid for a period equivalent to the balance period available on the date of import of such defective/unfit goods.

Validity Period

3.20.8 The duty credit entitlement certificate shall be valid for a period of 24 months.

Revalidation of duty credit entitlement certificate shall not be allowed.

Focus Product Scheme

3.21 The policy pertaining to Focus Product Scheme is given in Chapter 3 of the Foreign Trade Policy.

3.21.1 The application for grant of credit under Focus Product Scheme shall be made to the Regional Authority concerned in the Aayaat Niryaat Form along with the documents prescribed therein. The application shall be filed on a six monthly basis i.e. April-September and October-March. However, each application within the same six monthly period shall include shipping bills from the same customs port only and separate applications shall be made for exports made from different custom ports.

The application for claiming duty credit under the scheme shall be submitted within a period of six months from the end of the period of the application or within a period of six months of the date of realization of the last export covered by the said application, whichever is later.

3.21.2 For direct as well as third party export, the Export Documents viz Export Order, Invoice, GR Form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

3.21.3 In cases where the applicant applies for the credit entitlement certificate after realization or shipments

are made against irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank and certified by the bank in the relevant Bank Certificate of Export and Realization, the credit entitlement certificate shall be issued with transferable endorsement. In other cases, the credit entitlement certificate shall be initially issued with non-transferable endorsement. Upon realization of export proceeds, such credit entitlement certificates can be endorsed as transferable, if the applicant so desires.

Port of Registration

3.21.4 The duty credit certificate shall be issued with a single port of registration and this will be the port from which the exports have been made. However, the applicant may use this duty credit for imports from any other port after obtaining TRA from the port of registration that includes ICD/LCS.

Facility for Split Scrips

3.21.5 For each duty credit entitlement certificate, split certificates subject to a minimum of Rs. 5 lakh each and multiples thereof may also be issued. A fee of Rs. 1000 each shall be paid for each split certificate. However, a request for issuance of split certificate(s) shall be made at the time of application only and shall not be considered at a later stage. The split certificate will have the same port of registration for the purposes of imports as appearing in the main certificate.

Import from private/public bonded warehouses

3.21.6 The entitlement can be used for import from private/public bonded warehouses subject to the fulfilment of provision of paragraph 2.28 of Foreign Trade Policy and the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue from time to time in respect of private/public bonded warehouses.

Re-export of goods imported under the Scheme

3.21.7 Goods imported under the Scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases, 98% of the credit amount debited against the scrip for the export of such goods, shall be generated by the concerned Commissioner of Customs in the form of a Certificate, containing the amount generated and the details of the original Scrip. Based on the certificate, a fresh Scrip shall be issued by the concerned Regional Authority. The fresh Scrip, so issued, shall have the same port of registration and shall be valid for a period equivalent to the balance period available on the date of import of such defective/unfit goods.

Validity Period

3.21.8 The duty credit entitlement certificate shall be valid for a period of 24 months.

Revalidation of duty credit entitlement certificate shall not be allowed.

CHAPTER-4

DUTY EXEMPTION/REMISSION SCHEME

Policy

4.1 The Policy relating to the Duty Exemption/Remission scheme is prescribed in Chapter 4 of the Policy.

General Provision

4.2 An application for grant of an Advance Authorisation/Advance Authorisation for Annual Requirement/DFRC/DEPB/DFIA may be made by the Registered office or Head office or a branch office or manufacturing unit of the eligible exporter, to the Regional Authority (RA) concerned.

4.3 Where the applicant is the branch office or manufacturing unit(s) of an exporter, it shall furnish (a) Self certified copy of valid RCMC where the name of the branch office or manufacturing unit is given.

Advance Authorisation

4.4 Where the SION have been published, an application in 'Aayaat Niryat Form', along with documents prescribed therein, shall be submitted to the Regional Authority concerned.

4.4.1 In case of export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the quantity, wastage and the value addition norms shall be as prescribed in paragraph 4A of the Policy and Handbook of Procedure (Vol. 1).

4.4.2 In case where norms have not been published, an application in 'Aayaat Niryaat Form', along with prescribed documents, shall be furnished to the concerned Norms Committee (NC) at DGFT Headquarter for fixation of Norms.

In such cases, the original copy of the application along with prescribed fee shall be filed with the Regional authority concerned and a self attested copy of the same shall be filed with NC. The authorisations in such cases shall be issued by the RA on the basis of recommendation of NC.

The Committee shall also function as a recommendatory authority for SION. The Director General of Foreign Trade may notify such norms as recommended by the NC.

4.4.3 Applications, where Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudoephedrine is required as an input for import, either in such cases where norms are fixed or in such cases where norms are not fixed, shall be filed with the Regional Authorities concerned. Copies of such applications shall also be simultaneously endorsed to the Drug Controller of India, Nirman Bhawan, New Delhi, Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and the respective Zonal Director of the Narcotics Control Bureau, along with a declaration that the applicant will maintain the prescribed records and also submit the prescribed returns.

Duty free import of spices (covered by Chapter 9 of the ITC (HS) Classifications of Export & Import items, 2004-09) for export under Advance Authorisation scheme shall be permitted only for value addition purposes like

crushing/grounding/sterilization or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, re-packing etc.

4.4.4 The Regional Authority, while issuing the Advance Authorisation for the import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo-ephedrine shall endorse a condition that before effecting imports, NOC shall be obtained from the Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and shall also endorse a copy of the authorisation to the Drug Controller, Nirman Bhawan, New Delhi and the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.

4.4.5 Exports made against the Government of India/ EXIM Bank Line of Credit would be entitled for benefits under the Advance Authorisation Scheme. Further, exports made under Deferred Payment/Suppliers Line of Credit Contract backed by ECGC Cover would also be entitled for the benefit under the Scheme.

Advance Authorisation for applicants with multi units

4.5 Transfer of any duty free material imported or procured against advance authorisation from one unit of the company to another unit of the same company for manufacturing purpose shall be done with the prior intimation to the jurisdictional Excise Authorities with a clear understanding that no benefit of CENVAT shall be claimed on such transferred inputs. In case of non-excisable company/products, the units should maintain a proper record of the same. However, to avail the facility, all such units should be available in the IEC certificate and follow the rules and regulation of Central Excise for jobwork.

Advance Authorisation for Free of Cost and Paid Material

4.6 In terms of paragraph 4.1.8 of the Policy, an exporter may apply for an Advance Authorisation for import of items mentioned in paragraph 4.1.3 of the Policy, some or all of which may also include items that are supplied free of cost.

In such cases, a specific endorsement shall be made on the exchange control copy of the Advance Authorisation disallowing remittances for the material being supplied free of cost. All inputs imported shall be utilised in the manufacturing of the product except the wastage.

The value addition in the case of such Advance Authorisations would be computed by adding the notional value of the free of cost material to both the CIF value of imports and FOB value of exports.

Self Declared Authorisations where SION does not exist

4.7 The Regional Authority may also issue Advance Authorisations, where SION are not fixed, based on self declaration and an undertaking by the applicant for a final adjustment as per Ad hoc/SION fixed by NC. However, no Advance Authorisation shall be issued under this paragraph by the Regional Authority for import of the following products :—

- i. All vegetable/edible oils classified under Chapter-15 and all types of oilseeds classified under Chapter-12 of ITC (HS) book;

- ii. All types of cereals classified under Chapter-10 of ITC (HS) book;
- iii. All spices other than light black pepper (light berries) having a duty of more than 30%, classified under Chapter-9 and 12 of ITC (HS) book;
- iv. All types of fruits/vegetables having a duty of more than 30%, classified under Chapter 7 and 8 of ITC (HS) book; and
- v. Horn, hoof and any other organ of animal.

For export of perfumes, perfumery compounds and various feed ingredients containing vitamins, no authorisation shall be issued under this paragraph by Regional Authority and the applicants may apply under Para 4.4.2 of this Handbook. Where export and/or import of biotechnology items are involved, authorisation under this paragraph shall be issued by the Regional Authority only on submission of a 'No Objection Certificate' from the Department of Bio-Technology.

Further, duty free import of spices (covered by Chapter 9 of the ITC (HS) Classifications of Export & Import items, 2004-09) for export under Advance Authorisation scheme shall be permitted only for value addition purposes like crushing/grinding/sterilization or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, re-packing etc.

Entitlement

4.7.1 The CIF value of one or more such authorisations shall be 500% of the FOB and/or FOR value of preceding year exports and/or supplies in case of status holders and Rs. 5 crore or 500% of the FOB and/or FOR value of preceding year exports and/or supply, whichever is more, for others.

However, in cases where NC has already ratified the norms for the same export and import products in respect of an authorisation obtained under paragraph 4.7, such norms shall be valid for a period of six months reckoned from the date of ratification.

The authorisation holder in such cases shall be entitled for further authorisation(s) as per the norms ratified by NC without the need for subsequent ratification by NC. In such cases the applicant would file the application under Ad hoc Norms Fixed category. However, NC should ensure that such ad hoc norm(s), if not notified already, are notified within a period of one month after six months of ratification of such ad hoc norm(s).

Authorisations shall be issued by the Regional Authority concerned under "Adhoc Norms Fixed" category and in such cases the application copies need not be forwarded to the NC for fixation/ratification of norms.

4.7.2 Once the norms are fixed by NC, the value limits mentioned in sub paragraph 4.7.1 above would not be applicable to Advance Authorisations issued under this paragraph. Such authorisations, subsequent to fixation of norms by NC, may be enhanced.

It is mandatory for the industry to provide production data etc. as may be required by DGFT/EPC for fixation of

SION. Otherwise, the applicant shall not be allowed to take the benefit of Advance Authorization scheme for taking repeat advance authorization on self-declared basis.

4.7.3. **Authorisation in Excess of Entitlement** An Applicant shall be entitled for authorisation under this paragraph in excess of entitlement mentioned in paragraph 4.7.1 subject to furnishing of 100% Bank Guarantee to Customs authority to cover the exemption from Customs duties. A specific endorsement to this effect shall be made on the authorisation.

4.7.4. **Application** The original application with prescribed documents shall be submitted to the concerned Regional Authority. The Regional Authority shall forward a copy of the application within 7 days from the date of issue of such authorisations to NC for fixation of norms within the prescribed time.

4.7.5. **Undertaking** The applicant shall give an undertaking that he shall abide by the norms fixed by NC and accordingly pay duty, together with 15% interest, on the unutilised inputs as per norms fixed by NC. However the holder of the authorisation has the option to undertake additional export obligation in proportion to the excess unutilized inputs. In case the application is rejected by the NC, then the authorization holder shall pay the customs duty saved along with 15% interest on the imported inputs.

In addition, an amount equivalent to 3% of the CIF value of unutilised imported material shall be required to be deposited through a TR in the authorised branch of Central Bank of India indicating the "Head Account : 1453, Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head 102". The Authorisation holder shall also be required to obtain a separate import licence for regularisation of the excess imported input(s). However, the provisions of this sub-paragraph shall not be applicable if the unutilised imported material was freely importable on the date of import.

4.7.6. In such cases, where the norms are not finalised by NC within four months from the date of issuance of authorisation, the norms as applied for shall be treated as final and no adjustment will be made. However, where the application for fixation of adhoc/SION is rejected on account of non-furnishing of required documents/information, the authorisation holder shall be liable for penalty as stated in the above paragraph. In case SION for the said product is notified, the SION would be made applicable for the purpose of deciding the wastage norms and export obligation.

In such cases where the export obligation is completed pending fixation of norms by NC, the entitlement for the authorisation as given in paragraph 4.7.1 may be re-credited upon production of documentary evidence (copies of Shipping bill/bill of export)/Central Excise certified copies of invoices/showing fulfillment of export obligation in respect of the previous authorisations. However, bond waiver/redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases.

Financial Powers**4.8 The financial powers are given in the table below :**

Category of Application	On published norms and under paragraph-4.7 of this Handbook			
	Regional Authority		Regional Authorities on the recommendation of NC	
	Petroleum/ Petrochemical Products & Advance Authorisation for Annual Requirements	Others	Petroleum/ Petrochemical Products & Advance Authorisation for Annual Requirements	Others
CIF value of Authorisation crore above	Less than Rs. 500 crore	Less than Rs. 100 crore	Rs. 500 crore or above	Rs. 100 or

4.9 Standardisation of Adhoc Norms: For standardization of norms, an application may be made by the manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer, duly filled in with complete data. Such applications shall be made to the Norms Committee (NC) in the form given in 'Aayaat Niryaat Form'.

Import of fuel may also be allowed under SION by NC subject to the following —

- The facility of import of fuel shall be allowed only to the manufacturer having captive power plant.
- In cases where SION specifically allows fuel, the same shall be permitted under advance authorisation. However, if fuel is not covered specifically under SION, it may be allowed as per general fuel Policy for products covered under SION or under paragraph 4.7
- Fuel should be allowed only against an actual user authorisation. However in case of transferable DFIA/DFRC, fuel can only be transferred to agencies granted marketing rights by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
- Even where fuel is included as an input under SION, it shall not be taken into account while fixing the DEPB rate for such products against which fuel has been allowed as an input.
- The applications of fixation for fuel entitlement for new sectors and modification of the existing entitlement as per the General Note for Fuel in the Handbook of Procedures (Vol. 2) would be made to the Norms Committee along with the requisite data in 'Aayaat Niryaat Form' pertaining to the "Data Sheet for Fuel Rate".

The Advance Authorisation holders wishing to procure the fuel may apply for an Advance Release Order or Back to Back Inland Letter of Credit. The indigenous supplier supplying fuel shall be entitled for deemed export benefits given in paragraph 8.3(a), (b) & (c) of the Policy, as the case may be. In case the indigenous supplier is not willing to avail of deemed exports benefits under such supplies of fuel to the Advance Authorisation holder, he may issue a disclaimer (along with his IEC Number enclosed on it) on the basis of which the Advance Authorisation holder can avail of the deemed export benefits as per procedure given in Chapter 8 of this Handbook.

4.10 Modification of SION: An application for modification of existing SION may be filed before the NC by manufacturer exporter or merchant-exporter, tied to supporting manufacturer, in the form given in 'Aayaat Niryaat Form'.

4.10.1 Amendment of Export item and inputs : An application for amendment of an export item or inputs under SION or under ADHOC Norms may be filed by any manufacturer or merchant exporter as per 'Aayaat Niryaat Form' of this Handbook.

The applicant would give the justification for seeking the amendment and the same would be considered by the Regional Office with the specific approval of the head of the Office. In case of any major change in the input or the request for more wastage to that allowed under SION or the adhoc norms, the same should be referred to NC for ratification.

4.10.2 Revision of SION by NC : At the beginning of the financial year or at any other time as NC may find it necessary, NC may identify the SIONS which in its opinion are required to be reviewed. The exporters are required to submit revised data in form given in 'Aayaat Niryaat Form' for such revision. It is mandatory for the industry/exporter(s) to provide production and consumption data etc. as may be required by DGFT/EPC for revision of SION. Otherwise, the applicant shall not be allowed to take the benefit of Advance Authorization scheme.

4.11 Description of an Advance Authorisation : An Advance Authorisation shall specify :

- the names and description of items to be imported and exported/supplied;
- the quantity of each item to be imported or wherever the quantity cannot be indicated, the value of the item shall be indicated. However, if in Standard input output norms, the quantity and/or value of individual inputs is a limiting factor, the same shall be applicable.
- the aggregate CIF value of imports; and
- the FOB/FOB value and quantity of exports/supplies.

4.12 Exports in Anticipation of Authorisation : Exports/supplies made from the date of EDI generated file number for an Advance Authorisation may be accepted towards discharge of export obligation. Shipping/Supply document(s) should be endorsed with the File Number or

the Authorisation Number to establish co-relation of the exports/supplies with the Authorisation issued. If the application is approved, the authorisation shall be issued based on the input-output norms in force on the date of receipt of the application by the Regional Authority in proportion to the provisional exports/supplies already made till any amendment in the norms is notified. For the remaining exports, the Policy/Procedures in force on the date of issue of the authorisation shall be applicable.

4.12.1 The exports/supplies made in anticipation of the grant of an Advance Authorisation shall be entirely on the risk and responsibility of the exporter.

4.12.2 The conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permitted by the customs authorities in case the application for an Advance authorisation is rejected or modified by the Regional authority.

4.13. Advance Authorisation or DFRC or DFIA Intermediate Supplies : The application for grant of Advance Authorisation or DFRC or DFIA for Intermediate supply may be made on the basis of a tie-up agreement with the exporter (physical/deemed) holding an Advance authorisation or DFRC or DIA. The Regional Authority concerned shall consider such requests.

The Advance Authorisation or DFRC or DFIA for Intermediate supply shall be issued after making the Authorisation/Certificate invalid for direct import of items to be supplied by the intermediate manufacturer. In such cases, a copy of the invalidation letter will be given to the Authorisation/Certificate holder and copy thereof will be sent to the intermediate supplier as well as the Regional Authority of the intermediate supplier. The Authorisation/Certificate holder in such case has an option either to supply the intermediate product to holder of Advance Authorisation/DFRC/DFIA or to export (physical/deemed) directly. However, once the Electronic message transfer facility among the Regional Authorities becomes fully operational, the requirement of sending a copy of the invalidation letter/ARO to the jurisdictional Regional Authority shall not be required.

The facility of Advance Authorisation shall be available even in cases where the intermediate supplier has supplied or intend to supply the material subsequent to fulfilment of export obligation by the exporter holding the Advance Authorisation/DFIA from where the invalidation letter was issued.

4.14 Advance Release Order : An application may be made to the Regional Authority concerned for grant of Advance Release Order (ARO) to procure the inputs from indigenous sources/State Trading Enterprises.

4.14.1 The application shall specify (i) the name, description and quantity of the items and (ii) the individual value of items to be procured. An ARO may be issued along with the Advance Authorisation/DFRC/DFIA or subsequently, and its validity shall be co-terminus with the validity of the Advance Authorisation/DFRC/DFIA as specified in this Handbook.

An ARO issued for the procurement of an individual

item shall be automatically valid for procurement from one or more indigenous sources.

4.15 Back to Back Inland Letter of Credit (L/C) : The exporter may alternatively avail the facility of a back to back inland letter of credit from the banks. A holder of an Advance Authorisation/DFRC/DFIA, may approach a bank for opening an inland letter of credit (L/C) in favour of an indigenous supplier.

4.15.1 Before opening the L/C, the bank will ensure that the necessary BG/LUT has been executed by the Advance Authorisation holder/non-transferable DFIA and an endorsement to that effect has been made on the authorisation.

However, execution of BG/LUT shall not be required against DFRC or transferable DFIA. After opening the inland L/C, the bank shall make the following endorsement on the Exchange Control and Customs copy of the Advance Authorisation/DFRC/DFIA :

"The value of this Advance Authorisation/DFRC/DFIA stands reduced by a sum of Rs———, being the value of the inland LC No.———opened today by the licensee in favour of M/s——— (name and address of the indigenous supplier)."

4.15.2 The Authorisation/Certification shall be invalidated by the bank for direct import only in respect of the full quantity and value of the item being sourced indigenously.

4.15.3 The original Letter of Credit (L/C) may be retained by the bank for negotiation and only the non-negotiable copy of the L/C may be given to the indigenous supplier.

4.15.4 The responsibility of the bank shall be confined to making the endorsement. The bank shall not be liable for any misrepresentation or false statement made by the Authorisation/Certificate holder while requesting the bank to make the endorsement. The inland L/C opened by the bank in favour of the indigenous supplier shall not be cancelled for any reason whatsoever.

4.15.5 The non-negotiable copy of inland L/C together with the photocopy of the Advance Authorisation/DFRC/DFIA duly carrying endorsements made by the bank shall be sufficient for the indigenous supplier to claim deemed export benefits. L/C issued against DFRC shall, however, be entitled only to benefit given in paragraph 8.3(b) of Policy, whereas L/C for other categories shall be entitled to benefits given in paragraph 8.3 (b) and (c) of the Policy.

4.15.6 Where the import of gold/silver is permitted as an input under this scheme, such gold/silver can be sourced through the nominated agencies as given in paragraph 4A onwards in Chapter-4 of the Policy for supply against the Advance Authorisations/DFRC/DFIA issued in this behalf. Before supply of the material, the nominated agencies should follow the same procedure as given in paragraph 4.15.1 above.

Facility of Supporting Manufacturers/Jobber/Co-Authorisation Holder

4.16 The imported material may be used in any of the units of the holder of Advance Authorisation or

non-transferable DFIA or jobber/supporting manufacturer provided the same is endorsed on the authorisation by the regional office. If the applicant desires to have the name of any manufacturer or jobber added to the authorisation, he may apply for such endorsement. Such endorsement shall be mandatory where prior import before export is a condition for availing Advance Authorisation/DFIA scheme and the Authorisation holder desires to have the material processed through any other manufacturer or jobber.

Upon such endorsement made by the Regional Authority, the authorization holder and co-authorisation holder shall jointly and severally be liable for completion of export obligation. Any one of the Co-Authorisation holders may import the goods in his name or in the joint names. The BG/LUT shall also be furnished in their joint names.

However, if the Authorisation holder is registered with the Central Excise, he has an option of getting the names of the jobber endorsed by the Central Excise as per the Central Excise Rules in lieu of the endorsement on the authorisation by the regional office. In case the manufacturer exporter holding the authorisation is not registered/not required to be registered with the Central Excise authority, the job work may be allowed as per the Central Excise rules and regulations without insisting for endorsement of the name of the supporting manufacturer. However, the authorisation holder shall be solely responsible for the imported items and fulfilment of export obligation.

In case Bank Guarantee/LUT has been redeemed, the Advance Authorisation holder can get the duty free inputs processed from any manufacturer under Actual User condition as per job work regulations prescribed under the Central Excise Rules. However, such restriction shall not be applicable in case of transferable DFIA holder.

Facility of Co-Licensee

4.17 Deleted.

Acceptance of BG/LUT

4.18 At the time of issue of the authorisation, the acceptance of the undertaking given by the applicant to the Regional Authority concerned in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' will be endorsed on the reverse of the Advance Authorisation.

Note :—

- (a) No BG/LUT will be required where the specified export obligation has been fulfilled before making any import. In case of partial fulfilment of export obligation before effecting any imports, the BG/LUT may be reduced proportionately.

The Authorisation holder shall also produce EP copy of the shipping bills and Bank Certificate of Export and Realisation, and a statement of exports given details of shipping bill wise exports indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product substantiating the completion or the partial

fulfilment of the export obligation to the Regional Authority concerned.

However, realization of export proceeds shall not be insisted if the shipments are made against confirmed irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank. In both these arrangements, certification of this is to be made by the bank in column 14/15 of Appendix 22A.

- (b) In respect of an Advance Authorisation on which "No BG/LUT" facility has been provided, the Regional Authority shall forward a copy of the "No Bond Certificate" indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product, in respect of shipment which were taken into account for calculating fulfilment of export obligation to the Customs Authorities with whom the authorisation is required to be registered. Such details shall also be placed by the Zonal Offices in their website immediately after issuance of the export obligation discharge/redemption letter/No Bond Certificate and by DGFT Hqr in DGFT website on monthly basis for the customs authority to access it from the website.

Before allowing the imports against Advance Authorisation, the Customs shall verify that the details of the exports as given in the "No Bond Certificate", are as per their records.

- (c) The cancellation/redemption of BG/LUT would be undertaken by the Customs within 30 days of issue of Export Obligation Discharge Certificate (EODC)/bond waiver by the regional office.

Port of Registration

4.19 The Advance Authorisation shall be issued for the purpose of import and export through one of the sea ports or airports or ICDs or LCS specified below. The Authorisation holder shall register the authorisation at the port specified in the authorisation and thereafter all imports against the said authorisation shall be made only through that port, unless the Authorisation holder obtains permission from the Customs Authority concerned to import through any other specified port. However, exports may be made through any of the specified ports.

Sea Ports: Mumbai, Kolkata, Cochin, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagao, Chennai, Paradeep, Pipava, Sikka, Tuticorin, Vishakhapatnam, Dahej, Nagapattinam, Okha, Mundhra, Surat (Magdalla), Jamnagar, Nhava Sheva.

Airports: Ahmedabad, Bangalore, Bhubneshwar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore Air Cargo Complex, Cochin, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Chennai.

ICDs : Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati (Amingaon), Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodra, Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthi, Salem Mallanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Uadipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry, Garhi Harsaru Bhatinda, Dappar, Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur, Dadri and Tuticorin.

LCS : Ranaghat, Singhabad, Raaxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Mahadipur and Dawki.

SEZ : Any SEZ notified by the Central Government shall also be one of the specified ports for import and export under this paragraph.

4.19.1 The Commissioner of Customs may, either by a public notice or on the written request of the authorisation holder, by a special order and subject to such conditions as may be specified by him, also permit imports and exports from any Seaport/Airport/ICD or land custom station other than those mentioned above.

4.19.2 In such cases, where the authorisation has not been registered at the port specified in the authorisation and no import has taken place, the request for change in the Port of Registration may be considered by the Regional Authority concerned provided the authorisation has not been redeemed.

4.19.3 For imports from the Airport/Seaport/ICD other than the port of registration, a Telegraphic Release Advice (TRA) shall also be issued by the Customs Authority at the port of registration to the customs authority at the port of import.

Facility of Clubbing

4.20 The facility of clubbing shall be available only for redemption/regularisation of the cases, and no further import or export shall be allowed. For this facility, authorisations are required to have been issued under similar Customs notification even pertaining to different financial years. However, in case of authorisations issued in 2004—2009 period, Advance Authorisations of different customs notification can be clubbed.

4.20.1 The Regional Authority, under whose jurisdiction the authorisation is issued or NC in other cases, shall consider a request for clubbing all imports and exports of more than one Advance Authorisation provided the imported inputs are properly accounted for as per norms. The value addition of the authorisations so clubbed shall be the average of the minimum value addition prescribed in the Policy and the Procedure laid thereunder, imposed on individual authorisations. Upon clubbing, the

authorisations shall, for all purposes, be deemed to be one authorisation.

4.20.2 The accountability of imports and exports shall be restricted in relation to the individual categories of Advance Authorisations including Advance Authorisation for annual requirements issued under this scheme.

4.20.3 The facility is available only for Advance Authorisation(s) where there is shortfall in fulfillment of export obligation, and which is sought to be clubbed with an Advance Authorisation(s) which is valid for imports. For expired authorisation(s) with EO shortfall and which is sought to be clubbed with an Advance Authorisation(s) which is valid for imports, the applicant shall pay the composition fee for E.O. period extension as per the provision of paragraph 4.22.

4.20.4 In such cases, the exports effected beyond the E.O. extension period (allowed in terms of paragraph 4.22) after the issuance of the earliest authorisation shall not be considered for clubbing.

4.20.5 Notwithstanding the provisions of para 4.20.3 and 4.20.4 above, Clubbing of all expired licences may also be permitted provided all the expired licences have been issued during the Exim Policy period 1992-1997 & 1997-2002 i.e., 1st April, 1992 to 31st March, 2002. However clubbing of erstwhile Value Based Advance licences shall not be allowed.

Enhancement/Reduction in the Value of Authorisation

4.21 In respect of an Advance Authorisation, the Regional Authority concerned (as per their financial powers) may consider a request for enhancement/reduction in the CIF value of the authorisation, provided the value addition after such enhancement does not fall below the stipulated minimum value addition (as per the policy and the procedure laid thereunder) and provided there is no change in the input-output norms and the Policy under which the authorisation was issued.

4.21.1 The Regional Authority concerned (as per their financial powers) may also consider the request for enhancement/reduction in CIF value, quantity of inputs, FOB value of export obligation and quantity of exports of an Advance Authorisation provided there is no change in the input-output norms and value addition after such enhancement does not fall below the minimum value addition stipulated in the Policy and the Procedure laid thereunder.

4.21.2 The request for prorata enhancement in value and quantity may be made either before or after exports. In such cases where there is a change in the SION prior to the export of the said product, the prorata enhancement shall be given after calculating the entitlement on the revised SION.

4.21.3 The application for the enhancement/reduction in the value of the authorisation shall be made in 'Aayaat Niryaat Form' of the Handbook of Procedure (Vol. 1).

Application fee for enhancement

4.21.4 The application fee leviable for enhancement would be on the difference in the CIF values of the original and final authorisation. However, no application fee would be charged if the value of the authorisation is being reduced or the applicant has paid the maximum fee of Rs. 150,000 (for manual applications) and Rs. 75,000 (for digitally signed applications) respectively in the original application for Advance Authorisation.

Export Obligation Period and its Extension

4.22 The period fulfillment of export obligation under an Advance Authorisation shall commence from the date of issuance of authorisation. The export obligation shall be fulfilled within a period of 24 months except in the case of supplies to the projects/turnkey projects in India/abroad under deemed exports category where the export obligation must be fulfilled during the contracted duration of execution of the project/turnkey project.

In case of Spices [covered by chapter 9 of the ITC (HS) Classifications of Export & Import Items, 2004–2009], the export obligation shall be fulfilled within a period of 90 days from the date of receipt of the first import consignment i.e. the date on which the first import consignment is cleared by the customs authorities against the authorisation.

However, in case of Advance Authorisations for drugs, which have been issued against a specific export order and with pre-importer condition, the period of fulfillment of export obligation shall commence from the date of import of the first consignment and shall be fulfilled within a period of 6 months. Similarly, in the case of advance authorisation for tea, the period of fulfillment of export obligation shall commence from the date of import of first consignment and should be fulfilled within a period of six months.

4.22.1 The request for extension in export obligation period may be made in the form given 'Aayaat Niryaat Form'. The Regional Authority shall grant one extension for a period of six months from the date of expiry of the original export obligation period to the authorisation holder subject to payment of composition fee of 2% of the duty saved on all the unutilized imported items as per authorisation.

Request for a further extension of six months may be considered by the Regional Authorities subject to payment of composition fee of 5% of the duty saved on all the unutilized imported items as per authorisation.

For all the case of export obligation extension above, the composition fee on the duty saved on all the unutilized imported items would be computed with reference to the actual exports and imports made by the Authorisation holder.

However, the facility of extension of export obligation period shall not be allowed in case of Advance Authorisation wherein import of penicillin and its salts [ITC(HS) Code No. 29411 010] and 6-APA [ITC(HS) Code No. 29411 050] have been allowed as an input. The Regional Authority shall make an endorsement in the Advance Authorisation to this effect.

However, such extensions would not be permitted in the case of the erstwhile Value Based Advance Licences (VABALs). Additionally, no extension in export obligation would be allowed in respect of authorisations where misrepresentation/ fraud has come to the notice of the Regional Authorities. Further, in respect of authorisations/licences where adjudication orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible.

4.22.2 The Customs may allow provisional clearance of export consignment as and when the Authorisation holder produces documentary evidence of having applied for EO extension to the concerned RA.

Revalidation of Authorisation

4.23 The Regional Authority may consider a request of the original authorisation holder and grant one revalidation for a period of six months from the date of expiry of the original authorisation. The request(s) for revalidation of authorisation shall be made in the form given in 'Aayaat Niryaat Form'.

Monitoring of Obligation

4.24 The Regional Authority, with whom the Undertaking is executed by the Advance Authorisation holder, shall maintain a proper record in a master register indicating the starting and closing dates of obligation period and other particulars to monitor the export obligation.

Within two months from the date of expiry of the period of obligation, the authorisation holder shall submit requisite evidence in discharge of the export obligation in accordance with paragraph 4.25 of the Handbook.

However, in respect of shipments where six months period (one year in case of status certificate holder) for realisation of foreign exchange has not become due, the Regional Authority shall not take action for non submission of bank certificate of exports and realisation provided the other document substantiating fulfillment of Export Obligation have been furnished.

4.24.1 In case the Authorisation holder fails to complete the export obligation or fails to submit the relevant information/documents, the Regional Authority shall take action by refusing further authorisations, enforce the condition of the authorisation and undertaking and also initiate penal action as per law.

Advance Authorisation for Annual Requirement

4.24A (a) The exporters eligible for such authorisations shall file an application in 'Aayaat Niryaat Form' to the Regional Authority under whose jurisdiction the manufacturing unit of the applicant is located.

The Head office/Registered office of the company can also file an application on behalf of the manufacturing unit. In such cases, the Head office/Registered office shall furnish full address of the factory where the inputs shall be used in the resultant product for exports.

In case of merchant exporters, the application shall be made by the Head office/Registered office mentioning the name and address of the supporting manufacturer.

which shall be endorsed on the condition sheet attached to the authorisation.

(b) The applicant shall have the flexibility to import any input in respect of items mentioned in the authorisation. Items reserved for imports by State Trading Enterprises cannot be imported against Advance Authorisation. However those items can be procured from State Trading Enterprises against ARO issued to Advance Authorisation holder. The Authorisation holder shall have to account for the inputs as per SION/individual norms fixed by Norms Committee within the time period prescribed in this regard.

In respect of export products for which Standard Input Output Norms does not exist, the authorisation holder shall submit an application in 'Aayaat Niryaat Form' alongwith prescribed documents to NC before making the shipment. The applicant shall also furnish Advance Authorisation for Annual Requirement number and date alongwith the file number from which the same was issued in the covering letter to the application.

In such cases where there is a change in SION/individual norms fixed by Norms Committee during the validity period of the authorisation, the Authorisation holder shall account for raw material in respect of the exports made prior to the date of amendment, as per pre-revised norms and for exports made on or after the date of amendment as per revised norms.

However, in respect of following inputs, the exporter shall be required to give declaraton with regard to technical characteristics, quality and specifications in the application for Advance Authorisation for annual requirement and in the shipping bills. The Regional Authority while issuing the authorisation shall mention the technical characteristics, quality and specifications in respect of such inputs :—

Alloy steel including stainless steel, copper alloy, synthetic rubber, bearings, solvents, perfumes/essential oils/aromatics chemicals, surfactants, relevant fabrics and marble.

(c) At the time of imports, the authorisation holder shall furnish the details of inputs to the Customs Authorities for making entries in the imports column. The Authorisation holder shall maintain the nexus in the imported inputs and the resultant product.

(d) The applicant shall furnish details of the export product group, CIF value of authorisation and FOB value of the export obligation. However, the Authorisation holder shall have the flexibility to export any product falling under the export product group using the duty exempted material.

(e) The authorisation shall be valid for 24 months for imports and exports from the date of its issuance. Revalidation shall be governed by paragraph 4.23 of this handbook. Each authorisation will have one port of registration for imports. Exports can take place from any port mentioned in paragraph 4.19.

The request(s) for revalidation of authorisation shall be made in 'Aayaat Niryaat Form'.

(f) Within the eligibility, an exporter may apply for one or more than one authorisations in a licensing year,

subject to the condition that against one port of registration only one authorisation can be issued for the same product group.

On completion of export obligation against one or more authorisations, all issued in the same licensing year, the entitlement of an exporter for that licensing year shall be deemed to be revived by an amount equivalent to the export obligation completed against the authorisation(s).

(g) After expiry of the export obligation period, including the extended export obligation period, if any, the authorisation holder shall furnish proof of having fulfilled export obligation by submitting the documents prescribing in paragraph 4.25. In case of bonafide default in fulfillment of export obligation, the Authorisation holder can apply for regularization in terms of paragraph 4.28.

4.24B The provisions contained in paragraph 4.24A shall also be applicable to "for intermediate supplies" so far as they are not inconsistent with the following.

The facility is also available for intermediate supplies for the cases where the intermediate supplier intends to supply the material against invalidation letters issue to the holders of Advance Authorisation. In such cases, a copy of the invalidation letter which makes the authorisation invalid for direct import of items to be supplied by the intermediate manufacturer will be given to the Authorisation holder and copy thereof will be sent to the intermediate supplier as well as the Regional Authority of the intermediate supplier.

However, once the Electronic message transfer facility among the Regional Authorities becomes fully operational the requirement of sending a copy of the invalidation letter/ARO to the Jurisdiction Regional Authority shall not be required.

Further the invalidation letters should also contain the Authorisation number and date of 'Advance Authorisation for annual Requirement' to enable proper accounting of the invalidation letters. These would be submitted to the Regional Authority concerned by the intermediate supplier for the purpose of closure of Authorisation.

Fulfillment of Export Obligation

4.25 The Authorisation holder shall furnish the following documents in support of having fulfilled the export obligation :—

A. For physical exports :—

(i) Bank Certificate of Exports and Realisation in the form given at Appendix-22A or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix-22B in case of offsetting of export proceeds. However, realisation of export proceeds shall not be insisted if the shipments are made against :

- (a) confirmed irrevocable letter of credit or
- (b) bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank.

- The stipulations at (a) or (b) above must be certified by the bank in column 14/15 of Appendix-22A.
- (ii) EP copy of the shipping bill(s) containing details of shipment effected or bill of export in case of export to SEZ.
 - (iii) A statement of exports giving details of shipping bill wise exports indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product.
 - (iv) A statement of imports indicating bill of entry wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.
- B. For deemed exports (including intermediate supplies) :
- (i) A copy of the invoice or a statement of invoices duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply.

However, in case of supply of items which are non-excisable or supply of excisable items to a unit producing non-excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise certification.

However, in respect of supplies to EOU/EHTP/ STP/ BTP, the supplier has the additional option to furnish a copy of CT-3ARE-3 duly signed by the jurisdictional excise authorities/Bond Officer certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply in lieu of the excise attested invoice(s) or statement of invoices as given above.

- (ii) Payment certificate from the project authority in the form given in Appendix-22C. In the case of supplies to EOUs/EHTPs/ STPs / BTPs deemed exports (including Intermediate Supplies), documentary evidence from the bank substantiating the realisation of proceeds from the Authorisation holder or EOUs/EHTPs/ STPs/ BTPs or the Project Authority, as the case may be, through the normal banking channel, shall be furnished in the form given at Appendix-22B. However realisation of proceeds shall not be insisted upon if the shipments are made against :
 - (a) confirmed irrevocable inland letter of credit or
 - (b) inland bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co-Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank.

The stipulations at (a) or (b) above must be certified by the bank in column 5,6,7 of Appendix-22B.
- (iii) A statement of supplies giving details of supply invoices and indicating the invoice number, date, FOR value as per invoices and description of product.

- (iv) A statement of imports indicating bill of entry-wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.

Redemption

4.26 In case the export obligation has been fulfilled, the Regional authority shall redeem the case.

After redemption, the Regional Authority shall forward a copy of the redemption letter indicating the shipping bill number(s), date(s), FOB value in Indian rupees as per shipping bill(s) and description of export product to the Customs Authority at the port of registration. Such details shall also be place by the zonal offices in their website immediately after issuance of the export obligation discharge/redemption letter/No. Bond Certificate and by DGFT Hqr. in DGFT website on monthly basis for the Customs Authority to access it from the website.

Before discharging BG/LUT against Physical Exports, the Customs shall verify that the details of the exports as given in the "Redemption Certificate" are as per their records. However, before discharging BG/LUT against Intermediate Supplies and Deemed Exports, the Customs shall verify the details of the supplies from the Central Excise Authorities/Bond Officer.

Ordinarily, redemption of BG/LUT shall not preclude the Customs Authority from taking action against the authorisation holder for any misrepresentation, mis-declaration and default detected subsequently.

Further, the Regional Authority shall also take action against the Authorisation holder in case of non-submission of Appendix-23, duly filled in, as stipulated in Paragraph 4.30 of this Handbook or for any misrepresentation, misdeclaration and default detected subsequently in the details declared and furnish in Appendix-23. An endorsement to this effect shall be made by the Regional Authority in the redemption certificate.

Transitional Arrangement for Licences issued upto 31-8-2004

4.27 The Advance Licence including Advance Licence for Annual Requirement issued upto 31-8-2004 shall be governed by the provisions contained in Chapter-7 of the Handbook (Vol. I) (RE-2001) and Chapter 4 of the Handbook (2002—2007 as Notified on 31-3-2002) respectively as amended from time to time, excepting the provision relating to clubbing and extension in E.O. period which shall be governed by the provisions of paragraph 4.20 and 4.22.1 respectively of this Handbook and any other provision, as notified by DGFT.

However, wherever Customs duty is to be paid on unutilised material, the same shall be paid alongwith interest @15% per annum thereon. This facility shall be available to all pending cases of regularisation of *bona fide* default against Advance Licences, irrespective of the date of its issuance including erstwhile Advance Licence for physical exports, Annual Advance Licence, Advance Licence for deemed exports or Special Imprest Licence and Advance Licence for Intermediate supply or Intermediate Licence.

Regularisation of Bona fide Default

4.28 The cases of a *bona fide* default in fulfilment of export obligation may be regularised by the Regional Authority in the manner indicated below:

- (i) If the export obligation is fulfilled in terms of value, but there is a shortfall in terms of quantity, the authorisation holder shall, for the regularisation, pay :—
 - (a) To the customs authority, customs duty on the unutilised value of the imported material alongwith interest at the rate of 15% per annum thereon; and
 - (b) An amount equivalent to 3% of the CIF value of unutilised imported material through a TR in the authorised branch of Central Bank of India indicating the "Head Account: 1453, Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head 102". The authorisation holder shall also be required to obtain a separate import licence for regularisation of the excess imported input. However, the provisions of this sub-paragraph shall not be applicable if the unutilised imported material was freely importable on the date of import.
- (ii) If the export obligation is fulfilled in terms of quantity but there is shortfall in terms of value, no penalty shall be imposed if the authorisation holder has achieved the minimum value addition prescribed in the policy and the procedure laid thereunder. However, if the value addition falls below the minimum value addition prescribed in the policy and the procedure laid thereunder the Authorisation holder shall be required to deposit an equivalent amount through TR in the authorised branch of Central Bank of India indicating the "Head of Account- 1453 Foreign Trade and Export Promotion— Minor Head – 102" so that the 100 times the deposited amount and the FOB value realised in Indian rupees together account for prescribed minimum value addition over the CIF value.

This shall be calculated with reference to actual quantity of exports and FOB value of realisation with reference to *pro rata* quantity of imports and CIF value. For example, if the export performance is only 50% quantitywise but import has been for the complete CIF value permitted, then the value addition would be calculated on a *pro rata* basis, i.e with reference to 50% of the CIF value of imports. This would accordingly imply that where the authorisation holder is unable to export, no penalty on valuewise shortfall shall be imposed.
- (iii) If the export obligation is not fulfilled both in terms of quantity and value, the Authorisation holder shall, for the regularisation, pay as per (i) and (ii) above.

- (iv) In case, an exporter is unable to complete the export obligation undertaken in full and he has not made any import under the Authorisation, the Authorisation holder will also have an option to get the Authorisation cancelled and apply for drawback after obtaining permission from the Customs Authorities for conversion of shipping bills to Drawback Shipping Bills.
- (v) The Regional Authority shall compare the relevant portion of Appendix-23 duly verified and certified by Chartered Accountant with that of norms allowed in the Authorisation(s) and the actual quantity imported against the Authorisation(s) in the beginning of the financial year for all such Authorisations redeemed in the preceding licencing year. In this verification process, in case if it is found that the Authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than importe, the Authorisation holder shall be liable to pay customs duty on the unutilized value of imported material alongwith interest @ 15% per annum thereon or effect additional export within the export obligation period.

Time Period for Depositing Fines, Customs Duty, etc.

4.29 The customs duty with interest to be recovered from the Authorisation holder on account of regularisation or enforcement of BG/LUT, as the case may be, shall be deposited by the Authorisation holder in relevant Head of Account of Customs Revenue i.e. "Major Head 0037- Customs and Minor Head 001- Import Duties in prescribed T.R. Challan within 30 days of the demand raised by the Regional/Customs authority and documentary evidence shall be produced to this effect to the Regional/Customs Authority immediately.

On receipt of such documentary evidence from the Authorisation holder, the Regional Authority shall intimate the details of the recovery/deposits made to the Customs Authority at the port of registration under intimation to Joint Secretary (Drawback), Department of Revenue, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, New Delhi.

The payment of amount of duty, interest and any dues for regularisation shall, however, be without prejudice to any other action that may be taken by the customs authorities at any stage under the Customs Act, 1962.

Maintenance of Proper Accounts

4.30 Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported/domestically procured goods against each Authorisation as prescribed in Appendix-23. These records are required to be sent to the concerned regional Authority(ies) at the beginning of each licencing year for all those authorisations, which have been redeemed in the previous licencing year. However, these records in the said format are required to be submitted for authorisation issued on or after 13-5-2005. Such records should be preserved for a period of at least three years from the date of redemption.

Duty Free Replenishment Certificate (DFRC)

4.31 The Policy of Duty Free Replenishment Certificate (DFRC) is given in Chapter 4 of the Policy. The exporter exporting under DFRC shall be required to give a declaration in the EP copy of the Shipping Bill indicating the serial number and product group of SION of the export product.

In case of export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the wastage norms as per paragraph 4A.2 of the Handbook of Procedures (Vol. I) may be indicated on the EP copy of the shipping bill.

However in respect of the following items, the exporter shall be required to give declaration with regard to technical characteristics, quality and specification in the shipping bill. The Regional Authority while issuing Duty Free Replenishment Certificate shall mention the technical characteristics, quality and specification in respect of such inputs:

Alloy steel including Stainless Steel, Copper Alloy, Synthetic Rubber, Bearings, Solvent, Perfumes/Essential Oil/Aromatic Chemicals, Surfactants, Relevant Fabrics, Marble.

The DFRC and the specific inputs procured against it are subject to actual user condition under the following circumstances:

- i. the export proceeds have not been realised and the exports have not been made under an irrevocable letter of credit or the bill of exchange is not avalised/co-accepted/guaranteed, or
- ii. the DFRC is issued against a SION with actual user condition, or
- iii. specific inputs under a SION are subject to actual user condition.

Under all other circumstances, the inputs procured against DFRC are freely transferable. However, in case of fuel, the same can only be transferred to agencies granted marketing rights by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

Items reserved for imports by State Trading Enterprises cannot be imported against DFRC. However those items can be procured from State Trading Enterprises against ARO issued to DFRC holder.

4.31A DFRC shall also be available for supplies mentioned in Chapter 8 of the Policy except for supplies made to DFRC holders. Such DFRC shall be issued with a single port of registration mentioned in paragraph 4.19 of the Handbook (Vol. I) as per option of the applicant.

The CIF value of DFRC shall be arrived at after discounting 20% from the FOR value of supply. The FOR

shall be calculated on the basis of the document mentioned in sub-paragraph (ii) below. The application shall be accompanied by the following —

- i. A copy of the Invoice duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply. However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a Project Authority Certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise certification.
- Notwithstanding the above, in respect of supplies to EOU/EHTP/ STP/ BTP, the supplier has the additional option to furnish a copy of CT-3/ ARE-3 duly signed by the jurisdictional excise authorities/Bond officer certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply shall be furnished.
- ii. Payment certificate from the project authority in the form given in Appendix-22C. In the case of Intermediate Supplies/ deemed exports, supplies to the EOUs/EHTPs/STPs/BTPs, documentary evidence from the bank substantiating the realisation of proceeds from the authorised holder or EOUs/ EHTPs/ STPs/ BTPs, as the case may be, through the normal banking channel, shall be furnished in the form given at Appendix- 22B.

However realisation of export proceeds shall not be insisted upon if the shipments are made against confirmed irrevocable inland letter of credit or inland bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank and the same is certified by the bank in column 5/6/7 of Appendix-22B. Exports made against the Government of India/EXIM Bank Line of Credit and exports made under Deferred Payment/Suppliers Line of Credit Contract backed by ECGC Cover would also be entitled for the benefit under DFRC Scheme.

Export/ Imports under DFRC

4.32 Export shipments under DFRC can be effected from any port mentioned in paragraph 4.19 of the Handbook and to any of the SEZs. The DFRC shall be issued with single port of registration, which will be the port from where the exports have been effected. However for import from a port other than the port of export, TRA shall be issued by the Customs authority at the port of export to the Customs authority at the port of import.

Filing of Application

4.33 An application for grant of DFRC may be made to the Regional Authority concerned in the form given in

'Aayaat Niryaat Form' alongwith the documents prescribed therein. An application for DFRC shall be filed only after realisation of export/supply proceeds.

However, in case of exports/supplies against :

- (a) confirmed irrevocable letter of credit or confirmed irrevocable inland letter of credit or
- (b) bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank,

The application may be filed after exports/supplies.

The FOB value shall be calculated on the basis of the Bank Realisation Certificate. However in case of exports of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the CIF value would be computed from the FOB value as per the value addition given in paragraph 4A.2.1 of Handbook of Procedures (Vol.1).

Time Period

4.34 The application for DFRC shall be filed within six months from the date of realisation in respect of all shipments/supply for which DFRC is being claimed.

4.34.1 In case of exports against confirmed irrevocable Letter of Credit/supply against confirmed irrevocable inland letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank, the DFRC shall be filed within six months from the date of exports/supply for all shipments in respect of which DFRC is being claimed.

4.34.2 For exports/supply against advance payment, DFRC shall be filed within six months from the date of exports against advance payment.

4.34.3 Wherever provisional shipment has been allowed by the customs authorities, DFRC against such exports shall be issued only after the release of the shipping bill by the Customs. The time limit for filing of application in such cases shall be six months from the date of release/date of printing of shipping bill or three months from date of realisation, whichever is later.

Frequency of Application

4.35 The applicant shall file one application relating to one export product group from one port of export. Where export product falling under one product group have been exported from different ports, the exporter shall file more than one application for the same export product group.

Split up Facility

4.35.1 For each duty credit certificate, split certificates subject to a minimum of Rs. 5 lakh each and multiples thereof may also be issued. A fee of Rs. 1000/- each shall be paid for each split certificate. However, a request for issuance of split certificate(s) shall be made at

the time of application only and shall not be considered at a later stage. The duty credit certificate shall be issued with a single port of registration.

Verification by Customs

4.36 The Regional Authority shall ensure that while issuing the DFRC, the Shipping Bill no(s) and date(s), FOB value in Indian rupees as per Shipping Bill(s) and description of export product are endorsed on the reverse of DFRC. Before allowing the imports against DFRC, the Customs shall verify that the details of the exports as given on the DFRC are as per their records.

The Regional Authority while issuing DFRC for deemed exports shall endorse a copy of the same to the Customs at the port of registration and a copy to Excise Authorities having jurisdiction over recipient unit of the deemed exports alongwith details of invoice giving item of supply, its quantity, value and date of such supply.

In case there is any variation in the details furnished by the Regional Authority and the record verified by the Excise Authority, the Excise authority shall intimate to the Regional Authority and Customs at the port of registration immediately. The customs authority at the port of registration shall get the details of the supplies verified from the jurisdictional Excise Authority before allowing clearance against the certificate.

Re-export of goods imported under DFRC Scheme

4.36A Goods imported under DFRC scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases 95% of the CIF value debited against DFRC for the export of such goods, shall be generated by the concerned Commissioner of Customs in the form of a Certificate, containing the amount generated and the details of the original DFRC. Based on the certificate, a fresh DFRC shall be issued by the concerned Regional Authority. The fresh DFRC, so issued, shall have the same port of registration and shall be valid for a period equivalent to the balance period available on the date of import of such defective/unfit goods.

Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)

4.37 The Policy relating to Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB) Scheme is given in Chapter-4 of the Policy. The duty credit under the scheme shall be calculated by taking into account the deemed import content of the said export product as per SION and the basic custom duty payable on such deemed imports. The value addition achieved by export of such product shall also be taken into account while determining the rate of duty credit under the scheme.

Fixation of DEPB Rate

4.38 'Aayaat Niryaat Form' prescribes the form regarding fixation of DEPB rates. All applications for

concerned Export Promotion Council which shall verify the FOB value of exports as well as the international price of inputs covered under SION.

Provisional DEPB Rate

4.38A To encourage diversification and to promote export of new products, the DEPB Committee would be empowered to notifying provisional DEPB rates. However, such DEPB rates would be valid for a limited period of time during which the exporter would furnish the data on export and import for the regular fixation of rates

Exports in anticipation of DEPB Rate

4.39 No exports shall be allowed under DEPB scheme unless the DEPB rate of the concerned export product is notified.

Port of Registration

4.40 The exports/imports made from the specified ports given shall be entitled for DEPB.

Sea Ports Mumbai, Kolkata, Cochin, Dahej, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagao, Mundra, Chennai, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Vishakhapatnam, Surat (Magdalla), Nagapattinam, Okha, Dharanagar, Jamnagar and Nhava Sheva.

Airports Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore Air Cargo Complex, Cochin, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Chennai.

ICDs Agra, Ahmedabad, Bangalore, Bhiwadi, Coimbatore, Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Faridabad, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Jodhpur, Kanpur, Kota, Ludhiana, Madurai and the land Customs station at Ranaghat Mallanpur, Moradabad, Meerut, Nagpur, Nasik, Gauhati (Amingaon), Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Rudrapur (Nainital), Salem Singanalur, Surat, Tirupur, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Waluj, Bhilwara, Pondicherry, Garlu-Harsara, Bhatinda, Dapoor, Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur Dadri and Tuticorin.

LCS Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Mahadipur and Dawki.

SEZ Exports made to any Special Economic Zone (SEZ), notified by the Central Government, are also entitled to DEPB and the port of registration in such cases will be the respective SEZ only.

Provided further that the Commissioner of Customs may, either by a public notice or on the written request of the exporter/DEBP holder, by special orders and subject to such conditions as may be specified by him permit imports or exports from any other sea port, airport, inland container depot or through a Land Customs Station.

4.40.1 The DEPB shall be issued with single port of registration, which will be the port from where the exports have been effected.

Maintenance of Record

4.40.2 Each Custom House at the ports shall maintain a separate record of the details of the exports made under the DEPB shipping bill.

Credit under DEPB and Present Market Value

4.41 In respect of products where the rate of credit entitlement under DEPB Scheme comes to 10% or more, the amount of credit against each such export product shall not exceed 50% of the Present Market Value (PMV) of the export product. At the time of export, the exporter shall declare on the shipping bill that the benefit under DEPB Scheme against the export product would not exceed 50% of the PMV of the export product.

However PMV declaration shall not be applicable for products for which value cap exists irrespective of the DEPB rate of the product.

Utilisation of DEPB credit

4.42 The credit under DEPB shall be utilised for payment of customs duty on any item which is freely importable.

Application for DEPB

4.43 An application for grant of credit under DEPB may be made to the Regional Authority concerned in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' alongwith the documents prescribed therein. The agency commission shall be allowed for the DEPB entitlement upto the limit of 12.5% of FOB value only. The FOB value in free foreign exchange shall be converted into Indian rupees as per the exchange rate for exports, notified by Ministry of Finance, as applicable on the date of order of "Let Export" by the Customs.

4.43A In respect of consignment exports wherein the exporter has declared the FOB value of the product on a provisional basis, the exporter shall be eligible for final assessment of such shipping bill based on the actual FOB realised upon sale of such goods in freely convertible currency. The agency commission shall be allowed for the DEPB entitlement upto the limit of 12.5% of FOB value only. However, the FOB value of foreign exchange shall be converted into Indian rupees as per the exchange rate for exports, notified by Ministry of Finance, as applicable on the date of order of "Let Export" by the Customs.

4.43B An application for grant of credit for supplies from DTA to SEZ can be made by the DTA unit or the SEZ

unit. The DTA unit may claim the benefits either from the Regional Authority or the Development Commissioner concerned. In case claim have been filed with the Regional Authority, the Regional Authority while allowing the benefits to the DTA unit will simultaneously endorse a copy of the communication to the concerned Development Commissioner alongwith the details of export documents against which benefits have been allowed for confirmation of the transaction involved. In case the DTA supplier prefers claim with the Development Commissioner, the Development Commissioner shall verify the Denied Entity List (DEL) status of the supplier from the DGFT website before allowing DEPB benefits. The SEZ unit will file application with the Development Commissioner concerned in 'Aayaat Niryaat Form' along with the following documents :

1. Bank receipt (in duplicate)/ demand draft evidencing payment of application fee in terms of Appendix 21B.
2. A copy of bill of exports issued by Customs in the SEZ.
3. A copy of invoice showing FOR value of supply, DEPB entitlement on such supply and total value realised from such sale.
4. Bank certificate of realisation in the form given in Appendix 22B.
5. In case SEZ unit opts to apply for the DEPB benefit for such supplies received, a disclaimer (along with the IEC of DTA Unit endorsed on it) certificate from DTA unit declaring that the DTA unit shall not claim any benefit on such supplies and authorising SEZ units to claim DEPB benefit on such supplies.

4.44 In cases where the applicant applies for DEPB after realisation or shipments are made against Confirmed irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank and certified by the bank in the relevant Bank certificate of export and Realisation, the DEPB shall be issued with transferable endorsement. In other cases, the DEPB shall be initially issued with non-transferable endorsement. Upon realisation of export proceeds, such DEPBs can be endorsed as transferable, if the applicant so desires.

Monitoring of Realisation

4.45 The Regional Authorities shall monitor the cases where the DEPB has been granted prior to realisation of export proceeds (except the cases where shipments are made against Confirmed irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co-Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank) so as to ensure that realisation takes place within the prescribed time failing which they shall initiate action for recovery of an amount equivalent to DEPB credit

with 15% interest. The recovered amount in such cases shall be deposited in the head of account of Customs as stated in paragraph 4.29.

4.45.1 If the export proceeds is not realised within six months or such extended period as may be allowed by RBI, the DEPB holder shall pay in cash an amount equivalent to the duty free credit utilised on imports, against such exports with 15% interest from the date of import till the date of deposit. In such cases, where the amount realised in foreign exchange is less than the amount on which DEPB credit has been obtained, the holder of DEPB shall pay, in cash, an amount proportionate to the duty free credit utilised on imports, with 15% interest from the date of imports till the date of deposit.

Time Period

4.46 The application for obtaining credit shall be filed within a period of twelve months from the date of exports or within six months from the date of realization or within three months from the date of printing/ release of shipping bill, whichever is later, in respect of shipments for which the claim have been filed.

4.47 Wherever provisional shipment has been allowed by the customs authorities, DEPB against such exports shall be issued only after the release of the shipping bill by the Customs. In such cases, application for DEPB shall be filed within six months from the date of release of such shipping bill or six months from the date of realisation, whichever is later.

Frequency of Application

4.48 All the shipping bills in any one application must relate to exports made from one Custom House only. There is no limit on the number of shipping bills which can be filed through EDI mode in a single application.

Verification by Customs

4.49 In case of EDI shipping bills before 1-10-2005 and non-EDI shipping bills, the Regional Authority shall ensure that while issuing the DEPB, the Shipping Bill No(s), and date(s), FOB value in Indian rupees as per Shipping Bill(s) and description of export product are endorsed on the DEPB. Before allowing the imports against such DEPB the Customs shall verify that the details of the exports, as given on the DEPB, are as per their records. However, in case of EDI shipping bills issued on or after 1-10-2005 from EDI ports which are being transmitted electronically by Customs to DGFT, the DEPBs issued shall be sent to Customs at the port of registration through an electronic message exchange system and the DEPB shall be registered at the port of registration electronically. No verification of shipping bills against which such DEPBs have been issued will be required before allowing imports against the DEPBs.

Revalidation

4.50 No revalidation shall be granted beyond the original period of validity of DEPB unless it expires in the custody of the Regional/Customs Authorities as per the provisions under para 2.13 of the Handbook.

Re-export of goods imported under DEPB Scheme

4.51 Goods imported under DEPB scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases 98% of the credit amount debited against DEPB for the export of such goods, shall be generated by the concerned Commissioner of Customs in the form of a Certificate, containing the amount generated and the details of the original DEPB. Based on the certificate, a fresh DEPB shall be issued by the concerned Regional Authority. The fresh DEPB, so issued, shall have the same port of registration and shall be valid for a period equivalent to the balance period available on the date of import of such defective/unfit goods.

Issuance of DEPB and other duty credit certificates/DFRC against lost EP copy of the Shipping Bills

4.52 In case where EP copy of the Shipping Bill has been lost, the DEPB and other duty credit certificates/DFRC claim can be considered subject to submission of the following documents:-

- a) A duplicate/certified copy of the Shipping Bill issued by the Customs Authority in lieu of original;
- b) An application fee equivalent to 2% of the DEPB or other duty credit entitlement or 1% of DFRC entitlement, as the case may be, in respect of lost Shipping Bills. However, no fee shall be charged when the Shipping Bill is lost by the Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted;
- c) An affidavit by the exporter about the loss of Shipping Bills and an undertaking to surrender it immediately to the concerned Regional Authorities, in case the same is found subsequently.
- d) An indemnity bond by the exporter to the effect that he would indemnify the Government for the financial loss if any on account of DEPB or other duty credit certificate /DFRC issued against lost Shipping Bills.

The Customs Authority, before allowing clearance, shall ensure that no DEPB/DFRC benefit has been availed against the same shipping bill.

4.52.1 The claim against the lost Shipping Bill shall be preferred within a period of six months from the date of release of duplicate copy of shipping bill and any application received thereafter will be rejected. However, if a provisionally assessed DEPB shipping bill is lost, the time period for filing an application for DEPB would be six months from the date of release of the finally assessed shipping bill.

Loss of Original Bank Certificate

4.53 In such cases where original bank certificate has been lost, the DEPB/DFRC claim can be considered subject to submission of following documents:

- a) A duplicate copy of the Bank Certificate issued by the bank authority in lieu of original loss.
- b) An application fee equivalent to 2% of the DEPB entitlement or 1% of DFRC entitlement, as the case may be, in respect of lost Bank Realisation Certificate.
- c) An affidavit by the exporter about the loss of Bank Certificate and an undertaking to surrender it immediately to the concerned Regional Authorities, in case the same is found subsequently.
- d) An indemnity bond by the exporter to the effect that he would indemnify the Government for the financial loss if any on account of DEPB/DFRC issued against lost Bank Certificate.

The claim against the lost Bank Certificate shall be preferred within a period of six months from the date of realisation and application received thereafter will be rejected.

In such cases, where both the documents have been lost, the exporter shall follow the procedure laid down in paragraph 4.51 and 4.52.

Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme

4.54 The Policy relating to the Duty Free Import Authorisation Scheme is prescribed in Chapter 4 of the Policy.

Application

4.55 An application in 'Aayaat Niryaat Form' with the import entitlement as per SION, along with documents prescribed in the application form, shall be submitted to the Regional Authority concerned.

4.55.1 In case of export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the quantity, wastage and the value addition norms shall be as prescribed in paragraph 4A of the Policy and Handbook of Procedure (Vol. I).

4.55.2 Applications, where Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudoephedrine is required as an input for import and prescribed in SION, shall be filed with the Regional Authorities concerned.

Copies of such applications shall also be simultaneously endorsed to the Drug Controller of India, Nirman Bhawan, New Delhi, Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and the respective Zonal Director of the Narcotics Control Bureau, along with a declaration that the applicant will maintain the prescribed records and also submit the prescribed returns.

Duty free import of spices (covered by Chapter 9 of the ITC (HS) Classifications of Export and Import items.

2004—09) for export under DFIA scheme shall be permitted only for value addition purposes like crushing/grounding/sterilization or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, re-packing etc.

The Regional Authority, while issuing the DFIA for the import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo-ephedrine, shall endorse a condition that before effecting imports, NOC shall be obtained from the Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and shall also endorse a copy of the Authorisation to the Drug Controller, Nirman Bhawan, New Delhi and the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.

4.55.3 However in respect of the following items, the exporter shall be required to give declaration with regard to technical characteristics, quality and specification in the shipping bill. The Regional Authority while issuing DFIA shall mention the technical characteristics, quality and specification in respect of such inputs :

Alloy steel including Stainless Steel, Copper Alloy, Synthetic Rubber, Bearings, Solvent, Perfumes/Essential Oil/Aromatic Chemicals, Surfactants, Relevant Fabrics, Marble, Articles made of polypropylene, Articles made of Paper and Paper Board, Insecticides, Lead Ingots, Zinc Ingots, Citric Acid, Relevant Glass fibre reinforcement (Glass fibre, Chopped/Stranded Mat, Roving Woven Surfacing Mat), Relevant Synthetic Resins (unsaturated polyester resin, Epoxy Resin, Vinyl Ester Resin, Hydroxy Ethyl Cellulose), Lining Material.

4.55.4 Exports made against the Government of India/EXIM Bank Line of Credit would be entitled for benefits under the DFIA Scheme. Further, exports made under Deferred Payment/Suppliers Line of Credit Contract backed by ECGC Cover would also be entitled for the benefit under the Scheme.

DFIA for applicants with multi units

4.56 Transfer of any duty free material imported or procured against non-transferable DFIA from one unit of the company to another unit of the same company for manufacturing purpose shall be done with the prior intimation to the jurisdictional Excise Authorities with a clear understanding that no benefit of CENVAT shall be claimed on such transferred inputs. In case of non-excisable company/products, the units should maintain a proper record of the same. However to avail the facility all such units should be available in the IEC certificate and follow the rules and regulations of Central Excise for job work.

DFIA for Free of Cost and Paid Material

4.57 An exporter may apply for a DFIA for import of items as per SION, some or all of which may also include items that are supplied free of cost.

In such cases, for calculation of value addition, the notional value of free of cost inputs along with value of other duty-free inputs shall be taken into consideration. However, if all the inputs are supplied free of cost, the

exporter shall also have the option to follow the provision prescribed in paragraph 4.2.7 of the Policy.

In such cases, a specific endorsement shall be made on the exchange control copy of the DFIA disallowing remittances for the material being supplied free of cost. All inputs imported shall be utilised in the manufacturing of the product except the wastage.

The value addition in the case of such DFIA's would be computed by adding the notional value of the free of cost material to both the CIF value of imports and FOB value of exports.

Financial Powers

4.58 The financial powers under DFIA scheme shall be as per paragraph 4.8 of this Handbook.

Description of a DFIA

4.59 A DFIA shall specify :

- (a) the names and description of items to be imported and exported/supplied;
- (b) the quantity of each item to be imported or wherever the quantity cannot be indicated, the value of the item shall be indicated. However, if in Standard input output norms, the quantity and value of individual inputs is limiting factor, the same shall be applicable.
- (c) the aggregate CIF value of imports; and
- (d) the FOB/FOR value and quantity of export/supplies.

Exports in Anticipation of DFIA

4.60 Exports/supplies made from the date of EDI generated file number for a DFIA, may be accepted towards discharge of export obligation. Shipping/Supply document(s) should be endorsed with the File Number or the Authorisation Number to establish co-relation of the exports/supplies with the authorisation issued. If the application is approved, the authorisation shall be issued based on the input-output norms in force on the date of receipt of the application by the Regional Authority in proportion to the provisional exports/supplies already made till any amendment in the norms is notified. For the remaining exports, the Policy/Procedures in force on the date of issue of the authorisation shall be applicable.

4.60.1 The exports/supplies made in anticipation of the grant of a DFIA shall be entirely on the risk and responsibility of the exporter.

4.60.2 The conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permitted by the Customs Authorities in case the application for a DFIA is rejected or modified by the Regional Authority.

Port of Registration

4.61 The DFIA shall be issued for the purpose of import and export through port(s) as specified in paragraph 4.19 of this Handbook.

Acceptance of BG/LUT

4.62 At the time of issue of the non transferable DFIA, the acceptance of the undertaking given by the applicant to the Regional Authority concerned in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' will be endorsed on the reverse of the DFIA.

Note : - No BG/LUT will be required where the specified export obligation has been fulfilled before making any import. In case of partial fulfillment of export obligation before effecting any imports, the BG/LUT may be reduced proportionately.

Enhancement/Reduction in the Value of DFIA

4.63 In respect of a DFIA, the Regional Authority concerned (as per their financial powers) may consider a request for enhancement/reduction in the CIF value, FOB value, quantities of import or export of the certificate, provided the value addition after such amendment does not fall below the stipulated minimum value addition (as per the policy and the procedure laid thereunder) and provided there is no change in the input-output norms and the Policy under which the authorisation was issued.

The request for pro-rata enhancement in value and quantity may be made either before or after exports. In such cases where there is a change in the SION prior to the export of the said product, the pro-rata enhancement shall be given after calculating the entitlement on the revised SION.

The application for the enhancement/reduction in the value or quantity of the authorisation shall be made in 'Aayaat Niryaat Form' of the Handbook of Procedure (Vol. I).

Export Obligation period and its extension

4.64 The period of fulfillment of export obligation and its extension shall be governed as per the provision contained in paragraph 4.22 of this Handbook. However, any extension beyond 36 months from the date of issuance of the authorisation shall not be allowed.

Revalidation of DFIA

4.65 Facility of revalidation shall be available to the DFIA holder as per the provision contained in paragraph 4.23 of this Handbook.

Re-export of goods imported under DFIA Scheme

4.66 Goods imported against transferable DFIA, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases 95% of the CIF value debited against DFIA for the export of such goods, shall be generated by the concerned Commissioner of Customs in the form of an authorisation, containing the amount generated and the details of the original DFIA.

Based on the certificate, a fresh DFIA shall be issued by the concerned Regional Authority.

The fresh DFIA, so issued, shall have the same port of registration and shall be valid for a period equivalent to the balance period available on the date of import of such defective/unfit goods.

Monitoring of Export Obligation

4.67 The Regional Authority, with whom the undertaking is executed by the DFIA holder, shall maintain a proper record in a master register indicating the starting and closing dates of obligation period and other particulars to monitor the export obligation.

Within two months from the date of expiry of the period of obligation, the certificate holder shall submit requisite evidence in discharge of the export obligation in accordance with paragraph 4.25 of this Handbook.

However, in respect of shipments where six months period (one year in case of status certificate holder) for realisation of foreign exchange has not become due, the Regional Authority shall not take action for non submission of bank certificate of exports and realisation provided the other document(s) substantiating fulfillment of Export Obligation have been furnished.

In case the Authorisation holder fails to complete the export obligation or fails to submit the relevant information/documents, the Regional Authority shall take action by refusing further authorisations, enforce the condition of the authorisation and undertaking and also initiate penal action as per law.

Fulfillment of Export Obligation

4.68 The Authorisation holder shall furnish the following documents in support of having fulfilled the export obligation :-

A. For physical exports :-

- (i) Bank Certificate of Exports and Realisation in the form given at Appendix-22A or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix-22B in case of offsetting of export proceeds. However, realisation of export proceeds shall not be insisted if the shipments are made against;
 - (a) Confirmed irrevocable letter of credit; or
 - (b) bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank
- (ii) The stipulations at (a) or (b) above must be certified by the bank in column 14/15 of Appendix-22A.
- (iii) EP copy of the shipping bill(s) containing details of shipment effected or bill of export in case of export to SEZ.

A statement of exports giving details of shipping bill wise exports indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product.

A statement of imports indicating bill of entry wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.

B For deemed exports (including intermediate supplies) :

- (i) A copy of the invoice or a statement of invoices duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply.

However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise certification.

However, in respect of supplies to EOU/EHTP/STP/BTP, the supplier has the additional option to furnish a copy of ARE-3/CT-3 form duly signed by the jurisdictional excise authorities/Bond Officer certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply in lieu of the excise attested invoice (s) or statement of invoices as given above.

- (ii) Payment certificate from the project authority in the form given in Appendix-22C. In the case of supplies to EOUs/EHTPs/STPs/BTPs, deemed exports (including Intermediate Supplies), documentary evidence from the bank substantiating the realisation of proceeds from the Authorisation holder or EOUs/EHTPs/STPs/BTPs or the Project Authority, as the case may be, through the normal banking channel, shall be furnished in the form given at Appendix-22B. However realisation of proceeds shall not be insisted upon if the shipments are made against :

- (a) confirmed irrevocable inland letter of credit; or
(b) inland bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank.

The stipulations at (a) or (b) above must be certified by the bank in column 5/6/7 of Appendix-22B.

- (iii) A statement of supplies given details of supply invoices and indicating the invoice number, date FOR value as per invoices and description of product.
(iv) A statement of imports indicating bill of entry wise item of import, quantity of import and its CIF value.

Maintenance of proper accounts of the inputs

4.69 The original DFIA holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty

free imported/domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix-23. These records are required to be sent to the concerned Regional Authority (ies) along with the request for bond waiver/redemption/discharge of export obligation/transferability. Such records should be preserved for a period of at least three years from the date of redemption.

Redemption

4.70 In case the export obligation has been fulfilled, the Regional Authority shall redeem the case.

After redemption, the Regional Authority shall forward copy of the redemption letter indicating the shipping bill number(s), date(s), FOB value in Indian rupees as per shipping bill(s) and description of export product to the Customs Authority at the port of registration. Such details shall also be placed by the Zonal Offices in their website immediately after issuance of the export obligation discharge/redemption letter/ 'No Bond Certificate' and by DGFT HQr in DGFT website on monthly basis for the Customs Authority to access it from the website.

Before discharging BG/LUT against Physical Exports, the Customs shall verify that the details of the exports as given in the "Redemption Certificate", are as per their records. However before discharging BG/LUT against Intermediate Supplies and Deemed Exports, the Customs shall verify the details of the supplies from the Central Excise Authorities/Bond Officer.

Ordinarily, redemption of BG/LUT shall not preclude the customs authority from taking action against the Authorisation holder for any misrepresentation, mis-declaration and default detected subsequently.

Further the Regional Authority shall also take action against the certificate holder in case of non-submission of Appendix 23, duly filled in, as stipulated in Paragraph 4.30 of Handbook, Vol. 1 or for any misrepresentation, misdeclaration and default detected subsequently in the details declared and furnished in Appendix 23. An endorsement to this effect shall be made by the Regional Authority in the redemption certificate.

The cancellation/redemption of BG/LUT would be undertaken by the Customs within 30 days of issue of EODC/bond waiver by the Regional Authority.

Regularisation of Bonafide default

- 4.71(a) The cases of a bonafide default in fulfillment of export obligation may be regularised by the Regional Authority in the manner prescribed in paragraph 4.28 of this Handbook.

Transferability of the DFIA

4.72 Once the export obligation is fulfilled and the required documents as stipulated in paragraph 4.68 of this Handbook has been furnished, the Regional Authority shall make the authorisation transferable subject to the

conditions stipulated for this scheme. However the restricted item endorsed in the authorisation shall be allowed to be transferred only against a separate import licence/permission issued as per Foreign Trade Policy and the procedure laid thereunder.

GEMS AND JEWELLERY

4A. The Policy relating to Gem Replenishment Authorisation, and scheme for gold/silver/platinum jewellery is given in paragraph 4A of Chapter-4 of the Policy.

Replenishment Authorisation

4A.1 An application for REP Authorisation may be made in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' alongwith the documents prescribed therein to the Regional Authority concerned as given in Appendix-1A.

4A.1.1 The application shall be filed within six months following the month/quarter during which the export proceeds are realised. For export proceeds realised during the month/quarter, consolidated application for entire month/quarter shall be filed. However, if any supplementary application is to be filed, it may be accepted with a cut of 10% on entitlement. In case of third party exports, Replenishment benefit shall be admissible provided the EP copy of the Shipping Bill shows the names of both the manufacturer and the third party and REP Authorisation against such exports is claimed by either of the parties after furnishing a disclaimer (along with the IEC Number) from the other party. REP Authorisations will be transferable.

4A.1.2 In case where part payment has been realised against an invoice, the application for REP Authorisation may be made within six months following the month during which part payment was realised, provided;

- a) Not more than two such applications may be made for each such invoice; and
- b) The first such application shall be made only after 50% of the proceeds of the invoice is realised.

4A.1.3 In case where payment is received in advance and exports take place subsequently, the application for REP Authorisation shall be filed within six months following the month during which the exports are made.

4A.1.4 For the purpose of clarity, it is again reiterated that the month in which the export has been made in the case of advance payment and the month in which export proceeds have been realised in part or full after making of the exports, shall be excluded while calculating the period of six months for the purpose of filing of application for REP Authorisation.

Wastage Norms

4A.2 The wastage or manufacturing loss on gold/silver/platinum jewellery and articles thereof is as follows:

Sl. No.	Item of Exports	Percentage of wastage by weight with reference to Gold/Platinum/Silver content in the export item	
		Gold/Platinum	Silver
(a)	Plain jewellery and articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads / imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones.	3.5%	4.5%
(b)	Studded jewellery and articles thereof.	9.0%	10%
(c)	Mountings and findings manufactured (by non-mechanised process) indigenously.	3.5%	4.5%
(d)	Any jewellery/articles manufactured by a fully mechanised process and unstudded.	1.25%	1.25%
(e)	Mountings, whether imported or indigenously procured/manufactured, used in the studded jewellery.	2.5%	2.5%
(f)	Gold/silver/platinum medallions and coins (excluding the coins of the nature of the legal tender).	0.25%	0.25%
(g)	Findings and mountings manufactured by mechanized process.	1.25%	1.25%

Value Addition

4A.2.1 Under the scheme for export of jewellery, the value addition shall be calculated as per paragraph 4A.6 of FTP.

The minimum value addition shall be as mentioned below:

Sl. No.	Item of Exports	Minimum Value Addition
1	2	3
(a)	Plain gold/platinum /silver jewellery/ Articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads/Imitation stones, precious stones and semi-precious stones, cubic zirconia, diamonds, precious and semi-precious stones.	4.5%

1	2	3
(b)	All types of Studded gold/platinum/silver jewellery and articles thereof.	15%
(c)	Any jewellery/articles manufactured by fully mechanised process.	3%
(d)	Gold/silver/platinum medallions & coins (excluding the coins of the nature of legal tender).	3%
(e)	Gold/silver/platinum findings/mountings manufactured by mechanised process.	5%

4A.2.2 The entitlement of quantity of gold/silver/platinum against the export shall be the quantity of gold/silver/platinum in the item of export plus the admissible wastage/manufacturing loss.

Loss of Gem and Jewellery

4A.3 Consignments of gem and jewellery items exported out of the country and lost in transit after exports, where foreign exchange against such exports has been realised or insurance claims settled, will also be eligible for REP Authorisation.

Gem & Jewellery Replenishment Authorisations

4A.4 The Gem REP Authorisations shall be valid for import of precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls. In addition, the Authorisations shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 5% of the value of the Authorisations within its overall CIF value. The Gem REP Authorisations issued against export of studded gold/silver/platinum jewellery articles, shall also be valid for import of cut and polished precious/semi-precious stones other than emerald upto 10% of the CIF value of the Authorisation, within its overall CIF value.

4A.4.1 The Gem REP Authorisation, are available as per the scale given in Appendix-12B.

Filing of Application

4A.4.2 (i) An application for Gem Rep Authorisation may be given to the Regional authority concerned as given in Appendix-1A in the form given in Appendix-22F alongwith the documents prescribed therein.

(ii) In case E.P Copy of the Shipping Bill and Customs attested invoice is submitted to the nominated agencies, the exporter shall furnish a self certified photo copy of the same along with a certificate from the nominated agencies certifying the carat/value of studdings

in case of studded jewellery and excess the value addition achieved in the case of plain jewellery and articles.

(iii) The provision of paragraph 4A.1.1 to 4A.1.4 will also be applicable for Gem Rep Authorisation.

Agency Commission

4A.5 The exporter availing the scheme of gold/silver/platinum jewellery are allowed to pay agency commission. The value addition shall be calculated after deducting agency commission. Wherever such agency commission is paid, the value addition shall be correspondingly increased by the percentage of agency commission.

Endorsement on Shipping Bill and Invoice

4A.6 At the time of export of jewellery, the shipping bill and the invoice presented to the Customs Authorities shall contain the description of the item, its purity, weight of gold/silver/platinum content, wastage claimed thereon, total weight of gold/silver/platinum content plus wastage claimed and its equivalent quantity in terms of 0.995/0.999 fineness for gold/silver and in terms of 0.9999 fineness for platinum and its value, fob value of exports and value addition achieved. If the purity of gold/silver/platinum used is the same in respect of all or some of the items made out from each of these metals for export, the exporter may give the total weight of gold/silver/platinum and other details of such similar items which are of the same purity. In case of studded items, the shipping bill shall also contain the description, weight and value of the precious/semi-precious stones/diamonds/pearls used in manufacture, and the weight/value of any other precious metal used for alloying the gold/silver.

Conditions of Exports

4A.7 The exports shall be allowed by the Customs Authorities provided the endorsement made on the shipping bill and the invoice are correct and the value addition achieved is not below the minimum prescribed in the Policy.

Proof of Exports

4A.8 The exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, by furnishing the following documents:

- E.P copy of the shipping bill;
- Customs attested invoice;
- Bank certificate of export in the form given in Appendix-22A showing that documents have been sent for negotiation/collection; and
- A declaration on the following lines:

"I/We declare that outstanding realisation of

export proceeds beyond 180 days does not exceed 10% of average exports of preceding three licensing years. I/We further declare that no export proceeds are outstanding beyond one year or such extended period for which RBI permission has been obtained."

In case of Personal carriage of jewellery by foreign buyer, the following documents should be submitted by the exporter/seller as proof of exports for claiming export entitlements :

- (a) Copy of the shipping bill filed by the Indian Seller;
- (b) A copy of the Currency Declaration Form filed by the Foreign Buyer with the Customs at the time of his arrival; and
- (c) Foreign Exchange Encashment Certificate from the Bank.

In addition to this, Personal Carriage on Documents Against Acceptance (DA)/ Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. The exporter will have to furnish the following documents as proof of exports for claiming export entitlements:

- (i) Copy of Shipping Bill filed by the Indian Seller; and
- (ii) Bank Certificate of Export and Realisation Instructions issued by the Customs Department in this regard should be followed mutatis mutandis.

Conversion of Purity/Fineness

4A.9 For conversion of quantity of gold/ silver/ platinum in terms of equivalent quantity in terms of fineness, the following formula shall be used :

- (i) Where items of gold has been exported in terms of carats, the quantity of gold shall be multiplied by the number of carat of gold exported, divided by 24 and thereafter again divided by 0.995/0.999/0.900 to arrive at the equivalent quantity of gold in terms of fineness of 0.995/0.999/0.900 respectively; and
- (ii) Wherever the purity of the item of export is expressed in terms of fineness, the quantity of gold/silver/platinum shall be multiplied by the fineness of gold/silver/platinum exported and thereafter divided by 0.995/0.999/0.900 to arrive at the equivalent quantity of gold/ silver/ platinum in terms of 0.995/0.999/0.900 fineness respectively.

Release of Gold/Silver/ Platinum by Nominated Agencies

4A.10 The gold/silver/platinum shall be released to the exporter of jewellery by the nominated agencies/RBI authorised banks in multiples of 10 gms. or in Ten Tola Bars in respect of golds. However, silver shall be released to the exporters in multiples of 1 Kg. only. Any balance of gold/ silver/ platinum shall be available to the exporters along with his future entitlement. The gold/ silver shall be released by the nominated agencies in terms of 0.995 fineness or more and platinum in terms of 0.900 fineness or more.

Terms of payment

4A.11 Export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof shall be against irrevocable letter of credit, payment of cash on delivery basis, Documents Against Acceptance (DA) basis or advance payment in foreign exchange.

Port of Export

4A.12 Exports under the schemes of gold/silver/ platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai, Calcutta, Chennai, Cochin, Delhi, Jaipur, Bangalore, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Dabolin Airport, Goa and Hyderabad. Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai, Calcutta, Chennai, Cochin Coimbatore, Delhi, Jaipur, Bangalore, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakhs per consignment.

Export by Post

4A.13 Policy for export of gems and jewellery parcel by post is given in paragraph 4A.17 of the policy. At the time of exports, the exporter shall submit the following documents :

- (i) Shipping bills or invoice presented at the foreign Post Office;
- (ii) Certificate from nominated agencies indicating the price at which gold/ silver/platinum was booked or given on outright sale basis or loan basis;
- (iii) Three copies of invoice.

4A.14 Deleted

Export Against Supply By Foreign Buyer

4A.15 Before clearance of each consignment of import supplied by the foreign buyer, the nominated agency shall execute a bond with the Customs, undertaking to export within the period stipulated in the contract, gold/ silver/platinum jewellery or articles equivalent to the entire import quantity of gold/silver/platinum, mountings and findings etc excluding the admissible wastage.

In case of direct supply of gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum and plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery to status holder/ exporter, the Status Holder/exporter shall furnish a Bank Guarantee/LUT, as per Customs Rules and regulations to the Customs equivalent to the Customs Duty leviable on imported gold/ silver/ platinum, alloys, findings and mountings of gold/ silver/ platinum and plain semi-finished gold/ silver/ platinum jewellery etc.

The Bank Guarantee/LUT, as the case may be, executed with the Customs shall be valid for one year. In case of direct supply to the Status Holder/exporter, exports shall be completed within 90 days. In case of non-fulfillment of export obligation/non-achievement of stipulated value addition, Customs Department shall proceed to recover custom duty alongwith interest which may include enforcement of Bank Guarantee/LUT, as the case may be. Besides the importer will be liable to penal action under the Customs Act.

4A.15.1 The nominated agency/Status Holder/exporter shall be liable to pay customs duty leviable on that quantity which is proved to have been not exported.

4A.15.2 The goods shall be cleared through Customs by the nominated agency Status Holder/exporter. Even where export order is received by an Associate, the goods shall be cleared through Customs by the nominated agency only and not the Associate. The associate shall, in such cases, authorise the nominated agency to act as its agent to file bill of entry and shipping bill.

4A.15.3 At the time of export, the shipping bill presented to the Customs shall also contain the following:

- (i) Name and address of the associate/Status Holder/exporter;
- (ii) An endorsement by the nominated agency that the export is made against an order received by the concerned associate, its date of registration with the nominated agency. In case of exports by Status Holder/exporter, a Self Declaration shall be provided to this effect;
- (iii) The name of the Customs House through which gold/silver/platinum/plain semi-finished gold/ silver/ platinum jewellery was imported and the corresponding Bill of Entry No. and date and the date of import.

4A.15.4 Each shipping bill shall be valid for exports only through the Customs House located at the place where the office of the nominated agency/Status Holder/exporter concerned is situated. It shall be valid for shipment for a period of seven days including the date on which the endorsement was made by the nominated agency in case of exports through nominated agency. If the exports cannot be made within this period, the exporter shall file a fresh shipping bill.

4A.15.5 At the time of export, the exporter shall submit the following documents:

- (i) Shipping bill with two extra copies where exports are made from a Customs House other than the Customs House through which the corresponding import of gold/ silver/ platinum/ plain semi-finished gold/silver/ platinum jewellery was effected. In other cases, shipping bill with an extra copy;
- (ii) Three copies of invoice;
- (iii) Certificate from the nominated agency indicating the quantity and value of items supplied by the foreign buyer.

4A.15.6 The customs authorities shall return two copies of the shipping bill and the connected invoice duly attested. One copy shall be sent to the person who presented the documents and the other copy shall be sent by the Customs to the office of the Nominated Agency/ Status holder/exporter.

4A.15.7 In case of exports through Nominated Agency, the exporter shall submit proof of exports to the Nominated Agency within 15 days of exports, who shall, after verifying the documents, release admissible quantity of the gold/ silver/platinum etc. to the exporter.

4A.15.8 The exporter may also obtain, in advance, gold/silver/platinum etc. supplied by the foreign buyer by furnishing a bank guarantee for an amount equal to the international price of such items and Bank Guarantee/LUT, as the case may be for the customs duty payable thereon. The bank guarantee/LUT shall be redeemed only when the exporter has furnished proof of exports to the Nominated Agency and accounted for the use of items supplied in advance in the export product.

4A.15.9 For the purpose of redemption of bond/Bank Guarantee/LUT, as the case may be, executed with the Customs, the Nominated Agency/Status Holder/exporter shall furnish a statement indicating the items, its quantity and value supplied by the foreign buyer, the corresponding Bill of Entry number and date, number of each of the shipping bills against which corresponding exports was made.

Maintenance of Accounts

4A.16 The Nominated Agency shall maintain complete account, consignment-wise, of the gold, silver, platinum, mountings, findings/plain semi-finished gold/ silver/platinum jewellery etc. imported for execution of each export order, the exports effected and the quantity of gold, silver, platinum mountings, findings etc. released against such exports. In case of direct exports, similar accounts shall also be maintained by the Status Holder. Such accounts shall be maintained for a minimum period of three years from the date of exports.

Export Through Exhibitions/Export Promotion Tours/ Export of Branded Jewellery

4A.17 The Nominated Agencies shall produce to the Customs Authorities letter in original or its certified copy, containing Government's approval for holding the exhibition/export of branded jewellery. Any other person shall produce to the Asstt. Commissioner, Customs the letter in original or its certified copy containing GJEPC's approval for holding the exhibitions/export promotion tour/export of branded jewellery.

In case of re-import, such items, on arrival, shall be verified along with the export documents before clearance.

4A.18 (a) The exports under this scheme shall be subject to the following conditions for the following modes of export:

- (i) Export of Gems and Jewellery for holding/participating in overseas exhibition.

The export under this scheme shall be subject to the following conditions:

Items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of the close of the exhibition. However, in case the exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of the first exhibition, then the 60 days shall be counted from the date of close of the last exhibition. In case of personal carriage of gems and jewellery for holding/participating in overseas exhibitions, the value of such gems and jewellery shall not exceed US \$2 million. The gold/silver/platinum content on items sold in such exhibitions may be imported as replenishment. The exporter shall take replenishment from the Nominated Agency within 120 days from the close of the exhibition gold/silver/platinum for the purpose of replenishment content against the items sold abroad in exhibition.

- (ii) Personal Carriage of gems & jewellery or export through airfreight/post parcel route for Export Promotion Tours/photo shoots/fashion shows overseas.

Personal carriage/export through airfreight/post parcel route of gold/silver/platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US\$ 100,000 for export promotion tours/photo shoots/fashion shows and temporary display/sale abroad is also

permitted with the approval of Gem & Jewellery & Jewellery Export Promotion Council subject to the condition that the promoter would bring back the jewellery/goods or repatriate the sale proceeds within 45 days from the date of departure through normal banking channel. In case of personal carriage for export promotion tours, the exporter shall declare personal carriage of such samples to the Customs while leaving the country and obtain necessary endorsement on the Export Certificate issued by Jewellery Appraiser of the Customs. In such cases the exporter shall book with the nominated agency, within 120 days after the export promotion tour or the expiry of the stipulated period of 45 days, whichever is earlier, gold/silver/platinum for the purpose of replenishment content against the items sold abroad.

- (iii) Export of branded jewellery.

Export of branded jewellery is also permitted with the approval of Gem & Jewellery and Jewellery Export Promotion Council for display/sale in the permitted shops set up abroad or in the showroom of their distributors/agents. Items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days. The exporter shall book with the Nominated Agency within 120 days after the end of the stipulated period of 180 days, gold/silver/platinum for the purpose of replenishment content against the items sold abroad.

- (b) The following documents shall be submitted for claiming such replenishment:

- (i) Customs attested invoice;
- (ii) Copy of the approval letter issued by the Government/GJEPC;
- (iii) Certificate from the Nominated Agency/GJEPC in the form given in Appendix-22F.

- (c) In case of exhibitions organised by the nominated agencies, the gold/silver/platinum shall be imported as replenishment by the Nominated Agencies within 60 days from the close of the exhibition.

4A.19 The Nominated Agencies shall maintain a complete account of the exports made, goods sold abroad, goods re-imported, and metals purchased abroad and imported into India. Such account shall be maintained for a minimum period of three years from the date of close of the exhibition.

Export Against Supply by Nominated Agencies

4A.20 The exporter under the scheme may obtain gold/silver/platinum on following basis :

- (i) Replenishment basis after completion of exports;
- (ii) Outright purchase basis in advance;
- (iii) Loan basis.

Replenishment Basis

4A.21 The exporter may apply to the Nominated Agency for booking of precious metal gold/silver/platinum. The quantity of the precious metal booked with the Nominated Agency shall be equivalent to the precious metal content in the export product and the admissible wastage.

4A.21.1 The applicant shall at the time of booking deposit an earnest money for a minimum amount of 20% of the notional price of the precious metal, which shall be adjusted at the time of actual sale.

4A.21.2 The exporter may also export jewellery on a notional rate based on the certificate provided by the Bank. The exporter must fix the price within the credit terms allowed to the buyer and realise proceeds within the due date of the credit terms or 180 days, whichever is earlier. The exporter exporting on a notional basis under Replenishment Scheme must book the same quantity of gold with the Nominated Agency on the same rate that he may have booked with the buyer. The Nominated Agencies shall purchase the precious metal on behalf of the exporter at the rate so fixed and thereafter issue a purchase certificate bearing a serial number to the exporter indicating the quantity of gold/silver/platinum and the CIF value, in dollars including the Rupee equivalent. The price shall be the actual price at which gold/silver/platinum is purchased by the Nominated Agencies *plus* permitted service charges levied by the Nominated Agencies shall be included with the price of gold/ silver/ platinum for the purpose of value addition. The duplicate and triplicate copies of exporter's application together with copies of purchase certificate for the exporter shall be sent by the Nominated Agencies to the concerned Custom House as well as to the negotiating bank who will confirm realization at which the gold has been purchase. The exporter exporting under the notional rate will get the replenishment only after the proceeds are realised.

4A.21.3 The exports shall be effected within a period of 120 days from the date of booking and the drawal of the precious metal shall be completed within a period of 150 days from the date of booking or within 30 days from the date of export whichever is later.

Outright Purchase Basis in Advance

4A.22 The exporter may obtain the required quantity of precious metal in advance on outright purchase basis

subject to furnishing of Bank Guarantee/LUT, as the case may be to the Nominated Agencies for an amount as may be prescribed by the Nominated Agency. On failure to effect exports within the period prescribed, the Nominated Agencies shall enforce the Bank Guarantee/LUT.

4A.22.1 The exports shall be effected within a maximum period of 90 days from the date of outright purchase of the precious metal.

Loan Basis

4A.23 The exporter may obtain the required quantity of precious metal on loan basis subject to furnishing of Bank Guarantee for the precious metal and Bank Guarantee/LUT; as the case may be, for the customs duty to the Nominated Agencies for an amount as may be prescribed by the Nominated Agencies. On failure to effect exports within the period prescribed, the Nominated Agencies shall enforce the Bank Guarantee and /or LUT.

4A.23.1 The exporter has to pay interest on gold taken on loan basis at the rate as may be specified.

4A.23.2 The export has to be completed within a maximum period of 90 days from the date of release of gold on loan basis. No extension for fulfilment of export obligation shall be allowed.

4A.23.3 The exporter shall be permitted to export the jewellery on the basis of a notional rate certificate to be issued by the Nominated Agency/the Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). This rate will be based on the prevailing Gold/USD rate and the USD/INR rate in the notional rate certificate. The certificate issued by the Nominated Agency/GJEPC should not be older than 7 working days of the date of shipment.

The value addition will have to be achieved on rate as may be got fixed with the buyer and the Nominated Agency.

The exporter shall have the flexibility to fix the price and repay the Gold Loan within 180 days from the date of export. This price shall be communicated to the Nominated Agencies who will issue a certificate showing the final confirmation of the rate to the bank negotiating the documents, to ensure export proceeds are realized at this rate.

4A.24 The nominated agencies may accept payment in dollars towards the cost of import of the precious metal from the EEFC account of the exporter.

Exports against Advance Authorisation

4A.25 The procedure applicable to Advance Authorisations under Chapter-4 of this Handbook shall generally apply to this scheme except the norms for value addition, export obligation period and the regularization of default.

4A.25.1 The export obligation will be required to be fulfilled within 120 days from the date of import of each

consignment against the authorisation. However the export obligation period shall be 180 days from the date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery. No further extension in export obligation period will be allowed. The Advance Authorisation holder may also import gold as replenishment after completion of exports.

4A.25.2 The Advance Authorisation holder may obtain gold/silver/ platinum from the Nominated Agencies in lieu of direct imports. In such a case, the Nominated Agency shall make, both the exchange control copy and customs purpose copy of the authorisation invalid for direct imports.

Diamond Imprest Authorisation

4A.26 Policy for the Diamond Imprest Authorisation is prescribed in paragraph 4A.14 of the Policy.

Application

4A.26.1 For the purpose of the scheme, an application in 'Aayaat Niryaat Form', alongwith documents prescribed therein shall be submitted to the Regional Authority concerned.

Export Obligation

4A.26.2 The export obligation against each consignment shall be fulfilled within a period of five months from the date of clearance of such consignment through Customs. However, at no point of time, the importer shall be required to maintain records of individual import consignments nor will they be required to co-relate export consignments with the corresponding import consignments towards fulfilment of export obligation.

Regularisation of Bonafide Default

4A.27 The cases of bonafide default in fulfilment of export obligation by an exporter who has obtained precious metals from the nominated agencies may be regularised provided the exporter has paid customs duty alongwith 15% interest thereon to the Customs. However, in the case of Advance Authorisation, the provisions as given in paragraph 4.28 of this Handbook shall apply. This shall be without prejudice to any action that may be taken against the exporter under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Order or the Rules issued thereunder.

Replenishment Authorisation for Import of Consumables

4A.28 A Replenishment Authorisation for duty free import of consumables, equal to 2% of FOB value of exports of the preceding year may be issued on production of Chartered Accountant's Certificate indicating the export performance. This Authorisation shall be non-transferable and subject to actual user condition. This Replenishment Authorisation shall be valid for duty free import of consumables as notified by the Customs.

Application for import of consumables as given above may be made to the concerned Regional Authority in the form given in 'Aayaat Niryaat Form'.

Personal Carriage of Gems & Jewellery Export Parcels

4A.29 Personal Carriage of Gems & Jewellery Parcels by Foreign Bound Passengers from all EOU/SEZ units and all firms in DTA through the Airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Cochin Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, Jaipur is permitted. The procedure for Personal Carriage of exports shall be as prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realised through normal banking channel. For claiming the Replenishment in case of Personal Carriage of Exports by Foreign Bound passenger, documents shall be the same as mentioned under paragraph 4A.21.2 of this Handbook. Authorised Courier Companies are also permitted to operate on the above lines.

Personal Carriage of Gems & Jewellery Import Parcels

4A.30 Personal Carriage of Gems & Jewellery import parcels by an Indian importer/ Foreign National may be permitted into all EOUs/SEZ units and all firms in DTA through the airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad Jaipur. The procedure will be the same as for import of goods by air-freight except that the parcels shall be brought to the Customs by the Importer/ Foreign National for examination and release. The clearance of imports under this scheme shall be as per the normal Authorisation system of Chapter-4 of the Policy.

Duty free import of samples

4A.31 Duty free import of gems and jewellery samples upto Rs. 3 lakhs or 0.25% of the average of the last three years export turnover of gems and jewellery items, whichever is lower, shall be allowed in a financial year as per the terms and conditions of Customs notification.

Re-import of rejected jewellery

4A.32 An exporter of plain/ studded precious metal jewellery shall be allowed to re-import duty free the jewellery rejected and returned by the buyer upto 2% of the FOB value of exports in the preceding licencing year with the refund of any duty exemption/refund/ replenishment benefit availed on the inputs used as per customs rules and regulations.

4A.32.1 However, an exporter desirous of re-importing plain/studded precious metal jewellery for re-export shall submit a CA certified copy of the export of his preceding year to the jurisdictional Customs Authorities and also execute a bond with them to re-export equivalent quantity of plain/ studded jewellery of same quantity (equivalent weight of gold & value of studdings that were re-imported) within 60 days of the re-import.

Diamond & Jewellery Dollar Accounts

4A.33 The policy for Diamond and Jewellery Dollar Accounts is given in paragraph 4A.19 of FTP. Detailed procedure for its operation will be notified separately.

Import of precious metal scrap/used jewellery for melting and re-export of jewellery

4A.34 The policy for Import of precious metal scrap/used Jewellery for melting and re-export of jewellery is given in paragraph 4A.21 of FTP. The procedure is laid as under:

Imported precious metal scrap/used jewellery shall be allowed to be cleared by the Customs subject to the condition:

- (a) that the importer files a bond along with Bank Guarantee for a sum equivalent to one and half times the customs duty leviable on the said used jewellery/precious metal scrap;
- (b) the importer fulfils the export obligation and value addition as notified by Central Government;
- (c) such import will not be allowed through Hand Baggage.

The detailed procedure including value addition requirement and export obligation period etc. for operationalisation of the facility under this paragraph shall be notified separately by DGFT.

CHAPTER-5**EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME****Policy**

5.1 The Policy relating to Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme is given in Chapter 5 of the Policy.

Application Form

5.2 An application for the grant of an Authorisation may be made to the Regional Authority concerned in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' along with documents prescribed therein.

Consideration of Applications

5.3 The applicant may apply for EPCG Authorisation wherein duty saved amount is Rs. 50 crores, to the Regional Authority along with a certificate from the independent chartered engineer on the proforma annexed to 'Aayaat Niryaat Form' certifying the end use of capital goods sought for import for its use at pre production, production or post production stage for the product undertaken for export obligation.

For the cases wherein duty saved amount is above Rs. 50 crores, the applicant may apply to DGFT Headquarters directly with a copy endorsed to the concerned Regional Authority. In such cases, based on the recommendations of Headquarters EPCG Committee/approval of competent authority the concerned Regional Authorities will issue the EPCG Authorisation accordingly.

5.3.1 The Regional Authority concerned shall, on the basis of the nexus certificate from an Independent Chartered Engineer (CEC) submitted by the applicant in Appendix 32A, issue the EPCG Authorisation and thereafter forward a copy of the EPCG Authorisation to the concerned Jurisdictional Central Excise Authority.

5.3.2 The Authorisation holder shall produce to the concerned Regional Authority a certificate from the jurisdictional Central Excise authority confirming

installation of Capital goods at the factory/premises of the Authorisation holder or his supporting manufacturer(s) vendor(s) within six months from the date of completion of imports.

However, Authorisation holders who are not registered with Central Excise Authorities and service providers can give a certificate either from the jurisdictional excise authority or an Independent Chartered Engineer confirming installation of movable and immovable capital goods at the premises of the Authorisation holder/supporting manufacture.

5.3.3 The EPCG Authorisation shall be issued with a single port of registration mentioned in paragraph 4.19 of the Handbook of Procedure for the purpose of imports. All imports shall be made from that particular port unless the specific permission of the Customs Authorities is obtained. However, exports can be made from any of the ports specified in paragraph 4.19.

5.3.4 (i) The applicant may also apply for import of spares including refractory, catalyst and such consumables as are required for installation and maintenance of capital Goods imported/to be imported under the EPCG Scheme.

The application shall contain list of plant/machinery installed in the factory/premises of applicant for which spares are required, duly certified by Chartered Engineer or Jurisdictional Central Excise Authorities.

In such cases EPCG Authorisation shall not specify the list of spares but shall indicate :

- (a) Name of plant/machinery for which spares are required.
 - (b) Value of duty saved allowed under the Authorisation.
 - (c) Description of product to be exported with value of export obligation as per the Policy.
- (ii) The Regional Authority, after issue of EPCG Authorisation for spare shall forward a copy of Authorisation to concerned Jurisdictional Central Excise Authority.
 - (iii) Further at the time of final redemption of export obligation Authorisation holder shall submit certificate from the Independent Chartered Engineer confirming the use of spares so imported in the installed capital goods on the basis of stock & consumption register maintained by Authorisation holder.

EOU/SEZ Units under EPCG Scheme

5.4 An EOU/SEZ unit may apply for an EPCG Authorisation in terms of paragraph 6.18(d) of the Policy. Such application shall be made in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' alongwith the documents prescribed therein. In addition, the applicant shall also furnish a copy of the 'No Objection Certificate' from the Development Commissioner showing the details of the capital goods imported/indigenously procured by the applicant, its value at the time of import/sourcing and the depreciated value for the purpose of assessment of duty under the scheme.

Such cases shall not be required to be forwarded to Headquarters EPCG Committee. The concerned Regional authority shall issued EPCG Authorisations based on the 'No Objection Certificate' produced from the concerned Development Commissioner.

Indigenous Sourcing of Capital Goods

5.5 The EPCG Authorisation holder intending to source capital goods indigenously, shall make a request to the Regional Authority for invalidation of the EPCG Authorisation for direct import. The EPCG Authorisation holder shall also given the name and address of the person from whom he intends to source the capital goods.

5.5.1 On receipt of such request, either at the time of issuance of Authorisation or subsequently, the Regional Authority shall make the Authorisation invalid for direct import and issue an invalidation letter, in duplicate, to the EPCG Authorisation holder. The Regional Authority shall simultaneously grant permission to the EPCG Authorisation holder to procure the capital goods indigenously in lieu of direct import.

5.5.2 The indigenous manufacturer intending to supply capital goods to the EPCG Authorisation holder may apply to the Regional Authority in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' for the issuance of Advance Authorisation for import of inputs including components required for the manufacture of capital goods to be supplied to the EPCG Authorisation holder.

Benefits to indigenous supplier of Capital Goods

5.5.3 For the purpose of claiming benefit of deemed exports, the indigenous supplier of capital goods shall furnish:

- (a) Certificate from the respective Assistant Commissioner of Customs and Central Excise Authorities having jurisdiction over the factory/premise as evidence of having supplied/received the manufactured capital goods and in case of service provider, a certificate from independent Chartered Engineer confirming the supplies/receipt of the Capital Goods.
- (b) Evidence of payments received through normal banking channel from the EPCG Authorisation holder in the form given in Appendix-22B.

Leasing of Capital Goods

5.6 An EPCG Authorisation holder may, on the basis of firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic leasing company in accordance with paragraph 2.25 of the Policy. In such cases, the Bill of Entry of imported capital goods or the commercial invoice of indigenously procured capital goods, as the case may be, shall be signed jointly by the EPCG Authorisation holder and the leasing company at the time of import/local supply respectively. However, the EPCG

Authorisation holder shall alone be fully responsible for fulfilment of export obligation.

Condition for Fulfilment of Export Obligation

5.7 In addition to the conditions mentioned in paragraph 5.4 of the Policy, the following conditions shall also be applicable for fulfilment of export obligation under the scheme :—

5.7.1 The exports shall be direct export in the name of the EPCG Authorisation holder. However, the export through third party(s) as defined in Chapter 9 of the Policy is also permitted under the EPCG scheme. If a merchant exporter is the importer, the name of the supporting manufacturer shall also be indicated on the shipping bills. At the time of export, the EPCG Authorisation No. and date shall be endorsed on the shipping bills which are proposed to be presented towards discharge of export obligation.

5.7.2 Export proceeds shall be realised in freely convertible currency except for deemed exports under paragraph 5.7.3. However, in case of exports against irrevocable letter of credit or if the bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank, realisation of export proceeds need not be insisted for fulfilment of export obligation provided the final receipts are in free foreign exchange.

5.7.3 Exports made against the Government of India/ EXIM Bank Line of Credit and exports made under Deferred Payment/Suppliers Line of Credit Contract backed by ECGC Cover would also be counted for fulfilment of export obligation under the Scheme.

5.7.3.1 The supplies made to the Oil and Gas sector also may be counted towards discharge of export obligation against an EPCG licence provided the licence has been issued on or before 31-3-2000 and no benefit under paragraph 8.3 of the Policy has been claimed on such supplies.

5.7.4 Wherever average level of export obligation was fixed taking into account the exports made to former USSR or to such countries as notified by the Directorate General of Foreign Trade under this paragraph, the average level of exports shall be reduced by excluding exports made to such countries. This waiver shall be applicable to all EPCG licences, which have not been redeemed/regularised.

However, exports made against any EPCG licence/ Authorisation, except the EPCG licences/Authorisations which have been redeemed, shall not be added up for calculating the average export performance for the purpose of the subsequent EPCG Authorisation.

5.7.5 Where the manufacturer exporter has obtained Authorisations for the manufacture of the same export product both under EPCG and the Duty Exemption or Diamond Imprest Authorisation Scheme or made exports

under DEPB/Advance Authorisation/DFRC/DFIA/ Replenishment Authorisations, the physical exports or deemed exports for categories mentioned in paragraph 5.7.3 made under these schemes shall also be counted towards the discharge of the export obligation under EPCG scheme.

5.7.6 In case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, aqua-culture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry, sericulture and services, the export obligation shall be determined in accordance with paragraph 5.1 of the Policy, but the Authorisation holder shall not be required to maintain the average level of exports as specified in paragraph 5.4 (i) and 5.9 of the Policy.

The goods excepting tools imported under EPCG scheme by such sectors shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled.

However, the transfer of capital goods would be permitted within the group companies or managed hotels under intimation to the Regional Authority and the jurisdictional Central Excise Authority in case of manufacturer/merchant exporters and to the Regional authority only in the case of Service providers.

Moreover, in cases where the service provider wants to discharge export obligation by export of goods also, he shall have to maintain the average level of foreign exchange earning for the preceding three licensing years in respect of goods proposed to be exported for discharge of export obligation.

5.7.7 The Export Obligation shall be fulfilled as per conditions given in para 5.4 of the Policy.

Fulfillment of Export Obligation

5.8 The Authorisation holder under the EPCG scheme shall fulfill the export obligation over the specified period, in the following proportions:

Period from the date of issue Authorisation	Minimum export of obligation to be fulfilled
Block of 1st to 6th year	50%
Block of 7th to 8th year	50%

5.8.1 In respect of Authorisations, on which the value of duty saved is Rs. 100 crore or more, the export obligation shall be fulfilled over a period of 12 years in the following proportion :—

Period from the data of issue Authorisation	Minimum export of obligation to be fulfilled
Block of 1st to 10th year	50%
Block of 11th to 12th year	50%

5.8.2 However, the export obligation of a particular block of year may be set off by the excess exports made in the preceding block of year. The Authorisation holder would intimate the regional authority on the fulfillment of the export obligation as well as average exports annually by secured electronic filing using digital signatures.

5.8.3 Where export obligation of any particular block of years is not fulfilled in terms of the above proportions, except in such cases where the export obligation prescribed for a particular block of year is extended by the competent authority, such Authorisation holder shall, within 3 months from the expiry of the block of years, pay duties of customs plus 15% interest of an amount equal to that proportion of the duty leviable on the goods which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation.

5.8.4 However, the licences issued under the scheme upto 31-3-2000 shall be governed by provisions laid down in paragraph 6.11 as given in Handbook (Vol. 1) (RE-99), Notwithstanding the provisions in Handbook (Vol. 1) (RE-99), the licence holder shall not have to surrender Special Import Licence in case of valuwise shortfall.

Licences issued from 1st April, 2000 upto 31st March, 2002 shall be governed by the provisions of Chapter 6 of the Handbook (Vol. 1)(RE-01) as amended from time to time.

Licences issued from 1st April, 2002 upto 31st August, 2004 shall be governed by the provisions of para 5.8 of the Handbook (Vol. 1)(RE-02) as amended from time to time. However, the provision of clubbing even in case of old Authorisations would be as per the current provision of para 5.18 of this Handbook.

Maintenance of Average

5.8.5 The average exports under the EPCG Authorisation has to be maintained as per the provisions of para 5.4(i) and 5.9 of the Policy.

Monitoring of Export Obligation

5.9.1 The Authorisation holder shall submit to the Regional authority by 30th April of every year, report on the progress made in fulfillment of export obligation against the Authorisation issued as well as annual average level of exports achieved. The report shall be submitted electronically on the DGFT website. The Regional authority may issue partial EO fulfillment certificate to the extent of EO fulfilled in a particular year.

Automatic Reduction/Enhancement upto 10% of CIF value and Prorata Reduction/Enhancement in Export Obligation

5.10 If the Authorisation issued under the scheme has actually been utilized for import of a value in excess of

10% of the CIF value/duty saved amount of the Authorisation, Authorisation shall be deemed to have been enhanced by that proportion. The Customs shall automatically allow the clearance of goods in excess upto 10% of the Authorisation value/duty saved amount without endorsement by the Regional authority.

In such cases, the Authorisation holder shall furnish additional fee to cover the excess imports effected in terms of CIF value/duty saved amount to the Regional authority within one month of the excess imports taking place. The export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.

5.10.1 Similarly, if the EPCG Authorisation holder has utilised the Authorisation less than the value earmarked in the Authorisation, has export obligation shall stand reduced on prorata basis with reference to actual utilisation of Authorisation.

Extension of Export Obligation Period

5.11 The concerned Regional authority, may consider one or more request for grant of extension in export obligation period for a period of 2 years, on payment of a composition fee of 2% of the total duty saved under the Authorisation or an enhancement in export obligation imposed to the extent of 10% of the total export obligation imposed under the Authorisation, as the case may be, at the choice of the exporter, for each year of extension sought.

However extension in EO period beyond the two years period available above, may be considered, for a further extension upto 2 years with a condition that 50% of duty payable in proportion to the unfulfilled export obligation is paid by the Authorisation holder to the Custom authorities before an endorsement of extension is made on the EPCG Authorisation by the Regional authorities. In such cases, no composition fee is to be paid or additional EO is to be imposed as prescribed in the Para above. In case the firm is still not able to complete the export obligation the duty already deposited will be deducted from the total duty plus interest to be paid for EO default.

The extension in export obligation period shall also be subject to such terms and conditions as may be prescribed by the competent authority. Wherever the export obligation period is extended, the Authorisation holder shall be required to maintain average export obligation during the extended period as well. Export made on or after the date of receipt of application for EO extension shall only qualify for discharge of EO fulfillment under the Scheme.

5.11.1 The firm/company or group company registered within the original/extended E.O. period with the BIFR or state rehabilitation Scheme for SSI unit as a

sick unit or any firm/company acquiring a unit, which is under BIFR may apply for extension in export obligation period for fulfillment of export obligation to Director General of Foreign Trade.

The firm/company, which is applying for registration with BIFR/Rehabilitation Department of State Government shall also intimate DGFT with regard to relief sought for EPCG Licence/Authorisation, if any, within 30 days of receipt of the application by agency concerned.

The DGFT, on receipt of intimation/notice received from the BIFR/operating agency/Rehabilitation Department of State Government shall take up the matter with the agency concerned to safeguard government interest on account of default in fulfillment of export obligation imposed on EPCG licence/Authorisation obtained by such firm.

DGFT may consider such application for grant of extension in the period of export obligation upto 12 years or as per the rehabilitation package prepared by operating agency and approved by BIFR board/state authority, on its merit.

Export Obligation Shortfall

5.12 The regional authority may also consider condonation of shortfall upto 5% in the export obligation within the validity of the export obligation period, subject to such terms and conditions as may be prescribed by them.

Redemption

5.13 As evidence of fulfillment of export obligation, the Authorisation holder shall furnish the following documents:

(a) For Physical Exports:

A consolidated statement of exports made in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' duty certificate by a Chartered Accountant and bank evidencing exports and realisation in freely convertible currency or statements of exports in the form given in 'Aayaat Niryaat Form' for individual banks duty certified by a Chartered Accountant.

However in case of exports made under irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank, realization of export proceeds would not be insisted upon.

The EPCG Authorisation holder shall submit a copy of the irrevocable letter of credit or the bill of exchange unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and confirmed by the exporters bank for availing of the benefit of EPCG.

(b) For Deemed Exports:

- (i) Copy of ARO/Back to Back Inland letter of Credit or Advance Authorisation for Intermediate Supplies.

OR

Supply invoices or ARE 3 duly certified by the Bond Office of EOU concerned showing that supplies have been received;

- (ii) The Authorisation shall also furnish the evidence of having received the payment through normal banking channel in the form given in Appendix- 22B or a self certified copy of payment certificate issued by the Project authority concerned in the form given in Appendix-22 C.

However in case of exports made under irrevocable inland letter of credit or the inland bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co- Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank, realization of export proceeds would not be insisted upon.

(c) For Services rendered:

Consolidated statement or individual statements (bank/authorised dealer wise) of services rendered in the 'Aayaat Niryaat Form', duly certified by a Chartered Accountant and bank/ authorised dealer evidencing foreign exchange earning received through normal banking channel.

On being satisfied, the regional authority shall issue a certificate of discharge of export obligation to the EPCG Authorisation holder and send a copy of the same to the customs authorities with whom BG/LUT has been executed.

Regularisation of Bonafide Default

5.14 In case, EPCG Authorisation holder fails to fulfill the prescribed export obligation, he shall pay duties of Customs plus 15% interest per annum to the Customs authority as per paragraph 5.8.3. This facility of payment of interest @15% shall be available to all pending cases of regularisation of EPCG Authorisation irrespective of the date of its issuance.

Maintenance of Records

5.15 Every EPCG Authorisation holder shall maintain, for a period of 3 years from the date of redemption, a true and proper account of the exports/supplies made and services rendered towards fulfilment of export obligation under the scheme.

Re-Export of Capital Goods Imported Under EPCG Scheme

5.16 Capital Goods imported under the EPCG scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on importation thereof with the permission of the regional/Customs Authority. However, in such cases the Authorisation holder shall fulfill the balance export obligation under the Authorisation from export of alternate products/services or the Authorisation holder shall pay duty equivalent to a proportionate amount of duty saved to the unfulfilled export obligation under the Authorisation.

Replacement of Capital Goods

5.16.1 The Capital Goods imported under the scheme and found defective or otherwise unfit for use may be exported and Capital Goods in replacement thereof be imported under the scheme. In such cases, while allowing export, the Customs shall credit the duty benefit availed which can be debited again at the time of import of such replaced Capital Goods.

Penal Action

5.17 In case of failure to fulfill the export obligation or any other condition of the Authorisation, the Authorisation holder shall be liable for action under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, the Orders and Rules made there under, the provisions of the Policy and the Customs Act, 1962.

Clubbing of EPCG Authorisations

5.18 The clubbing of two or more EPCG Authorisations of the same Authorisation holder would be permitted as per the provisions given herewith. The expiry period mentioned in the subparas of this para would be with reference to the export obligation period of the EPCG Authorisation.

5.18.1 The accountability of imports and exports shall be restricted to the items mentioned in the EPCG Authorisations to be clubbed.

5.18.2 An application for clubbing can be made only to the regional authority under whose jurisdiction the Authorisation is issued in 'Aayaat Niryaat Form'. Clubbing shall not be permitted in case the Authorisation are issued by different Regional Authorities. The concerned Regional Authority would consider the request for clubbing only on the fulfillment of the following conditions :

- The EPCG Authorisations have been issued during the same licensing year.
- The EPCG Authorisations have been issued under the same Customs Notification.
- EPCG Authorisations must be for the export of the same product(s) or same services.

5.18.3 The total export obligation for the Authorisations so clubbed would be refixed taking into account the total duty saved or total CIF value of imports as the case may be of the clubbed Authorisation.

The export obligation period of the clubbed Authorisation would be as per the policy applicable for the clubbed CIF value/clubbed duty saved amount, as the case may be. In case of any discrepancy in the export obligation periods of the two Authorisations, clubbing would not be permitted.

5.18.4 On clubbing, the Authorisation for all purposes shall be deemed to be a single EPCG Authorisation issued under the said Customs Notification and the export obligation period for the clubbed Authorisation shall be reckoned from the date of issuance of the first Authorisation. However, in cases where the clubbed CIF/duty saved value exceeds Rs. 100 crore, no corresponding benefit of increase in export obligation period shall be admissible.

5.18.5 The average export obligation to be maintained for the clubbed Authorisation would be the highest of the average export obligations endorsed on the individual Authorisations put up for clubbing.

5.18.6 No clubbing would be permitted in the case of expired EPCG Authorisations. In case any specific (as against general extensions under Para 5.11) export obligation extension has been given for any EPCG Authorisation, the same Authorisation cannot be considered for clubbing.

Refixation of Export Obligation

5.19 (a) The EPCG Authorisation holder can apply for the refixation of export obligation as given in para 5.4 (i) of the Policy in the 'Aayaat Niryaat Form'.

(b) Deleted.

(c) For all EPCG Authorisations, the Authorisation holder should have fulfilled the mandated (original or amended, as the case may be) blockwise export obligation at the end of the previous block in which the application is made. This facility is extended to the applications made in the extended export obligation period as well. However, in such cases, extended export obligation period would be treated as the last block for the purpose of EO re-fixation. In all such cases, the refixed export obligation would be computed as under:

$(\% \text{ export obligation unfulfilled}) \times (8) \times (\text{duty saved on the date of issuance of the Authorisation})$

- (d) In cases where the remaining original export obligation period (and not the extended export obligation period) of the EPCG Authorisation is less than two years on the date of application for refixation, and the mandated (original or extended, as the case may be) block-wise export obligation has been fulfilled, the export obligation would be refixed at two times the duty saved on the date of issuance of Authorisation.
- (e) There would be no change in average export obligation fixed or the export obligation period of the original Authorisation.
- (f) An application under 'Aayaat Niryaat Form' can also be made if the EPCG Authorisation holder has got his average and EPCG export obligation refixed on account of the change in product/ service as per the provisions of para 5.4 (i) of the Policy.

Technological Upgradation of Capital Goods

5.20 The EPCG Authorisation holders can opt for the Technological upgradation of the capital goods imported under the EPCG Scheme as per the provisions of Para 5.10 of the Policy.

In case an EPCG Authorisation holder wants to upgrade the existing capital goods imported under the EPCG scheme, he can opt for the Technological upgradation subject to the following conditions :

- (i) The capital goods to be imported must be new and technologically superior to the earlier capital goods. It must be used for the manufacture of the similar product for which the original EPCG Authorisation was issued.
- (ii) The export obligation for the new capital goods would be the difference of the sum total of 6 times the duty saved on both the capital goods and the exports already made under the old capital goods.
- (iii) The export obligation period would be 8 years from the date of issuance of the new Authorisation.
- (iv) The block-wise export obligation fulfillment would be as per Para 5.8 of this Handbook.
- (v) The average export obligation for the upgraded capital goods would be the same as that of the capital goods being replaced.

The application for technological upgradation of the capital goods would be made in 'Aayaat Niryaat Form'.

Import of Refurbished/ Reconditioned Spares and Tools

5.21 The import of refurbished spares as mentioned in paras 5.1 and 5.1A of the Policy shall be permitted under the EPCG Scheme.

However such refurbished/reconditioned spares must have a residual life not less than 80% of the life of the original spare which would be certified by the EPCG Authorisation holder.

The tools imported under the EPCG scheme may be transferred to any of the units or group companies of the applicant.

5.22 Revalidation of Authorisation issued under EPCG scheme shall not be allowed.

CHAPTER-6

EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) SCHEME AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs).

Scheme

6.1 The Policy relating to Export Oriented Units (EOUs), Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-Technology parks (BTPs) Scheme is given in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy.

Definitions

6.2 For the purpose of Export Oriented Units (EOUs), Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-Technology Parks (BTPs) unless the context otherwise requires, the words and expressions shall have the meanings attached to them as given in the Policy.

Approval/Application and renewal of Application

6.3.1 For setting up an EOU, three copies of the application in the form given in Appendix- 14-IA may be submitted to the Development Commissioner.

6.3.2 Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of unit in the service sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the criteria indicated in Appendix-14-IB and sector specific conditions

relating to the approval given in Appendix-14-IC. In other cases, approval may be granted by the Development Commissioner after clearance by the Board of Approval.

6.3.3 Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the Board of Approval (as per Appendix-14-ID) and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days on merits.

6.3.4.1 Software Technology Park (STP)/Electronics Hardware Technology Park (EHTP) complexes can be set up by the Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof, duly approved by the Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Information Technology). Application for setting up EHTP/STP unit shall be in the format prescribed by the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Information Technology) and shall be submitted to the officer designated by the Department of Information Technology.

6.3.4.2 Bio Technology Park (BTP) can be set up by the Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof. Application for setting up of BTP shall be submitted to the Department of Bio-Technology and such applications which meet the guidelines prescribed by the Department of Bio-Technology will be approved and recommended to the DGFT for notification. Application for setting up of BTP unit shall be submitted to the Officer designated by the Department of Bio-Technology.

6.3.6 The LOP/LOI shall specify the item(s) of manufacture/service activity, annual capacity, projected annual export for the first five years in dollar terms, Net Foreign Exchange earnings (NFE), limitations, if any, regarding sale of finished goods, by-products and rejects in the DTA and such other matter as may be necessary and also impose such conditions as may be required.

6.3.7 LOP/LOI issued to EOU/EHTP/STP/BTP units by the concerned authority would be construed as a authorisation for all purposes. Standard format for LOP for EOU units is given in Appendix 14-IE.

6.3.8 EOUs shall have separate ear-marked premises for separate LOP. Similarly, EOUs may be approved on leased premises provided the lease has been obtained from Government Department / Undertaking / Agency. However, in case lease is obtained from private parties, it shall have a validity period of five years from the date of LUT and the Development Commissioner shall satisfy himself of genuine nature of the lease.

6.3.9 On completion of the approval period as provided for in paragraph 6.6 of Policy, it shall be open to the unit to continue under the scheme or opt out of the scheme. If no intimation in this regard is received from the unit within a period of six months of expiry of the approval period, the Development Commissioner will take action, suo moto, to cancel the approval under the EOU scheme and take further action in this regard. Where the unit opts to continue, the Development Commissioner concerned will extend the approval period.

Legal Undertaking

6.4.1 The approved EOU/EHTP/STP/BTP unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner / Designated Officer concerned as per the format given in Appendix- 14-IF.

6.4.2 All EOU/EHTP/STP/BTP units should have permanent e-mail address. No LUT for new units shall be executed unless the unit has its permanent e-mail address and digital signature on the said e-mail ID. In the event of an EOU not having permanent e-mail address and digital signature, further imports and DTA sale shall not be permitted by the Development Commissioner.

Export of goods and services

6.5.1 Software units may undertake exports using data communication links or in the form of physical exports (which may be through courier service also), including export of professional services.

6.5.2 The EOUs shall be permitted to export jewellery on the basis of a notional rate certificate issued by the nominated agency. This rate will be based on the prevailing Gold/US\$ rate and the US\$/INR rate in the notional rate certificate. The certificate issued by the nominated agency should not be older than 3 working days of the date of shipment.

6.5.3 The exporter shall have the flexibility to fix the price and repay the gold loan within 180 days from the date of export. The price shall be communicated to the nominated agencies who will issue a certificate showing the final confirmation of the rate to the bank negotiating the document, to ensure export proceeds are realized at this rate.

6.5.4 Gem & Jewellery and Jewellery EOUs may re-export imported goods and export domestically procured goods, including goods generated out of partial processing/manufacture. Besides, supply of unsuitable/broken cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones upto 5% of the value of imported or indigenously procured goods to the DTA against the valid

Gem & Jewellery REP as applicable on payment of appropriate duty is also permitted.

Import / Domestic Procurement of Goods

6.6.1 Goods permitted to be imported /procured from Domestic Tariff Area shall include:

- (a) Raw materials, components, consumables, intermediates, spares and packing materials;
- (b) Capital goods, whether new or second-hand, including inter-alia the following and their spares:
 - (i) DG sets, captive power plants, transformers and accessories for all above.
 - (ii) Pollution control equipment.
 - (iii) Quality assurance equipment.
 - (iv) Material handling equipment, like fork lifts and overhead cranes, mobile cranes, crawler cranes, hoists and stackers.
 - (v) Un-interrupted Power Supply System (UPS), Special racks for storage, storage systems, modular furniture, computer furniture, anti-static carpet, teleconference equipment, Servo Control System, Air-conditioners / Airconditioning system, panel for electricals and special data transmission cable.
 - (vi) Security Systems.
 - (vii) Tools, jigs, fixtures, gauges, moulds, dyes, instruments and accessories.
- (c) Raw material for making capital goods for use within the unit.
- (d) Others including:
 - (i) Prototypes and technical samples for existing product(s) and product diversification development or evaluation.
 - (ii) Drawings, blue prints, charts, microfilms and technical data;
 - (iii) Office equipment, including PABX, Fax machines, projection system, Computers, Laptop, server.

- (e) Spares and consumables for all the above items.
- (f) Any other items not mentioned above with the approval of Board of Approval.

6.6.2 EOU's may import plain/studded gold/platinum or silver jewellery for export after repairs/remaking.

Conditions of Import

6.7 The import of goods by EOU/EHTP/STP/BTP units shall be subject to the following conditions:

- (a) The goods shall be imported into the EOU / EHTP/STP/BTP premises. However, agriculture and allied sectors and granite sector units in EOU may supply/transfer the capital goods and the inputs in the farm/ fields/ quarries with prior intimation to the jurisdictional Customs/Central Excise authorities, provided the ownership of the goods rests with EOU units. The granite sector would also be allowed to take spares upto 5% of the value of the Capital Goods to the quarry site.
- (b) The procedure as prescribed under Customs/Excise rules for EOU's and units in EHTP/STP/BTP will be followed and appropriate bond executed with Customs/Excise authorities.
- (c) The goods, except capital goods and spares, shall be utilised by EOU/EHTP/STP/BTP units within a period of three years or as may be extended by Customs authorities. However, imported tea shall be utilized within a period of 6 months from the date of import. Similarly, export obligation against import of items (covered by chapter 9 of the ITC (HS) Classifications of Export & Import Items, 2004-09, shall be fulfilled within a period of 90 days from the date of receipt of the first import consignment i.e. the date on which the first import consignment is cleared by the Customs authorities.
- (d) Goods already imported/shipped/arrived before the issue of LOP/LOI are also eligible for duty free clearance under the EOU/EHTP/STP/BTP scheme provided customs duty has not been paid and the goods have not been cleared from Customs.

Fax machines/laptop computers outside approved premises

6.8.1 EOU/EHTP/STP/BTP units may install one fax machine at a place of its choice, outside the premises of the unit, subject to intimation of its location to the concerned Customs/Central Excise authorities.

6.8.2 EOU/EHTP/STP/BTP units may, temporarily

take out of the premises of the unit duty free laptop computers and video projection systems for working upon by authorized employees.

6.8.3 EOU/EHTP/STP/BTP units may install personal computers not exceeding two in number, imported/procured duty free in their registered/administrative office subject to the guidelines issued by Department of Revenue in this behalf.

6.8.4 For IT and IT enabled services, persons authorized by the software units may access the facility installed in the EOU/EHTP/STP/BTP unit through communication links.

Leasing of Capital Goods

6.9 The value of imported capital goods financed through leasing companies or obtained free of cost and/or on loan/lease basis shall also be taken into account for the purpose of calculation of NFE as defined in the Policy.

Net Foreign Exchange Earnings (NFE)

6.10.1 EOU/EHTP/STP/BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. Net Foreign Exchange Earnings (NFE) shall be calculated cumulatively for a block of five years from the commencement of production according to the formula given below. Items of manufacture for export specified in the Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) alone shall be taken into account for calculation of NFE.

$$\text{Positive NFE} = A - B > 0$$

Where :

NFE is Net Foreign Exchange Earning.

'A' is the FOB value of exports by the EOU/EHTP/STP/BTP unit; and 'B' is the sum total of the CIF value of all imported inputs and the CIF value of all imported capital goods, and the value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends, interest on external borrowings/ high sea sales during the first five year period or any other charges. "Inputs" mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

6.10.2 If any goods are obtained from another EOU/EHTP/STP/SEZ/BTP unit, or procured from an international exhibition held in India, or bonded warehouses or precious metals procured from nominated agencies the value of such goods shall be included under B.

6.10.3 If any capital goods imported duty free or leased from a leasing company, received free of cost and/or on loan basis or transfer, the CIF value of the capital goods shall be included pro-rata, under 'B' for the period it remains with the units.

6.10.4 For annual calculation of NFE the value of imported capital goods and lumpsum payment of foreign technical know-how fee shall be amortized as under:

1st - 10th year 10%

Maintenance of accounts

6.11.1 EOU/EHTP/STP/BTP unit shall maintain proper account, and shall file digitally signed quarterly and annual report as prescribed in Annexure to Appendix-14-IF to the Development Commissioner/Designated Officer in the Ministry of Information & Technology/Department of Bio-Technology and Customs and Central Excise authorities.

6.11.2 The unit shall be able to account for the entire quantity of each category of homogenous goods imported/procured duty free, by way of exports, sales/supplies in DTA or transfer to other SEZ/EOU/EHTP/STP/BTP units and balance in stock. However, at no point of time the units shall be required to co-relate every import consignment with its exports, transfer to other SEZ/EOU/EHTP/STP/BTP units, sales in the DTA and balance in stock. Any matter for clarification as to whether goods are homogenous or not shall be decided by Units Approval Committee.

Monitoring of NFE

6.12.1 The performance of EOU units shall be monitored by the Units Approval Committee as per the guidelines given in Appendix -14-IG. Performance of EHTP/STP/BTP shall be monitored by Ministry of Information & Technology/Deptt. of Bio-technology jointly with the jurisdictional Central Excise /Customs Authority.

6.12.2 Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of the LOP/LOI/IL/LUT shall render the unit liable to penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the Rules and Orders made there under without prejudice to action under any other law/rules and cancellation or revocation of LOP/LOI/IL.

Conversion of Scrap/Dust/Sweeping of Gold/Silver/Platinum into standard Bars.

6.13 Scrap/dust/sweeping of gold/silver/ platinum may be sent to the Government of India Mint/Private Mint from the EOU/EHTP/STP units and returned to them in standard bars in accordance with the procedure prescribed by the Customs authorities or may be permitted to be sold in the DTA on payment of applicable Customs duty, on the basis of gold/silver/platinum content, as may be notified by Customs authorities.

DTA supplies

6.14 Notwithstanding the provision of DTA sales in Para 6.8 of Policy, such DTA sales shall not affect the application to any goods of any other prohibition or regulation affecting import thereof in force at the time when such goods are imported. This also does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from any commitment or compliance with any requirements to which the importer may be subject to under other laws or

regulations.

Supplies to other EOU/EHTP/STP/SEZ/BTP units

6.15 Supplies to other EOU/SEZ/ EHTP/ STP/BTP units shall be counted towards NFE provided that such goods are permissible for procurement by these units.

Transfer of Power from one unit to another

6.16 Transfer of power from Captive Power plants (DG Sets) from one unit of EOU/EHTP/STP/BTP to another is permitted as prescribed in sector specific condition in Appendix 14 IC.

Supply of precious/semiprecious/Synthetic stones from DTA.

6.17 Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOUs shall be eligible for grant of Replenishment Authorisation at the rates and for the items mentioned in the Handbook (Vol.I). The procedure for submission of application for grant of Replenishment Authorisation as contained in the relevant Chapter of the Handbook (Vol-I) shall be applicable. However, the application shall be made to the Development Commissioner concerned. Such supplies to EOUs are not treated as deemed exports for the purpose of any of the deemed export benefits.

Application for grant of entitlements

6.18 Application for grant of all the entitlements may be made to the Development Commissioner concerned

Export through other exporters

6.19 An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export goods manufactured/software developed by it through other exporter or any other EOU/ EHTP/STP/SEZ/BTP unit subject to the condition that:

- (a) Goods shall be produced in the EOU/EHTP/STP/BTP unit concerned.
- (b) The level of NFE or any other conditions relating to the imports and exports as prescribed shall continue to be discharged by the EOU/EHTP/STP unit concerned.
- (c) The export orders so procured shall be executed within the parameters of EOU/EHTP/STP/BTP schemes and the goods shall be directly transferred from the unit to the port of shipment.
- (d) Fulfilment of NFE by EOU/EHTP/STP/BTP units in regard to such exports shall be reckoned on the basis of the price at which the goods are supplied by EOUs to other Exporter or other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ unit.
- (e) All export entitlements, including recognition as Status Holder would accrue to the exporter in whose name foreign exchange earnings are realized. However, such export shall be

counted towards fulfilment of obligation under EOU/EHTP/STP/BTP scheme only.

Other Entitlements

6.20.1 The FOB value of export of an EOU/ EHTP / STP / BTP unit can be clubbed with FOB value of exports of its parent company in the DTA or vice versa for the purpose of according Star Export House status.

6.20.2 Sectoral norms as notified by the Government shall apply to FDI in service activities.

6.20.3 Software units may also use the computer system for training purpose (including commercial training) subject to the condition that no computer terminal shall be installed outside the bonded premises for the purpose.

6.20.4 Export of iron ore shall be subject to the decision of the Government from time to time. Requirements of other conditions of exports like minimum export price/export in consumer pack etc. as per ITC(HS) shall apply in case the raw materials are sourced from DTA and exported without further processing/manufacturing by the EOU. Export of textile items shall be covered by bilateral agreements. Wood based units shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court contained in its order dated 12-12-1996 in Writ (Civil) No. 202 of 1995-T.N. Godavarman Thirumulpad v/s. Union of India and others with WP(Civil) No. 171 of 1996 in regards to use of timber/other wood.

Sub-Contracting

6.21.1 Sub-contracting by EOU gems and jewellery units through other EOUs or SEZ Units or units in DTA shall be subject to following conditions:-

- (a) Goods, finished or semi finished, including studded jewellery, taken out for sub-contracting shall be brought back to the unit within 90 days.
- (b) No cut and polished diamonds, precious and semiprecious stones (except precious, semi-precious and synthetic stones having zero duty) shall be allowed to be taken out for sub-contracting.
- (c) Receive plain gold/silver/platinum jewellery from DTA/EOU/SEZ units in exchange of equivalent quantity of gold/silver/ platinum, as the case may be, contained in the said jewellery
- (d) EOUs shall be eligible for wastage as applicable as per para 4.A.2 of Handbook for sub-contracting and against exchange.
- (e) The DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold/ silver/platinum shall not be entitled to deemed export benefits.

6.21.2 The facility of getting job work done from DTA unit will be available even when the job worker is not registered with the Central Excise Authority subject to the

condition that the goods are brought back to the premises of the Unit on completion of the job work.

6.21.3 Export of finished goods from the job worker's premises may be permitted provided such premises are registered with the Central Excise Authorities. Where the job worker is SEZ/EOU/EHTP/STP/BTP unit, no such excise registration is required and export may be effected either from the job workers' premises or from the premises of the unit. Export of such products from the job worker's premises shall not be allowed through third parties as provided in the Policy.

6.21.4 EOUs may be permitted to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers and patterns and drawings to the premises of sub-contractors subject to the conditions that these shall be brought back to the premises of the units on completion of the job work within a stipulated period. The raw materials may or may not be sent along with these goods.

6.21.5 In case of sub-contracting of production process abroad, the goods may be exported from the sub-contractor premises subject to the conditions that job work charges shall be declared in the export declaration forms, invoices etc. and full repatriation of foreign exchange.

Contract farming

6.22 EOUs engaged in production/processing of agriculture/horticulture/aquaculture products, may on the basis of annual permission from the Customs authorities take out inputs and equipments (specified at Appendix-14- IJ) to the DTA farm subject to the following conditions:-

- (a) Supply of inputs by the EOUs to the contract farm(s) shall be subject to the input-output norms approved by the DGFT/BOA.
- (b) There shall be contract farming agreement between the EOU and the DTA farmer(s).
- (c) The unit engaged in export of agriculture/ horticulture/aquaculture products shall furnish bank guarantee equivalent to the duty foregone on the capital goods/inputs proposed to be taken out to the Deputy/ Assistant Commissioner of Customs/Central Excise.

Export through Exhibitions/ Export Promotion tours

6.23 EOU/EHTP/STP/BTP units may export goods for holding/ participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner subject to the following conditions :-

- (a) The unit shall produce to the Customs authorities the letter in original or its certified copy containing approval of the Development Commissioner. For gems and jewellery items, a self certified photograph of the products shall also be submitted.
- (b) In case of re-import, such items, on arrival shall be verified along with the export documents before clearance.

1057GI/06-17

- (c) Items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of the close of the exhibition. However, in case the exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of the first exhibition, then the 60 days shall be counted from the date of close of the last exhibition.
- (d) In case of personal carriage of goods and for holding /participating in overseas exhibitions, the value of such gems and jewellery shall not exceed US \$ 2 million.

Personal Carriage of gems and jewellery for Export promotion tours

6.24 Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US \$ 100,000 for export promotion tours and temporary display/sale abroad by EOUs is also permitted with the approval of the Development Commissioner subject to the following conditions:-

- (a) EOU shall bring back the goods or repatriate the sale proceeds within 45 days from the date of departure through normal banking channel.
- (b) The unit shall declare personal carriage of such samples to the Customs while leaving the country and obtain necessary endorsement.

Export through showrooms abroad/duty free shops

6.25 Export of goods is also permitted for display/sale in the permitted shops set up abroad or in the showrooms of their distributors/agents. The items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days.

Sale through show rooms/retail outlets at International Airports.

6.26 EOUs may set up showrooms/retail outlets at the International Airports for sale of goods in accordance with the procedure laid down by the Customs authorities. The items remaining unsold after a period of 60 days shall be exported or returned to the respective EOUs.

Personal carriage of Import/export Parcels including through foreign bound passengers

6.27.1 Import/ export through personal carriage of gem and jewellery items may be undertaken as per the procedure prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realized through normal banking channel. Import/export through personal carriage, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity.

6.27.2 For Personal carriage of jewellery by foreign bound passenger, the following documents shall be

submitted by EOU units as proof of exports.

- (a) Copy of the shipping bill filed by the EOUs;
- (b) A copy of the Currency Declaration Form filed by the Foreign buyer with the Customs at the time of his arrival; and
- (c) Foreign Exchange Realisation/ Encashment Certificate from the Bank.

6.27.3 In addition to this, Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance (DA)/Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. The EOUs will have to furnish the following documents as proof of exports:-

- (a) Copy of Shipping Bill;
- (b) Bank Certificate of Export and Realisation.

6.27.4 The procedure for personal carriage of import parcels will be the same as for import of goods by airfreight except that the parcels shall be brought to the Customs by the EOUs/ foreign national for examination and release. Instructions issued by the Customs authorities in this regard should be followed *mutatis mutandis*.

6.27.5 Personal carriage of parts by foreign bound passengers shall be allowed in case the same are required for repairs of exported goods at customer site. The following documents should be submitted as proof of exports:-

- (a) Permission letter from customs for exports.
- (b) Invoice with value (for payment or free of charge).

Replacement/Repair of imported/indigenous goods

6.28.1 The units may send capital goods abroad, for repair with the permission of the Customs Authorities. Any foreign exchange payment for this purpose will also be allowed. However, no permission will be required for sending capital good for repair within the country.

6.28.2 EOU/EHTP/STP/BTP units may, on the basis of records maintained by them and prior intimation to Customs authorities:-

- (a) Transfer goods to DTA/abroad for repair/ replacement, testing or calibration and return.
- (b) Transfer goods for quality testing/R&D purpose to any recognised laboratory/ institution upto Rs.5 lakhs per annum without payment of duty, on giving suitable undertaking to the customs for return of the goods. However, if the goods have been consumed/destroyed in the process of testing etc. a certificate from the laboratory/ institution to this effect be furnished to the Customs.

Samples

6.29.1 EOU/EHTP/STP/BTP units may on the basis of records maintained by them, and on prior intimation to Custom authority supply or sell samples in the DTA for display/market promotion on payment of applicable duties.

6.29.2 Remove samples without payment of duty, on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing back the samples within a stipulated period.

6.29.3 An EOU may export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through courier agencies/post.

6.29.4 An EOU on the basis of records maintained by them and on prior intimation to customs authorities may send samples to other EOUs for display on returnable basis within a period of 30 days.

Donation of Computer and Computer peripherals

6.30 EOU/EHTP/STP/BTP unit may be allowed by customs authorities concerned to donate imported/indigenously procured (bought or taken on loan) computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage units without payment of duty, two years after their import/procurement and use by the units, to a school run by the Central Government, or Government of a State or, a Union Territory or, a local body, an Educational Institution run on non-commercial basis by any organization, a Registered Charitable Hospital, a Public Library, a Public Funded Research and Development Establishment, a Community Information Center run by the Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or local body, an Adult Education Center run by the Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or a local body, or an organization of the Central Government or, a Government of a State or, a Union Territory as per Custom/Central Excise notification issued in this regard.

Destruction of goods

6.31 No duty shall be payable in case capital goods, raw material, Consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap/waste/ remnants/rejects are destroyed within the Unit after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the Unit with the permission of Customs authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

Distinct Identity

6.32 If an industrial enterprise is operating both as a domestic unit as well as an EOU/EHTP/STP/BTP unit, it shall have two distinct identities with separate accounts, including separate bank accounts. It is, however, not necessary for it to be a separate legal entity, but it should

be possible to distinguish the imports and exports or supplies affected by the EOU/EHTP/STP/BTP units from those made by the other units of the enterprise.

Unit Approval Committee for EOUs

6.33.1 The powers and functions of the Unit Approval Committee of EOUs shall be as under:-

- (a) To consider applications for setting up EOUs other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA). Items of manufacture requiring industrial licence under the Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 shall be considered by the BOA.
- (b) to consider and permit conversion of units in SEZ to EOU;
- (c) to monitor the performance of the Units;
- (d) to supervise and monitor permission, clearances, licences granted to the units and take appropriate action in accordance with law;
- (e) to call for information required to monitor the performance of the unit under the permission, clearances, licenses granted to it;
- (f) to perform any other function delegated by the Central Government or its agencies;
- (g) to perform any other function as may be delegated by the State Governments or its agencies; and
- (h) to grant all approvals and clearances for the establishment and operation of EOUs.

Approval of EHTP/STP/BTP units

6.33.2 In the case of units under EHTP/STP scheme, necessary approval/permission shall be granted by the officer designated by the Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology / Director (STPI). The designated officer shall also exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 in respect of STP/EHTP as mentioned in Gazette Notification No. S. O. 106 (E) dated 30-1-2006. Similarly in case of units under BTP, necessary approval/permission shall be granted by the officer designated by the Department of Bio-Technology. However, the designated officers shall adopt the criteria for automatic approval of new units as laid down in Appendix 14-IB.

Administration of EOUs/ Power of DC/ Designated Officer

6.34 The Development Commissioner/Designated Officer shall have the following powers in respect to the units. Jurisdiction of Development Commissioners is given in Appendix- 14-IK.

- (1) Conversion of sick/closed DTA unit into EOU;
- (2) Conversion of EOU to STP/EHTP/BTP and vice-versa as per the prescribed procedure;
- (3) To allow increase in the value of capital goods in terms of Indian Rupees, on account of foreign exchange rate fluctuations;
- (4) To permit capacity enhancement without any limit in case of de-licensed industries only;
- (5) Permit broad-banding for similar goods and activities mentioned in the LOP or to provide for backward or forwarded linkages to the existing line of manufacture;
- (6) Authorize change in name of the company or the implementing agency and change from a company to another provided the new implementing agency/company undertakes to take over the assets and liabilities of the existing unit;
- (7) Permit change of location from the place mentioned in the LOP to another and/or include additional location provided that no change in other terms and conditions of the approval is envisaged and that the new location is within the territorial jurisdiction of the Development Commissioner/Designated Officer;
- (8) Extend validity period of LOP by three years beyond the initial validity period of the LOP (except in case where there is a restriction on initial period of approval, like setting up of oil refinery projects);
- (9) Cancel LOP wherever warranted;
- (10) Permit merger of two or more units into one unit provided the units fall within the jurisdiction of the same Development Commissioner/Designated Officer subject to the conditions that the activities are covered under the provision of broad banding;
- (11) Exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 in respect of EOUs as mentioned in Gazette Notification No. SO. 194(E) dated 6-3-2000
- (12) Do valuation of exports declared on SOFTEX form by EOUs as per RBI A.D. (M.A Series) Circular AP (DIR series Circular No.9 dated 25-10-2001);
- (13) Issue eligibility certificates for grant of employment visa to low level foreign technicians to be engaged by EOUs as per Ministry of Home Affairs' letter No. 25022/7/99-F.1 dated 20-9-1999;

Registration-cum- Membership Certificate

- (14) Function as a Registering authority for EOU/EHTP/STP /BTP. A separate Registration-cum-Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in paragraph 2.44 of the Policy except in case of spices. In case of spices, it would be mandatory for the units to get themselves registered with the Spices Board also.

Importer Exporter Code No.

- (15) Allot Importer-Exporter Code number for EOUs, if the same has already not been allotted to the entity;

Green Card

- (16) Issue of Green Card automatically after execution of Legal Undertaking;

- (17) Grant/renewal of Status Certificate in respect of EOUs provided it does not involve clubbing of FOB value of exports of its parent company in the DTA;

- (18) Publicity of EOU/EHTP/STP/BTP Scheme under their jurisdiction.

Clearance of Capital Goods in DTA

6.35 Clearance of Capital Goods including second hand in DTA shall be allowed as per the Policy under EPCG Scheme. In other cases, clearance in DTA may be allowed on payment of applicable duty and Import Policy in force on the date of such clearance.

Depreciation norms

6.36.1 Depreciation upto 100% is permissible for Computers and Computer peripherals in 5 years and 10 years in case of other items.

Depreciation norms for Computers and Computer peripherals

6.36.2 Depreciation for computers and computer peripherals shall be as follows:-

10% for every quarter in the first year;

8% for every quarter in the second year;

5% for every quarter in the third year;

1% for every quarter in the fourth and fifth year;

Depreciation norms for other Capital goods

6.36.3 For capital goods, other than the above, the depreciation rate would be as follows:-

4% for every quarter in the first year;

3% for every quarter in the second and third year; and

2.5% for every quarter in the fourth and fifth year.

2% for every quarter thereafter.

Conversion

6.37.1 Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP/BTP unit, but no concession in duties and taxes would be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed. On conversion, they would get Income Tax concessions but limited to the period of 10 year from original commencement of manufacture or that prescribed under Section 10 of Income Tax Act whichever is earlier. For this purpose, the DTA unit may apply to the Development Commissioner/Designated Officer

concerned in the same manner as applicable to new units. In case there is an outstanding export commitment under the EPCG scheme, it will be subsumed in the export performance of the unit. If the unit is having outstanding export commitment under the Advance Authorisation Scheme, it will apply to the Norms Committee for reducing its export commitment in proportion to the quantum of duty free material actually utilised for production and permitted to carry forward the unutilized material imported against the Advance Authorisation, if any, under the EOU/ EHTP/ STP/BTP scheme.

6.37.2 The existing EHTP/STP/BTP units may also apply for conversion/merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, the units will continue to avail the permissible exemption in duties and taxes as applicable under the relevant scheme. EHTP/STP/BTP units desiring conversion as an EOU may apply to the Development Commissioner concerned through the Officer designated by the Department of Information Technology/Department of Bio-Technology in the same manner as applicable to new units. Likewise EOU desiring conversion into EHTP/ STP/BTP may apply to the officer designated by the Department of Information Technology /Department of Bio-Technology through the Development Commissioner concerned.

6.37.3 An EOU may be shifted to SEZ with the approval of Development Commissioner provided the EOU unit has achieved pro-rata obligation under the EOU scheme.

Revival of Sick units

6.38 Subject to a unit being declared sick by the appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by the Board of Approval. Guidelines on revival of sick units are given in Appendix - 14-IM.

6.39 FAST TRACK CLEARANCE PROCEDURE

Eligibility

6.39.1 EOUs having a status holder certificate under the Foreign Trade Policy shall be eligible for the Fast Track Clearance Procedure.

Examination of Import Cargo

6.39.2 The status holder units shall be exempted from examination of import cargo at the Port of import. The jurisdictional Commissioner of Customs / Central Excise may, however, examine consignments at the unit's place on random basis.

Domestic procurement and import of goods

6.39.3 The units having physical export turnover of Rs. 15 crores and above in the preceding financial year shall be allowed to import goods without payment of duty on the basis of pre-authenticated procurement certificate issued by the jurisdictional Customs/ Central Excise Authority.

Installation of Fax Machine/ Computers

6.39.4 The eligible EOUs may install one fax machine and two computers in their administrative/registered office outside the bonded premises under prior intimation to the jurisdictional Asst/Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.

Procurement of DG sets

6.39.5 Procurement of DG set of capacity commensurate with the actual requirement of the unit shall be permitted under intimation to the Development Commissioner and the jurisdictional Central Excise Authority.

Temporary Removal of Capital Goods

6.39.6 The eligible EOU units may remove their capital goods or parts thereof for repairs under prior intimation to the jurisdictional Asstt./Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.

Clearance of rejects in DTA

6.39.7 Request for permission for DTA clearance of rejects shall be considered by the jurisdictional Excise authority on priority basis.

Personal carriage of samples

6.39.8 Personal carriage of samples of Gems & Jewellery by status holder EOUs are allowed subject to the limit fixed in Para 6.24 without a need for prior permission from Development Commissioner/ Customs / Central Excise.

Activities which do not require permission

6.39.9 In respect of the following activities of a status holder, permission will not be required from the Development Commissioner or the jurisdictional Central Excise authority. However, prior intimation thereof needs to be given.

DTA sale of finished products in terms of para 6.8(a) of FTP, Participation in exhibition and Personal carriage of Gems & Jewellery for export promotion tours subject to fulfillment of conditions of para 6.24 of Handbook (Vol. I)

However, prior intimation thereof needs to be given.

Time bound disposal of application.

6.40 The Development Commissioner shall dispose off applications expeditiously. The following time schedule shall normally be followed to dispose of the applications provided the application is complete in all respects and is accompanied by the prescribed documents.

S. No.	Category of Application	Time limit for disposal
1	2	3
1	Issue of LoP/LoI	15 days
2	Conversion of LoP/LoI	15 days
3	Acceptance of LUT	3 days
4	Renewal of LUT	3 days
5	Permission for broad banding/ diversification	3 days

1	2	3
6	Permission for change in location	7 days
7	Permission for Advance DTA sale	2 days
8	Permission for merger of units.	7 days
9	Permission for enhancement of production capacity	3 days
10	Cancellation of LoP	3 days
11	Permission for debonding/exit	7 days
12	Permission for DTA sale	2 days
13	Eligibility certificate for employment visa for lower level technicians.	2 days
14	Issue of Green Card	2 days
15	Renewal of Green Card	Same days
16	Permission to lease CG	1 day
17	Permission for disposal of scrap/waste	2 days
18	Permission for change in name	2 days
19	Inter Unit Transfer	2 days
20	Wastage Norms, ad-hoc	2 days
21	Permission for re-import	Same day
22	Permission for re-export	Same day
23	Permission for replacement/repair of goods	Same days
24	Allotment of I. E. Code	1 day
25	Authorization of softex firm	1 day
26	Reimbursement of CST claims.	7 days
27	Issue of GSP Certificate	Same day
28	Permission for conversion of EOU to STPI, EPCG	5 days
29	Permission of final exit of EOU	5 days
30	Permission of extension of EOU	2 days
31	Permission to allow increase in value of CG	2 days
32	Permission for export through exhibition/tour	2 days
33	Reimbursement of Duty Drawback/TED	7 days

CHAPTER-7

SPECIAL ECONOMIC ZONES

The policy relating to Special Economic Zones is contained in Special Economic Zone Rules, 2006, notified in the Gazette of India, Extraordinary No. GSR 54(E) dated 10-2-2006.

CHAPTER—8

DEEMED EXPORTS

Policy

8.1 The Policy relating to Deemed Exports is given in Chapter-8 of the Foreign Trade Policy.

Criteria for claiming Deemed Exports Benefits

8.2.1 In respect of supplies under Paragraph 8.2(a) of the Policy, the procedure for issue of ARO and Back-to-Back Inland Letter of Credit is given in paragraphs 4.14 and 4.15 of the Handbook.

8.2.2 In respect of supplies under paragraph 8.2(b) of the Policy and DFIA/DFRC, the deemed export benefits may be claimed from the Development Commissioner or the Regional Authority concerned. Advance Authorisation DFIA and DFRC shall be claimed from the concerned Regional Authority. Such supplies shall be certified by the receiving agencies.

8.2.3 In respect of supply of capital goods under paragraph 8.2 (c) of the Policy, the supplier shall produce a certificate from the EPCG Authorisation holder evidencing supplies/ receipt of the manufactured capital goods.

8.2.4 In respect of supplies under categories mentioned in paragraphs 8.2(d),(e),(f),(g), (i) and (j) of the Policy, the application for advance Authorisation shall be accompanied with a project authority certificate in Appendix - 27. The payment against such supplies shall be certified by the Project Authority concerned in the prescribed format in Appendix-22C.

Procedure for claiming Deemed Exports Drawback & Terminal Excise Duty Refund/Exemption from payment of Terminal Excise Duty.

8.3.1 The procedure for claiming benefits under paragraph 8.3 (b) and (c) of the Policy shall be as under:—

- (i) An application in the Aayaat Niryaat form along with the documents prescribed therein, shall be made by the supplier to the Regional Authority concerned. The recipient may also claim the benefits on production of a suitable disclaimer from the supplier along with a self declaration in Appendix 22C of Handbook regarding non-availment of CENVAT credit in addition to the prescribed documents.
- (ii) In case of supplies under paragraph 8.2(a), (b) & (c), the claim shall be filed against receipt of payment through normal banking channel in the form given in Appendix -22B. Such claims shall be filed within a period of 6 months from the end of monthly/quarterly/half yearly period reckoned from the date of payment as per the option of the applicant. In cases where payment is received in advance, last date for submission of application may be correlated with the date of supply instead of date of receipt of payment.

- (iii) In respect of supplies under paragraph 8.2(b) of the Policy where the supplier wants to claim benefits from the Regional Authority, the Regional Authority shall allow deemed export benefits to the DTA supplier, on receipt of certified copies of Central excise attested invoice as proof of supplies made and/or excise attested CT3 from and proof of validity of LOP.
- (iv) In respect of supplies under categories mentioned in Paragraphs 8.2(d)(e)(f)(g)(h)(i) & (j) of the Policy, the claim may be filed for the payment received/supplies effected during a particular month/quarter/half year as per the option of the applicant either on the basis of proof of supplies effected or payment received. The claim may be filed either against a particular project or all the projects. Such claims shall be filed within a period of 6 months from the end of monthly/quarterly/half yearly period reckoned from the date of receipt of the supplies by the project authority or from the date of receipt of the payment as per the option of the applicant. Such claims may also be filed where part payments have been received.

8.3.2 For claiming exemption from payment of terminal excise duty, procedure prescribed by the Central Excise Authority shall be followed.

8.3.3 Where All Industry Rate of Drawback is not available or the same is less than 4/5th of duties actually paid on the materials or components used in the production or manufacture of the said goods, the exporter/ supplier may apply for fixation of brand rate in the application form as given in Aayaat Niryaat form to the Regional Authority or Development Commissioner as the case may be.

8.3.4 The claim application shall be filed along with the application for fixation of brand rate of duty drawback in case brand rate is required to be fixed. The provision of late cut under paragraph 9.3 and supplementary claim under paragraph 9.4 shall also be applicable under this sub-paragraph.

8.3.5 Regional Authorities may consider provisional payment to the extent of 75% of the drawback claim in the case of private companies and 90% in the case of Public Sector Undertakings, pending fixation of Brand Rate.

8.3.6 Subject to the procedure laid down in this Handbook, the Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1995 shall apply mutatis mutandis to deemed exports.

Procedure for claiming deemed export benefit by sub-contractor

8.4 In respect of supplies made by sub-contractor to the main contractor under paragraph 8.2 (d)(e) (f) (g)(i) and (j), the main contractor may make payment to the sub-contractor and issue payment certificate in the form given in Appendix-22C as Form I-C. However, for supplies under paragraph 8.2(d) (e) (f) (g) and (j), the payment certificate from main contractor shall not be insisted for refund of Terminal Excise Duty. The deemed exports benefits to the

sub-contractor would be available to the extent of goods that are manufactured and supplied by him or outsourced from other manufacturers, for the value as indicated in Appendix 22C of the Handbook.

CHAPTER -9

MISCELLANEOUS MATTERS

Change In Name and Constitution

9.1 If there is any change in the name/address or constitution of IEC Holder/Licensee/Authorisation Holder/Actual User eligible for import without a Authorisation/Licensee/Recognised Status License Holders, the concerned IEC Holder/Licensee/Authorisation/Holder/Actual User/Status Holders, as the case may be, shall cease to be eligible to import or export against the licence/IEC No. or any other facility permitted under the Policy and Handbook, after expiry of 90 days from the date of such change in his name or address or constitution, unless in the meantime,

- (a) The IEC Holder/Licensee/Authorisation/Holder/Status holders has got the consequential changes effected in the IEC Number/Authorisation/Licence or the recognition certificate, as the case may be, by the concerned Regional Authority;
- (b) The Actual User has got the consequential changes effected from the concerned authority in the Industrial Licence issued by the Secretariat for Industrial Assistance (Ministry of Commerce and Industry) or Certificate of Registration as an Actual User issued by Director of Industries of the State Government or has received an acknowledgement for filing of a memorandum with the Secretariat for Industrial Assistance. Provided, however, the licensing authority issuing the IE Code may, condone the delay on payment of a penalty of Rs. 1000/-.

However, the change in the director of a public limited company shall not be considered change in the constitution of the company for the purposes of payment of the aforesaid penalty.

The constitution for the purposes of amendment of an IEC and payment of the aforesaid penalty would mean the change in partners in a partnership firm, trustees of a trust, members of the board of a society and directors of a private limited company.

Denomination of Import Authorisation Licence/ Certificate/Permissions

9.2 Import Authorisation Licence/Certificate/Permissions issued under the Policy shall indicate the value both in Rupees and in freely convertible currency(s) at the exchange rate(s) prevailing on the date of issue of the

Authorisation/Certificate/Licence/Permission. In the case of Authorisation/Certificate/Licence/Permissions where export obligation is imposed, the value of the export obligation shall be indicated both in freely convertible currency(s) and in Rupees equivalent at the exchange rate(s) prevailing on the date of issue of the Authorisation/Licence/Certificate/Permission. Such exchange rate(s) shall also be indicated on the import Authorisation Licence/Certificate/Permission.

9.2.1 The remittance of foreign exchange and discharge of export obligation against the Authorisation Licence/Certificate/Permission shall, however, be regulated in freely convertible currency. No enhancement in Rupee value shall be necessary if the remittance of foreign exchange is covered by the value of Authorisation/Licence/Certificate/Permission shown in freely convertible currency.

9.2.2 However, on the Advance Authorisation Licence(s), issued for exports to ACU countries, export obligation shall be denominated and discharged in ACU dollars.

9.2.3 The export obligation against Advance Authorisation for intermediate supply and Advance Authorisation for deemed export, where supplies are to be made within the country, shall be denominated in Indian rupees and the export obligation shall be discharged in Indian rupees with reference to the CIF value of imports in Indian Rupees irrespective of CIF value indicated on the Authorisation.

Applications Received After Expiry of Prescribed Date of Receipt

9.3 Wherever any application is received after the expiry of the last date for submission of such application but within six months from the last date, such application may be considered after imposing a late cut @ 10% on the entitlement.

Supplementary Claims

9.4 Whenever any application for supplementary claim is received, within the specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @ 10% on the entitlement.

Furnishing of Information

9.5 Every importer/exporter shall furnish such information as may be called for by the Director General of Foreign Trade or any officer duly authorised by him.

Clarifications On Policy/Procedures

9.6 A request seeking clarifications on any provision of the Policy or Handbook of procedures, importability or exportability of items under ITC(HS), may be made to the Director General of Foreign Trade in the form given in Appendix-28. The clarification may also be sought on Email.

Consumption Register

9.7 The importer shall maintain a register of items imported under a Licence/Authorisation and its consumption. The importer shall also maintain such a

register of items imported without and Authorisation and its consumption provided such items are imported subject to actual user condition.

The register shall be maintained in the form given in Appendix-23 except in respect of the scheme wherein period for retention of the consumption register is specifically mentioned, in all other cases, the register shall be maintained upto 3 years period from the date of import.

Export Facilitation

9.8 In order to resolve exporters' problems in a co-ordinated manner, the field offices of the Directorate General of Foreign Trade shall act as Export Facilitation Centres.

These offices shall function as nodal agencies to attend to the problems and grievances of the exporters, and also co-ordinate with different Departments to resolve their trade and export related problems.

In addition, Nodal Officers have also been nominated in other Ministries/ Departments and a list of such officers nominated to assist exporters is given in Appendix-17.

For resolving problems relating to different departments, facilitation committees shall be constituted in each department which shall be serviced by Directorate General of Foreign Trade.

Standing Grievance Committee

9.9 The detail of the Grievance Redressal Mechanism is given in para 2.49 of the Policy.

In order to facilitate speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to the Policy and Procedure, Grievance Committees have been constituted.

These Grievance Committees are chaired by (i) the Director General of Foreign Trade at the Headquarters and (ii) head(s) of the concerned Regional Authority (s) in the respective regional offices.

Grievance Committee will include representatives of the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils/Commodity Boards, Development Authorities, and Government Departments/technical authorities as their members.

9.9.1 The Chairman of the respective Grievance Committee(s) may also co-opt any other member. The meetings of such Committees shall be held on a monthly basis.

9.9.2 Every exporter/importer shall have a right to seek and have an opportunity to make a representation to and be personally heard, if he so desires, by the Grievance Committee. For this purpose, he may send his request in writing seeking such personal hearing.

9.9.3 A representation to the Grievance Committee may be made in the form given in Appendix-26.

Counter Assistance

9.10 For speedy disposal of applications, "Counter Assistance" will function in all the offices of the Directorate General of Foreign Trade.

A Foreign Trade Development Officer (FTDO) shall be incharge of the counter in each office. On submission of the application at the counter, applicant will be handed over a token and would be advised on the same day whether his application has been found complete and admitted for further processing by the office or whether is any deficiency that needs to be rectified.

9.10.1 Counter Assistance will send the application to the concerned section on the same day of its receipt for necessary scrutiny. If there are any deficiencies, these will be noted by the concerned section and returned to the counter on the same day. In case of complete applications, the applicant will be given a formal receipt indicating file number for further reference.

In case of deficient applications, the same will be returned to the applicant for complying with all the deficiencies pointed out by the concerned section.

Complete applications shall be processed by the concerned section within the time frame as given under paragraph 9.10.

Communication of any deficiency noted subsequently should be undertaken only with the approval of the head of office who shall be responsible for effective functioning of Counter Assistance.

9.10.2 Counter Assistance may also be availed of for amendments of minor nature/enquiries. Applications, in such cases, will be received in the regional offices at the counter against a proper receipt and the Authorisation/list/enquiry, as the case may be, shall be returned after carrying out necessary amendments/ giving necessary reply as far as possible on the same day, across the Counter.

Time Bound disposal of applications

9.11 The Regional Authority shall dispose off applications expeditiously. The following time schedule shall normally be followed to dispose of the applications provided the application is complete in all respects and is accompanied by the prescribed documents.

Sl. No.	Category Of Application	Time Limit For Disposal
1	2	3
a)	IEC Code Number	2 working days
b)	Advance Authorisation where Input-Output norms are notified or under paragraph 4.7, Advance Authorisation for Annual Requirement and DFIA	3 working days

1	2	3
	Advance Authorisation where Input-Output norms are notified but cases are to be placed before Norms Committee (NC)	15 working days
	Advance Authorisation where Input-Output Norms are not notified	45 working days
	Fixation of input output norms	90 working days
c)	DFRC/DEPB	3 working days
d)	EPCG Authorisation on self declaration basis	3 working days
	EPCG Authorisation for Fixation of nexus (other than those covered in (i) above	45 working days
e)	All Authorisation under Gem & Jewellery Scheme.	3 working days
f)	Revalidation of Authorisation and extension of export obligation period by R.A	3 working days
g)	Acceptance of Bank Guarantee/ Legal Undertaking	3 working days
	Redemption of Bank Guarantee/ Legal Undertaking for Advance Authorisation and DFIA.	15 working days
	Redemption of BG/LUT for EPCG Authorisations.	30 working days
h)	Issuance/renewal of status certificate.	3 working days
i)	Amendment of any category of Authorisation	3 working days
j)	Fixation of deemed exports Drawback rate	45 working days
k)	Miscellaneous	10 working days
l)	All applications filed through EDI mode	1 working day

Cases of undue delay in disposal of applications may be brought to the notice of the head of the regional offices by way of a written representation, which shall be promptly enquired into and responded to.

Date of Shipment/ Dispatch in respect of Imports

9.11 A date of shipment/dispatch for the purposes of imports will be reckoned as under :—

Mode of Transportation	Date of Shipment/Dispatch
By Sea	The date affixed on the Bill of Lading.
By Air	The date of the relevant Airway Bill provided this represents the date on which the goods left the last airport in the country from which the import is effected.
From land-locked countries	The date of dispatch of the goods by rail, road or other recognised mode of transport to the consignee in India through consignment basis.
By Post Parcel	The date stamp of the office of dispatch on the packet or the dispatch note
By Registered Courier Service	The date affixed on Courier Receipt/ Waybill
Multimodal transport	The date of handing over the goods to the first carrier in a combined transport Bill of Lading.

Date of Shipment/ Dispatch in respect of Exports

9.12 Date of shipment/dispatch for the purposes of exports will be reckoned as under :—

Mode of Transportation	Date of Shipment/Dispatch
	2
(i) By Sea	For bulk cargo, the date of Bill of Lading or the date of receipt, whichever is later. a) For containerised cargo, the date of "Onboard Bill of Lading", or "Received for Shipment Bill of Lading", where the L/C provides for such Bill of Lading. For exports by containers from Inland Container Depot (ICD), the date of Bill of Lading issued by shipping agents at the time of loading of export goods in the ICD after customs clearance. b) For Lash barges, the date of Bill of Lading evidencing loading of the export goods on board.
(ii) By Air	The date mentioned by the appropriate Officer of Customs on the Shipping Bill, evidencing

	2
	loading or handing over of goods to the air cargo complex, which are not international airports, or by way of rotation of flight number and date.
(iii) By Post Parcel	The date stamped on the postal receipt.
(iv) By Rail	The date of RR (Railway Receipt).
(v) By Registered Courier Service	The date affixed on Courier Receipt/ Waybill.
(vi) By Road	The date on which the goods crossed the Indian border as certified by the Land Customs Authorities.

However, wherever the Policy provisions have been modified to the disadvantage of the exporters, the same shall not be applicable to the consignments already handed over to the Customs for examination and subsequent exports upto the date of the Public Notice.

Similarly, in such cases where the goods are handed over to the customs authorities before the expiry of the export obligation period but actual exports take place after expiry of the export obligation period, such exports shall be considered within the export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation.

General Power of review

9.13 The Director-General of Foreign Trade may, on his own or otherwise, call for the records of any case pending with or decided by an officer subordinate to him or an officer of any EPC/FIEO including a Group/ Committee of officers nominated, appointed or authorised by him and pass such orders as he may deem fit.

APPENDICES

APPENDICES ARE AN INTEGRAL PART OF THE HANDBOOK OF PROCEDURES – VOLUME 1 (2004-2009) INCORPORATING THE ANNUAL SUPPLEMENT AS NOTIFIED BY THE PUBLIC NOTICE NO.1 (RE-2006)/2004-09 DATED 7th APRIL 2006.

THE APPENDICES ARE AVAILABLE ON THE DGFT WEBSITE AND CAN BE ACCESSED AT <http://dgft.gov.in>